दैनिक
जलते दीप
जोधपुर, बुधवार 27 मार्च 2024

पंजाब में नशे का कारोबार

पंजाब में नशे के कारोबार पर नकेल कसना लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि अगर वह सरकार में आएगी, तो इस धंधे पर पूरी तरह रोक लगा देगी। मगर अभी तक इस दिशा में कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। ताजा मामला यह है कि मुख्यमंत्री के जिले संगरूर में जहरीली शराब पीने से इक्कीस लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों का इलाज चल रहा है। इसे लेकर यह प्रश्न लोगों की जेहन में अटक गया है कि जब मुख्यमंत्री के जिले में जहरीली शराब के धंधे और मादक पदार्थों की पहुंच पर रोक नहीं लग पाई है, तो बाकी जगहों पर क्या स्थिति होगी। पंजाब में काफी समय से नशे की वजह से हो रही नौजवानों की मौतों को लेकर चिंता जताई जाती रही है। सीमावर्ती राज्य होने के कारण वहां पाकिस्तान के रास्ते मादक पदार्थों की पहुंच पर रोक लगाना भी कठिन बना हुआ है। ऐसे में अगर जहरीली शराब से मौतों का नया मामला आया है, तो उसे लेकर स्वाभाविक ही नए सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने छह लोगों को गिरफ्तार कर इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। नकली शराब का कारोबार कमोबेश हर राज्य की समस्या है। चोरी-छिपे शराब बनाने और बेचने वाले हर कहीं मौजूद हैं, मगर जो सरकारें सचमुच इस समस्या से पार पाने को लेकर संजीदा होती हैं, वे ऐसे कारोबारियों पर नकेल कसने में कामयाब ही देखी जाती हैं। पंजाब की तुलना दूसरे राज्यों से फिलहाल इसलिए नहीं की जा सकती, क्योंकि वहां नशे पर काबू पाना सरकार की प्राथमिकता है। वहां नशे के कारोबार के फलने-फूलने की वजहें भी अब काफी हद तक साफ हैं। उसमें अनेक रसूखदार लोगों और बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। इस तरह माना जा सकता है कि वहां का प्रशासन इस समस्या को लेकर सतर्क है। फिर यह समझना मुश्किल है कि संगरूर में किस तरह नकली शराब बनाई जा रही थी और प्रशासन को इसकी भनक तब मिल सकी, जब जहरीली शराब पीकर लोग मरने लगे। इस तरह के धंधे स्थानीय लोगों की जानकारी से बाहर नहीं होते। फिर स्थानीय लोगों से पुलिस का तालमेल ठीक हो, तो उसे भी इस तरह के धंधे की जानकारी मिल ही जाती है। मगर नकली शराब के धंधे में अक्सर देखा जाता है कि इसे चलाने वालों की पुलिस से सांठगांठ होती है। संगरूर में भी ऐसी किसी गठजोड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। नकली शराब पीकर मरने वाले ज्यादातर गरीब लोग होते हैं, जो कम पैसे में नशे के लिए ऐसी शराब खरीदते हैं। इनमें से ज्यादातर अपने परिवार के लिए रोटी कमाने वाले होते हैं। उनके मरने से पूरे परिवार के सामने संकट खड़ा हो जाता है। उनका संकट कुछ मुआवजा देकर दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमेशा से नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की सिफारिश की जाती रही है। मगर सरकारों और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा यह निकलता है कि हर घटना के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, पर उन्हें ऐसी कोई सजा नहीं मिल पाती, जो दूसरों के लिए नजीर बने। इसलिए भी जहरीली शराब के कारोबारियों पर शिकंजा कसना मुश्किल बना हुआ है। पंजाब सरकार इस सच्चाई से अनजान नहीं है।

स्वतंत्र जांच जरूरी

लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव व आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला नया नहीं है। खासकर चुनावी वेला में तो यह स्थिति चरम पर होती है। लेकिन इस टकराव का प्रभाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के स्वाभाविक प्रभाव को बाधित करने वाला नहीं होनी चाहिए। युद्ध की तरह से राजनीति के भी अपने नियम होते हैं और मुकाबले के लिये बराबर का अवसर भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही यह जरूरी है कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध को दूर करने के लिये संवाद की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहनी चाहिए, ताकि अनावश्यक गतिरोध को टाला जा सके। बीते गुरुवार को देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में आरोप लगाए गए कि खाते फ्रीज करके पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश सत्ता पक्ष की ओर से की जा रही है। यूं तो कांग्रेस पिछले पांच वर्षों में लगातार सत्ता पक्ष की रीतियों-नीतियों पर हमलावर रही है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस द्वारा लगाए आरोपों की गंभीरता पर भी विचार किया जाना चाहिए। वैसे भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और विश्वसनीय बनाने के लिये विपक्षी दलों को मुकाबले का बराबर अवसर तो मिलना ही चाहिए। निश्चित रूप से इससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता व प्रामाणिकता को संबल मिलता है। कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य विपक्षी पार्टी को आयकर विभाग की कार्रवाई से वित्तीय संकट की ओर धकेला जा रहा है। हालांकि, कांग्रेस पार्टी की मुद्दे को लेकर गंभीरता इस बात से भी उजागर होती है कि हाल-फिलहाल यह पहला अवसर है कि पार्टी के तीन शीर्ष नेता कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। विशेष तौर पर ऐसी स्थिति में जब देश में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है कांग्रेस के आक्षेप को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से किसी भी लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि सत्ता पक्ष विपक्षी राजनीतिक दलों को बराबर का मौका उपलब्ध कराये, जिससे चुनावी मुकाबला न्यायसंगत बना रह सके। यदि मुख्य विपक्षी दल यह आरोप लगाए कि ऐन चुनाव के वक्त पार्टी के खाते फ्रीज करके उसके चुनाव लड़ने और प्रचार करने में बाधा उत्पन्न हुई तो यह स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिये अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस के आरोपों की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। पार्टी का कहना है कि खाते फ्रीज होने से पार्टी के समक्ष उत्पन्न आर्थिक तंगी से पार्टी न विज्ञापन दे सकती है और न ही अपने नेताओं के लिये हवाई टिकट बुक करा पा रही है। उसका यह भी कहना है कि उसे रैली आयोजित करवाने में परेशानी हो रही है। हालांकि, कांग्रेस के आरोपों से इतर सरकार व आयकर विभाग के अधिकारियों की अपनी दलीलें हैं। उल्लेखनीय है कि गत 13 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईटीएटी के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें सौ करोड़ से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिये कांग्रेस पार्टी को आयकर विभाग से जारी नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने पार्टी को तब नये स्थगन आवेदन के साथ आईटीएटी का रुख करने की स्वतंत्रता दी थी। ऐसे में इस मुद्दे पर अंतिम राय बनाने से पहले सभी पक्षों के तर्कों पर विचार भी जरूरी है। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता ने इन आरोपों को पार्टी की हताशा का परिणाम बताया है। यह भी कि कांग्रेस के आरोपों से भारतीय लोकतंत्र की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद यह तथ्य निर्विवाद है कि किसी भी लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को अनुचित ही कहा जाएगा। इससे चुनावों की पारदर्शिता व विश्वसनीयता पर आंच आ सकती है। विपक्षी दलों के इन आरोपों को भी बल नहीं मिलना चाहिए कि सरकार विपक्ष को दबाने के लिये सरकारी एजेंसियों व विभागों का इस्तेमाल कर रही है। निश्चित रूप से ऐसे आरोपों से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लेकर अच्छा संदेश नहीं जाएगा।

प्रसंगतः सेवा का रास्ता

ऑस्ट्रिया में पैस्टोला नामक एक छात्र डॉक्टरी पढ़ रहा था। एक दिन जब वह कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक बच्चा मिला। एक छोटे से बच्चे को अकेला देखकर पैस्टोला ने उसे अपने साथ ले लिया। उसने उसके अभिभावकों को खोजने के लिए पुलिस में सूचना दी काफी दिनों तक जब बच्चे के अभिभावकों का कुछ पता न चला तो पैस्टोला ने उसे एक अनाथालय में रखवा दिया। पर उसे उस बालक से बेहद लगाव हो गया था, इसलिए वह अक्सर उसे अनाथालय में देखने आता और उसके लिए कुछ उपहार भी लाता। धीरे-धीरे पैस्टोला ने नोट किया कि अनाथालय में बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था तो है, लेकिन वहां के कर्मचारियों में दयाभाव नहीं है। इसलिए बच्चे उन कर्मचारियों के संरक्षण में ढंग से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। पैस्टोला ने अपनी पढ़ाई खत्म होते ही एक आंदोलन चलाया और निःसंतान तथा छोटी गृहस्थी वाले लोगों से अनुरोध किया कि वे अनाथ बच्चों को अपने परिवार में सम्मिलित कर लें और उन्हें लाड़-प्यार से पालें। ऐसा करने से बच्चों का समुचित विकास हो पाएगा और उन्हें जीने की राह मिल पाएगी। पैस्टोला के इस आंदोलन का लोगों पर सकारात्मक असर हुआ। अनेक उदार, धनी व शिक्षित लोगों ने ऐसे असहाय बच्चों को अपने परिवार में शामिल कर लिया। आत्मीयता एवं अपनत्व भरे माहौल में उन बच्चों का विकास होने लगा। पैस्टोला ने उन अनाथ बच्चों की देख-रेख में अपना जीवन लगा दिया। वह आजीवन अविवाहित रहा। पैस्टोला ने अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने के अलावा विधवाओं व वृद्धाओं की भी निःस्वार्थ मदद की। अपनी पूरी आमदनी उसने जरूरतमंदों पर लगाई। पैस्टोला की प्रेरणा से अनेक उदार लोगों ने भी अपने परिवारों में निराश्रितों को सम्मिलित किया। धीरे-धीरे यह आंदोलन दूर-दूर तक फैल गया। पैस्टोला के काम कई लोगों ने हाथ में ले लिया। आज भी ऑस्ट्रिया के अनेक लोग पैस्टोला के बताए रास्ते पर चल रहे है और असहायों की मदद कर रहे हैं।

केजरीवाल को सहानुभूति की उम्मीद!

दिल्ली के मुख्यमंत्री और 'आप' पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे यह सब जानते थे। सवाल सिर्फ कब गिरफ्तार होंगे का था। अब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ई डी) ने गिरफ्तार कर लिया है। यह शब्द लिखे जाने तक उन्हें ज़मानत नहीं मिली है, और इसी तरह की पहली गिरफ्तारियों को देखते हुए यही लग रहा है कि ज़मानत आसान नहीं है। ई डी सरकार के इशारों पर काम करती है, इस आशय के आरोप लगाने वाले यह भी कह रहे हैं कि आम-चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करके केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के एक कद्दावर नेता को चुप करने का काम किया है। पिछले एक अर्से से जिस तरह विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर बनाने की कोशिश हो रही हैं, उसे देखते हुए केजरीवाल की गिरफ्तारी पर न तो आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है, और न ही यह कहा जा सकता है कि यह गिरफ्तारी अप्रत्याशित थी। यह अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है कि इस समय ही यह गिरफ्तारी क्यों हुई। चुनाव से ठीक पहले हुई इस गिरफ्तारी से मतदाता को एक संदेश तो मिलता ही है कि गिरफ्तार होने वाले ने कुछ तो ग़लत किया ही है। दूसरी और शायद केजरीवाल भी गिरफ्तारी का राजनीतिक लाभ उठाने की उम्मीद में बैठे थे। वह स्वयं को पीड़ित दिखाकर मतदाता की सहानुभूति की उम्मीद तो कर ही सकते हैं।

- विश्वनाथ सचदेव

मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए किसी को इस तरह गिरफ्तार किए जाने की भले ही यह पहली घटना हो, पर झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लगभग इसी तरह कमज़ोर बनाया गया था। यह सही है कि गिरफ्तारी से ठीक पहले उन्होंने पद से त्यागपत्र देकर अपने उत्तराधिकारी की राह आसान बना दी थी, पर मामला यहीं तक सीमित नहीं था। सवाल मुख्यमंत्री की इस तरह की गई गिरफ्तारी के राजनीतिक संकेतों का है। किसी केजरीवाल अथवा किसी सोरेन ने कोई अपराध किया है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ऐसी किसी कार्रवाई के मंतव्य को समझने की भी आवश्यकता होती है। जिन स्थितियों में और जिस तरीके से ऐसी कार्रवाई हुई है, या हो रही है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि इस सबके पीछे विपक्ष को कमज़ोर बनाने और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हो रही है। सरकार यह कह कर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ईडी, सीबीआई , इनकमटैक्स जैसी संस्थाओं को सांविधानिक संरक्षण प्राप्त है और उनके कामकाज में सरकार दखलंदाजी नहीं करती। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के ही एक माननीय न्यायाधीश ने कभी सीबीआई को 'पिंजरे में बंद तोता' कहा था! सत्ता की राजनीति में तब और और आज कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। उल्टे, देखा यह जा रहा है कि जन-समर्थन राजनीतिक नेतृत्व को और अधिक एकाधिकारवादी बना देता है। बना रहा है!

जनतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का होना या चुनाव में जीतना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनावों का सही तरीके से होना, चुनाव में भाग लेने के लिए सबको समान और उचित अवसर मिलना जनतंत्र के औचित्य की एक महत्वपूर्ण शर्त है। आज जो स्थितियां देश में बनती जा रही हैं, वे, दुर्भाग्य से, इस आशय का कोई आश्वासन नहीं दे रही हैं। किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना एक कथित आरोपी मात्र का गिरफ्तार होना नहीं होता। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे अपने किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन यदि सज़ा देने के नाम पर किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है तो उसे उचित नहीं माना जा सकता। इसीलिए यह सवाल उठता है कि किसी केजरीवाल या किसी सोरेन को चुनाव से ठीक पहले ही गिरफ्तार करना क्यों ज़रूरी समझा गया? क्या इसे मात्र किसी अपराध की सज़ा देने की कोशिश के रूप में ही देखा जाना चाहिए? शायद नहीं।

यहां सवाल जनतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का भी है। यह कहना तो ग़लत होगा कि देश में जनतंत्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जनतंत्र को नये अर्थ देने की कोशिशों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। समय पर चुनाव होने अथवा किसी नेता की लोकप्रियता के आधार पर जनतंत्र की सफलता अथवा औचित्य को नहीं नापा-परखा जा सकता। जनतंत्र का अर्थ होता है नागरिक के अधिकारों, और कर्तव्यों का भी, संरक्षण। जनतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता के मानकों पर व्यवस्था कितनी खरी उतरती है। असहमति का स्वीकार और सम्मान जनतंत्र को गरिमा और ताकत, दोनों, देता है। क्या यह सब हम आज अपने देश में होता देख रहे हैं? इसके साथ ही मज़बूत विपक्ष की महत्ता को समझा जाना भी ज़रूरी है। जनतंत्र में विपक्ष का काम मात्र आलोचना करना नहीं होता, विपक्ष को ईमानदार, सजग चौकीदार की भूमिका भी निभानी होती है। विपक्ष की सतत जागरूकता जनतंत्र के सफल और सार्थक होने की पहली और ज़रूरी कसौटी है। लेकिन, दुर्भाग्य से हम अपने देश में विपक्ष को लगातार कमज़ोर किए जाने की कोशिशों को होता देख रहे हैं। कभी-कभी तो संदेह होता है कि सत्तारूढ़ पक्ष विपक्षहीन जनतंत्र की कोशिश में ही तो नहीं लगा?

विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी अथवा उन पर कार्रवाई किए जाने की लटकती तलवार से यह संशय होना स्वाभाविक है कि हमारा ताकतवर सत्तारूढ़ पक्ष कहीं विपक्षहीनता की स्थिति लाने की जुगाड़ में तो नहीं है? जिस तरह विपक्ष की सरकारों को कमज़ोर करने या काम न करने देने की स्थिति में लाने की कोशिशें होती दिख रही हैं, वह अच्छा संकेत तो नहीं ही है। जिस तरह दल-बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया या उन्हें तोड़े जाने की कोशिशें हो हो रही हैं, वह जनतंत्र की दृष्टि से अच्छा संकेत नहीं है। किसी लोकप्रिय नेता का अहंकार भी जनतंत्र की मूल भावना के विपरीत ही होता है।

दस साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी थी तो उसने कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा दिया था। इस नारे में कहीं कुछ ग़लत नहीं था। लेकिन जब किसी एक राजनीतिक दल से मुक्ति के बजाय समूचे विपक्ष से मुक्त जनतंत्र की बात कही जाती है, अथवा इसके प्रयास होते दिखते हैं तो सत्तारूढ़ पक्ष की मंशा पर शक होना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी, राज्यपालों द्वारा विपक्षी सरकारों के काम में अड़ंगा डालना, दल- बदल के लिए लालच देना, विपक्ष को कम न करने देना जैसे उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि जनतंत्र की मूल भावना पर आघात हो रहे हैं। यह आने वाले खतरों का संकेत है।

जनतंत्र चुनाव से चुनाव तक की प्रक्रिया का नाम नहीं है। चुनाव समय पर हों, यह एक शर्त है स्वस्थ जनतंत्र की, लेकिन एकमात्र शर्त नहीं। स्वस्थ और समर्थ जनतंत्र का तकाज़ा है कि जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो। जैसे न्याय होना ही नहीं, होते हुए दिखना भी चाहिए, वैसे ही जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव भी सम्मान किये जाने की प्रक्रिया के होते हुए दिखने की भी अपेक्षा करता है। आज जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए इस खतरे की आशंका स्वाभाविक है कि कहीं हम चुनावी एकाधिकारवाद की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? यह सवाल उन सबके लिए महत्वपूर्ण है जो जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और जिनके लिए जनतांत्रिक आदर्श मूल्यवान हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार है।)

विएतनाम में उभरता भारत

विश्वभर मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बनी पहचान को अगर कहीं ज्यादा मजबूती मिली है तो उसमे निश्चित रूप से हमारी साझी संस्कृति से जुड़ा एक देश विएतनाम भी है। जहां विकास द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले दस साल में भारत से मिले सहयोग से इस देश ने प्रगति के एक नए पथ को प्रशस्त किया है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हमारा पड़ोसी देश विएतनाम भी रहा है। चीन से भय ही उसकी तरक्की के रास्ते में बाधा बना हुआ था, अन्यथा ऊर्जा के विशाल स्त्रोत और विविध खाद्य पदार्थों की बहुलता के जरिए विएतनाम काफी आगे निकाल सकता था। भारत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के बाद विएतनाम को नया संबल मिला है। चीन से मिल रही आर्थिक और सामरिक चुनौती को विएतनाम काफी हद तक कमजोर करने में सफल हुआ है। भारत के साथ मिलकर वह अपनी साझी सामरिक शक्ति को लगातार बढ़ा कर अपने लिए एक सुरक्षित ढांचा तैयार कर लिया है। सब मरीन से लेकर अन्य सैन्य साजो समान से लैस विएतनाम की सेना को भारत से लगातार प्रशिक्षण मिल रहा है। विएतनाम के बंदरगाहों का विकास भी त्वरित तरीके से हो रहा है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध मे परास्त करने वाले इस देश को रूस से ज्यादा अब भारत की साझेदारी पर भरोसा है।

विएतनाम एक कम्युनिस्ट देश है। वहां की वेशभूषा और रहन-सहन या फिर कहें कि भौगोलिक परिस्थिति के कारण जापान, साउथ कोरिया या फिर चीन जैसे देशों का प्रभाव दिखता है। इसके बावजूद आज विएतनाम भारत के साथ सहज महसूस अगर कर रहा है तो उसके पीछे हाल के दिनों में भारत की सांस्कृतिक विरासत को लेकर किया जा रहा काम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा के बाद हुई है। यह पिछले तीन साल के अंदर भारतीय विदेश सेवाके अधिकारी डॉ. मदन मोहन शेट्टी के अथक परिश्रम का नतीजा है। यह सुखद संयोग है कि इस अधिकारी की तैनाती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यात्रा के बाद की गई। शेट्टी विएतनाम के हो च मिन्ह (मुम्बई की तरह विएतनाम की व्यवसायिक शहर है) के कांसुलेट जनरल हैं। उन्होंने विएतनाम के 64 राज्यों में से 30 ज्यादा राज्यों का तूफानी दौरा किया और स्थानीय शासन के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए। कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद यहां के स्थानीय शासन की दिलचस्पी भारत के साथ अपनी सांस्कृतिक साझेदारी विकसित करने में दिखाई दे रही है।

पिछले 40 से 50 साल के बाद नरेन्द्र मोदी के रूप मे भारत के किसी प्रधानमंत्री की यात्रा से यहां के लोग खुशी से झूम उठे थे। विदेशमंत्री एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री का अनुसरण किया और डॉ. मदन जैसे एक ऐसे तेजतर्रार भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी यहां भेजा, जिन्होंने म्यांमार में भारत की मजबूत कूटनीति स्थापित

- महेश वर्मा

करने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यह सुखद संयोग है कि विएतनाम की एक चोटी से भगवान शिव के 9 फीट ज्यादा ऊंचा शिव लिंग निकल रहा है तो वहां की सरकार हिन्दू मंदिरों का अधिग्रहण कर उसका जीर्णोद्धार कर रही है। विश्व का आठवां आश्चर्य वहां के पहाड़ों की चोटी पर बुद्ध स्तूप की स्थापना है। लद्दाख के लामा ने इसे यहां स्थापित किया है। ऐसे कई और प्रकल्पों को अब और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकिभारत से गए सम्मिट इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने स्वयंभू शिवशंकर तीर्थ क्षेत्र और बुद्धिज़्म के विस्तार को लेकर निवेश सहमति पत्र हस्ताक्षर किया। भारत और विएतनाम की साझी सांस्कृतिक विरासत को इससे और मजबूती मिलेगी।

विएतनाम अपनी प्रगति में भारत के महत्व को बखूबी समझता है। इसका प्रमाण यह है कि पिछले कुछ साल में भारत से विएतनाम को किये जा रहे निर्यात में आया उछाल है। भारत और वियतनाम के बीच लंबे समय से व्यापार और आर्थिक संबंध हैं जो समय के साथ लगातार बढ़े हैं। वर्ष 2000 में मात्र 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से, द्विपक्षीय व्यापार 2022 में बढ़कर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। 2022-2023 के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार 3.98त्न की वृद्धि दर्ज करते हुए 14.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वियतनाम को भारत का निर्यात 5.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि वियतनाम से भारतीय आयात 8.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022 में 13.92त्न की वृद्धि दर्ज करते हुए 15.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। भारत द्वारा निर्यात 1.95त्न की वृद्धि के साथ 7.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जबकि भारत द्वारा आयात 7.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ गया। भारत से वियतनाम को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में लोहा- इस्पात, विद्युत मशीनरी और उपकरण, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, ऑटो घटक, मांस और मत्स्य उत्पाद, अनाज, मक्का, कपास, रसायन और रासायनिक उत्पाद, सामान्य धातु, रत्न और आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। वियतनाम से भारत में आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली के सामान, धातु और धातुओं से बनी वस्तुएं, रसायन, मशीनरी और यांत्रिक हिस्से, इस्पात की वस्तुएं, प्लास्टिक की वस्तुएं, कॉफी और चाय, जूते, रबर की वस्तुएं, उर्वरक और रेशम।

भारतीयों की विएतनाम में संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यहां 70 हजार से ज्यादा भारतीय हैं जो आज विएतनाम की समृद्धि में नई इबारत लिख रहे हैं। हर भारतीय यहां अरबों डॉलर के व्यवसाय को चला रहे हैं। भारत के उत्पादों को लेकर अगर वेयरहाउसिंग जैसी सुविधा भारत बढ़ा दे तो विएतनाम के अंदर भारतीय व्यवसायियो के व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। रेल, शिक्षा चिकित्सा और पोर्ट जैसे क्षेत्र में यहां निवेश की अपार संभावना है। अडानी ग्रुप इस काम में यहां तेजी से काम कर रहा है।

आर्थिक रूप से सम्पूर्ण विश्व की कमर तोड़ देने वाली विभीषिका कोरोना से विएतनाम भी पूरी तरह हिल गया था। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। चिकित्सा सहायता के साथ विएतनाम को आर्थिक मदद करने में भी भारत पीछे नहीं रहा।विएतनाम सरकार को ऐसा लगने लगा कि भारत ही उसके दुख-सुख का साथी बन सकता है। फिर कॉन्सुलेट जनरल डॉ मदन मोहन ने विएतनाम सरकार से कई एक फैसले ऐसे करवाने में सफल रहे जिससे भारत और विएतनाम के बीच व्यापारिक सहयोग परवान चढ़ने लगा है। भारत से होने वाले व्यापार की दुश्वारियों को कम कर दिया गया है।

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के कगार पर खड़े भारत के लिए विएतनाम का साथ मायने रखता है। भारत सरकार भी इसे समझती है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में भारत विएतनाम को स्वाभाविक साझेदार मानता है। इसलिए आने वालों समय मे विएतनाम सरकार और भी सहूलियतों के साथ भारत से अपनी व्यापारिक भागीदारी को बढ़ाने पर ध्यान देने जा रही है। विएतनाम की कई देशों के साथ फ्री व्यापार की संधि है, जिसके जरिए भारत के निवेशकों को मजबूती देने का काम कर सकता है।

(लेखक, सम्मिट इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हैं। वह हाल ही में वहां से लौटे हैं।)

अफ़ग़ान-पाक टकराव के निहितार्थ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकाया है कि यदि काबुल किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है, तो हम उस कॉरीडोर को बंद कर देंगे, जिसके बज़रिये भारत, अफ़ग़ानिस्तान से व्यापार करता है। इंडिया से अफ़ग़ानिस्तान तक माल पहुंचाने का एक रूट चाबहार पोर्ट है, जो पाकिस्तान की सरहद को नहीं छूता। जब तक ईरान से अफ़ग़ानिस्तान के बेहतर रिश्ते हैं, यह मार्ग महफ़ूज़ है। इस मार्ग को चाबहार-हाजीगाक कॉरीडोर कहते हैं। दूसरा, हवाई मार्ग है, जो 2016 से काबुल और कंधहार को भारत से जोड़ता रहा है। तो क्या पाकिस्तान इस तरह का बयान देकर भारत को इन्वॉल्व करना चाहता है?

16 मार्च 2024 को उत्तरी वजीरिस्तान में एक पाकिस्तानी चौकी पर आत्मघाती हमले में दो अधिकारियों समेत सात सैनिकों की जान चली गई। इसकी ज़िम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के 'बहादुर समूह' ने ली थी। जवाब में पाकिस्तान ने 18 मार्च 2024 को अफगानिस्तान के अंदर 'बहादुर समूह' के ठिकानों को निशाना बनाया। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने काबुल-इस्लामबाद के संबंधों को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। इससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। लोगों को इसका डर है कि पाकिस्तान-अफग़ानिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर न छिड़ जाए।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ-साथ, बहादुर समूह से जुड़े आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर कई हाई-प्रोफाइल हमले किये थे, जिनमें दा गज्यानो कारवां, दा सुफियानो कारवां और जैश फुरसान मुहम्मद शामिल हैं। समूह की पहुंच उत्तरी वजीरिस्तान से आगे तक फैली हुई है, जो बन्नू, लक्की मारवात, डेरा इस्माइल खान और टैंक जैसे निकटवर्ती जिलों में सुरक्षा बलों के लिए संवेदनशील है। इससे पहले, 5 फरवरी 2024 को ख़ैबर पख़्तूनख्वा (केपी) के डेरा इस्माइल ख़ान के छोड़वान पुलिस स्टेशन पर एक हमले में पाक सुरक्षाबलों के 10 लोग मारे गये थे। 2023 से अब तक के आतंकी हमले में 991 लोग मारे जा चुके हैं। अलग-अलग घटनाओं को जोड़ दें, तो घायलों की संख्या 1500 पार है। इसमें 16 मार्च 2024 को उत्तरी वजीरिस्तान में आत्मघाती बम विस्फोट, 26 नवंबर 2023 को बन्नू के बकाकेहल क्षेत्र में आत्मघाती बम विस्फोट और 31 अगस्त 2023 को बन्नू के जानी खेल क्षेत्र में एक सैन्य काफिले पर आत्मघाती हमला भी शामिल है।

फिलहाल पैदा तनाव की वजह हाफिज़ गुल बहादुर ही है। वह अफगानिस्तान की सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान में उस्मानजई वजीर जनजाति के माडा खेल कबीले से आता है। हाफिज़ गुल बहादुर के पूर्वज 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाने जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाफिज़ गुल बहादुर जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) की छात्र शाखा से जुड़े थे। 2001 के अंत में अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के बाद, ये आतंकवादी सीमा पार उत्तरी वजीरिस्तान सहित पाकिस्तान के कबिलाई इलाकों में भूमिगत हो गए। यही लोग कालांतर में पाकिस्तान के लिए सिरदर्द साबित हुए। राष्ट्रपति मुशर्रफ पर हत्या के दो प्रयासों और अमेरिका के बढ़ते दबाव के बाद, पाकिस्तान ने 2004 में इस क्षेत्र में अभियान शुरू किया। 2004 में स्थानीय तालिबान नेता, नेक मुहम्मद की हत्या के बाद ऑपरेशन का विस्तार हुआ। हालांकि, 2006 के मध्य तक, हाफिज़ गुल बहादुर ने अपना रुख बदल दिया और सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया। बहादुर की पाकिस्तान से दोस्ती से कुछ विदेशी आतंकवादी नाराज हो गए, जैसे कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान (आईएमयू) के आतंकवादी, जिन्होंने उन पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का आरोप लगाया। इस बीच, हाफिज़ गुल बहादुर ने उस इलाके में वर्चस्व के लिए कर वसूली और सज़ा के मकसद से एक शूरा परिषद की स्थापना की। हालांकि, पाक सरकार से समझौते के बावजूद गुल बहादुर के अफगान तालिबान के साथ संबंध नहीं टूटे। अल कायदा ने दिसंबर 2007 में टीटीपी के बैनर तले विभिन्न पाकिस्तानी तालिबान समूहों को एकजुट करने की मांग की, मगर बहादुर का गुट बाहर ही रहा।

अपनी अलग पहचान बनाए रखने के बावजूद, बहादुर समूह को हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा और यहां तक कि टीटीपी जैसे प्रभावशाली गुटों के साथ अपने संबंधों से लाभ मिलता रहता है। बहादुर समूह और पाक सरकार के बीच 2006 में हुआ शांति समझौता, मई 2014 के अंत में समाप्त हो गया, इससे ठीक पहले कि पाकिस्तान ने उत्तरी

सम्पादकीय

नगर निगम दिवालिया लेकिन फिर भी वसूली में लापरवाह

जयपुर शहर की सरकार नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर है। पिछली सरकार ने जयपुर नगर निगम को दो टुकड़ों में बांट दिया था। हम बात करेंगे संयुक्त जयपुर नगर निगम की क्योंकि नगर निगम के पास हमेशा से फंड का टोटा रहा है। वह तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत का भला हो कि उन्होंने जयपुर में जब चुंगी समाप्त की तो ये प्रावधान किया था कि चुंगी पुनर्भरण के रूप में नगर निगम को एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसी फंड की वजह से नगर निगम का काम चल जाता है अन्यथा नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन के भी लाले पड़ सकते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी जयपुर नगर निगम वसूली के मामले में शून्य है। एक रिपोर्ट के अनुसार जयपुर शहर में बड़े लोगों पर नगर निगम का अरबों रुपया राजस्व के रूप में बकाया चल रहा है। हालांकि जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने राजस्व की उगाही के लिए कुर्की की धमकियां देना शुरू किया है लेकिन ये तो हमेशा से ही होता रहा है। इस बार क्या होगा ये देखने लायक है। पिछले एक महीने की रिपोर्ट देखें तो ग्रेटर निगम ने शहर में 308 से ज्यादा संस्थाओं पर रिकवरी के लिए कुर्की की कार्रवाई की है। ये सब छोटी मोटी मछलियां है। सेंट्रल पार्क स्थित पोलो क्लब, जेएलएन मार्ग वर्ल्ड ट्रेड पार्क, टोंक रोड स्थित राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) समेत कई सरकारी और प्राइवेट एजेंसियां हैं। इनसे 10 लाख से लेकर 10.39 करोड़ रुपए तक का यूडी टैक्स वसूलना है। इस बार एक अप्रैल 2023 से 21 मार्च 2024 तक निगम ग्रेटर ने 65.28 करोड़ रुपए का यूडी टैक्स वसूल कर लिया है। अभी 10 दिन का समय और है। हालांकि बड़ी संस्थाएं जिन पर एक करोड़ रुपए या उससे ऊपर बकाया चल रहा है। उन पर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इन सभी संस्थाओं को नोटिस जारी करने की औपचारिकता को पूरी कर ली गई है। कुछ संस्थाओं ने अब तक जवाब नहीं दिया। नगर निगम को चाहिए कि वह बड़े बकायादारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल लाए। जब बड़ों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो छोटे तो अपने आप ही लाइन पर आ जाएंगे। नगर निगम को बड़ी संस्थाओं और बकायादारों के खिलाफ सम्पत्ति जब्त करने की कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। ताकि नगर निगम कड़की के दौरे से बाहर निकल सके।

खुशहाल समाजों की रैंकिंग से भारत भ्रमित न हो

पाकिस्तान पिछली बार 108वें स्थान पर था, इस बार 122वें पर आ गया है, पर तब भी भारत से चार पायदान ऊपर है। जिस देश में खूब महंगाई है, जहां की जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही है, जहां धार्मिक उन्माद व्यापक है, जो आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, वह देश भी अगर हमसे खुशहाल है, तो ऐसी खुशहाली मापने के तरीकों पर विचार होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि खुशहाली को तय करने के पैमानों में अवश्य ही कोई पूर्वाग्रह या आग्रह है। क्योंकि ऋण की गुहार लगाता एवं त्राहिमाम करता पाकिस्तान को 122वें स्थान की रैंकिंग देना विडंबनापूर्ण एवं विसंगतिमय हैं, जो इस सूचकांक के महत्व को घटा देती हैं। जो दुनिया के खुश देशों के आकलन में त्रुटि की पूरी संभावनाएं होने को दर्शाता है। अनेक सवाल खड़े करती है यह खुशहाल देशों की रैंकिंग। यह विडंबना ही है कि धार्मिक पाबंदियों वाला कुवैत दुनिया का 13वां सबसे खुशहाल देश है। ऐसी अतार्किक सूची देखकर अफसोस एवं आश्चर्य भी होता है और चिंता भी होती है। क्या खुशहाली को धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता के आधार पर ज्यादा नहीं देखा जाना चाहिए? खुशहाली को केवल आर्थिक समृद्धि और संसाधनों की अधिकता में घटाकर देखना सही नहीं है। खुशहाली की रैंकिंग को देखकर भारत को कतई भ्रमित नहीं होना चाहिए।

ललित गर्ग।

143 देशों के विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर रहा है जिसमें फिनलैंड ने लगातार छठीं बार सर्वोच्च स्थान पाया है। यह बात भी गौर करने की है कि भारत में दस अंकों का सुधार हुआ है, फिर भी भारत के लिये आश्चर्यकारी एवं विचारणीय है। फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश करार दिया गया है, पर गौर कीजिए, वहां आबादी सिर्फ 56 लाख है। मतलब, इस देश की चुनौतियां बहुत कम हैं। धार्मिक वातावरण ऐसा है कि विद्वेष की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। छोटा राष्ट्र होने की वजह से सरकारों के सामने समस्याएं कम है। अत: फिनलैंड की स्थिति अच्छी है, पर उसकी तुलना भारत जैसे 140 करोड़ आबादी वाले देश से कैसे हो सकती है? यह बहस का विषय है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित इस वार्षिक रिपोर्ट में नॉर्डिक देशों ने 10 सबसे खुशहाल देशों में अपना स्थान बनाए रखा है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन ने शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। इन सभी देशों में समाज समस्यामुक्त एवं काफी सुलझा हुआ है और विविधता वहां ज्यादा समस्याएं पैदा नहीं करती है। देखने की बात है कि खुशहाली की रिपोर्ट विगत एक दशक से भी ज्यादा समय से जारी हो रही है और पहली बार अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देशों को शीर्ष 20 देशों में स्थान नहीं मिला है।

निर्मम युद्ध लड़ रहा इजरायल पांचवां सबसे खुशहाल देश है! पीड़ित फलस्तीन 103वें स्थान पर है, तो रूस 72वें स्थान पर और यूक्रेन 105वें स्थान पर। ये देश युद्ध के बावजूद भारत से ज्यादा खुशहाल हैं। पता नहीं, इस रैंकिंग पर कितना भरोसा किया जाए? जहां तक भारत का सवाल है, खुशहाली के सभी पैमानों पर हमें अपने प्रयास बढ़ाने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि हम प्रसन्न समाजों की सूची में क्यों नहीं अव्वल आ पा रहे हैं? यह सवाल सत्ता के शीर्ष नेतृत्व को आत्ममंथन करने का अवसर दे रहा है, वहीं नीति-निर्माताओं को भी सोचना होगा कि कहां समाज निर्माण में त्रुटि हो रही है कि हम लगातार खुशहाल देशों की सूची में सम्मानजनक स्थान नहीं बना पा रहे हैं। भारत सरकार इस रिपोर्ट को कितनी गंभीरता से लेती है, यह देखने वाली बात है। भारत में खुशहाली को बढ़ावा देने में यहां की जनसंख्या सबसे बड़ी बाधा है। भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की कट्टरता एवं संकीर्णता भी खुशहाल समाज निर्माण की बड़ी बाधा है। भारत जैसे विशाल और असमान विकास वाले देश के लिए 126वां स्थान कितना मायने रखता है? भारत में कई तरह का भारत है, एक अमीर व खुशहाल भारत है, तो उसमें एक गरीब भारत भी है। गरीब भारत भी विकास कर रहा है, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि अभी देश को समग्रता में खुशहाल देशों में अव्वल स्थान बनाने में वक्त लगेगा। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की आबादी महज 56 लाख है, उसके लिए विकास आसान है। भारत के मुम्बई, दिल्ली, कोलकता शहर में इसमें कहीं ज्यादा लोग रहते हैं। वैसे भी खुशी महसूस करना व्यक्ति के खुद की सोच पर निर्भर करता है। इसलिये प्रश्न है कि हमारी खुशी का पैमाना क्या हो? अधिकतर लोग छोटी-छोटी जरूरतें पूरी होने को ही खुशी मान लेते हैं। इससे उन्हें उस पल तो संतुष्टि मिल जाती है, उनका मन खिल जाता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, स्थायी नहीं होती। इच्छा पूरी होने के साथ ही उनकी खुशी भी कमजोर होने लगती है। खुशी एवं प्रसन्नता हम सबकी जरूरत है, लेकिन प्रश्न है कि क्या हमारी यह जरूरत पूरी हो पा रही है, ताजा आकलन से तो यही सिद्ध हो रहा है कि हम खुशी एवं प्रसन्नता के मामले में लगातार पिछड़ रहे हैं। विडम्बनापूर्ण स्थिति तो यह है कि हमारा भारतीय समाज एवं यहां के लोग अपने ज्यादातर पड़ोसी समाजों से कम खुश है। खुशहाली की रिसर्च में खुशहाली को राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक सुविधाओं से मापा जाता है। लेकिन खुशियां का दायरा इतना छोटा तो नहीं होता। विकास की सार्थकता इस बात में है कि देश का आम नागरिक खुद को संतुष्ट और आशावान महसूस करे। स्वयं आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बने, कम-से-कम कानूनी एवं प्रशासनिक औपचारिकताओं का सामना करना पड़े, तभी वह खुशहाल हो सकेगा। डिजिलीकरण, आर्थिक नवाचार जैसी घटनाओं ने आम आदमी को अधिक परेशानी एवं समस्याएं दी है। समस्याओं के घनघोर अंधेरों के बीच उनका चेहरा बुझा-बुझा है। न कुछ उनमें जोश है न होश। अपने ही विचारों में खोए-खोए, निष्क्रिय और खाली-खाली से, निराश और नकारात्मक तथा ऊर्जा विहीन। हाँ सचमुच ऐसे लोग पूरी नींद लेने के बावजूद सुबह उठने पर खुद को थका महसूस करते हैं, कार्य के प्रति उनमें उत्साह नहीं होता। ऊर्जा का स्तर उनमें गिरावट पर होता है। क्यों होता है ऐसा? कभी महसूस किया आपने? यह स्थितियां एक असंतुलित एवं अराजक समाज व्यवस्था की निष्पत्ति है। ऐसे माहौल में व्यक्ति एवं समाज खुशहाल नहीं हो सकता। खुशहाली सूचकांक के लिए अर्थशास्त्रियों एवं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम व्यापक स्तर पर शोध करती है, यह टीम समाज में सुशासन, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, जीवित रहने की उम्र, भरोसा, सामाजिक सहयोग, परोपकार, दान भावना, स्वतंत्रता और उदारता आदि को आधार बनाती है। रिपोर्ट का मकसद विभिन्न देशों के शासकों को आईना दिखाना है कि उनकी नीतियां लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाने में कोई भूमिका निभा रही हैं या नहीं? हमारा शीर्ष नेतृत्व आजादी के बाद से ही निरन्तर आदर्शवाद और अच्छाई का झूठ रचते हुए सच्चे आदर्शवाद के प्रकट होने की असंभव कामना करता रहा है, इसी से जीवन की समस्याएं सघन होती गयी है, नकारात्मकता के इस व्यूह को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुशी एवं प्रसन्न जीवन के लक्ष्य को आकार दिया है, उन्होंने गहन अंधेरों से देश की जनता को बाहर निकालते हुए विगत एक दशक में अपने कामकाज एवं नीतियों से एक आशावाद उकेरा है। भारत में युवा सबसे अधिक खुश हैं, जबकि निम्न मध्यमवर्गीय लोग सबसे कम खुश हैं। भारत में अधिक उम्र उच्च जीवन संतुष्टि से जुड़ी है और यह उन दावों के विपरीत है कि उम्र और जीवन संतुष्टि के बीच सकारात्मक संबंध केवल उच्च आय वाले देशों में मौजूद है। भारतीयों के बीच संतोष के भाव, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता के भाव में विस्तार जारी रहना चाहिए। भारत का वर्तमान खुशहाली वाला समाज बनने को तत्पर है, भले ही दुनिया की कुछ खुशहाली रैंकिंग तय करने वाली एजेंसियां इससे असहमत हो।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
नौकरी में पदोन्नति होगी। गृहस्थ जीवन में भी आनंद का वातावरण छाया रहेगा। व्यापार के उद्देश्य से कहीं बाहर भी जाना हो सकता है। आज स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम रहने की संभावना है। शारीरिक रूप से आलस्य की भावना रहेगी।

वृष
काम की भागदौड़ के कारण परिजनों के प्रति ध्यान नहीं दे पाएंगे। हानिकर विचार, वर्तन और आयोजन से दूर रहें। पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। कहीं जाने का कार्यक्रम आज हो सकें, तो टाल दें। सरकारी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।

मिथुन
क्रोध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज आपके अहम को कोई चोट न पहुंचे और आपका किसी से झगड़ा न हो, इसका ध्यान रखें। शारीरिक रूप से शिथिलता और मानसिक रूप से चिंता बनी रहेगी।

कर्क
आज आप दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ काम कर सकेंगे। सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा तथा आर्थिक व्यवहार करने में सफलता प्राप्त होगी। आज नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का अच्छा सहयोग मिलेगा। भागीदारों से लाभ होगा।

सिंह
आज आपको अपने उग्र स्वभाव पर संयम रखने की जरूरत है। शारीरिक और मानसिक रूप से शिथिलता का अनुभव होगा। अधिक परिश्रम के बावजूद अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। संतान के विषय में आपको चिंता हो सकती है।

कन्या
विवाहोत्सुक लोगों को जीवन साथी प्राप्त होने के योग हैं। रुचिकर भोजन प्राप्त होगा। आज का दिन आप के लिए शुभ फलदायी होगा। व्यावसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा। काम में सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। आंखों में पीड़ा होने की संभावना है।

तुला
आर्थिक दृष्टिकोण से सावधानी बरतने का समय है। आज नकारात्मक मानसिकता के साथ व्यवहार न करें। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे। मन में दुख और असंतोष की भावना हो सकती है।

वृश्चिक
मित्रों और स्वजनों के साथ वैचारिक स्तर पर मनमुटाव हो सकता है। स्वभाव में उग्रता और क्रोध की भावना रहेगी। धार्मिक काम में धन का खर्च होगा। धन का आकस्मिक व्यय हो सकता है। विवाद या झगड़े से हर संभव दूर रहें।

धनु
नई परियोजना की शुरुआत के लिए आज दिन शुभ है। सरकार की ओर से लाभ मिलने संभावना है। छोटे प्रवास का आयोजन हो सकता है। दोस्तों, करीबियों या पड़ोसियों के साथ पुरानी अनबन की घटना में सकारात्मक परिणाम आएगा।

मकर
आप नए संपर्क बना सकेंगे। मित्रों के साथ मौज-मस्ती करने का समय है। प्रवास की भी संभावना है। जीवनसाथी के साथ संबंध अधिक मधुर बनेंगे। सहोदरों एवं बुजुर्गों से लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ
आपके लिए आज का दिन शुभफलदायी होगा। विविध क्षेत्रों में मिलने वाले लाभ से आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। मित्रों के पीछे खर्च भी होगा और उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। किसी प्रवास या पर्यटन स्थल पर जाने से दिन रोमांचक बन जाएगा।

मीन
पारिवारिक जीवन में खुशी रहेगी। सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। सरकारी कामकाज की बाधाएं दूर होंगी। आपके काम सरलतापूर्वक संपन्न होंगे। तन-मन में आनंद की अनुभूति होगी। आपके भाग्य में निखार आ सकता है। आर्थिक हानि होगी। पानी से दूर रहें।

आज का इतिहास

27 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- इंग्लैंड के शासक चार्ल्स द्वितीय ने बांबे को 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था।
- स्पेन और फ्रांस ने 1721 में मैड्रिड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- अमेरिकी कांग्रेस ने देश में नौसेना की स्थापना को 1794 में स्वीकृति दी।
- पहले स्टीम फायर इंजन का सफल परीक्षण सन 1841 में न्यूयार्क में किया गया।
- अब्राहम गेस्नर ने 1855 में केरोसिन(मिट्टी के तेल) का पेटेंट कराया।
- पहला अंतरराष्ट्रीय रग्बी मैच स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच 1871 में खेला गया।
- बोस्टन से न्यूयार्क के बीच 1884 में पहली बार फोन पर लंबी दूरी की बातचीत हुयी।
- इतालवी आविष्कारक जी मारकोनी द्वारा 1899 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच पहला अंतरराष्ट्रीय रेडियो प्रसारण किया गया।
- अमेरिका ने 1901 में फिलीपीन्स के विद्रोही नेता एमिलियो एग्विनाल्डो को अपने कब्जे में लिया।
- जापान ने 1933 में लीग ऑफ नेशंस से खुद को अलग कर लिया।
- यूरोपीय देश लिथुआनिया में 1944 में लगभग दो हजार यहूदियों की हत्या कर दी गयी।
- अमेरिकी सरकार ने 1956 में कम्युनिस्ट अखबार डेली वर्कर को जब्त कर लिया।
- सन 1961 में आज के दिन से पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई।
- टेनेरीफ़ में 1977 में दुनिया की सबसे भयानक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें तकरीबन 600 लोग मारे गए थे।
- यूरोपियन फ़ाइटर एअरक्राफ़्ट यूरोफाइटर ने 1977 में पहली उड़ान भरी।
- ए.एफ़.एम.ए.चौधरी 1982 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे।
- अंतरिक्ष में 1989 में अमेरिका के मिसाइल रोधी उपग्रह का परीक्षण विफल हुआ।
- पहला मैक्रो वायरस मेलिसा की 1999 में सूचना दी गई।
- रूस ने 2003 में घातक टोपोल आर एस-12 एम बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया।
- यासीन मलिक ने 2006 में कश्मीर में जनमत संग्रह कराए जाने की मांग की।
- अंतरिक्ष यान एंडेवर 2008 में पृथ्वी पर सफलतापूर्वक सुरक्षित लौटा।

27 मार्च को जन्मे व्यक्ति

- जर्मनी के एक भौतिकशास्त्री एवं गणितज्ञ वेलहेलम रोंटगन का 1845 में जन्म हुआ।
- फ्रांसीसी लेखक स्टेफन वल का जन्म 1922 में हुआ।
- एक प्रसिद्ध मानव विज्ञानी और नारीवादी विद्वान लीला दुबे का जन्म 1923 में हुआ।
- भारतीय राजनीतिज्ञ बनवारी लाल जोशी का जन्म 1936 में हुआ।
- फ्रांसीसी कवियों के अनुवादक और पत्रकारिता के प्रोफ़ेसर हेमन्त जोशी का जन्म 1954 में हुआ।

27 मार्च को हुए निधन

- भारत में मुहम्मदन एंग्लो-ओरिएण्टल कॉलेज की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान की 1898 में पुण्यतिथि।
- ग़दर पार्टी के प्रमुख नेता पंडित कांशीराम का 1915 का निधन।

विशेष आलेख

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के सात चरणों का चक्रव्यूह पार करना नहीं होगा आसान

अजय कुमार।

उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर पूरे देश मे कौतुहल दिखाई दे रहा है। लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़े राज्य यूपी में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में एक तरफ एनडीए के तले मोदी की 'सेना' जीत की हुंकार भर रही है तो दूसरी ओर राहुल गांधी के अगुवाई में 'इंडी' गठबंधन ताल ठोक रहा है। दोनों गठबंधनों में बस फर्क इतना है कि जहां एनडीए की ओर से मोदी पुन: प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वहीं इंडी गठबंधन ने कौन होगा पीएम पर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन लगता यही है कि यदि इंडी गठबंधन के लिये सत्ता की राह बनी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे। खैर, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। कौन होगा अगल प्रधानमंत्री ? यह सात चरणों के मतदान के बाद 04 जून को पता चलेगा, जब वोटों की काउंटिंग होगी। इसी लिये फिलहाल तो सात चरणों के चक्रव्यूह को भेदने के लिये ही सभी पार्टियो मैदान में ताल ठोंक रही हैं। 19 और 26 अप्रैल को प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण का मतदान होगा। इन दोनों चरणो में पश्चिमी यूपी की 16 सीटों पर वोटिंग होगी। प्रथम चरण और दूसरे चरण के मतदान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्रमश: आठ-आठ सीटों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। 07 मई को भी तीसरे चरण में दस सीटों पर मतदान होगा इसमें भी दस में से पश्चिमी यूपी की चार सीटें शामिल होंगी। इसके बाद 13 मई को चौथे, 20 मई को पांचवें, 25 मई को छठे और 01 जून को सातवें चरण का मतदान होना होगा। शुरू के तीन चरणों में जो राजनैतिक जंग पश्चिमी यूपी से शुरू होगी वह चौथे और पांचवे चरण में रूहेलखंड, अवध की सीटों पर तो छठे और सातवें चरण में पूर्वांचल में पहुंच कर समाप्त हो जायेगी। चार जून को नतीजे आयेंगे। 2024 लोकसभा चुनावों की शुरुआत पश्चिमी यूपी की आठ लोकसभा सीटों पर से होगा। पहले चरण में चुनाव के लिए आठ सीटों में से, भाजपा ने 2014 के चुनावों में सभी सीटें जीती थीं। 2014 में पार्टी ने अकेले प्रदेश भर में 71 सीटें जीतीं थीं। जबकि एनडीए गठबंधन के पास कुल 73 सीटें थीं। 2019 के चुनाव में इन सीटों पर सपा-रालोद और बसपा गठबंधन के खिलाफ लड़ाई में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने 8 में से केवल तीन सीटें जीतीं। ऐसे में सपा और बसपा को पूर्वांचल में कई सीटें मिलीं, जबकि बीजेपी को पूरे प्रदेश में सिर्फ 62 सीटें मिलीं थीं। 2024 का चुनाव संग्राम भी फिर पश्चिम यूपी से शुरू होगा। शुरुआत में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से यहां के राजनीतिक हालात में काफी बदलाव आया है, जिसका असर चुनाव में दिख रहा है। यह चुनाव क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति रालोद नेता जयंत चौधरी की स्थिति भी तय करेगा। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान की हैट्रिक कोशिशों की परीक्षा होगी। यह चुनाव तय करेगा कि बीजेपी नेता वरुण गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। यह चुनाव यह भी तय करेगा कि नखतौर विधायक ओम कुमार संसद में जा सकेंगे या नहीं। यह क्षेत्र किसान और जाट नेता अजीत सिंह के प्रभाव वाला माना जाता है। चाहे आप जीतें या हारें, जीतने वाला पक्ष हमेशा सोचता है कि उसका पलड़ा भारी है। अजीत को अपनी बदनामी की भारी राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ी। यह चुनाव अजीत सिंह के बिना होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से जयंत चौधरी को अजीत का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिशें अंत तक जारी रहीं। आख़िरकार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की सत्ताधारी पार्टी की चाल सफल रही। पिछले चुनाव में जयंत जाट दलित मुस्लिम गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। यह चुनाव तय करेगा कि जयंत का फैसला कितना सही है। 2019 का लोकसभा चुनाव में जो सपा,बसपा और रालोद एक गठबंधन का हिस्सा थे,वह बिखर चुके हैं। बसपा अकेली चुनाव लड़ रही है तो रालोद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बार पहले चरण की आठ सीटों में से चार पर सपा, तीन पर बसपा और एक पर रालोद को संघर्ष करना पड़ा। बसपा ने अपने हिस्से की तीनों सीटें (सहारनपुर, बिजनौर और नगीना) जीत लीं। सपा ने चार में से दो सीटें (मुरादाबाद और रामपुर) जीतीं। आरएलडी का खाता नहीं खुल सका। बीजेपी ने कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में सीटें जीती थीं।

बात आजम की चर्चा के बिना पूरी नहीं हो सकती है। प्रथम चरण में ही रामपुर की संसदीय सीट के लिये मुकाबला होना है। 2019 और उसके पहले के चुनाव में कभी समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान की रामपुर समेत कई सीटों पर जीत तय रहती थी।

केजरीवाल की गिरफ्तारी असाधारण घटना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक ऐसी बड़ी घटना है, जिसकी तुलना किसी भी पूर्व गिरफ्तारी से नहीं हो सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके पूर्व 2 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे और त्यागपत्र देने के बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। वस्तुत: केजरीवाल का मामला इस रूप में गुणात्मक रूप से भिन्न है क्योंकि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियानों, आंदोलन की अगुवाई करते हुए यहां तक पहुंचे। उनके बैनर का नाम ही था इंडिया अगेंस्ट क्रप्शन और उन्होंने यू.पी.ए. सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कई केंद्रीय मंत्रियों जिनमें प्रणब मुखर्जी से लेकर कपिल सिब्बल, पी.चिदंबरम आदि शामिल थे, सबको भ्रष्टाचारी बताते हुए उनका त्यागपत्र देने एवं गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। आम लोगों में छवि यह बनी थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हीरो अन्ना हजारे के संरक्षण में उभरा है और उसके पास एक टीम है जिसमें लडने् और व्यवस्था बदलने का माद्दा है। हालांकि लंबे समय तक उनकी घोषणा यही रही कि वह राजनीति में नहीं जाएंगे कोई दल नहीं बनाएंगे। राजधानी दिल्ली में उनकी पूरी लड़ाई ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर थी। पूरी दिल्ली में उन्होंने धरना, प्रदर्शन, सभाएं कीं और जनता के बड़े समूह को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि लोगों को कठिनाइयां थीं, और वह जो बात बोलते थे वह व्यावहारिक रूप से सबके जीवन में लागू हो रही थी। शीला दीक्षित, उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए तब केजरीवाल और उनके साथियों का जवाब देना मुश्किल होता था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठकर खड़ा होने वाला नेता अगर ऐसे शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो इससे बड़ी त्रासदी भारतीय एक्टिविज्म और राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकती। किसी का गिरफ्तार होना या उस पर आरोप लगा होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। न्यायालय ही उसके दोषी या निर्दोष होने का प्रमाण देता है। इसलिए देश भर के ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के अंत की कामना से किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों उन सबके लिए यह अत्यंत दुखद स्थिति है। सबकी चाहत यही होगी कि केजरीवाल और उनके साथी भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हों। ऐसा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी आंदोलन पर भारत के आम लोग लंबे समय तक विश्वास नहीं करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले की कानूनी कार्रवाई अब तक जिस दिशा में आगे बढ़ी है और छानबीन के आधार पर जिस तरह की बातें सामने आई हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चुनाव में भाषा का संयम एवं वचनों की मयार्दा जरूरी

-ललित गर्ग

लोकसभा चुनावों जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, कई नेताओं की जुबान फिसलती जा रही है, वे राजनीति से इतर नेताओं की निजी जिंदगियों में तांक-झांक वाले, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले ऐसे बोल बोल रहे हैं, जो न सिर्फ. आपत्तिजनक हैं, बल्कि राष्ट्र-तोड़क है। चुनावी रैलियों में जनता के सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने के मकसद से ये नेता मयार्दा, शालीनता और नैतिकता की रेखाएं पार करते नजर आए हैं। गलत का विरोध खुलकर हो, राष्ट्र-निर्माण के लिये अपनी बात कही जाये, अपने चुनावी मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाये, लेकिन गलत, उच्छृंखल एवं अनुशासनहीन बयानों की राजनीति से बचना चाहिए। बड़ा सवाल है कि एक ऊजार्वान एवं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या वाकई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल औचित्यपूर्ण है? चुनाव की तारीख तय होने एवं चुनावी पारा बढ़ने के बाद नेताओं के बयानों में तीखापन एवं हल्कापन आ गया है। एक तरफ गर्मी चुभन का अहसास करा रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में भाषायी अभद्रता एवं उच्छृंखलता घाव पर नमक छिड़क रही है। नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि सही तरीके से बोले गए शब्दों में लोगों को जोड़ने की ताकत होती है, जबकि गलत भाषा एवं बोल का इस्तेमाल राजनीतिक धरातल को कमजोर करता है।

नेताओं के बयान शालीनता एवं मयार्दा की सारी सीमाएं लांघ रही है। राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई संबंधी टिप्पणी ह्यशक्ति से जुड़े धार्मिक मूल्यों का अपमान करने और कुछ धार्मिक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए धर्मों के बीच शत्रुता पैदा करने के ह्यदुर्भावनापूर्ण इरादे को दशार्ती है। प्रारंभ में लालूप्रसाद यादव का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर परिवार विषयक आरोप भाजपा के लिये रामबाण औषधि बना है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को लेकर किए पोस्ट में एक्ट्रेस की फोटो के साथ भद्दा कमेंट महिला-शक्ति का अपमान बना है। ईवीएम के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी के लिए निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि तथ्यों के सत्यापन के बिना इस तरह का ह्यदुष्प्रचार और गलत सूचना राष्ट्रीय अखंडता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए नुकसानदायक है। ईवीएम और निर्वाचन आयोग के बारे में भ्रामक टिप्पणी ह्यलोक अव्यवस्था पैदा करने के इरादेह्ल से की गई हैं। जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, विवादास्पद बयानों की झड़ी भी लगने लगी।

हमारे देश की राजनीति में संयमित भाषा एवं अनुशासित बोल-बयान एक महत्वपूर्ण अंग होती है। लोकतंत्र में उसी नेता का बोल-बाला होता है, जिसकी भाषा एवं वचनों पर पकड़ मजबूत होती है। आजादी के बाद देश में जिस प्रकार राजनीति में बदलाव आता गया, उसी प्रकार राजनेताओं की भाषा और आरोप-प्रत्यारोप की शैली भी बदलती गई। आज कुछ राजनीतिक दलों के नेता अपने विपक्षी राजनेता को ह्यपप्पूह्ल जैसे शब्दों से ताना मारते हैं, तो कोई विपक्षी नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिये चौकीदार चोर है या चायवाला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हमारे देश की राजनीति में मयार्दा नाम का कोई शब्द बचा है? ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने से पहले हमारे ये राजनेता जरा भी नहीं सोचते कि उसका उनकी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

भारतीय राजनीति में स्तरहीन, हल्की और सस्ती बातें कहने का चलन काफी समय से है। लेकिन पिछले दो दशकों में यह वीभत्स रूप धारण कर चुका है। उस समय जब राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा था तो काफी विवाद हुआ और बड़ी तादाद में लोगों ने लोहिया का विरोध किया। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे भी काफी कुछ बोल चुके हैं और उनका पीएम मोदी के लिए रावण वाला बयान काफी चर्चा में रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हल्की बात कहते हैं मणिशंकर अय्यर। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत ही सस्ते शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने तो नीच, कातिल जैसे शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल किया था जिसमें उनकी हताशा साफ झलकती है। कड़वे एवं गलत बयानी के मामले में कांग्रेसियों की तो सूची काफी लंबी है। चाहे वह अधीर रंजन हों या दिग्विजय सिंह या फिर संजय निरुपम और प्रियंका गांधी। आम आदमी पार्टी के नेता एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने तो सारी हदें पार कर दी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम की निंदा चोर के रूप में की थी। सभी ने मौका देखकर बेहद हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी खीझ एवं बौखलाहट का पता चलता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मोदी और उनकी पार्टी ने ऐसे अमर्यादित शब्दों और टिप्पणियों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने करोड़ों समर्थकों के सामने इन शब्दों और उन्हें बोलने वालों के खिलाफ माहौल बना दिया। नरेन्द्र मोदी को चाय वाला कहकर उनका उपहास उड़ाने वाले विपक्षियों को तो उन्होंने अपने कार्यों और उपलब्धियों से आईना दिखा दिया। आज चाय वाला शब्द मेहनतकश लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गया है।

मतदाताओं को आकर्षित एवं अपने पक्ष में करने के फेर में राजनीति को रसातल में धकेलने की मानो होड़ मची हुई है। क्षणिक रोमांच एवं तत्काल चुनावी लाभ के लिए मयार्दा को तार-तार करने वाले इन नेताओं को आत्म-चिंतन की सख्त जरूरत है। मर्यादित भाषा में विभिन्न दलों और नेताओं की आलोचना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। भाषा की मयार्दा और वाणी में संयम भारत के लोकतंत्र का आधार है। बेलगाम भाषा से क्षणिक प्रचार और सुर्खियां बटोरना सम्भव है लेकिन अतीत में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो ये दशार्ते हैं कि ऐसे नेताओं को जनता भी कुछ समय बाद ही भूल जाती है। नेताओं को हर हालत में भाषा की मयार्दा एवं शालीनता को बनाए रखना चाहिए। भले ही चुनाव का वक्त आसमान से तारे तोड़ लाने के वायदे करने का वक्त है और खामियों को दबाने और उपलब्धियों के बखान का वक्त है। लेकिन यह सब करते हुए भाषा की शालीनता एवं कड़वे बोल से बचने की जरूरत है।

यह वक्त मतदाता के जागने एवं विवेक से मतदान करने का भी है। वह अच्छे-बुरे का फर्क करके तार्किक आधार पर अपने बेशकीमती मत का उपयोग करे। विडंबना ही है कि अमृतकाल से गुजरते देश में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग विष और अमृत के भेद को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाया है। नेताओं के गलत, बेबुनियाद एवं तथ्यहीन बयानों कर सत्यता को जाने बिना उन पर विश्वास कर मतदाता लोकतंत्र को कमजोर करता है। भारतीय राजनीति में दागियों का दखल और धनबल का बढ़ता वर्चस्व यही बताता है कि हमारा मतदाता इन संवेदनशील मुद्दों के प्रति जागरूक नहीं हो पाया है। निश्चित रूप से मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो वोट डालने घर से नहीं निकलता। जो बड़ा तबका निकलता भी है वह भी धर्म, जाति, क्षेत्र और धनबल से रचे सम्मोहन से मुक्त नहीं हो पाता।

विशेषतः दक्षिण भारत की राजनीति में भाषा को राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु के नेता इसी भाषाई आग्रह के साथ कब और क्या बोल दें, यह कोई नहीं जानता। इससे समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ मामलों की चर्चा आज भी होती है। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान एक नेता की टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस तरह के बयानों से बना बनाया खेल बिगड़ जाता है और निजी छवि भी धूमिल हो जाती है। फिर अगर आप बड़े पद पर हैं और आपको हजारों लोग फॉलो करते हैं तो भाषा संयम और मयार्दा अत्यंत जरूरी हो जाती है। द्रविड़ राजनीति में गाहे-बगाहे ऐसे अवसर आते रहते हैं जब मंच से नेता वाहवाही बटोरने के लिए ऐसा कुछ कह जाते हैं, जिससे न केवल उनकी बल्कि पार्टी की भी फजीहत होती है। एक वर्ग को खुश करने की चाह में और अपने आला नेता की चाटुकारिता में बिना सोचे समझे बोलने के गंभीर परिणाम होते हैं। हकीकत यह है कि यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ रही है। कौन सा नेता कब वाणी का संयम खो दे, कहा नहीं जा सकता।

प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा क्यों था जरुरी, जबकि देश में लोकसभा के महत्वपूर्ण चुनाव हो रहे है?

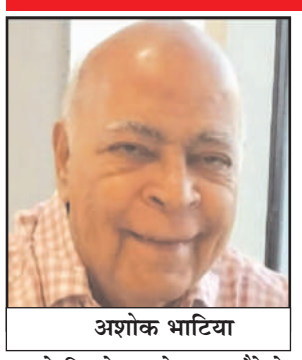

अशोक भाटिया

दो दिन के अपने भूटान दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब वापस भारत आ गए हैं। लेकिन इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री के बयान और भूटान के राजा के कदम चर्चा में रहे। इसके अलावा इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिले भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान और भारत और भूटान के बीच हए अहम समझौतों की भी चर्चा रही।मोदी का भूटान दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब देश के भीतर लोकसभा चुनावों और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है।अपने दौरे के दौरान मोदी ने ये आश्वासन दिया कि विकास की राह में भारत भूटान के साथ खड़ा रहेगा और अगले पांच सालों तक भूटान को 10 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देगा।एक महीने के भीतर मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री की ये दूसरी मुलाकात है। लगभग दो सप्ताह पहले 14 मार्च को भूटान के प्रधानमंत्री ने अपने पांच दिन के दौरे के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत और भूटान एक अनूठी और स्थायी साझेदारी साझा करते हैं जो आपसी विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित है। जो हमारी साझा आध्यात्मिक विरासत और लोगों के बीच मधुर संबंध हमारे असाधारण संबंधों में गहराई और जीवंतता जोड़ते हैं। यह यात्रा दोनों पक्षों को हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और हमारी अनुकरणीय साझेदारी को विस्तारित और तीव्र करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे लोगों के लाभ के लिए है ।14 मार्च को, टोबगे ने नई दिल्ली में मोदी के साथ एक बैठक की, जिसके दौरान टोबगे ने उन्हें भूटान आने का निमंत्रण दिया था । इस साल जनवरी में अपने देश के दूसरी बार प्रधान मंत्री चुने जाने के बाद टोबगे की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा थी।

बैठक के बाद, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें मोदी ने कहा कि भारत भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के अनुरूप उच्च आय वाला राष्ट्र बनने की कोशिश में भूटान के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। भूटान के लोग और शाही सरकार।बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के अनुरोध पर विचार करने सहित भूटान की 13वीं एफवाईपी (पंचवर्षीय योजना) के लिए समर्थन बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है । भारत की विकास सहायता बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापक रूप में कनेक्टिविटी के निर्माण की दिशा में होगी जिसमें सड़क, रेल, वायु और डिजिटल कनेक्टिविटी और कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कौशल और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अंतरिम बजट 2024-25 में विदेश मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 22,154 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सहायता पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा भूटान को 2023-24 में 2,400 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,068 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ दिया गया है।

अपने देश को उस आर्थिक दलदल से बाहर निकालने के लिए, जिसमें वह खुद को पा रहा है, टोबगे ने भारत के समर्थन से 15 अरब रुपये की महत्वाकांक्षी आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। 29 फरवरी को थिम्पू में एक प्रेस-मीट सत्र में यह घोषणा करते हुए टोबगे ने कहा कि एक व्यापक रणनीति तैयार करने और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। हिमालयी राज्य में नेशनल असेंबली चुनावों से पहले, टोबगे की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने 'भूटान के साथ अनुबंध' शीर्षक वाले अपने घोषणापत्र में, भूटान को आर्थिक मंदी से बाहर निकालने का वादा किया था। टोबगे ने घोषणापत्र में लोगों को दिए एक संदेश में कहा, ₹हमारे देश की अर्थव्यवस्था पतन के कगार पर है।₹ ह्लपिछले पांच वर्षों में केवल 1।7 प्रतिशत की औसत विकास दर के साथ, हमारी अर्थव्यवस्था हमारे हालिया इतिहास में सबसे खराब स्थिति में है। निजी क्षेत्र, जो हमारे विकास का मुख्य चालक है, स्थिर हो गया है, कई व्यवसाय या तो बंद हो गए हैं या कम क्षमता पर चल रहे हैं। युवा बेरोजगारी 28।6 प्रतिशत की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।ह्व

उन्होंने कहा कि भूटान का सार्वजनिक ऋण अपने उच्चतम स्तर पर है, विशेष रूप से गैर-हाइड्रो ऋण, जो कि नू 108 बिलियन (108 बिलियन रुपये) की भारी मात्रा में है। विदेशी मुद्रा भंडार उस स्तर तक कम हो गया है जिससे संवैधानिक आवश्यकता के उल्लंघन का खतरा है। राजकोषीय घाटा बढ़ गया है जबकि राष्ट्रीय राजस्व प्रवाह कम हो गया है।

टोबगे ने कहा, कि 2022 में कुल 80,614 भूटानी लोग गरीबी में रहेंगे। अर्थात, आठ में से लगभग एक भूटानी भोजन और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास लगभग ठप्प हो गया है। मामले को बदतर बनाने के लिए, हाल के वर्षों में, पेशेवरों और कुशल व्यक्तियों सहित अभूतपूर्व संख्या में भूटानी, विदेशों में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में देश छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे सार्वजनिक सेवा वितरण पर भारी दबाव पड़ा है, जिससे देश के अस्पताल, स्कूल और सार्वजनिक संस्थान प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा, ये अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतियाँ और भूटानियों का सामूहिक पलायन ऐसे समय में हो रहा है जब भूटान प्रजनन दर में भारी गिरावट का सामना कर रहा है, जो वर्तमान में 2।1 की प्रतिस्थापन दर से नीचे 1।8 प्रतिशत है।

टोबगे ने लोगों को आगाह किया था कि अगर हम इन प्रवृत्तियों को उलटने में असमर्थ हैं, तो हमारे राष्ट्र की व्यवहार्यता खतरे में पड़ जाएगी।अगर हमने तुरंत कदम नहीं उठाया, तो हमारे प्यारे राष्ट्र का अस्तित्व और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और पुनर्जीवित करने और भूटान को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए, पीडीपी ने कुछ प्रमुख आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लिया। जहां तक भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता का सवाल है, तो यह उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली 1960 के दशक की शुरूआत से ही हिमालयी राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जब उसने अपनी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थीं। भारत भूटान का प्रमुख विकास भागीदार बना हुआ है।

यह महत्वाकांक्षी पहल, हिमालय की तलहटी में तारयथांग गेवोग से सिंग्ये गेवोग तक लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करते हुए, गेलेफू को एक समृद्ध आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है, जिससे न केवल भूटान को लाभ होगा बल्कि व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भी योगदान मिलेगा। अपने संबोधन में, वांगचुक ने गेलेफू एसएआर के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसमें देश को अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक उन्नति की ओर ले जाने में विदेश में रहने वाले भूटानी व्यक्तियों के प्रभाव को मान्यता दी गई। यह प्रतिबद्धता अपने वैश्विक प्रवासी की क्षमता का दोहन करने के लिए सरकार के समर्पण को रेखांकित करती है।

वांगचुक ने कहा कि एक आर्थिक केंद्र के रूप में गेलेफू एसएआर को आवश्यक कानून और नीतियां बनाने की स्वायत्तता होगी। इसमें कार्यकारी स्वायत्तता और कानूनी स्वतंत्रता होगी। मोनार्क ने कहा, ₹इस एसएआर की स्थापना का उद्देश्य एक जीवंत आर्थिक केंद्र बनाना है।₹ ह्लकहीं और आर्थिक केंद्र हैं जो अनुकूल कारोबारी माहौल और आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करके विदेशी निवेश को आमंत्रित करते हैं। भूटान का आर्थिक केंद्र वह सब और बहुत कुछ प्रदान करेगा। 14 मार्च को मोदी और टोबगे के बीच बैठक के बाद जारी 'साझा समृद्धि के लिए भारत-भूटान साझेदारी' शीर्षक वाले संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने जल-विद्युत सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और अपने अधिकारियों को कार्यान्वयन पर शीघ्र विचार-विमर्श करने का निर्देश दिया। नई परियोजनाओं के लिए तौर-तरीके। मोदी की इस भूटान यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना नहीं थी , क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हालाँकि, यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति, विशेष रूप से हिमालयी साम्राज्य और उसके उत्तरी पड़ोसी के बीच विवादित सीमा पर। इससे भारत में चिंता बढ़ गई है। भारत भूटान का सबसे करीबी सहयोगी रहा है और उसने भूटान की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।भूटान एशियाई दिग्गजों भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य के रूप में कार्य करता है। भूटान की चीन के साथ 477 किलोमीटर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। चीन 1961 में एक मानचित्र प्रकाशित करने के बाद से भूटान के क्षेत्रों पर दावा कर रहा है।

फिर 2017 में डोकलाम ट्राइ-जंक्शन पर भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक गतिरोध चला। डोकलाम पठार भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। यह टकराव तब पैदा हुआ जब चीन ने भूटान के दावे वाले क्षेत्र में सड़क का विस्तार करने की मांग की। भारत ने अपने समग्र सुरक्षा हितों पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कड़ी आपत्ति जताई। कई दौर की बातचीत के बाद, भारत-चीन के बीच आमना-सामना आखिरकार समाप्त हो गया। इसके बाद, अक्टूबर 2021 में, भूटान और चीन ने बातचीत में तेजी लाने और अपने सीमा विवाद को संबोधित करने के लिए ₹तीन-चरणीय रोडमैप₹ की रूपरेखा तैयार करते हुए एक समझौता किया।इन सबके मद्देनजर मोदी की यह भूटान यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

दिशाहीन होता धार्मिक अतिवाद और औपनिवेशिक विस्तारवाद

संजीव ठाकुर

वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक स्तर पर धार्मिक अतिवाद औपनिवेशिक विस्तारवाद के कारण कई देशों के मध्य युद्ध तथा हिंसा का तांडव मचा हुआ है जो वैश्विक शांति, मानवता, सौहार्द के लिए सर्वथा बहुत ज्यादा घातक एवं भविष्य में अप्रिय परिणाम देने वाले हैं। धर्म की अवधारणा परोपकार, जनकल्याण, अहिंसा तथा मानवता को निरंतर आगे बढ़ाना है। जबकि अतिवाद किसी मान्यता विचार व अवधारणा को जबरन लागू करने की प्रक्रियागत सोच है। अतिवाद ही किसी भी विचारधारा या किसी पंथ को अति होने तक ले जाना है। अतिवाद किसी भी धार्मिक और राजनीतिक विषय में ऐसी विचारधारा के लिए प्रयुक्त होता है जो समाज की मुख्यधारा के नजरिए को स्वीकार नहीं करती है। यह एक ऐसा राजनीतिक अथवा धार्मिक सिद्धांत है जो अमर्यादित नीति का पक्षधर है तथा इसमें मध्यस्थता की कोई गुंजाइश भी नही होतीहै। यह धर्म की ओर एवं कठोर मान्यताओं को लोगों पर जबरदस्ती थोपने का कार्य करता है, तथा हिंसा ,हत्या बलात्कार आदि को सर्व मान्य रूप से सही ठहराता है। भारत में धार्मिक विवाद का असर युवाओं पर सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि युवा मन अपरिपक्व तथा किसी विचारधारा में ढला हुआ नहीं रहता और भारत में 65% 35 साल से कम उम्र के युवा निवासरत हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है' स्वतंत्रता के बाद से भारत के संविधान में लोकतंत्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया है' देश की भौगोलिक तथा जनसंख्यात्मक विशालता में कुछ तत्व सांप्रदायिक हिंसा एवं अराजकता के परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकतें हैं, पर भारतीय लोकतंत्र की महानता एवं विशालता है कि इससे संवैधानिक भारतीय लोकतंत्र को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर यह तय है कि सांप्रदायिक हिंसा एवं धार्मिक कट्टरता से लोकतंत्र की अवधारणा थोड़ी दिग्भ्रमित जरूर होती है पर इसकी मजबूती ना तो पहले कम हुई है और ना ही भविष्य में होने की कोई गुंजाइश ही है। हिंसा ,विवाद किसी भी बात का कोई हल नहीं। यह लोकतंत्र के लिए एक धब्बे के समान है। किसी भी देश में लोकतंत्र की आम धारणा आपसी सद्भाव और समभाव को लेकर आधारभूत रचनात्मक रूप से की गई है। विश्व के शांति प्रस्तावक भारत देश में हिंसा और हिंसक आंदोलन की कोई जगह नहीं एवं यह किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक असहमति का परिणाम तो कतई नहीं हो सकती है।भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक,प्रजातांत्रिक स्वतंत्र राष्ट्र है।वैचारिक चिंतन, प्रभुद्धता लोकतंत्र के प्रमुख अवयव होते हैं, राष्ट्र के किसी भी नीति में सहमत और असहमत होना एक सामान्य प्रक्रिया, प्रतिक्रिया हो सकती है, और आम जनमानस का किसी मुद्दे पर सहमत होना भी एक सामान्य बात हो सकती है पर किन्ही भी परिस्थितियों में असहमति हिंसा के रूप में कतई बर्दाश्त के योग्य नहीं होनी चाहिए, विरोध का स्वरूप राष्ट्रीय संपत्ति की बबार्दी तो किसी भी काल और खंड में स्वीकार्य नहीं है। यह राष्ट्र के लिए घातक और विकास की अवधारणा को अवरुद्ध करने वाला आत्मघाती कदम है।आंदोलन का स्वरूप सदैव शांति पूर्वक हो तो राष्ट्र तथा आमजन के हित में ही होगा। आंदोलनकारियों को शायद यह गुमान नहीं है कि राष्ट्रीय सरकारी संपत्ति आपके द्वारा दिए गए टैक्स के रूप में रुपयों से ही निर्मित होती है, इसे नष्ट करके आप स्वयं अपनी संपत्ति का नुकसान ही कर रहे हैं। आजादी के बाद से भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध खड़े किए हैं' देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं,जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत क्लिष्ट बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए-नए रूप तथा आयाम देती आई है और सदैव समाज में वर्ग विभेद आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लू सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते है बल्कि शासन प्रशासन के विरोध में भी सदैव खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाती ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा देश के समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिंदू ,मुस्लिम,सिक्ख,इसाई जातीय संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमां चुका है, वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़े देश में अशांत माहौल पैदा करने का एक बड़ा सबक बन चुके है।और यही वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग-अलग स्तर पर सतह

पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है। संविधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है। और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्व हीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी ,बेरोजगारी ,नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता,भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सर उठाये घूम रही हैं, हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नागरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवधारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा,तब जाकर भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा। किसी बात का विरोध हिंसा के बिगड़े स्वरूप की तरफ शासकीय संपत्ति को नष्ट करना देश हित में नहीं।

मदरसा शिक्षा पर गहराते संकट के मायने को ऐसे समझिए

किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं व परम्पराओं को संरक्षण और बढ़ावा देना कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन जब सत्ताधारी दल द्वारा वोट बैंक के नजरिए से किसी धर्म को शह दिया जाए और किसी धर्म को नजरअंदाज किया जाए, तो यह गलत बात है। वहीं, विपक्षी दल द्वारा भी ऐसा किया जाना ठीक नहीं है। इस नजरिए से भारतीय धर्मनिरपेक्षता सदैव शक के कठघरे में खड़ा रहती आई है।

खासकर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो कुछ पक्षपाती प्रावधान वक्त दर वक्त तय किए गए, वो जब न्यायालय के समक्ष किसी जनहित याचिका के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं तो तर्क और नियमन की कसौटी पर कदापि नहीं टिक पाते। कतिपय मामलों में बहुसंख्यक धर्मावलंबियों को भी जब टारगेट करने की कोशिश की गई, तो वो प्रावधान भी कोर्ट में टिक नहीं पाए।

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, प्रयागराज ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ भी है, जो संविधान के मूल ढांचे का अंग है। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को योजना बनाकर इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया। इससे एक बात साफ हो चुकी है कि अब उत्तरप्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त 560 से अधिक मदरसों पर ताला लगेगा।

उल्लेखनीय है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता अंशुमान सिंह राठौड़ ने मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए मदरसों का प्रबंधन केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर

दैनिक इबादत सम्पादकीय

आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही कांग्रेस

धीरज नाम का शब्द तो शायद कांग्रेस की डिक्शनरी में है ही नहीं और शायद यही कारण है कि कभी देश पर राज्य करने वाली पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टियों के आगे उनकी शर्तों पर चौथे स्तर पर आकर झोली फैलाए कुछ सीटों की भीख मांगती नजर आती है और कभी कभी तो धुत्कारें भी खाती है। अगर कांग्रेस अपना आत्मविश्वास कायम रख कर धीरज के साथ केवल अपने बल पर चुनाव लडती तो आज उसकी इतनी अधिक बुरी स्थिति तो निश्चित रूप से नहीं होती। निश्चित रूप से वह जनता के बीच भाजपा के विकल्प के रूप में स्थापित रहती मगर सत्ता की लोलुपता और अधीरता ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा है वरना जिन दलों ने उसकी जड़ों में मट्ठा डालकर उसे सत्ताविहीन करने का खुला खेल खेला है, उन्हीं के साथ समझौते पर समझौते करने के प्रयास नहीं कर रही होती?। यूं तो पूरे देश में एकछत्र राज करने का जो सुख कांग्रेस ने अंग्रेजों के स्वाभविक उत्तराधिकारी के रूप में भोगा है, वह मोदी की इतनी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि तथा लगन के साथ और अर्धशती से अधिक आरएसएस के भगीरथ प्रयासों के बाद भी भाजपा अभी तक नहीं पा सकी है मगर भाजपा वर्तमान में उससे कहीं अधिक, जो स्थिति प्राप्त कर सकी है, उसके पीछे उसका आत्मविश्वास और धैर्यशीलता ही है वरना धर्मनिरपेक्षता के नशे में डूबे हिन्दू समाज को गहरी नींद से जगाना सम्भव ही नहीं होता। आज भाजपा जिस जगह पर है उसके पीछे उसकी लगन, मेहनत, दूरगामी दृष्टि और उसके आत्मविश्वास के साथ उसका धैर्यवान चरित्र भी है। उसने हमेशा दूरगामी नीतियों पर चलना स्वीकार किया है जबकि कांग्रेस अपने जन्म से ही तुष्टिकरण और जातिवाद जैसे 'शार्टकट्स' का सहारा लेकर सता प्राप्त करने में विश्वास रखती रही है। अगर हम इतिहास पर गहरी नजर डालें तो हम देखते हैं कि अपने सत्तासुख के लिए कांग्रेस ने कई कई बार राष्ट्रीय हितों को भी दांव पर लगाया है जबकि भाजपा ने हमेशा 'राष्ट्रहित प्रथम' का चरित्र बनाये रखा है। सत्ता की तीव्र लालसा में कांग्रेस किस तरह से अपना आगा पीछा नहीं देखती, इसके केवल दो ही उदाहरण काफी होंगे, पहला पश्चिम बंगाल का और दूसरा दिल्ली, गोवा और पंजाब का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस से किनारा कर और उस से कुछ प्रभावी सदस्यों को तोड़ कर तृणमूल कांग्रेस बनायी और धीरे धीरे पूरी कांग्रेस का इस हद तक सफाया कर दिया कि पिछले कई चुनावों में कांग्रेस एक या दो सीटों पर अपनी लाज बहुत कम वोटों से बचा पाती है। कांग्रेस सब कुछ भूल कर केवल मोदी और भाजपा को मात देने के चक्कर में ममता से समझौता करने का प्रयास करती है और बुरी तरह धुत्कारी भी जाती है। अगर कांग्रेस दृढ इच्छाशक्ति और आत्मविश्वास के साथ थोड़े धीरज से जमीनी स्तर पर अपना वर्चस्व उभारने के प्रयास करती तो निश्चितरूप से अपना इन्फ्रास्ट्र. र फिर से खड़ा करने में सफल हो जाती।

अगर कांग्रेस के रणनीतिकार चतुर खिलाड़ी होते तो अपने जलाल पर आयी हुयी भाजपा से बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली, पंजाब में आप को भाजपा से लड़ कर कमजोर होने देती मगर उसे तो 2004 की पुनरावृति की लालसा है जब वह बिना प्रयास सत्ता में आ गयी थी मगर वह यह भूल जाती है कि तब की राजनैतिक परिस्थितियों और अब की परिस्थितियों में तो जमीन आसमान का अंतर है ही! भाजपा का नेतृत्व भी आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले मोदी के हाथों में है जो सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं?।

आम आदमी पार्टी की गले की फांस बना शराब घोटाला

दिल्ली की नई शराब नीति पर जब कांग्रेस और भाजपा ने बवाल मचाया तब दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने उपराज्यपाल से उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत की। जिसके बाद केजरीवाल समझ गए कि वे लपेटे में आ जाएंगे तो वह नीति रद्द कर दी गई। लेकिन कांग्रेस और भाजपा द्वारा की गई शिकायतें और अधिकारी की रिपोर्ट पर सीबीआई और ईडी सक्रिय हुई और फिर कुछ व्यापारियों सहित मनीषश् सिसौदिया और संजय सिंह पकड़े गए।

– राजेश माहेश्वरी

शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी उनके आवास पर 10वां समन लेकर पहुंची थी और करीब 2 घंटे की पूछताछ की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद 6 दिन के रिमांड पर ले लिया गया। चर्चित शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से जेल में हैं। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.सी. रेड्डी की बेटी भी गिरफ्त में है। शराब घोटाले में कुछ और लोग भी जेल की हवा खा रहे हैं। ये प्रकरण इतना उलझ जाएगा ये अनुमान किसी को न था।

शराब घोटाले में ईडी ने इस साल 15 मार्च को तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी के कविता को गिरफ्तार किया था। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी हैं। ईडी ने दावा किया है कि जांच से पता चला कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली शराब नीति-निर्माण और इसे लागू करने में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं के साथ साजिश रची। इसके लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपए दिए गए। एजेंसी का दावा कि आप के लिए शराब के थोक विक्रेताओं से अवैध धन की उगाही की गई। साथ ही साथ के कविता और उनके सहयोगियों के जरिए आगे भी आम आदमी पार्टी को एडवांस में भुगतान करना था, जिसके जरिए फायदा कमाया जा सके। ये पूरा मामला दिल्ली की आबकारी नीति में बदलाव कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने से जुड़ा है। केजरीवाल सरकार ने 2021 में शराब उत्पाद शुल्क नीति में कई बदलाव किए थे। नई नीति में शराब पीने की न्यूनतम उम्र को घटाकर 21 वर्ष करना, सरकारी शराब ठेकों को पूरी तरह बंद करके सारे ठेके निजी हाथों में सौंपना और प्राइवेट वेंडरों को लिकर स्टोर का लाइसेंस जारी करने समेत कई बदलाव किए गए थे।

ईडी का दावा है कि इस घोटाले में 338 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं। एजेंसी 338 करोड़ रुपये की ट्रेल अदालत में पेश कर चुकी है। ईडी ने दावा किया है कि इस केस में आरोपी शराब कारोबारी समीर महेंद्रू ने बयान दिया कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रभारी विजय नायर ने उनकी मुलाकात केजरीवाल से कराई थी। समीर के मुताबिक, फेस टाइम ऐप के जरिए केजरीवाल से मुलाकात हुई। समीर का दावा है केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था। आरोप है कि नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के घर बैठक हुई थी, जिसमें मार्जिन प्रॉफिट 12 फीसदी किया गया था। केजरीवाल की मंजूरी से मार्जिन-प्रॉफिट बढ़ाया गया था। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में

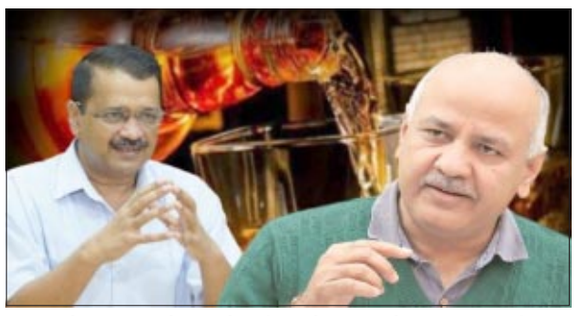

सरकार ने खुदरा कारोबार को पूरी तरह से निजीकरण कर दिया। इस तरह उत्पाद शुल्क की चोरी और अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लग गया। इससे 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व की कमाई का लक्ष्य रखा गया। राजधानी के सभी 272 नगरपालिका वार्डों में से प्रत्येक में कम से कम दो शराब की दुकानें खोली जानी थी। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जुलाई 2022 में नई आबकारी नीति को लेकर जांच की। उन्होंने बताया कि नीति में जानबूझकर और गंभीर खामियां बरती गई और लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ दिया गया। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मुख्य सचिव की जांच के कुछ मुद्दे सीबीआई एफआईआर का हिस्सा बन गए।

अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सबसे पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 नवंबर 2023 को दूसरा नोटिस भेजा गया, तब भी उन्होंने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी ने 3 जनवरी और 18 जनवरी को समन भेजा। 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी को भेजे नोटिस पर भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा था। केजरीवाल, ईडी के भेजे किसी समन पर पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि एजेंसी के समन अवैध हैं, उसके पास कोई सबूत नहीं हैं। केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार ईडी और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए करती है। दिल्ली की नई शराब नीति पर जब कांग्रेस और भाजपा ने बवाल मचाया तब दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने उपराज्यपाल से उसमें भ्रष्टाचार की शिकायत की। जिसके बाद केजरीवाल समझ गए कि वे लपेटे में आ जाएंगे तो वह नीति रद्द कर दी गई। लेकिन कांग्रेस और भाजपा द्वारा की गई शिकायतें और अधिकारी की रिपोर्ट पर सीबीआई और ईडी सक्रिय हुई और फिर कुछ व्यापारियों सहित मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पकड़े गए। जांच में उजागर हुआ कि शराब नीति में मिली घूस का उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया और अरविंद केजरीवाल भी घोटाले से जुड़े हुए थे। इस पर उन्हें पूछताछ हेतु समन भेजे जाते रहे किंतु वे किसी न किसी बहाने से उनको अनदेखा करते गए। 9 समन भेजने के बाद भी पूछताछ हेतु न आना उन्हें संदिग्ध बनाने के लिए पर्याप्त था। केजरीवाल ने अपनी संभावित गिरफ्तारी रोकने उच्च न्यायालय की शरण ली किंतु उसने उनकी अर्जी ठुकरा दी जिसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। चूंकि लोकसभा चुनाव सिर पर हैं इसलिए आम आदमी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष भाजपा और केंद्र सरकार पर चढ़ बैठा। गत दिवस अदालत ने रिमांड अर्जी मंजूर करते हुए अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ा दीं। उसके बाद सवाल उठा कि दिल्ली सरकार कैसे चलेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इंकार करते हुए जेल से सरकार चलाने की बात कही। इसके संवैधानिक पहलू पर बहस चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी की ये पहली गिरफ्तारी है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गिरफ्तारी के पहले इस्तीफा दे दिया था। आश्चर्य ये है कि यही केजरीवाल ईडी को ललकारते हुए सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने कहते थे। शराब नीति के विरोध में कांग्रेस नेताओं के पुराने साक्षात्कार भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। जहां तक सवाल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किये जाने के औचित्य का है तो ईडी के 9 समन रद्दी में फेंकने का दुस्साहस निश्चित तौर पर अक्षम्य है। मुख्यमंत्री किसी जांच एजेंसी के बुलाये जाने पर एक दो बार तो व्यस्तता का बहाना बना सकता है किंतु वह न जाने की जिद पकड़ ले तो उसका नैतिक और कानूनी पक्ष स्वाभविक रूप से कमजोर हो जाता है। पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में न आकर केजरीवाल ने चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत को चरितार्थ कर दिया। उनको पता था कि अंततः वे गिरफ्तार होंगे। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पर ईडी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से विपक्ष अपनी खुद की कमजोरी उजागर कर रहा है। जो कांग्रेस इस मामले में केजरीवाल सरकार का बचाव कर रही है वह खुद शराब नीति में भ्रष्टाचार को उजागर करने में अग्रणी रही। इसलिए दिल्ली और पंजाब के उसके तमाम नेता लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबन्धन के विरुद्ध थे। लेकिन आलाकमान ने उस विरोध को नजरअंदाज कर दिया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करके कांग्रेस और विपक्ष ने अपनी नीति और नीयत देश को बता दी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष बुरी तरह फंसा हुआ है। और वो जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताता है। सही मायनों में शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है। पार्टी का भविष्य अंधकारमय दिखाई देता है।

(लेखक राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

ऊल-जलूल और विवादित बयानों से गरमाई देश की सियासत

– बाल मुकुन्द ओझा

देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मौसमी गर्मी के संग चुनाव प्रचार की गर्मी देश भर में प्रचंड रूप लेने जा रही है। इसी के साथ नेताओं के विवादित, अभद्र और शर्मसार करने वाले बयानों ने भाषा की मर्यादा को तार तार करके रख दिया है। नेता लोग अक्सर चर्चा में रहने के लिए ऊल-जलूल और समाज में कटुता फैलाने वाले बयान देते रहते है। विशेषकर चुनावों के दौरान गंदे बोलों से चुनावी बिसात बिछ जाती है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंडी से भाजपा प्रत्याशी और अभिनेत्री कंगना रनौत पर बेहद विवादस्पद टिप्पणी कर आग में घी डालने का कार्य किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में है। केजरीवाल की पार्टी आप के नेताओं ने इस गिरफ्तारी से बौखलाकर प्रधानमंत्री पर जिस भाषा में आरोप प्रत्यारोपों की बौछारे शुरू की है वह निश्चय ही लोकतंत्र के लिए घातक है।तमिलनाडु के नेता लगातार अभद्र बयान दे रहे है। वहीं कांग्रेस के नेता यह कहने लगे है तानाशाह मोदी जीत गया तो यह आखिरी चुनाव होगा। मोदी के परिवार को लेकर पहले ही अभद्र टिप्पणियां मीडिया में सुर्खियां लिए हुए है।

कुछ सियासी नेताओं ने तो लगता है विवादित बयानों का ठेका ले रखा है। कई नेताओं पर विवादित बयानों पर मुक़दमे भी दर्ज़ हुए। कुछ को न्यायालय से सजा भी मिली। मगर इसका उनपर कोई फर्क नहीं पड़ा। विवादित बयानबाजी के कारण सुर्खियों में रहना नेताओं को शायद आनंद देने लगा है। देश के न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर नफरत और घृणा के बादल मंडरा रहे है। नफरत और घृणा के इस महासागर में सभी सियासी पार्टियां डुबकी लगा रही है। न्यूज चैनलों पर विभिन्न सियासी दलों के प्रतिनिधि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते है उन्हें देखकर लगता नहीं है की यह गाँधी, सुभाष, नेहरू, लोहिया और अटलजी का देश है। देश की सर्वोच्च अदालत कई बार इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर नियामकीय नियंत्रण की कमी पर अफसोस ज़ाहिर कर चुकी है । सुप्रीम कोर्ट ने नेताओं के भाषण और टीवी चैनलों को नफरती भाषण फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में कई बार टेलीविजन चैनलों को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी चैनल ऐसे चैनल एजेंडे से संचालित होते हैं, जो विभाजन पैदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीवी चैनल सनसनीखेज न्यूजों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और अपने धनदाताओं (मालिकों) के आदेश के अनुसार काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नफरत फैलाने वाली बातें एक 'बड़ा खतरा हैं और भारत में स्वतंत्र एवं संतुलित प्रेस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एंकरों और न्यूज़ चैनल के प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई हो तो सब लाइन पर आ जाएंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि आजकल सब कुछ टीआरपी से संचालित होता है और चैनल एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं तथा समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं।

पिछले दो दशक से गंदे और विवादित बोल बोले जा रहे है। नेताओं के बयानों से गाहे बगाहे राजनीति की मर्यादाएं भंग होती रहती है। अमर्यादित बयानों की जैसे झड़ी लग जाती है। राजनीति में बयानबाजी का स्तर इस तरह नीचे गिरता जा रहा है उसे देखकर लगता है हमारा लोकतंत्र तार तार हो रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक नेता विवादित बयान दे रहे हैं, उसकी वजह से चुनावी माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है। विवादित बयान देने में कांग्रेस और भाजपा सहित कोई भी नेता पीछे नहीं है। कहते है राजनीति के हमाम में सब नंगे है। यहाँ तक तो ठीक है मगर यह नंगापन हमाम से निकलकर बाजार में आजाये तो फिर भगवान ही मालिक है। सियासत में विवादास्पद बयान को नेता भले अपने पॉपुलर होने का जरिया मानें, लेकिन ऐसे बयान राजनीति की स्वस्थ परंपरा के लिए ठीक नहीं होते। हमारे माननीय नेता आजकल अक्सर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। देश के नामी-गिरामी नेता और मंत्री भी मौके-बेमौके कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं, जिसे सुनकर कान बंद करने का जी करता है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, जगतपुरा रोड)

कविता

सामना

रुख पहाड़ों की तरफ किया
तो समझ आया
जन्नत इस धरा पर भी है।

रुख बादलों की तरफ किया
तो समझ आया
बदमाशी इनमें भी है।

रुख बहती नदी की तरफ किया
तो समझ आया
जीवन का बहाव इनमें भी है।

रुख हरे-भरे खेतों की तरफ किया
तो समझ आया
जीवन का अंश इनमें भी है।

रुख वृक्षों की तरफ किया
तो समझ आया
जीवन की समझदारी इनमें भी है।

रुख डूबती हुई नाव की तरफ गया
तो समझ आया
जीवन का अंतिम पड़ाव
इनमें भी है।

डॉ. राजीव डोगरा
(युवा कवि व लेखक, जनयानकड़, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश)

वनों का विनाश रोकने के लिए सार्थक पहल करने की सख्त जरूरत

– विजय गर्ग

परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मनुष्यों और जीव-जंतुओं के अलावा वृक्षों तथा वनों का भी बेहद महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। दरअसल, वन जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास स्थान होने के साथ-साथ भोजन का माध्यम भी हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्त्व है आक्सीजन, धरती पर वन ही हैं, जो बड़ी मात्रा में वातावरण से कार्बन डाई आक्साइड सोखकर उसे आक्सीजन में बदलते हैं। वन वर्षा कराने, तापमान को नियंत्रित रखने, मृदा के कटाव को रोकने तथा जैव-विविधता को संरक्षित करने में सहायक होते हैं और सही मायनों में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता वनों के कारण ही है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में वनों की अहम भूमिका होती है। हालांकि दुनिया भर में वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण अब पृथ्वी पर वन और उनमें रहने वाले जीव-जंतुओं के आवास स्थल काफी सिमट गए हैं। हर वर्ष लगने वाली आग के कारण लाखों हेक्टेयर जंगल तथा जीव-जंतुओं की अनेक प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट के मुताबिक पिछले तीन दशक में विश्वभर में करीब एक अरब एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। कुछ दशक पहले तक जहां पृथ्वी का करीब पचास फीसद भू-भाग वनों से आच्छादित था, अब यह महज तीस फीसद रह गया है। अगर इसी रफ्तार से वनों का सफाया होता रहा, तो इसमें और कमी आएगी। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वनों की संख्या घटते जाने का सीधा असर जैव विविधता पर पड़ेगा। इससे आने वाले समय में जहां जल चक्र, मृदा संरक्षण और जैव मंडल पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, वहीं जीव- जंतुओं के आवास पर भी संकट आएगा और अनियमित मौसम से भयंकर दुष्प्रभाव सामने आएंगे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण ही अब पृथ्वी पर 'ग्लोबल वार्मिंग' के साथ-साथ प्राकृतिक आपदा की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। वन पृथ्वी के फेफड़ों की भांति कार्य करते हैं, जो वातावरण से सल्फर डाईआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड, अमोनिया, ओजोन आदि प्रदूषक गैसों को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में प्राणवायु छोड़ते हैं। यही कारण है कि वैश्विक स्तर पर लोगों को वनों के महत्त्व के प्रति जागरूक करने, इनके संरक्षण के लिए समाज का योगदान हासिल करने और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 'अंतरराष्ट्रीय वन दिवस' या 'विश्व वानिकी दिवस' मनाया जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक विषय-वस्तु निर्धारित की जाती है, जिसे जंगलों पर सहयोगात्मक भागीदारी द्वारा चुना जाता है। इस वर्ष इसकी विषय-वस्तु 'वन और नवाचार' निर्धारित की गई है। यह विषय वनों की सुरक्षा, प्रबंधन और पुनर्स्थापित करने में प्रौद्योगिकी और रचनात्मक दृष्टिकोण की महत्त्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता तथा नवाचार द्वारा निभाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर देता है। अगर शुरुआत से अभी तक की विषय-वस्तु पर नजर डालें तो 2014 से 2021 के बीच अंतरराष्ट्रीय वन दिवस की विषय-वस्तु क्रमशः 'हमारे वन, हमारा भविष्य', 'वन, जलवायु परिवर्तन', 'वन और जल', 'वन और ऊर्जा', 'वन और शहर', 'वन और शिक्षा', 'वन और जैव विविधता', 'वन बहाली- पुनर्प्राप्ति और कल्याण का मार्ग' तथा 'वन तथा सतत उत्पादन और खपत' रखी जा चुकी हैं।

भारत में मुख्य रूप से सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन हैं। सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहा जाता है, जो भारत में पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर भारत जैसे उच्च वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 2021 के ग्लासगो जलवायु सम्मेलन में सौ से ज्यादा देशों ने वर्ष 2030 तक वनों की कटाई पर पूर्ण पाबंदी लगाने का संकल्प लिया था। वनों की अंधाधुंध कटाई तथा बढ़ते प्रदूषण के कारण ही अब विश्वभर में कई ग्लेशियर लुप्त होने के कगार पर हैं और 'ग्लोबल वार्मिंग' का खतरा निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर वनों का विनाश रोकने के लिए सार्थक पहल करने की सख्त जरूरत महसूस की जाने लगी है।

(सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार मलोट)

हर राज्य से स्कूलों में बच्चों के साथ शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार मारपीट की खबरें आती रही हैं। बच्चों को टॉर्चर करने में प्राइवेट स्कूल भी पीछे नहीं हैं। फीस के लिए धूप में बैठाने,बच्चों से मारपीट करने और एग्जाम नहीं देने के मानसिक दबाव बनाना आम बात बन गया हैं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के बर्तन साफ कराने और टॉयलेट साफ कराने की शिकायतों से हर राज्य का शिक्षा विभाग चिंतित है। शारीरिक उत्पीड़न पर कानूनी रोक के बावजूद इस पर रोक लगाना स्वप्न बना है।

मासूम बच्चों की जान से खेलते टीचर !

– मनोज कुमार अग्रवाल

हाल ही में कर्नाटक में एक 14 साल की छात्रा ने 16 मार्च को सुसाइड कर लिया. छात्रा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल में चोरी का आरोप लगाकर छात्रा का यूनिफॉर्म उतरवाकर तलाशी ली गई थी. जिससे आहत होकर उसने सुसाइड कर लिया. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के साथ चार अन्य छात्राओं के भी यूनिफॉर्म उतरवाए गए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।आरोपी टीचर भी पुलिस की गिरफ्त में है। ये पूरा मामला बागलकोट का है।

पुलिस के मुताबिक, 14 मार्च को पीड़िता के क्लास में 2 हजार रुपये की चोरी हुई थी. रुपये चोरी के शक में टीचर ने स्टाफ और हेडमास्टर के सामने ही बच्चियों के कपड़े उतरवाकर तलाशी ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप है कि हेड मास्टर सहित शिक्षण कर्मचारियों ने लड़कियों को घेर लिया. उन्हें पास के मंदिर में भी ले जाया गया, वहां पर कसम दिलाई गई. मंदिर में ही सबके सामने कपड़े उतरवाकर तलाशी ली गई.इस वारदात के लिए कदमपुर स्कूल की शिक्षिका जयश्री मिश्रीकोटी और एक अन्य शिक्षक के.एच.मुजवारा को आरोपी बनाया गया हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, छात्रा ने दुर्गा देवी के सामने कसम खाई थी कि उसने पैसे नहीं चुराये हैं, लेकिन शिक्षकों ने उसकी बात नहीं सुनी।अपनी बेगुनाही को साबित करने के बाद भी छात्रा को दो हजार रुपये की चोरी के लिए संदेह की नजर से देखा गया और इस सबके चलते एक बेगुनाह 14 साल की नाबालिग बच्ची ने फांसी लगा ली। वह स्कूल में हुए दुर्व्यवहार के कारण अपने अपमान से दुखी थी। जिस स्कूल में वह ससम्मान पढ़ती थी, वहां के शिक्षकों की चूक ने ही नाबालिग बच्ची को अन्तर्मन तक चोटिल कर दिया । बच्ची पर स्कूल में 2 हजार रुपये चोरी का आरोप लगा दिया गया । बच्ची को दुर्गा मंदिर में ले जाकर कसम खिलाई गई। इससे भी संतोष नहीं मिला तो बच्ची के कपड़े उतारकर तलाशी ली गई। रुपये तो नहीं मिले मगर लोगों के बीच निर्वस्त्र होते ही बच्ची का दिल भर आया और उसका किशोर मन क्षुब्ध हो गया। जिन शिक्षकों पर बच्चों को जीवन में सदाचार साहस और हर मुसीबत से टकराने का जिम्मा है उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ दो हज़ार रुपये की कथित चोरी और चोरी के आरोप में बच्चियों की निर्वस्त्र कर तलाशी लेना समूची स्कूली व्यवस्था और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर सवालिया निशान है।

क्या बेसिक शिक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले शिक्षकों को इतना प्रशिक्षण भी नही दिया गया कि उन्हें बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? नादान उम्र की इस मासूम बच्ची की आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? चोरी का आरोप लगाने वाला लैंग्वेज टीचर या बच्ची को मंदिर में कसम खिलाने वाला प्रिंसिपल। कपड़े उतरवाने वाले टीचर या वे लोग, जो चुपचाप पूरी घटना को देखते रहे। ऐसे अभिभावक को जिम्मेदार नहीं माना जाना चाहिए, जिन्होंने घटना के बाद स्कूल में अपना विरोध दर्ज नहीं कराया। उस स्कूल में लड़की की बड़ी बहन भी पढ़ती है, उसने ही घर में पूरा वाकया सुनाया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद से ही बच्ची गुमसुम रहने लगी थी। सार्वजनिक अपमान से दुखी होकर वह स्कूल नहीं गई। बागलकोट के एसपी अमरनाथ रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने उसकी मौत की परिस्थितियों के बारे में सुनने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। बागलकोट में सार्वजनिक शिक्षा के उप निदेशक इस केस में खामोश हैं। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है मगर यह केस कई सवाल छोड़ गया है। गौर तलब है कि हर राज्य से स्कूलों में बच्चों के साथ शिक्षकों द्वारा दुर्व्यवहार मारपीट की खबरें आती रही हैं। बच्चों को टॉर्चर करने में प्राइवेट स्कूल भी पीछे नहीं हैं। फीस के लिए धूप में बैठाने, बच्चों से मारपीट करने और एग्जाम नहीं देने के मानसिक दबाव बनाना आम बात बन गया हैं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के बर्तन साफ कराने और टॉयलेट साफ कराने की शिकायतों से हर राज्य का शिक्षा विभाग चिंतित है। शारीरिक उत्पीड़न पर कानूनी रोक के बावजूद इस पर रोक लगाना स्वप्न बना है। कर्नाटक के स्कूलों में स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाने के कई मामले पहले भी चुके हैं। दो महीने पहले ही कलबुर्गी के एक स्कूल में छात्र के साथ मारपीट की गई थी। आंबेडकर पूजा नहीं करने के कारण उसे नंगा कर हॉस्टल में घुमाया गया था। मांड्या के सरकारी स्कूल में 100 रुपये की तलाशी के लिए 12 छात्राओं के कपड़े उतरवाए गए थे। करीब एक साल पहले मांड्या जिले के गणनगुरु गांव के सरकारी स्कूल में मोबाइल लेकर आई छात्रा को प्रिंसिपल ने सहपाठियों के सामने बेरहमी से पीटा था और कपड़े उतरवाकर घंटों बैठाए रखा था। प्रिंसिपल ने बच्ची को घंटों पानी तक नहीं पीने दिया था। इसी तरह दलित छात्र द्वारा शिक्षक का पानी का मटका छूने पर पिटाई से मासूम की मौत का मामला आप भूले नहीं होंगे अब चोरी के इल्जाम में 14 साल की लड़की के साथ दुर्व्यवहार और फिर बच्ची की खुदकुशी का मामला बेहद गंभीर व शर्मनाक है।

इन हालातों में जब अल्पायु बच्चों में संवेदनशीलता का स्तर काफी बढ़ गया है लगातार बाल व किशोर छात्र छात्राओं को स्कूली शिक्षा के एग्जाम व मार्क्स सिस्टम के भारी भरकम दबाव ने उनसे बचपन छीन लिया है। यह मैकाले की शिक्षा व्यवस्था बाल मन पर ग्रहण बन कर उनके स्वाभाविक विकास में बाधा बन रही है। आज छोटे बच्चे जरा सी डांट फटकार को भी अन्तर्मन तक महसूस करते हैं और तनिक सा उनकी आत्म सम्मान की भावना या ईगो को हर्ट करने वाला दुर्व्यवहार उन्हे भीतर तक अवसाद या मानसिक संताप से भर देता है ऐसे बदलते परिवेश में शिक्षकों की बच्चों के साथ व्यवहार करते समय जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है घायल शरीर का उपचार किया जा सकता है लेकिन घायल मन का उपचार कठिन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित होने के बाद तैनाती दी जाती है फिर इस प्रशिक्षण में कहां कमी है जो शिक्षक लगातार बच्चों के साथ असंवेदनशील दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज के बालक बेहद संवेदनशील और जीवन से पलायन की मानसिकता ओर आसानी से आकर्षित हो रहे हैं ऐसे दौर में स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारी और अ

चुनाव बांड

विपक्ष की मांग

चुनाव बांड मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है। अब समाप्त कर दिए गए 'चुनाव बांडों' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनीतिक फंडिग का डेटा सार्वजनिक होने के एक दिन बाद अनेक एक्टिविस्ट योजना के सभी आयामों की जांच करने के लिए स्वतंत्र विशेष जांच टीम-एसआईटी की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बहस तीखी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इन विशेष वित्तीय उपकरणों संबंधी कथित कदाचारों को उजागर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में जांच की मांग की है। उसके द्वारा लगाए 'प्री-पेड, पोस्ट-पेड व पोस्ट-रेड रिश्वतों' के आरोप ने चुनाव फाइनेंसिंग योजना में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की आवश्यकता उजागर की है। 2018 में शुरू चुनाव बांडों का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बरतना तथा व्यक्तियों व निगमों द्वारा अपना नाम उजागर किए बिना राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग करना था। इसका उद्देश्य चुनावों में काले धन के प्रयोग पर लगाम लगाना था। लेकिन शुरुआत से ही ये बांड आलोचना का शिकार हो गए थे। आरोप है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के बावजूद वे एक या दूसरी राजनीतिक पार्टी को रिश्वत देने का माध्यम बन गए। कांग्रेस का आरोप है कि ये बांड अवैध लेनदेन का मार्ग बन गए तथा इन्होंने राजनीतिक पार्टियों को बेनामी पैसे का प्रवाह सुनिश्चित किया। उसके अनुसार, इन बांडों का प्रयोग न केवल राजनीतिक अभियानों को चलाने, बल्कि पिछले दरवाजे से नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए किया गया।

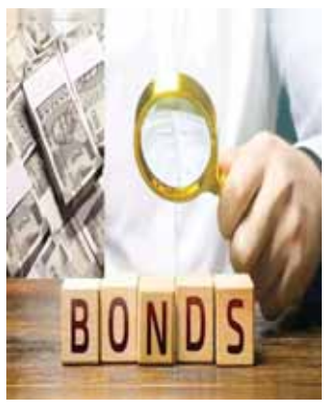

हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में चुनाव बांडों की जांच की मांग सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी रूप से घेरने की चाल भी है क्योंकि चुनाव बांडों से धन प्राप्त करने वाली अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। मीडिया द्वारा किए खुलासों से स्पष्ट है कि चुनाव बांडों से केन्द्र तथा राज्यों में सत्तारूढ़ लगभग सभी दलों को पैसा मिला है। इसके साथ ही पैसा देने वाले निगमों या संस्थानों का केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं से कोई सीधा संबंध नहीं मिला है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा छापे मारने के बाद या उसकी आशंका से किसी निगम या व्यक्ति ने चुनाव बांड खरीदे हों। देश में ढांचागत संरचना निर्माण क्षेत्र में कार्यरत बड़ी कंपनियों द्वारा भी चुनाव बांड खरीदे जाने का खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि, राजनीति पर पैसे के प्रभाव को लेकर चिन्ता भारत समेत दुनिया के अनेक लोकतंत्रों में होती रहती है, पर इससे बचने का कोई सुसंगत तरीका अब तक सामने नहीं आया है। उदाहरणार्थ, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र अमेरिका में चुनावी फंडिंग का मामला बहुत जटिल है और यह पता लगाना लगभग असंभव है कि किस निगम या व्यक्ति ने किस उम्मीदवार को चंदा दिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों व अर्थशास्त्रियों का कहना है कि चुनाव बांडों को असंवैधानिक घोषित करने के बाद चुनाव फंडिंग पर फिर 'काले धन' का प्रभाव बढ़ सकता है, जबकि चुनाव बांडों से दानदाताओं का पता लगाना तथा 'मनी ट्रेल' तलाशना आसान था। समग्र रूप से देखें तो चुनाव सुधार एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग भी शामिल है। लेकिन अनेक मुद्दों की तरह इस मुद्दे का समाधान भी अदालत के माध्यम से नहीं हो सकता है। चुनाव सुधारों तथा राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए राजनीतिक दलों के बीच संवाद, विचार-विमर्श एवं 'सहमति' जरूरी है, लेकिन फिलहाल इसका अभाव दिख रहा है।

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका

रूस-यूक्रेन युद्ध लगातार जारी रहने और उसके विस्तार लेने की संभावना ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा कर दी है। हालांकि, अमेरिका व रूस के नेताओं से शांति की दिशा में कदम उठाने व समझदारी की उम्मीद है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी रहने और उसके विस्तार लेने की संभावना ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषक तथा भू-राजनीतिक स्थितियों पर नजर रखने वाले लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है? यदि वर्तमान घटनाक्रम जारी रहे तो ऐसी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। एक ओर 'नाटो' तथा उसके सहयोगी पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं, वहीं रूस इसे अपनी संप्रभुता और अखंडता पर गंभीर खतरा मानता है। कुछ देशों ने भविष्य में यूक्रेन में नाटो सैन्यबलों की उपस्थिति की संभावना से भी इनकार नहीं किया है। इसे देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने 18 मार्च, 2024 को कहा कि रूस और 'नार्थ एटलांटिक ट्रीटी आर्गेनाइजेशन'-नाटो के बीच सीधे टकराव का अर्थ होगा कि यह ग्रह अब तीसरे विश्वयुद्ध से केवल एक कदम दूर रह गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि शायद ही कोई ऐसी स्थिति बनने देना चाहता हो। अन्य रूसी नेताओं ने भी ऐसी संभावना को अनदेखा नहीं किया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उप-सचिव अलेक्सांद्र वेनडिक्टोव ने 13 अक्टूबर, 2022 को कहा था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना इस बात की गारंटी होगा कि उस देश में बढ़ता टकराव तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता है। पश्चिमी देशों ने भी रूस से युद्ध और व्यापक होने की संभावना पर गंभीर हैं। जर्मन अखबार 'बिल्ड' ने 15 जनवरी, 2024 को खबर दी कि देश की सेना बाल्टिक देशों-लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया पर 2025 की गर्मियों में रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। यह इस वर्ष वसंत में यूक्रेन पर ताजा हमलों के साथ हो सकता है। रूस द्वारा तृतीय विश्व युद्ध की बात संभवत: एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। रूस इस तरह की बात कर यूक्रेन को संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय देशों का समर्थन घटाना चाहता है।

हालांकि, जर्मन अखबार द्वारा सामने आई उपरोक्त प्रतिक्रिया का अर्थ इस बात का संकेत है कि जर्मनी और पश्चिमी देश रूस द्वारा तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। वास्तव में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने लिथुआनिया के रक्षा मंत्री आर्वीदास अनासुस्कास के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत लिथुआनिया में 4,800 जर्मन सैनिकों तथा 200 सिवियिलनों की तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न देशों द्वारा किसी संभावित युद्ध के लिए की जा रही तैयारियों को देखते हुए यूक्रेन में जारी युद्ध के विस्तार लेकर तीसरे विश्व युद्ध में बदलने की आशंकाओं को समझा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह व्यापक सवाल भी है कि विश्व युद्ध क्या है? विश्व युद्ध को ऐसे बड़े पैमाने के युद्ध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दोनों और से अनेक देश शामिल हों, इसका विस्तार धरती के बड़े हिस्से तक हो और इससे वे देश भी प्रभावित हों जो इसमें सीधे संलिप्त नहीं हैं।

वर्तमान भू-राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए आशंका है कि संभावित तीसरे विश्व युद्ध में एक और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो देश होंगे जो रूस के खिलाफ युद्ध करेंगे। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए संभावना है कि बेलारूस, चीन और उत्तर कोरिया भी रूस के पक्ष में नाटो के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं।

यूक्रेन युद्ध के कारण तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का खतरा देखते हुए दुनिया के सभी महत्वपूर्ण नेता कह रहे हैं कि वे न तो तीसरा विश्व युद्ध चाहते हैं और न इसकी कोई संभावना है। इन नेताओं में जो बाइडेन व व्लादीमिर पुतिन भी शामिल हैं। लेकिन अतीत की घटनाओं पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि अमेरिका को 7 दिसंबर, 1941 को पर्ल हार्बर पर जापानी हमले की जरा भी आशंका नहीं थी। इस भयानक हमले में अमेरिकन प्रशांत समुद्री नौसैनिक बेड़े को भारी नुकसान पहुंचा था। इसी प्रकार यूरोपीय शक्तियां भी यह उम्मीद नहीं करती थीं कि 1 सितंबर, 1939 को जर्मनी अचानक पोलैंड पर हमला बोल देगा। जर्मनी के इस हमले ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को भड़का दिया था। वर्तमान स्थितियों पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि दुनिया के बहुत से लोग द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से ग्रस्त हैं क्योंकि उस समय पूरी दुनिया दो परस्पर विरोधी समूहों में बंट गई थी। उस समय अमेरिका के नेतृत्व में देशों का एक समूह नाटो, सेंट्रल ट्रीटी आर्गेनाइजेशन-सेंटो और साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी आर्गेनाइजेशन-सीटो जैसी संधियों के आधार पर एकजुट हुआ था। नाटो और सेंटो जहां यूनियन आफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स-यूएसएसआर पर निशाना लगाते थे, वहीं तीसरा समूह सीटो के निशाने पर चीन था। उस समय एक अन्य समूह पूर्वी यूरोपीय देशों का था जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूएसएसआर के प्रभाव क्षेत्र में आ गए थे। ये सभी देश 'वारसा संधि' में शामिल थे। चीन को इस संधि में प्रेक्षक का दर्जा मिला था, लेकिन वह 1861 में इससे अलग हो गया था। दुनिया में देशों के दो समूहों के बीच 'शीत युद्ध' निष्क्रिय या तटस्थ संबंधों से परिभाषित होता था।

हालांकि, इन समूहों के बीच कोई प्रत्यक्ष युद्ध जैसी स्थिति नहीं थी। 'शीत युद्ध' को प्रत्यक्ष युद्ध में बचने से रोकने का कारण अमेरिका और यूएसएसआर के पास बड़ी संख्या में नाभिकीय आयुधों की उपस्थिति थी। बात में चीन भी नाभिकीय आयुधों की दौड़ में शामिल हो गया, जबकि ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी इनके थोड़े भंडार थे। ऐसे में आशंका थी कि दोनों समूहों के बीच युद्ध में नाभिकीय आयुधों का प्रयोग हो सकता है। संभावित नाभिकीय युद्ध की भयानक विभीषिका को यूएसएसआर के प्रधानमंत्री निकिता खुश्चेव ने इस प्रकार कहा था कि तब 'जीवित लोग मरे लोगों से ईर्ष्या करेंगे।'

लेकिन इसके बावजूद दोनों समूह दो बार युद्ध के बिल्कुल निकट पहुंच गए थे। 1 मई, 1960 को एक सोवियत मिसाइल ने एक यू-2 जासूसी विमान रूसी क्षेत्र में मार गिराया था जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलीजेंस एजेंसी-सीआईए के अंतर्गत कार्यरत था। पैराशूट से सुरक्षित उतरने वाले उसके पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को बंदी बना लिया गया था। इस घटना ने अमेरिका-यूएसएसआर संबंधों में खटास पैदा की जबकि इसके पहले कैंप डेविड, मैरीलैंड में अमेरिकन राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजेनहावर तथा प्रधानमंत्री खुश्चेव के बीच सितंबर, 1959 में बैठक हुई थी। इसने मई मध्य में पेरिस में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर के बीच बैठक को भी प्रभावित किया जब यू-2 मिशन पर आइजेनहावर के माफी मांगने से इनकार करने पर खुश्चेव ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। दूसरी घटना अक्टूबर, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय सामने आई। उस समय यूएसएसआर ने क्यूबा में एसएस-3 व एसएस-6 मिसाइल लगाने की दिशा में कदम उठाए थे जो अमेरिका को निशाना बना सकती थीं। बाद में राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी के आदेश से अमेरिका ने क्यूबा की नौसैनिक घेरेबंदी कर दी थी और यूएसएसआर ने इसे तोड़ने की घोषणा की थी।

हालांकि, बाद में इस मामले में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच समझौता हो गया था। क्रेमलिन ने क्यूबा में प्रस्तावित मिसाइल स्थलों पर निर्माण कार्य रोक दिया था तथा वह ऐसे आक्रामक आयुध भी क्यूबा से हटाने पर सहमत हुआ था जिनको अमेरिका अपने लिए खतरा मानता था। इसके जवाब में अमेरिका ने जूपिटर इंटरमीडियट रेंज बैलेस्टिक मिसाइलें हटाने पर सहमति जताई थी। इन मिसाइलों को यूएसएसआर से सटी तुर्की की सीमा पर तैनात किया गया था। तुर्की नाटो का सदस्य देश था। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए वर्तमान स्थितियों में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका और रूस एक बार फिर परस्पर सहमति बनाने पर तैयार हो जाएंगे? क्या यूक्रेन के मामले में भी वे उसी तरह समझदारी से काम करेंगे जैसा उन्होंने पहले दो अवसरों पर कर दिखाया था? इन सवालों के जवाब के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन एक चीज पूरी तरह स्पष्ट है कि यूक्रेन मुद्दे पर संबंधित पक्षों के बीच जल्द ही वार्ताओं के माध्यम से समाधान के गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

कार्यस्थल की महत्वपूर्ण संस्कृति

> कार्यस्थल संस्कृति में मूल्यों, व्यवहारों तथा संगठनात्मक गतिशीलता का महत्वपूर्ण योगदान शामिल है।

साक्षी सेठी
(लेखिका, शिक्षक हैं)

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कार्यस्थल पर बिताता है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल का परिवेश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृति का अर्थ दूसरों के साथ व्यक्तिगत संवाद है जिसका परिणाम कार्य प्रक्रियाओं के रूप में सामने आता है। लेकिन हम विरले ही संस्कृति को अपने भौतिक परिवेश से आगे जा कर देखते हैं। कार्य संस्कृति की नैतिकता विलंबित संतुष्टि, अत्यधिक-प्रतियोगिता तथा लगातार मशीनों से बेहतर प्रदर्शन करने में निहित है। किसी संगठन की संस्कृति में कर्मचारियों का जीवन अनुभव शामिल है जिस पर संगठन के कार्यकारियों तथा निर्णय प्रक्रिया में शामिल लोगों का प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में कार्यस्थल संस्कृति या कार्यस्थल परिवेश एक प्रक्रिया है जिसका संबंध लोगों के सीखने के तरीकों से है। कर्मचारियों का व्यवहार अक्सर पुरस्कारों या परिणामों की व्यवस्था से प्रभावित होता है और इसी को कार्य संस्कृति कहते हैं।

सकारात्मक कार्यस्थल परिवेश बनाने के लिए भौतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक आयामों पर ध्यान देना जरूरी है जो कर्मचारियों के अनुभव तथा संतोष को प्रभावित करते हैं। कर्मचारियों की बेहतरी तथा सहायक व समावेशी संस्कृति को प्राथमिकता दे कर संगठन एक उपयुक्त कार्यस्थल परिवेश सृजित कर सकते हैं। इससे संगठन ऐसा कार्यस्थल परिवेश विकसित कर सकते हैं जहां कर्मचारी फलते-फूलते हैं तथा बिजनेस की सफलता में अपना योगदान करते हैं। स्वीकार्यता एवं पुरस्कार की व्यवस्थायें कर्मचारियों के आदर्शों व उनकी अभिप्रेरणा को बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए स्वीकार करना तथा उनको प्रगति एवं

विकास के अवसर देने से सकारात्मक कार्यस्थल परिवेश विकसित होता है और यह प्रबंधकों के लिए मानक तथा बार-बार दुहराये जाने वाला व्यवहार बन जाता है। इसके बाद यह संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। आज संगइन कार्य-जीवन संतुलन में सहायता कर कर्मचारियों को वह लचीलापन व संसाधन उपलब्ध कराते हैं जिसने व्यक्तिगत व पेशेवर जीवन का प्रबंधन संभव होता है। इसमें काम के लचीले घंटे, रिमोट कार्य के विकल्प तथा ऐसी नीतियां शामिल हैं जो कर्मचारियों को अपनी आवश्यकतानुसार अवकाश का अवसर देती हैं। इनमें लाइटिंग, तापमान, शोर का स्तर, उपयुक्त फर्नीचर तथा कर्मचारियों को अद्यतन तकनीक उपलब्ध कराना शामिल है। इसमें काम करने के उपयुक्त उपकरण भी शामिल हैं जो न केवल कर्मचारियों को आराम देते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता तथा संगठन में उत्साह बढ़ाते हैं। सकारात्मक कार्य संस्कृति कर्मचारियों का योगदान सुनिश्चित करती है जहां कर्मचारी भावनात्मक रूप से अपने काम से जुड़ रहते हैं। इसमें प्रमुख अधिकारियों व प्रबंधकों का व्यवहार और कार्रवाइयां महत्वपूर्ण हैं जो कार्यस्थल परिवेश को बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं।

खुलेपन को बढ़ावा देने वाला प्रभावी नेतृत्व फीडबैक को प्रोत्साहित कर कर्मचारियों के विकास में सहायता करता है तथा सकारात्मक व सशक्तीकरण वाला कार्य परिवेश प्रोत्साहित कर सकता है, जबकि इसके उलट नकारात्मक कार्य संस्कृति विभिन्न प्रकार से असंतोष, तनाव तथा कर्मचारियों में उत्पादकता घटाने का काम करता है। जब अधिकारी माइक्रो प्रबंधन में गलत व्यवहार, पक्षपात या पारदर्शिता की कमी पैदा करते हैं तो इससे भय तथा कर्मचारियों के बीच अविश्वास पैदा होता है। संवाद की कमी या पारदर्शिता के साथ सूचनाओं का साझा न करने पर अफवाहें फैलती हैं जिससे विश्वास और कम होता है। इसके कारण कर्मचारी स्वयं को महत्वहीन मानते हैं, उनका समुचित मूल्यांकन नहीं होता है और उनके काम को स्वीकार्यता नहीं मिलती है। आजकल इसके लिए 'क्वाइट क्विटिंग' शब्द का प्रयोग होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि संगठन से जुड़ाव अनुभव करने वाले कर्मचारी अक्सर ज्यादा उत्पादक, अभिप्रेरित तथा कंपनी की सफलता में योगदान करने वाले सिद्ध होते हैं। इससे पता चलता है कि कार्यस्थल परिवेश में कार्य के भौतिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक आयाम शामिल होते हैं। इससे कर्मचारियों के अनुभव तथा बेहतरी प्रभावित होती है। इसमें लेआउट से लेकर आफिस स्पेस की डिजाइन, सहकर्मियों के बीच संबंध तथा संगठनात्मक संस्कृति शामिल हैं। याद रखें के अच्छा वेतन आपको महीने में एक बार प्रेरित करता है, पर अच्छी कार्यसंस्कृति रोज प्रेरणा देती है। संगठनात्मक संस्कृति को परिभाषित करने वाले मानक और व्यवहार कार्यस्थल परिवेश को प्रभावित करते हैं। पारदर्शिता, विश्वास और सम्मान को महत्व देने वाली संस्कृति कर्मचारियों के जुड़ाव व संतोष को प्रोत्साहित करती है।

आप की बात

शराब की लत

शराब खराब है, फिर भी बहुत से लोग उससे बच नहीं पाते हैं। आम आदमी के साथ आम आदमी पार्टी भी शराब के कारण बरबादी की कगार पर पहुंच गई है। उसके कई नेता, मंत्री और अब मुख्यमंत्री भी इसमें डूब गए। अजीब बात है कि एक ओर सामाजिक संस्थाएं शराब छुड़ाओ अभियान चलाती हैं तो दूसरी ओर सरकारें शराब की नई-नई दुकानें खुलवाने के लिए नए-नए ठेकेदारों को अपने पास बुलाती है। उनको इस बात की जरा भी चिन्ता नहीं है कि आम आदमी भले ही शराब में डूबकर अपनी जिंदगी बरबाद कर ले किन्तु सरकार का खजाना सूखने न पाए। आम जनता अपने आस-पास व आवासीय इलाकों से शराब की दुकानें हटाने की मांग करते हुए अभियान चलाती है, लेकिन सरकारें ज्यादा से ज्यादा दूकानें खुलवाने में लगी रहती हैं। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस प्रवृत्ति से मुक्त नहीं है। शराब घोटालों के साथ ही नकली व मिलावटी शराब से हजारों लोगों की जान या आंखें चली जाती हैं। लेकिन इससे बचने के लिए अच्छी और सस्ती शराब हर जगह उपलब्ध कराना कोई विकल्प नहीं है। इसलिए संपूर्ण शराबबंदी और इसकी अत्यधिक उपलब्धता तथा राजस्व के लालच में मदिरापान को प्रोत्साहन की दो अतिवादी स्थितियों से बचने की जरूरत है। शौक व लत में अंतर होना चाहिए।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

केजरीवाल से निराशा

पूर्व जस्टिस संतोष हेगड़े ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह निराश हैं। जिन्हें आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो लालच आप पर हावी हो जाता है। मैं पूरी तरह निराश हूं। मैंने सोचा था कि आप प्रशासनिक निष्पक्षता लाएगी जबकि ऐसा नहीं है। संतोष हेगड़े अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में केजरीवाल के साथ शामिल थे। केजरीवाल से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं, मगर उनकी सरकार सर्वाधिक भ्रष्ट निकली। सरकार के उप-मुख्यमंत्री व अन्य बड़े नेता पहले इसी मामले में बंद हैं। इससे एक बार फिर जाहिर हो गया कि सत्ता के हम्माम में सभी नंगे हैं। अपने बगंले पर भारी धनराशि का खर्च तथा मंत्रियों व विधायकों के वेतन व सुविधाओं में असाधारण वृद्धि वैसे भी किसी जन सेवक के लक्षण नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार होने का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब वह जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। क्या इसे ठीक कहा जा सकता है? क्या आप में कोई और योग्य नेता नहीं बचे हैं जो मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल सकें?

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

एप्पल पर कार्रवाई

अमेरिकन न्याय विभाग ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एप्पल पर मुकदमा दर्ज कराया है। उसने एप्पल पर स्मार्टफोन बाजार पर एकाधिकार करने और प्रतिस्पर्धा को कुचलने का आरोप लगाया है। इसके अनुसार, कंपनी ने आईफोन ऐप स्टोर पर अपने नियंत्रण का दुरुपयोग किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरोप दुनिया भर की अनेक सरकारें, खासकर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां एप्पल पर लगाया करती थी वो गलत नहीं था। क्योंकि अब अमेरिकी सरकार ने भी माना हे कि स्मार्ट फोन बाजार में नंबर एक बने रहने के लिए एप्पल ने गलत तरीके अपनाये। दुनिया भर में अक्सर अनेक प्रकार की कंपनियों के खिलाफ बाजार पर अनावश्यक रूप से कब्जा करने और कानूनों की धज्जियां उड़ाने के मुक़दमे चलते रहते हैं। कुछ समय पहले एक संगीत स्ट्रीमिंग प्रतियोगिता को लेकर यूरोपीय संघ ने एप्पल पर लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। एप्पल पर इन कार्रवाइयों से स्पष्ट है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां पूंजीवाद में प्रतियोगिता के कथित आदर्शों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

कार्पोरेट की जिम्मेदारी

तीन अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत एक शोध रिपोर्ट के अनुसार देश की 40 प्रतिशत संपत्ति 1 प्रतिशत अमीरों के पास सिमट कर रह गई है। दूसरी ओर आम जनता महंगाई और आर्थिक तंगी से परेशान है। अंतरराष्ट्रीय तनाव व युद्धों के कारण दुनिया भर में खाद्य, औषधि व अन्य संसाधनों का संकट पैदा हो गया है। भारत में समाजवाद का प्रयोग तो सफल नहीं हो सका मगर कुछ ऐसे कानून कायदे तो बनाए जा सकते हैं कि देश के उपलब्ध संसाधनों का लाभ देश के निचले तबके तक पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि जहां सरकार देश में गरीब से गरीब व्यक्ति को शिक्षा, आवास, चिकित्सा, भोजन, जल, आदि मूलभूत जरूरतें सस्ती कीमतों पर प्रदान करे, वहीं देश के अति धनवान लोग भी अपनी कमाई का कुछ भाग जन-कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करें। विकसित देशों में अनेक अमीरों ने दानदाता के रूप में अपनी ख्याति स्थापित की है, पर भारत में ऐसे लोगों की कमी है। कार्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी को पारदर्शी व न्यायोचित ढंग से जमीन पर उतार कर वे भारत में बढ़ती असमानता घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

नई दिल्ली, बुधवार 27 मार्च 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

वरूण फैक्टर को लेकर भाजपा में असमंजस

देश के प्रथम राजनैतिक परिवार के एक सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरूण गांधी को लेकर इन दिनों कयास और असमंजस का दौर जारी है। दरअसल पीलीभीत लोकसभा का पिछले दो बार से प्रतिनिधित्व करने वाले वरूण का टिकट इस बार भाजपा ने काट दिया है। उनकी मां मेनका गांधी का सुलतानपुर का टिकट बरकरार रखा है जहां की वे पहले से सांसद हैं। पहले मेनका पीलीभीत की नुमाइंदा हुआ करती थीं परन्तु 2009 में उन्होंने वह सीट अपने बेटे को सौप दी। चार लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर गांधी परिवार से अलग हो चुके एक अन्य सदस्य ने अपना तूफानी आगाज़ किया था। याद हो कि इंदिरा गांधी के एक तरह से तयशुदा वारिस माने जाने वाले दूसरे पुत्र संजय गांधी की आपातकाल के दौरान एक जहाज दुर्घटना में जब मौत हो गयी थी तो बड़े बेटे राजीव पायलेट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आये थे। पारिवारिक मतभेदों के कारण मेनका अपने पुत्र के साथ अलग रहने लगी थी। पले जनता दल व बाद में वे भाजपा में आ गयीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह एवं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वे मंत्री भी बनीं। उन्होंने कई सीटों पर हार-जीत दोनों का ही स्वाद चखा।

नरेन्द्र मोदी की 2014 में बनी सरकार में भी मेनका मंत्री बनीं लेकिन दूसरी बार (2019) में पुन: निर्वाचित होने के बावजूद उन्हें यह मौका नहीं मिला। इस साल के चुनाव प्रचार में वरूण के उग्र बयानों से उम्मीद थी कि उन्हें या वरूण को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मोदी-2 सरकार में मिल सकती है लेकिन ऐसा न हुआ। इतना ही नहीं, जब वरूण ने पिछले कुछ समय में अपने बयानों को संयमित एवं सर्वस्पर्शी बनाना शुरू किया तो भाजपा नेतृत्व के कान खड़े हो गये। विशेषकर उन्होंने शासकीय सुविधाएं अल्पसंख्यकों समेत सभी वर्गों तक पहुंचाने की ज़रूरत बतलाई। उन्होंने लखीमपुर खीरी में किसानों को एक केन्द्रीय राज्यमंत्री के पुत्र द्वारा कुचले जाने की भी आलोचना की जिसमें करीब आधा दर्जन किसान मारे गये थे। वरूण लेखन भी करते हैं। उन्होंने एक लेख में शासकीय योजनाओं की असफलताओं पर भी लेख लिखा जिसके कारण केन्द्र सरकार की फज़ीहत हुई थी। इसी से आभास हो गया था कि मां-बेटे पर संकट आ सकता है। ऐसा ही हुआ जब बारम्बार मंत्रिमंडल के विस्तार या उसमें फेरबदल के बावजूद दोनों में से किसी को भी स्थान नहीं मिला। उल्टे, सांगठनिक फेरबदल के अंतर्गत मेनका को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी निकाल बाहर किया गया। अंदेशा तो यहां तक था कि दोनों के टिकट कट सकते हैं तथा पीलीभीत व सुलतानपुर सीटों से अन्य प्रत्याशी आजमाये जायेंगे। यह आशंका आधी खरी उतरी। मेनका की सीट तो परिवार ने बचा ली लेकिन वरूण की जगह पर दूसरे को उतारा गया।

सियासी पेंच यहीं से शुरू होता है। कयासों एवं अनुमानों की गुंजाइशें भी यहीं से खुलती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि अगर वरूण अपनी सीट से लड़ते हैं, या किसी भी सीट से तो सपा उन्हें समर्थन देगी। अगर उनकी चाही किसी सीट पर उम्मीदवार भी घोषित हो गया हो तो वह खाली करा दी जायेगी। वरूण-मेनका को लेकर अनुमान थे कि यदि उन्हें टिकटें न मिलीं तो दोनों पार्टी छोड़ सकते हैं। अब वह स्थिति तो भाजपा हाईकमान ने टाल दी है लेकिन वरूण के निर्दलीय चुनाव लड़ने से लेकर सपा या कांग्रेस में जाने तक के विकल्प खुले हैं। हालांकि अब साफ है कि वे अपनी मां की स्थिति को खराब नहीं करेंगे क्योंकि उनके ऐसे कदम से मेनका की जीत की सम्भावना भीतरघात से धूमिल हो सकती है। हालांकि एक-एक सीट के लिये तरसते मोदी, जो तीसरी मर्तबा पीएम बनने का सपना संजोये हुए हैं, ऐसा नहीं होने देंगे लेकिन स्थानीय नेतृत्व या कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं, भला इसकी गारंटी कौन ले सकता है? वैसे कोई शक नहीं कि मेनका की इतनी लोकप्रियता तो है कि पार्टी के सम्भावित अंदरूनी विरोध के बाद भी वे अपने दम जीत सकती हैं। तो भी माना जा रहा है कि पुत्र की ओर से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जायेगा जो मां को अड़चन में डाले।

अब बात रहती है कि क्या वे निर्दलीय चुनाव लडेंगे, तो यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वे अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। बात तो कांग्रेस के राहुल गांधी के भी वहां से लड़ने की होती रही है, पर साफ है कि जब देश ऐसे नाज़ुक मोड़ पर खड़ा है जिसमें राहुल की संसद में मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, तो वे अपनी सुरक्षित सीट वायनाड (केरल) के ही जरिये आएंगे। यहां तक माना जाता है कि वर्तमान सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिये राहुल के मुकाबले वरूण कहीं बड़ी चुनौती होंगे। यह अलग बात है कि मेनका गांधी ने 1982 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद इसी सीट पर अपना पहला चुनाव अपने जेठ राजीव गांधी के खिलाफ लड़ा था परन्तु वे बुरी तरह पराजित हुई थीं। वैसे तब से अब तक का सियासी परिदृश्य काफी बदल चुका है। अब दोनों स्थापित नेता हैं।

एक और उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि वरूण कांग्रेस में आ सकते हैं। हालांकि उनके पुराने बयान कांग्रेस की नीति के खिलाफ जाते हैं। लगभग एक साल पहले स्वयं राहुल कह चुके हैं कि उनके विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित होने के कारण उन्हें यहां (कांग्रेस में) दिक्कत होगी। तो भी चुनावी रणनीति के तहत कुछ भी मुमकिन है। जो भी हो, वरूण का टिकट काटकर भाजपा कई तरह की दिक्कतों का सामना कर सकती है क्योंकि इस युवा सांसद का किसी पार्टी की टिकट पर या निर्दलीय लड़ना लगभग तय है। वे चुनाव प्रपत्र पहले ही खरीद चुके हैं। देखना होगा कि भाजपा वरूण फैक्टर से कैसे निपटेगी?

एकजुट विपक्ष और मोदी का 370-400 सीटों का लक्ष्य

देश होली मना चुका है। लोगों के शरीरों पर लगा रंग तो उतर रहा है, पर अब सही मायनों में सियासी रंग चढ़ने लगा है। वह इसलिये क्योंकि सवा-डेढ़ माह दूर रह गये लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे सभी दल या तो अपने प्रत्याशी तय कर चुके हैं या फिर उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। जहां तक गठबन्धन की बात है, तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ कथित रूप से तीन दर्जन से अधिक राजनीतिक दल एनडीए के हिस्से हैं। वहीं प्रमुख चुनौती बनकर उभरी कांग्रेस ने अपने इंडिया गठबन्धन में दो दर्जन पार्टियों को शामिल कराकर भाजपा एवं उसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चिंताएं बढ़ा दी हैं जो अपने लिये तीसरा कार्यकाल तय मानकर चल रहे थे। सीटों का बंटवारा भी अपने-अपने लिहाज से हो रहा है। कांग्रेस जहां पांच न्याय एवं 25 गारंटियों के ईर्द-गिर्द अपना घोषणापत्र लगभग बना चुकी है, वहीं भाजपा मोदी के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये एक बार और सत्ता चाहती है। हालांकि वे कौन से काम हैं जो पूरे किये जाने हैं, यह अस्पष्ट, अपराभाषित व अव्याख्यायित है। उल्टे, उनके 10 साल के कामों को देखते हुए तो वह बड़ी हद तक आशंका पैदा करने वाले हैं।

इस चुनावी चरण से निकलकर अब कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। भारत के मानचित्र को सामने रखकर जब इस पर विचार होता है तो लोगों के सामने यह आश्चर्य बनकर उभरता है कि मोदी ने जो लक्ष्य बनाया है, वह कैसे पाया जा सकता है। विभाजित प्रतिपक्ष के बावजूद 2019 के चुनाव में भाजपा की स्थिति ऐसी कतई नहीं थी कि वह पहले से भी बड़ा बहुमत लेकर सत्ता में लौट सके। वह तो ऐन वक्त पर घटा पुलवामा कांड था जिसकी आड़ में मोदी दूसरी बार पीएम बने। उन्होंने शहीदों के नाम पर सहानुभूति और वोट दोनों बटोरे। पहले दौर की ही तरह मोदी का दूसरा कार्यकाल भी असफलताओं से भरा साबित हुआ। 2014 से 2019 के बीच नोटबन्दी लोगों के लिये जानलेवा साबित हुई तो 2019 से अब खत्म होने जा रहे कार्यकाल के दौरान कोरोना ने देश को तबाह कर दिया। देश चाहे आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका हो परन्तु मोदी के चंद पूंजीपति मित्र अमीरों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गये। साफ था (और है भी) कि मोदी का वरदहस्त उन पर था। इसके खिलाफ़ संसद के भीतर व बाहर जमकर आवाजें उठीं, भ्रष्टाचार के पर्दाफाश भी हुए लेकिन इस पर सरकार ने मौन साधे रखा। उल्टे, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर विरोधी आवाजों को बन्द करने के संगठित, सुनियोजित एवं राज्य प्रायोजित उपक्रम हुए। कुछ में सरकार कामयाब हुई तो कुछ आवाजों को वह दबा न सकी।

वैसे तो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिये मोदी-भाजपा ने तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी थीं, लेकिन सबसे बड़ा दांव अयोध्या स्थित राममंदिर का था जिसमें रामलला की मूर्ति की 22 जनवरी को आनन-फानन में प्राण-प्रतिष्ठा तो हुई लेकिन उसका खास फायदा होता नज़र नहीं आया क्योंकि श्रद्धा की जो लहर उठाई गयी थी, वह हफ्ते भर में ही विलीन हो गयी। फिर, नागरिकता संशोधन कानून का भी अपेक्षित फायदा मिलता नहीं दिख रहा है। चूंकि कामों के बारे में किसी भी तरह का उल्लेख करने की स्थिति में भाजपा और मोदी हैं ही नहीं, तो मोदी अपनी रैलियों व भाषणों में भावनात्मक मुद्दे उभारने की कोशिशें कर रहे हैं, जिनमें कभी वे संदेशखाली (पश्चिम बंगाल) की महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न पर आंसू बहाते हैं तो कभी बताते हैं कि राहुल गांधी युवाओं को 'नशेड़ी' बतला रहे हैं। ऐसे ही, राहुल गांधी द्वारा दिये गये इस बयान को भी उन्होंने हास्यास्पद ढंग से तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की जिसमें राहुल ने कहा था कि वे (राहुल) एक 'शक्ति' के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने मोदी की दमनात्मक शक्तियों की ओर ईशारा किया था लेकिन मोदी ने उसे बड़े ही बचकाना तरीके से 'स्त्री शक्ति' से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। वे साबित करना चाहते थे कि राहुल व कांग्रेस महिला तथा हिन्दू विरोधी हैं। उनकी ऐसी चालें बेअसर हो रही हैं क्योंकि लोग अब जान गये हैं कि जो मोदी संदेशखाली की महिलाओं की स्थिति को लेकर इतने द्रवित हैं वे मणिपुर और महिला पहलवानों के मामलों में चुप्पी साधे बैठे हैं। उनके दोनों ही आचरण उनकी राजनीति के हिस्से हैं।

डॉ. दीपक पाचपोर

> **इस चुनावी चरण से निकलकर अब कयासों का दौर शुरू हो चुका है कि अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। भारत के मानचित्र को सामने रखकर जब इस पर विचार होता है तो लोगों के सामने यह आश्चर्य बनकर उभरता है कि मोदी ने जो लक्ष्य बनाया है, वह कैसे पाया जा सकता है। विभाजित प्रतिपक्ष के बावजूद 2019 के चुनाव में भाजपा की स्थिति ऐसी कतई नहीं थी कि वह पहले से भी बड़ा बहुमत लेकर सत्ता में लौट सके। वह तो ऐन वक्त पर घटा पुलवामा कांड था जिसकी आड़ में मोदी दूसरी बार पीएम बने। उन्होंने शहीदों के नाम पर सहानुभूति और वोट दोनों बटोरे।**

2014 में वे कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार, परिवारवाद आदि के जिन मुद्दों को लेकर जीते थे, आज भी वे ही उनके मुख्य सियासी राग हैं। इसका कारण यही है कि पीएम के पास उनके कथित आर्थिक मॉडल और विकास सम्बन्धी कोई भी बात बतलाने के लिये है ही नहीं। ऐसे में कांग्रेस व इंडिया गठबन्धन अपने कुछ आंतरिक दिक्कतों के बावजूद लगातार मजबूत हो रहा है। असली बात यह है कि वह एकजुट बना हुआ है जिसके बारे में भाजपा ने उम्मीद ही नहीं की थी। यह तो सही है कि कई राज्यों या सीटों पर इंडिया के भागीदार दलों के बीच मतभेद हैं लेकिन उन पर परस्पर चर्चाएं हो रही हैं। बड़ी बात नहीं कि कुछ पर विवाद बने रहें और उनके आखिर तक हल न ढूंढे जा सकें पर सवाल यह है कि मोदी ने अबकी बार जो भाजपा की 370 व एनडीए की 400 सीटों का लक्ष्य रखा है वह क्या प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में यह लक्ष्य पाना कठिन दिखता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो यह है कि यह इसलिये व्यवहारिक नहीं हो सकता क्योंकि भाजपा का दावा है कि उनके एनडीए में 38 दल हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भाजपा अपनी सहयोगी 37 पार्टियों से सिर्फ 30 सीटों की उम्मीद रखती है। फिर, अपने चरमोत्कर्ष काल में भाजपा 303 सीटें ही जीत सकी थी तो इनमें लगभग 70 का इज़फ़ा वह कैसे करेगी? कुछ का कहना है कि यह केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो मोदी लड़ रहे हैं। वे ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे है जिससे लोगों को लगे कि भाजपा सरकार ज्यादा बड़े बहुमत से जीतकर आ रही है। दूसरे, वे विपक्ष का मनोबल गिराना चाहते हैं।

नया घटनाक्रम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी का है जिसके कारण भाजपा और भी फंस गयी है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार करने से इंडिया गठबन्धन और भी एकजुट हो गयी है। आप की मौजूदगी दिल्ली के अलावा सरकार के रूप में पंजाब में है। इसके साथ ही चंडीगढ़ में उसका मेयर है तथा गोवा, गुजरात, हरियाणा के अलावा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में भी उसकी उपस्थिति है। इस गिरफ्तारी से भाजपा की 'बी' टीमें कहलाने वाली पार्टियां भी सतर्क हो गयी हैं। बड़ी बात नहीं कि वे चुनाव के पहले या बाद में इंडिया से जुड़ जायें क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो केजरीवाल अक्सर भाजपा के लिये मददगार साबित हुए हैं, वे भी असुरक्षित हैं, फिर तो किसी पर भी गाज गिर सकती है। उधर भाजपा के कई लोग चुनाव लड़ने से इंकार कर चुके हैं। कई ने पार्टी टिकटें तक लौटा दीं। साफ है कि लोग भाजपा की टिकट पर लड़ना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। कुछ भाजपायी सांसदों ने तो राजनीतिक संन्यास का ऐलान तक कर दिया है। ये सारे ही स्पष्ट संकेत हैं कि 370-400 पार का भाजपायी नारा छलावा मात्र है।

(लेखक देशबन्धु के राजनीतिक सम्पादक हैं)

क्या रामलीला मैदान अपना 1977 का इतिहास दोहराएगा!

इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि शराब घोटाले के आरोपों में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ठीक उस समय हुई है जब चुनावी बांड महाघोटाले की परतें बाकायदा उधड़नी शुरू हो चुकी हैं। इसी का नतीजा है कि आम आदमी पार्टी की इस दलील का लोगों के बीच काफी हद तक असर हो रहा है कि कथित रूप से 100 करोड़ रु0 के दिल्ली के शराब घोटाले में अगर कोई ''मनी ट्रेल'' है भी तो, वह तो सीधे भाजपा तक जाती है, जिसके सबूत बांड घोटाले से संबंधित रहस्योद्घाटनों के हिस्से के तौर पर सामने आ चुके हैं। याद रहे कि जिस स्थापित दवा कारोबारी, शरतचंद्र रेड्डी की उक्त घोटाले के मुख्य अभियुक्त के रूप में गिरफ्तारी के बाद, वादामाफ गवाह बनाकर रिहाई के बाद, मुख्यत: उसकी गवाही की ही बिनाह पर मनीष सिसोदिया तथा संजय सिंह के बाद, अब खुद अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है, उससे जुड़ी कंपनियों ने इसी दौरान, बांड के जरिए भाजपा को पूरे 55 करोड़ रु0 का चंदा दिया था। इसमें 5 करोड़ रु0 का चंदा तो रेड्डी की जमानत पर रिहाई के फौरन बाद दिया गया था और बाकी 50 करोड़ का चंदा अलग-अलग किस्तों में बाद में दिया गया। अगर वाकई 100 करोड़ रु0 का घोटाला हुआ था, जैसाकि ईडी का आरोप है, तो इसे बेशक घोटाले की अवैध कमाई के प्रवाह की मुख्य धारा माना जाना चाहिए। हां! अगर कोई यह दलील देने लगे तो बात दूसरी है कि भाजपा को बांड के जरिए दिया गया 55 करोड रु0 तो ईडी द्वारा इस दवा व्यापारी से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए, सीधी-साधी हफ्ता वसूली या एक्सटॉर्शन का मामला है!

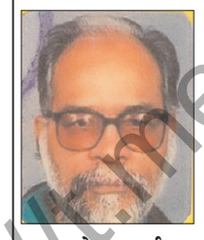

राजेन्द्र शर्मा

> **इसीलिए, संघ-भाजपा और उनका सेवादार मीडिया, ध्यान बंटाने के जरिए, इस महाघोटाले को ज्यादा से ज्यादा अनदेखा करने की ही कार्यनीति का ज्यादा सहारा ले रहे हैं। लेकिन, उनके दुर्भाग्य से इस घोटाले के संबंध में, स्वतंत्र संगठनों तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा सामने लाया जा रहा मसाला इतना विस्फोटक है कि मुख्यधारा के मीडिया के एक हिस्से को, खासतौर पर मुख्यधारा के प्रिंट मीडिया के एक हिस्से को भी, इन रहस्योद्घाटनों को जगह देनी ही पड़ रही है।**

इस पूरे मामले से इसका कुछ अंदाजा तो लग ही सकता है कि चुनावी बांड घोटाले का भूत, भाजपा की सारी कोशिशों के बावजूद, आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यह घोटाला इतना बड़ा और इतनी अवैधताओं को समेटे हुए है कि कम से कम इस आम चुनाव तक तो, इसकी नयी-नयी परतें खुलती ही रहेंगी। इसीलिए, हैरानी की बात नहीं है कि इस मामले में मोदी सरकार और सत्ताधारी पार्टी के बचाव के लिए, संघ-भाजपा की ओर से अमित शाह तथा निर्मला सीतारमण से लेकर, खुद आरएसएस के महासचिव, होसबले को उतारे जाने के बावजूद, घोटाले से लेकर हफ्तावसूली तक के आरोपों को जवाब देना तो दूर रहा, उन्हें भोंथरा तक नहीं किया जा सका है। और तो और संघ-भाजपा का इसका प्रचार भी खास काम नहीं आया है कि बांड के जरिए अगर अवैध तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है, तो इस तरह अकेले भाजपा ने ही पैसा थोड़े ही जुटाया है, दूसरी पार्टियों ने भी तो बांड से पैसा उठाया है और तृणमूल कांग्रेस, टीआरएस, एसआरसीपी, बीजेडी आदि क्षेत्रीय पार्टियों ने तो खासतौर पर उल्लेखनीय मात्रा में इस रास्ते से पैसा उठाया है।

प्रचार की सारी ताकत लगाए जाने के बावजूद, इस दलील को एक तो इस तथ्य ने बेअसर कर दिया है कि दूसरी तमाम पार्टियों को मिलकर बांड से जितना पैसा मिला था, उससे ज्यादा पैसा अकेले भाजपा ने बटोरा था। दूसरे कुछ क्षेत्रीय सत्ताधारी पार्टियां स्थानीय रूप से कुछ बड़े उद्योगपतियों को उपकृत करने के बदले में उनसे बांड से चंदा लेने की स्थिति में रही भी हों तब भी, केवल केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ही केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर के हफ्ता वसूली करने और इन्फास्ट्रक्चर, खनन आदि क्षेत्रों की भीमकाय कंपनियों को ठेकों, मंजूरियों आदि के जरिए उपकृत करने के बदले में चंदा बटोरने की स्थिति में थी। और इससे भी महत्वपूर्ण यह कि केंद्र में सत्ता में बैठी भाजपा ही, यह जानने की स्थिति में थी कि कौन सा उद्योगपति, उसके अलावा भी किस पार्टी को, कितना चंदा दे रहा था? इस जानकारी को हथियार बनाकर, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए आसानी से यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि चंदे का यह दरवाजा, सिर्फ और सिर्फ सत्तापक्ष के लिए खुला रहे, विरोधियों के लिए नहीं। कांग्रेस का चुनावी बांड से कमाई में तृणमूल कांग्रेस से भी पीछे, बहुत दूर तीसरे नंबर पर रह जाना और बांड से मिले कुल चंदे के दस फीसद से भी कम और भाजपा को मिले चंदे से चौथाई से भी कम में सिमट जाना, इसी की ओर इशारा करता है।

इसीलिए, संघ-भाजपा और उनका सेवादार मीडिया, ध्यान बंटाने के जरिए, इस महाघोटाले को ज्यादा से ज्यादा अनदेखा करने की ही कार्यनीति का ज्यादा सहारा ले रहे हैं। लेकिन, उनके दुर्भाग्य से इस घोटाले के संबंध में, स्वतंत्र संगठनों तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा सामने लाया जा रहा मसाला इतना विस्फोटक है कि मुख्यधारा के मीडिया के एक हिस्से को, खासतौर पर मुख्यधारा के प्रिंट मीडिया के एक हिस्से को भी, इन रहस्योद्घाटनों को जगह देनी ही पड़ रही है। मिसाल के तौर पर लीगेसी मीडिया भी पूरी तरह से इस तरह की कहानियों को कैसे अनदेखा कर सकता है कि बांड से करीब 1,000 करोड़ रु0 का चंदा देने वाली 32 दवा कंपनियों में, 7 ऐसी दवा कंपनियां भी शामिल थीं, जिनके खिलाफ घटिया दवाएं बनाने के लिए, सरकारी मशीनरी द्वारा जांचें/ कार्रवाइयां की जा रही थीं! या यही कि कुख्यात सिलक्यारा टनल, जिसके बैठ जाने से, इकतालीस मजदूर कई हफ्ते तक फंसे रहे थे और इसके बावजूद उसे बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, उसने भी भाजपा को 55 करोड़ रु0 का चंदा बांड के जरिए दिया था! और यह भी कि बीसियों कंपनियों ने अपने मुनाफे से कई-कई गुना ज्यादा चंदा बांड के जरिए दिया था और इनमें एक दर्जन से ज्यादा ऐसी कंपनियां शामिल थीं, जिन्होंने अपनी स्थापना के साथ ही यानी कोई मुनाफा आने से पहले ही चंदा देना शुरू कर दिया था या जिनके सारे लक्षण शैल या खोखा कंपनियों के थे।

इस सब के सामने आने से, मीडिया पर मुकम्मल नियंत्रण और अधिकतम संभव प्रचार के बल पर, गढ़ी गयी मोदी राज की ''न खाऊंगा, न खाने दूंगा'' की छवि, भरभरा कर गिरनी शुरू हो गयी है। इसके स्वाभाविक परिणाम के रूप में, विपक्षी नेताओं को ''भ्रष्ट'' बनाकर पेश करने की संघ-भाजपा की मुहिम, भोंथरी होती जा रही है। ऐसे में और खासतौर पर चुनाव से ऐन पहले, केंद्रीय एजेंसियों के सहारे विपक्ष के खिलाफ कोई भी कार्रवाई, नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए उल्टी ही पड़ सकती है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में ठीक यही होता नजर आ रहा है। इससे पहले, जनवरी की आखिरी तरीख को, ऐसे ही गढ़े हुए मामले में, झारखंड के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था; तब भी संघ-भाजपा अपना मनचाहा हासिल नहीं कर पाए थे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के संदर्भ में जिस तरह, सरकार का वैकल्पिक नेतृत्व सामने आ गया, जिसने आसानी से बहुमत साबित कर दिया और जिस तरह हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ खासतौर पर झारखंड के आदिवासी गोलबंद हुए, उसने मोदी राज के मंसूबों पर कम से कम झारखंड के स्तर पर पानी फेर दिया। आम चुनाव के संदर्भ में इसका एक इशारा, राज्य से कांग्रेस की इकलौती सांसद को और हेमंत सोरेन की भाभी को दलबदल करा के, हाथ के हाथ लोकसभा के लिए भाजपा का टिकट दे दिया जाना है।

बहरहाल, केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में मोदी राज के मंसूबों की विफलता, और दूर तक जाती नजर आती है। अगर, चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई के पीछे यह विचार था कि केजरीवाल को जेल में डालने से, उनकी पार्टी पंगु हो जाएगी, चुनाव अभियान चलाने में असमर्थ हो जाएगी, तो साफ तौर पर यह विचार गलत साबित होने जा रहा है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से लेकर, केजरीवाल की पार्टी के चुनाव प्रचार तक पर, शायद ही कोई असर पड़ता नजर आता है। उल्टे आम आदमी पार्टी कहीं लड़ाकू तेवर में नजर आती है और चुनाव प्रचार के मंच से केजरीवाल की अनुपस्थिति से जो कमी रह भी जाएगी, उससे ज्यादा की भरपाई केजरीवाल के मोदी राज के जुल्म-ज्यादती के शिकार बनाए जाने की छवि कर देने वाली है।

वास्तव में इसका असर सिर्फ दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा व पंजाब तक ही सीमित रहे, यह भी जरूरी नहीं है, हालांकि दिल्ली और हरियाणा में इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों पर तालमेल हो चुका है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, उनकी अपनी पार्टी ने ही नहीं बल्कि समूचे विपक्ष ने जिस तरह से प्रतिक्रिया की है, उसमें इस गिरफ्तारी के देश भर में मोदी राज की तानाशाही के प्रतीक के रूप में देखे-पहचाने जाने की संभावनाएं नजर आती हैं। केरल, तमिलनाडु आदि समेत, देश के अनेक हिस्सों में हुई विरोध कार्रवाइयां, इसी की ओर इशारा करती हैं। 31 मार्च को बुलायी गयी रामलीला मैदान की विरोध रैली, जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के नेताओं के शामिल होने की ही उम्मीद नहीं की जा रही है, जिसके लिए वामपंथ तथा कांग्रेस समेत सभी पार्टियां सक्रिय रूप से गोलबंदी कर रही हैं, इसी सिलसिले को और आगे ले जाएगी।

इस संदर्भ में 1977 के आम चुनाव की पूर्व-संध्या में दिल्ली के रामलीला मैदान में ही हुई विपक्ष की संयुक्त रैली की याद आना स्वाभाविक है, जिसने इमर्जेंसी के लिए जिम्मेदार श्रीमती गांधी की विदाई की पटकथा लिख दी थी। रामलीला मैदान एक बार फिर अपना यह इतिहास दोहरा पाता है या नहीं, नरेंद्र मोदी की विदाई की पटकथा लिख पाता है या नहीं, यह तो आने वाले हफ्तों और दो महीनों में पता चलेगा। लेकिन, इतना तय है कि स्थितियां उसी ओर बढ़ती नजर आती हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी, नरेंद्र मोदी निजाम की बढ़ती तानाशाही को तेजी से बहस के केंद्र में ला रही है। यही वह धुरी है, जहां से नरेंद्र मोदी की गाड़ी को बेपटरी किया जा सकता है। पहले, ओडिशा में बीजू जनता दल और अब पंजाब में अकाली दल का भाजपा के गठबंधन के न्यौते को ठुकरा देना, इसी दिशा में एक और इशारा लगता है।

पावन प्रसंग

मानसिक और वैचारिक चिकित्सा

स्वाध्याय की उपयोगिता असाधारण एवं अद्भुत है। यह मानसिक आरोग्य एवं वैचारिक संवर्द्धन के लिए अत्यावश्यक है। क्योंकि मन और विचार के शुद्ध परिष्कृत हुए बगैर स्वस्थ शरीर एवं शालीन व्यवहार की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वाध्याय के द्वारा पहले मन स्वस्थ होता है, फिर जीवन। सोच-विचार के तंत्र में प्रकृति बनी रहने पर शारीरिक एवं व्यवहारिक परेशानियां तथा समस्याएं बनी रहती हैं। स्वाध्याय इन सबको ठीक करने के लिए सर्वप्रथम विचारतंत्र को परिष्कृत परिमार्जित करता है और अपने स्व अर्थात अस्तित्व का बोध कराता है। अत: अध्यात्म जगत में इसे चिकित्सा का स्थान दिया गया है, परंतु विडंबना यह है कि वर्तमान समय में स्वाध्याय की प्रवृत्ति घटी है और यहां तक कि अध्ययन के प्रति सम्मान में भी कमी आई है। अध्ययन और पढ़ने में अंतर होता है तथा इन दोनों से स्वाध्याय का स्थान पर्याप्त ऊंचा और श्रेष्ठ है। अखबार और पत्र-पत्रिकाओं को उलटना-पलटना पढ़ने की कोटि में आता है। पढ़ना एक प्रकार से सूचना संग्रह करने की प्रक्रिया है। अध्ययन के अंतर्गत श्रेष्ठ साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि आते हैं, जिनमें विषय की गहराई होती है। अध्ययन में मनन-चिंतन का पर्याप्त स्थान होता है; क्योंकि इसके बिना विषय की गहराई में उतर पाना संभव नहीं है। स्वाध्याय में ऐसे साहित्य आते हैं,जो हमारे अस्तित्व को बताने के लिए सहायक होते हैं। इन साहित्य के माध्यम से ऐसे सूत्र प्राप्त किए जाते हैं जिनसे हमारी स्वचेतना के विकसित होने की अवस्था में एक नई दिशा-दशा उपलब्ध हो सके। स्वाध्याय स्वयं को जानने की विधा है, जीवन को पढ़ने की कला है। जीवन के मर्मज्ञ एवं द्रष्टा मानते हैं कि जीवन इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रोमांचक पुस्तक है। स्वाध्याय से इसके रहस्य परत दर परत खुलते चले जाते हैं और हम रहस्य के क्षेत्र में प्रवेश करते चले जाते हैं।

मन को अपने अनुरूप मनोरंजन की आवश्यकता है। अत: यदि इसे श्रेष्ठ विचारों से युक्त साहित्य नहीं मिलेगा तो वह निम्नस्तरीय साहित्य के प्रति आकर्षित होगा ही। इसी स्तरीय साहित्य के सुबोध और सरल भाषा में लिखे होने के अभाव में ही ऐसी मानसिक विपन्नता फैली है, बढ़ी है। स्वाध्याय चिकित्सा के द्वारा इस मानसिकता को परिष्कृत कर स्वस्थ एवं श्रेष्ठ विचारों से संपन्न किया जा सकता है। सोच विचार या बोधतंत्र को निरोग करने की सार्थक प्रक्रिया स्वाध्याय से बढ़कर और कुछ नहीं है। ध्यान देने योग्य बात है कि स्वाध्याय अध्ययन नहीं है और न इसका पयार्य ही है। अध्ययन केवल बौद्धिक विकास तक सीमित रहता है, जबकि स्वाध्याय अपने बोध को संवारने,तराशने की महान प्रक्रिया है।

मानवीय चेतना के गंभीर जानकार एवं मनीषी इस बोध के दो आयाम बताते हैं। पहला है- बाह्य बोध और दूसरा है- आंतरिक बोध। बाह्य बोध इंद्रियों की सहायता से होने वाला बोध है और आंतरिक बोध अर्थात बौद्धिक विवेचन विश्लेषण एवं आंतरिक अनुभूतियों से होने वाला ज्ञान है। बोध के दोनों आयाम आपस में जुड़े एवं हुए हैं। जो इंद्रियां अनुभव करती हैं बुद्धि उस पर विचार किए बिना नहीं रहती। इसी प्रकार से हमारी आंतरिक सोच में जो विचार, भावनाएं, विश्वास, आस्थाएं, अपेक्षाएं व आग्रह समाये रहते हैं, वे इंद्रिय अनुभूतियों को अपने रंग में रंगे बिना नहीं रहते। यदि दृष्टिकोण को स्वस्थ बना लिया जाए तो जीवन के सभी आयाम अपने आप ही स्वस्थ हो जाते हैं। स्वाध्याय इस दृष्टिकोण की चिकित्सा करता है, देखने के नजरिए को बदल देता है।

स्वाध्याय सूक्ष्म अध्ययन की श्रेष्ठ प्रविधि है। इस विधि के चार मुख्य बिंदु हैं। इस क्रम में सबसे पहले ऐसे ग्रंथों का चयन किया जाता है, जो 'स्व' की अनुभूति से संपन्न महामानवों द्वारा सृजित किए गए हों, इनके लिए उपनिषद,गीता, श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि के लिखे ज्ञान की बातें पढ़ी जा सकती हैं।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

उस दौर में जनता की जबान पर एक ही मांग ,हैंडपम्प लगवा दे

यूपी,बिहार ,ओडिशा और

हिन्दुस्तान 1936 सत्य • सार्थक • सदैव

जेल से सरकार

कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्थापित परंपरा से अलग जाते हुए जेल से सरकार चलाने का जो फैसला किया है, उसने एक नए विवाद और नए विमर्श को जन्म दिया है। विवाद इसलिए कि पूर्व में जब भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई, तो संबंधित मुख्यमंत्री ने हिरासत में लिए जाने से पहले अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उन मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे राजनीतिक शुचिता और सांविधानिक गरिमा की रक्षा के नैतिक दबाव से प्रेरित रहे। मगर, केजरीवाल के रुख ने विरोधियों को उन पर हमले का मौका मुहैया करा दिया है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी की हिरासत में हैं, तो उनके पास लेखन सामग्री कहां से आई कि वह अपने मंत्रियों को निर्देश जारी कर रहे हैं? अब उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग कर डाली है। जाहिर है, आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केजरीवाल और उनकी पार्टी के मौजूदा रुख के पीछे जहां दिल्ली व देश के मतदाताओं तक यह पैगाम पहुंचाना है कि सलाखों के पीछे भी आपके हितों के लिए मुख्यमंत्री सक्रिय हैं, तो वहीं भाजपा व एनडीए का पूरा प्रयास उनके इस कदम को अनैतिक ठहराने का है।

राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों से परे इस प्रकरण ने देश और समाज के आगे विमर्श का एक गंभीर मुद्दा पेश किया है, क्योंकि संविधान इस संदर्भ में मौन है। संविधान यही कहता है कि मंत्रियों की एक परिषद होगी, जो शासन संबंधी फैसले लिया करेगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक की सदारत के लिए मुख्यमंत्री की उपस्थिति की भी बाध्यता नहीं है, काबीना का वरिष्ठतम मंत्री यह दायित्व निभा सकता है। ऐसे में, सरकार के दैनंदिन कार्यों में फौरी तौर पर कोई खास व्यवधान नहीं आने वाला। फिर जेल मैनुअल भी विचाराधीन कैदियों को सप्ताह में एक दिन मुलाकात का मौका देता है और यह भी प्रावधान है कि सभी कैदी पंद्रह दिनों में एक बार अपने रिश्तेदारों, साथियों, कानूनी सलाहकारों को पत्र लिख सकते हैं। ऐसे में, यह सवाल स्वाभाविक है कि यदि यह मामला लंबा खिंचता है, तो क्या इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में दिल्ली सरकार जेल से चलेगी?

यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठने लगा है कि यदि यह मामला लंबा खिंचता है, तो क्या इस विधानसभा के शेष कार्यकाल में दिल्ली सरकार जेल से चलेगी?

निस्संदेह, केंद्र अभी इस स्थिति को लेकर कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मगर इस कथित घोटाले में जांच एजेंसियों की दक्षता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि इतने महीनों बाद भी इस मामले में ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ? नैतिकता का कोई सवाल एकांगी नहीं होता। किसी अन्य से नैतिकता की अपेक्षा करते हुए खुद भी मजबूत नैतिक धरातल पर खड़े रहना पड़ता है, वरना उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। दुर्योग से पिछले कुछ समय से हमारे समूचे राजनीतिक माहौल में जिस एक चीज का सबसे अधिक ह्रास हुआ है, वह नैतिकता ही है। इसलिए अगली संसद से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे मसलों पर वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करे। ऐसे गंभीर मसलों में, जिसमें किसी गिरफ्तारी से एक निर्वाचित सरकार का कामकाज आंशिक रूप से भी प्रभावित हो, जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। इससे न सिर्फ उनकी निष्पक्षता मजबूत होगी, बल्कि प्रतिशोध की राजनीति के लिए गुंजाइश भी कम होगी। इस विमर्श को एक वैधानिक अंजाम तक ले जाने के लिए नई संसद में पक्ष-प्रतिपक्ष को एकराय होना होगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 27 मार्च, 1949

कमजोर नीति

हिंदेशिया के मामले में सुरक्षा कौंसिल बराबर कमजोर नीति का अनुसरण कर रही है। हाल में ही उसने कनाडा की ओर से प्रस्तावित एक प्रस्ताव स्वीकार किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के हिंदेशियाई कमीशन को हिदायत दी गई है कि वह हिंदेशिया के प्रजातंत्रवादियों और डचों के बीच (१) जोग्जाकार्टा में प्रजातंत्री सत्ता की पुनर्स्थापना और (२) स्वतंत्र हिंदेशियाई संघ की रचना के लिए हेग में गोलमेज कांफ्रेंस बुलाये जाने के बारे में समझौते कराने की कोशिश करे। सुरक्षा कौंसिल का यह प्रस्ताव इतना गोलमोल और हल्का है कि उस पर हिंदेशिया के प्रजातंत्री हल्कों में कोई उत्साह नहीं पैदा हुआ है। भारत की हिंदेशिया के मामले में गहरी दिलचस्पी है। यहां के सरकारी हल्कों में भी सुरक्षा कौंसिल के प्रस्ताव पर निराशा प्रकट की गई है। सुरक्षा कौंसिल ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं किया कि उसके २८ जनवरी के प्रस्ताव को न मानने की जिम्मेदारी डचों पर है। उसके लिए सीधा मार्ग यही हो सकता था कि वह नीदरलैंड सरकार के विरुद्ध ऐसा कदम उठाती कि जिससे उसका यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा सकता। किन्तु सुरक्षा कौंसिल में अभी इतना सामर्थ्य नहीं मालूम देता कि वह राष्ट्रों से अपने निश्चयों पर अमल करवा सके।

सुरक्षा कौंसिल ने यह आदेश दिया था कि हिंदेशिया में फौजी कार्रवाई तुरन्त बन्द कर दी जाये और प्रजातंत्री नेताओं को रिहा किया जाये। ये दोनों ही बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं। बटाविया की २४ मार्च की खबर है कि गत सप्ताह मध्य जावा में विस्तृत लड़ाई हुई, जिसमें प्रजातंत्री गुरिल्लों को भारी हानि उठानी पड़ी। पूर्वी जावा और सुमात्रा में भी इसी प्रकार की लड़ाई होने के समाचार दिये गये हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि डचों ने हिंदेशिया में फौजी कार्रवाई बन्द नहीं की है। दूसरे उन्होंने प्रजातंत्री नेताओं को प्रजातंत्री राजधानी जोग्जाकार्टा में लौटने की स्वतंत्रता नहीं दी है और इसलिए उन्होंने फिलहाल उसी टापू में रहने का निश्चय किया है, जहां डचों ने उन्हें नजरबन्द किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के हिंदेशियाई कमीशन ने सुरक्षा कौंसिल को स्पष्ट रूप में लिखा था कि डचों ने सुरक्षा कौंसिल के प्रस्ताव की अवहेलना की है। इसके बावजूद सुरक्षा कौंसिल का डचों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाना तो दरकिनार रहा, उसकी निन्दा तक न करना उसकी दुर्बलता का ही परिचायक हो सकता है।

तमिलनाडु में जोर दिखाती भाजपा

दक्षिण एक्सप्रेस

यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

यहां भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपना मत-प्रतिशत बढ़ाने की दिख रही है। वह 20 फीसदी से अधिक मत-प्रतिशत हासिल करके यहां की कुछ सीटें जीतना चाहती है।

लोकसभा चुनाव से ऐन पहले फरवरी और मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु के कम से कम पांच दौरे से भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में ही वोट डाले जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री की आखिरी यात्रा लोकसभा चुनावों की घोषणा से एक दिन पहले हुई थी। मगर भाजपा कार्यकताओं व नेताओं का जोश उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद ठंडा पड़ता दिख रहा है।

भाजपा आलाकमान ने यहां प्रत्याशियों के चयन में अपनी पुरानी परंपरा का ही पालन किया है और राज्य व केंद्र की नामचीन हस्तियों पर अपना दांव लगाया है। इन शख्सियतों में अभिनेता, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि गवर्नर रहे लोग भी शामिल हैं। उसने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को मैदान में उतारा है, और तेलंगाना में राज्यपाल पद से अभी-अभी इस्तीफा देने वाली तमिलिसाई सौंदर्यराजन व राज्य पार्टी प्रमुख अन्नामलाई को भी प्रत्याशियों की सूची में शामिल किया है। छोटे परदे की जानी-मानी अभिनेत्री राधिका पर भी दांव लगाया गया है, जिनके अभिनेता-निर्माता पति शरत कुमार ने पिछले दिनों अपनी पार्टी का भाजपा में विलय किया है। पार्टी ने पॉन राधाकृष्णन पर भी फिर से भरोसा किया है, और उन्हें 10वीं बार कन्याकुमारी से मैदान में उतारा है।

भाजपा यहीं तक नहीं रुकी, उसने एनडीए के अपने सहयोगी दलों को भी जाने-माने चेहरों को तरजीह देने को कहा है। मसलन, उसने पीएमके को अंबुमणि रामदास की पत्नी सौम्या को टिकट देने के लिए प्रेरित किया। राज्य के उत्तरी हिस्से में खासा प्रभाव रखने वाले जाति-आधारित इस दल ने आखिरी क्षणों में एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया था, जो भाजपा के लिए बड़ी राहत लेकर आया, क्योंकि वह चुनाव में उतरने के लिए किसी विश्वसनीय सहयोगी की तलाश में थी।

भाजपा ने पहले जूनियर अंबुमणि को ही चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उन्होंने अपनी अनिच्छा जताई, क्योंकि उनका निर्वाचन हाल ही में राज्यसभा के लिए हुआ है। इसके बाद पार्टी ने उनकी पत्नी सौम्या को परिवार की पारंपरिक सीट धर्मपुरी से लड़ने के लिए मनाया। पार्टी ने पीएमके को सामाजिक फिल्मों के जाने-माने अभिनेता और निर्देशक थंगर बच्चन को भी टिकट देने के लिए कहा। वास्तव में, भाजपा ने सहयोगी दलों को अपने स्टार उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारने की सलाह दी है। इसी का परिणाम है कि जॉन पांडियन, टीटीवी दिनाकरन, परिवेंदर, एसी शनमुगम, ओ पनीरसेल्वम जैसे नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, जबकि इनमें से कई इसके लिए तैयार न थे। अन्नाद्रमुक से बाहर किए जाने के बाद भी पार्टी महासचिव का दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम से तो साफ-साफ कहा गया कि वह या तो भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ना ही होगा। उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ना स्वीकार किया है। पनीरसेल्वम ने कभी यह सोचकर भाजपा का साथ दिया था कि ई पलानीसामी के साथ उनकी लड़ाई में केंद्र सरकार उनका साथ देगी, पर उन्हें ऐसी कोई मदद नहीं मिल सकी। अब उनसे या तो भाजपा में शामिल होने को कहा गया या अपनी पार्टी बनाने के लिए, ताकि वह हमेशा के लिए अन्नाद्रमुक की कमान संभालने के अयोग्य हो जाएं।

इसी तरह, तमिलिसाई भी बाकी दूसरों की तरह चुनाव नहीं लड़ना चाहती थीं। नगालैंड और झारखंड के गवर्नर क्रमशः इला गणेशन और सीपी राधाकृष्णन ने भी विनम्रतापूर्वक आग्रह अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि राज्य प्रमुख अन्नामलाई भी, जिन्होंने सत्तारूढ़ द्रमुक के खिलाफ आलोचनाओं की बौछार करके और अपनी निरंतर मीडिया उपस्थिति से तमिलनाडु में पार्टी को जीवंत बनाए रखा, चुनावी जंग में उतरना नहीं चाहते थे। उन्होंने यह बात पार्टी नेतृत्व को साफ-साफ बता दी थी, फिर भी उनको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। अन्नामलाई ने अपने समर्थकों से कहा था कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों से ज्यादा उनकी दिलचस्पी 2026 के विधानसभा चुनाव में है, जिसमें उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया जा सकता है। मगर आलाकमान के फैसले से उनको और उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी है। इन सबसे अन्नाद्रमुक नेता ईपीएस, यानी ई पलानीसामी काफी खुश होंगे, क्योंकि इस मौके को वह अपने हक में भुनाने का ख्वाब देख सकते हैं।

ईपीएस इसलिए अन्नामलाई से नाराज थे, क्योंकि वह उन पर निजी हमले कर रहे थे। उनको महाराष्ट्र जैसी स्थिति की आशंका थी कि भाजपा एक दिन अन्नाद्रमुक का समर्थन करते हुए उसका विलय कर लेगी। ईपीएस की चिंता तब और बढ़ गई, जब अन्नामलाई ने कहा कि भाजपा व अन्नाद्रमुक 2026 का विधानसभा चुनाव साथ-साथ लड़ सकती हैं और मुख्यमंत्री पद का साझा चेहरा वही होंगे। यह अन्नाद्रमुक के लिए अकल्पनीय था, क्योंकि उसके पास 2021 के विधानसभा चुनाव में 33.5 प्रतिशत मत था, जबकि भाजपा के पास सिर्फ 2.62 प्रतिशत। इसीलिए ईपीएस ने भाजपा के साथ अन्नाद्रमुक का गठबंधन तोड़ने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि अन्नामलाई और ईपीएस, दोनों गौंडर जाति से आते हैं, जिसका तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में खासा प्रभाव है। ईपीएस इसी ताकत के बूते अन्नाद्रमुक के सबसे बड़े नेता को तौर पर उभरे हैं।

जाहिर है, ईपीएस और अन्नामलाई, दोनों की असल परीक्षा 2026 के चुनाव में ही होगी। दोनों नेता इसी पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। तो क्या इसका यह मतलब निकालें कि इस आम चुनाव में उनकी कोई रुचि नहीं? द्रमुक के लिए रास्ता खाली हो गया है? फिलहाल इसके बारे में साफ-साफ नहीं कहा जा सकता।

वैसे, भाजपा की रणनीति अपना मत-प्रतिशत बढ़ाने की दिख रही है, जो फिलहाल 2.6 फीसदी है। वह 20 फीसदी से अधिक मत-प्रतिशत हासिल करके यहां की कुछ सीटों को जीतना चाहती है। पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2014 में दिखा था, जब गठबंधन के रूप में एनडीए को 18.8 प्रतिशत मत हासिल हुए थे और पार्टी को अपने दम पर 5.5 प्रतिशत। हालांकि, भाजपा के कट्टर समर्थक भी अभी यही सोचते हैं कि इस बार पार्टी का मत-प्रतिशत बेशक बढ़ेगा, पर सीटें कितनी मिलेंगी, यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे में, अन्नामलाई का यह बयान पार्टी समर्थकों की उलझन बढ़ा रहा है कि उनकी असली दिलचस्पी 2026 में है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दुनिया में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते पश्चिमी देश

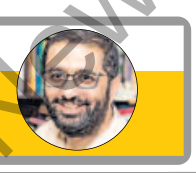

यहां स्कैन करें

नितिन पाई | निदेशक, तक्षशिला संस्थान

वर्ष 416 ईसा पूर्व की गरमियों में एक एथेनियन नौसैनिक बेड़ा मेलोस द्वीप पर आया और मांग की कि वहां लोग गुलामी के लिए पेश हो जाएं। मेलोस द्वीप के लोगों ने तर्क दिया कि वे तटस्थ रहना चाहते हैं, इसलिए बड़ी शक्तियों के लिए यह सही होगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। इस तर्क पर एथेनियन प्रतिक्रिया विश्व इतिहास की प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक है, 'आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं कि न्याय के बारे में कोई भी फैसला सिर्फ उन लोगों के बीच प्रासंगिक है, जिनके पास फैसला लागू करने की ताकत है। ताकतवर जो करते हैं, उसे कमजोर लोग स्वीकार करते हैं।' इसी बात को प्रभावशाली ढंग से लेखक रिचर्ड क्रॉले ने भी *हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वार* में कहा कि ताकतवर लोग वही करते हैं, जो वे कर सकते हैं और कमजोर लोग वही सहते हैं, जो उन्हें सहन करना चाहिए।'

हम इस बात को आज अनेक वैश्विक मामलों में देख रहे हैं कि अमेरिका, चीन और रूस द्वारा किए गए हस्तक्षेप या प्रहारों के चलते नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था चरमरा रही है। पिछले दिनों मुझे नोबेल विजेता एंगस डिएटन का चिंतनपरक लेख पढ़कर एथेनियन कथन की याद हो आई। साल 2015 में नोबेल जीतने वाले एंगस ने पिछले 30 वर्षों में वैश्वीकरण व आप्रवासन के आर्थिक फायदों को नामंजूर कर दिया है। इस निष्कर्ष से अधिक चिंताजनक उनका यह दावा है कि संकटग्रस्त लोगों की मदद करना निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य है, पर हमारे साथी नागरिकों के प्रति हमारा अतिरिक्त दायित्व भी है, जो दूसरों के प्रति नहीं है। दूसरे शब्दों में, प्रख्यात अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि अमीर देशों के लिए दुनिया के गरीबों के हितों की तुलना में अपने नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देना नैतिक है। यदि आप नहीं जानते कि डिएटन एक वामपंथी हैं, तो आप यही मानेंगे कि यह तर्क पश्चिम में किसी दक्षिणपंथी की ओर से आया है।

वैश्विक मानदंडों के प्रति पश्चिमी देशों का उपेक्षा-भाव दुनिया को खतरे में डाल रहा है। पृथ्वी पर हर किसी के लिए इसके गंभीर परिणाम होंगे।

मुक्त व्यापार व नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से पश्चिमी देशों का पीछे हटते जाना दुनिया के लिए अशुभ है। बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद से बहुपक्षवाद और अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए पश्चिमी देशों की प्राथमिकता अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही तय हुई है। फिर भी, शायद एक दशक पहले तक यह धारणा थी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अर्थशास्त्र के जटिल मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संस्थानों के माध्यम से हल किया जा सकता है, पर अब ऐसा नहीं है। विश्व व्यापार संगठन निष्क्रिय है, क्योंकि अमेरिका ने इसका दम घोंट दिया है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका घट गई है, क्योंकि पश्चिम ने इसकी बारीकियों की परवाह करना बंद कर दिया है। रूस व चीन इस स्थिति में अपने योगदान से बच नहीं सकते, हालांकि किसी भी देश ने नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने का दावा नहीं किया है।

मुझे नहीं लगता कि पश्चिमी व्यवहार का यह चलन निकट भविष्य में बदलेगा। कुल मिलाकर, दक्षिणपंथी और वामपंथी, दोनों का नतीजा समान है : व्यापार, आव्रजन पर प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की उपेक्षा। बाकी देश पश्चिमी देशों का व्यवहार देख रहे हैं और उसके अनुरूप आचरण के लिए बाध्य हैं।

सबसे बड़ा सवाल जलवायु परिवर्तन को लेकर है। क्या होगा, अगर पश्चिम जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं से मुकर जाए? ऐसा पहले भी हो चुका है। उदाहरण के लिए, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन 2017 में पेरिस समझौते से पीछे हट गया था। यूरोपीय संघ का दृष्टिकोण नतीजों की परवाह किए बिना अन्य देशों पर बोझ डालना है। दुनिया की सरकारों और उद्योगों को अमेरिका व यूरोप, दोनों से जूझना पड़ रहा है। दुर्भाग्य से, मैं नहीं देखता कि पश्चिमी देशों की राजनीति ऐसे नेताओं को सामने ला सकती है, जो अंतरराष्ट्रीयता को फिर से जीवंत कर सकेंगे।

खैर, मेलोस के लोगों की कहानी पूरी कर दूं। पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ वार्ताओं के बाद एथेनियाई लोगों ने मेलोस पर कब्जा कर लिया। आबादी को दीवारों में बंद कर दिया और खाद्य आपूर्ति रोक दी गई। मेलोस वासियों ने कुछ दिन तक विरोध किया। अगले वर्ष अपने 500 लोगों को वहां भेजने से पहले एथेनियाई लोगों ने हमला बोल दिया, सभी मर्दों को मार डाला और महिलाओं, बच्चों को गुलाम बना लिया।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अब तो बस उसी राह चलना

यह एक शाश्वत प्रश्न है कि मनुष्य प्राण को अलग क्यों नहीं करना चाहता? हर जीव जीवित रहना क्यों चाहता है? दरअसल, शरीर जब तक क्रियाशील है, इसमें जब तक प्राण है, तभी तक मन सुख का भोग कर सकता है। शरीर सुख का भोग नहीं करता, मन करता है। मन तभी तक सुख भोग सकता है, जब तक कि उसमें प्राण है। यदि प्राण नहीं, तो मन कहां होगा, फिर सुख-दुख की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए मनुष्य प्राण से अलग होना नहीं चाहता। इसीलिए प्राण या जीवन हर जीव के लिए सर्वाधिक प्रिय है।

सुख भोगने का वास्तविक अर्थ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, खूब धन इकट्ठा करना, समाज में सम्मान पाना नहीं है। अगर आपके साथ किसी का व्यवहार खराब है और वह आपको आपकी पसंद का स्वादिष्ट व्यंजन खिलाता है, तब भी आप खुश नहीं हो सकते। यह मानव मन की विशेषता है। इसका कारण यह है कि मानव मन देह-केंद्रित नहीं है, यानी सिर्फ इंद्रिय सुख, बाहरी सुख मन का स्थायी सुख नहीं है। मानव मन देहातीत भी है, पर वह शरीर के अंदर हर बिंदु में क्रियाशील है। जब मनुष्य जितना चाहता है, उतना या उससे अधिक पाता है, तो वह चिल्ला-चिल्लाकर अपने सुख को अभिव्यक्त करता है। वहीं, जब वह अपनी निम्न चाह भी नहीं पाता, तो रोने लगता है। रो-रोकर अपनी अनुभूति को व्यक्त करता है।

मनुष्य से इतर दूसरे जीवों के बारे में विचार करें, तो पाएंगे कि कोई पूंछ हिलाकर अपना सुख अभिव्यक्त करता है, तो कोई कान हिलाता है। जब वह आनंदित होता है, तो अलग तरह की आवाजें निकालता है। दुखी होता है, तो उसकी अलग तरह की आवाज होती है। ऐसे में, मनुष्य ने समझ लिया कि एक ही सत्ता है, जिसकी प्रेरणा से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। उस सत्ता से पेड़-पौधे परिचित नहीं हैं। उससे परिचित होने के लिए उनमें मानसिक शक्ति का अभाव है। लेकिन परमपिता की कृपा से मनुष्य में वह शक्ति मिली हुई है। इसी शक्ति से मनुष्य के जीवन में, मानव जगत में धर्म का शुभागमन हुआ। यह मनुष्य की खोज की प्रथम जिज्ञासा थी। यह धर्म साधना का रहस्य है।

प्राचीन काल में ही हमारे संत-महात्माओं, ऋषियों ने मेहनत करके इस उत्तर को खोज लिया है कि ईश्वर के सिवाय कोई चीज मनुष्य को स्थायी सुख नहीं दे सकती।

मनुष्य ने यह समझ लिया है कि इस ब्रह्मांड में जिनके कारण आनंद की अनुभूति हो रही है, वही हमारे लक्ष्य हैं। उनके सिवाय हमारे सामने और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता। उनके सिवाय और किसी से मनुष्य की मुहब्बत नहीं हो सकती। उनके सिवाय कोई चीज मनुष्य को स्थायी सुख नहीं दे सकती। प्राचीन काल में ही हमारे संत-महात्माओं, ऋषियों ने मेहनत करके इस उत्तर को खोज लिया है। आज के मनुष्य को तो सिर्फ उन राहों पर चलना है, सिर्फ आगे बढ़ना है।

श्री श्री आनन्दमूर्ति

शेखर कपूर | फिल्म निर्देशक

फिल्म निर्माताओं की अगली पीढ़ी को सिनेमा बनाने की वर्तमान तकनीक को सीखने की जरूरत नहीं होगी.. उन्हें एआई सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के बेहतर तरीके को समझने की आवश्यकता होगी।

विपक्ष की एकजुटता का परिणाम

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ के चार साल बाद हुए चुनाव में वाम-बापसा उम्मीदवारों की जीत बहुत कुछ कहती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्राणांतक जुनून से लड़ा था। इसे जीतने के लिए उसने अपनी सारी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शक्तियों को संगठित किया था। हालत यह थी कि सोशल मीडिया पर जेएनयूएसयू खोजने पर परिषद की जीत की इबारतें भरभराकर सामने आ जातीं। ये सारी इबारतें शब्दशः एक होतीं। ये दुनिया भर के हैंडलों से पोस्ट की जाती थीं।

पिछले एक दशक से जेएनयू को भगवा करने का अभियान सौर मिशन की तरह चलाया जा रहा है। कहने वाले कहते हैं कि नियुक्तियों से लेकर दाखिले तक राष्ट्रहित की सरकारी परिभाषा को कठोरता से लागू किया गया है। बेतहाशा फीस बढ़ाकर गरीब-गुरबे का आना मुश्किल कर दिया गया है। डेप्रिवेशन पॉइंट्स, यानी वंचना बिंदु के उस प्रावधान को पहले ही खत्म किया जा चुका है, जिसके कारण वंचित श्रेणियों की भारी आबादी जेएनयू चली आती थी। जेएनयू के वामपंथी जनवादी सेकुलर मिजाज को बनाने वाला जनाधार यही था। अब यह सब बदल चुका है। जेएनयू को विकसित भारत की दौड़ में खींच लेने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। मगर यह सब कुछ होते हुए भी इस चुनाव में वाम और बापसा की संयुक्त ताकत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यह तब हुआ, जब जनरल सेक्रेटरी के पद पर वाम के उम्मीदवार को आखिरी लम्हों में अयोग्य करार दे दिया गया और वाम व बापसा को इस पद पर एकजुट होना पड़ा।

इसका मतलब यह है कि वामपंथ की यह जीत कुछ अलग है। इसमें उन आम छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो किसी विचारधारा से सक्रिय रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। जेएनयू की अस्मिता पर लगातार हो रहे प्रायोजित हमलों ने भी एक हद तक जेएनयू छात्र समुदाय को एकजुट किया होगा, लेकिन इस जीत पर सरकारी नीतियों से उपजी निराशा और विक्षोभ की भी बड़ी छाया है। तेजी से बढ़ती दृश्य-अदृश्य बेरोजगारी, विषमता की गहरी होती खाई और लोकतांत्रिक आजादी के खात्मे जैसे कारकों ने नौजवानों की हताशा को बढ़ाया है। विपक्ष के लिए इस जीत का एक ही संदेश है- एकजुट हो जाओ। कुछ महीने और साल जेल में बिताने से डरो मत। दस-बीस सीटों के इधर-उधर होने की फिक्र मत करो। दांव पर इस समय देश का भविष्य है, नौजवानों की उम्मीद है, इंसाफ की लड़ाई है। एकजुट हो जाओ, अन्यथा भावी पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी।

आशुतोष कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

जेएनयू चुनाव

जेएनयू में भी जल्द ढहेगा वाम दुर्ग

अपने देश में छात्र राजनीति का इतिहास करीब पौने दो सौ साल पुराना है। कहा जाता है कि 1848 में दादा भाई नौरोजी ने 'द स्टूडेंट साइंटिफिक ऐंड हिस्टोरिक सोसाइटी' की स्थापना करके छात्र राजनीति की नींव रखी थी, जिसमें आजादी से पहले और बाद में, समय के साथ काफी बदलाव आया है। आजादी से पहले छात्र राजनीति के केंद्र में देश की आजादी थी, तो आजादी के बाद देश बदलने की जिजीविषा। यही कारण है कि छात्र राजनीति को भविष्य की राजनीति की पौधशाला भी कहा जाता है। इसमें जेएनयू का स्थान अलग है, क्योंकि यहां की छात्र-शक्ति ने जब किसी बड़े आंदोलन को जन्म दिया या किसी घटना विशेष पर तीखा प्रहार किया, तो देश व समाज में सकारात्मक बदलाव होते देखे गए। इसी कारण, यहां की छात्र राजनीति से उभरने वाले छात्र बाद में देश के बड़े नेताओं में भी शुमार हुए।

कहने वाले कह सकते हैं कि यह दुर्ग वामपंथियों के कब्जे में रहा है और यही इसकी खूबसूरती है, लेकिन ऐसा कहने वाले भूल जाते हैं कि भारत विविधताओं का देश है और अलग-अलग विचार मिलकर ही इस देश की मजबूत बुनियाद रचते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए भले जेएनयू में जीत दूर हो, लेकिन जिस तरह से यह संगठन लगातार यहां मजबूत हो रहा है, उससे यही लगता है कि एक दिन वामपंथियों का यह दुर्ग भी ढह जाएगा। इसकी वजह यही है कि एबीवीपी लगातार छात्र हितों के मुद्दों पर सक्रिय रहती है। जिन मुद्दों को वाम दल सांप्रदायिक मानकर किनारे कर देते हैं, एबीवीपी उनको भी प्रमुखता से उठाती है और यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय न हो।

कुछ लोग जेएनयू में वाम की जीत को आम चुनाव की पूर्वपीठिका मान रहे हैं। बेशक, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में देश-दुनिया के तमाम विषयों पर बहस होती है, लेकिन इसमें जीतता वही है, जो स्थानीय, विशेषकर विश्वविद्यालय के मसलों को जोर-शोर से उठाता है। जबकि, आम चुनाव का दायरा काफी बड़ा होता है, जिसमें पूरे देश के मुद्दे प्रभावी रहते हैं। वैसे भी, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भाजपा के पास है, चुनाव में उसे हराना काफी कठिन है। इस जोड़ी की यह उपलब्धि है कि एनडीए सरकार के दस साल होने के बाद भी सत्ता-विरोधी रुझान कहीं नहीं दिख रहा। इसलिए, जेएनयू चुनाव को लोकसभा चुनाव से मत जोड़िए। जेएनयू में भले एबीवीपी को जीत नहीं मिली है, लेकिन आम चुनाव में इसकी मातृ संस्था भाजपा को बड़ी जीत मिलने जा रही है।

कृष्णकुमार, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । बुधवार, 27 मार्च 2024

युद्धविराम की ज़रूरत

आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में तत्काल युद्धविराम की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया। सोमवार को पारित इस प्रस्ताव में सभी बंधकों की अविलंब बिना शर्त रिहाई और गाजा में अधिक मानवीय सहायता पहुंचाने की भी बात कही गई है।

विश्व जनमत का दबाव | छह महीने से जारी इस जंग के दौरान यह पहला मौका है, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम का प्रस्ताव पारित किया है। यह इसलिए संभव हुआ कि अमेरिका ने इसे वीटो करने से परहेज किया। निश्चित रूप से सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव विश्व जनमत से उपजे दबाव की अभिव्यक्ति है।

सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव

हताहतों में आम लोग | पिछले सात अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए आतंकी हमले के खिलाफ जब इस्राइल ने कार्रवाई की बात कही तो अमेरिका और भारत समेत तमाम देशों की सहानुभूति उसके साथ थी। लेकिन इस्राइल ने जिस तरह से गाजा में हवाई हमले शुरू किए और वहां से आम लोगों के हताहत होने की खबरें आने लगीं, उसके बाद यह आवाज तेज होती गई कि इस्राइल को अपने अभियान का स्वरूप बदलना चाहिए। अब तक गाजा में करीब 32 हजार लोगों के मारे जाने की खबरें हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं।

अमेरिकी रुख में बदलाव | अफसोस की बात थी कि अलग-अलग देशों में हो रहे प्रदर्शनों में व्यक्त होती जनभावना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के रूप में बाहर नहीं आ पा रही थी। खुद अमेरिका इससे पहले गाजा युद्ध विराम से जुड़े तीन प्रस्ताव को वीटो कर चुका था। सोमवार को मतदान से अलग रहते हुए भी उसने इस प्रस्ताव को पारित होने दिया, जो उसके अब तक के रुख में अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

इस्राइल को संकेत | अमेरिकी रुख में आए इस कथित बदलाव पर इस्राइल ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। इस्राइली पीएम नेतन्याहू ने इसी सप्ताह बातचीत के लिए अमेरिका जाने वाले एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम को रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि अमेरिका ने अपने रुख में बदलाव से इनकार किया है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि अमेरिका का ताजा कदम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इस्राइल उसके समर्थन को तय मानकर न चले।

लचीले रुख की जरूरत | बेशक अमेरिका के रुख में यह बदलाव और सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव सकारात्मक संकेत हैं। लेकिन फिर भी इनके संभावित परिणामों को लेकर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। हालांकि अभी बात इस्राइल और फलस्तीन के बेहद लंबे और जटिल विवाद की नहीं, बस गाजा में चल रहे युद्ध को बंद करने और बंधकों को रिहा करने की संभावनाओं तक सीमित है। लेकिन यह सीमित लक्ष्य भी तमाम अनिश्चितताओं से घिरा है। ऐसे में फिलहाल सिर्फ यह उम्मीद और अपील की जा सकती है कि सभी संबंधित पक्ष इस मामले में पॉजिटिव और लचीला रुख अपनाएं।

ऑफबीट

वह वाली बात नहीं रही

सौरभ श्रीवास्तव

होली बीत गई। एक वाक्य जो पिछले पूरे हफ्ते सुनाई देता रहा- अब होली में वह बात नहीं रही। आखिर क्या थी 'वह बात', जो अब नहीं रही? कॉलोनी के बुजुर्गवार को पकड़ ही लिया। पूछा- क्या थी वह बात जो पहले के त्योहारों में हुआ करती थी, अब नहीं होती। बोले-होली को ही लीजिए, न पापड़ बनते हैं, न चिप्स घिसे जाते हैं। पिछले दो साल से तो गुझिया भी बाजार से आ रही है। हम बूढ़ा-बुढ़िया से तो होता नहीं। बेटा और बहू मोबाइल या लैपटॉप में ही सिर दिए रहते हैं।

किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन बुजुर्गवार के परिवार के बारे में जानते हैं, जिससे हालात का सही आंकलन किया जा सके। घर में दो बुजुर्ग माता-पिता, बेटा-बहू और एक नौकर है। बेटा-बहू मल्टिनैशनल कंपनी में काम करते हैं। होली वाले दिन बेटे की तो छुट्टी थी पर बहू की नहीं, क्योंकि उसकी कंपनी US बेस्ड है, तो वह घर से ही काम कर रही थी। यह वही बहू है जिसके पैकेज के बारे में बताते हुए बुजुर्गवार की सीना फक्र से कभी चौड़ा हुआ जाता था। यहां हमारा उद्देश्य पितृसत्तात्मक समाज की तुरपाई खोलना नहीं है। हम तो सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि त्योहारों में 'वह वाली बात' न रहने के पीछे वजह क्या है? देखिए, यदि कोई व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम के तहत ही सही अमेरिकी या किसी यूरोपीय देश की कंपनी में काम करता है तो वह भारतीय संस्कृति से कदमताल करने में पिछड़ जाएगा। वह कमा भी तो डॉलर या यूरो में रहा है। 'जहां की करंसी वहां का कल्चर' यह हमारे वक्त का ब्रह्म वाक्य है। अब डॉलर में आय का सुख लेना है तो घर की बनी गुझिया या चिप्स का लुत्फ छोड़ना ही होगा। हर इंसान को यह हक है कि वह ऐसा काम करे जिससे उसे अपनी स्किल्स की भरपूर कीमत मिले। लेकिन घर नहीं संभालेंगे तो जीवन चलेगा। इस बात को ऐसे समझिए- स्विट्जरलैंड में खेती बहुत कम होती है तो क्या वहां लोग भूखे मरते हैं। नहीं, पेसमेकर, कीमती घड़ियों, पर्यटन और स्विस बैंक के जरिए तो खूब सारी आमदनी होती है। उससे स्विट्जरलैंड अनाज, फल आदि दूसरे गरीब देशों से खरीद लेता है। लेकिन अपनी मेधा उन कामों में खर्च करता है, जिससे ज्यादा आमदनी होती हो। हां, वहां के लोगों को बगीचे से तोड़े गए फल खाने का लुत्फ तो नहीं ही मिलता। यह ठीक वैसा ही है जैसे घर में बने पापड़ और गुझिया खाने का सुख। हां, बुजुर्गों के लिए त्योहार का यह स्वरूप देखना कल्चर शॉक जरूर है पर इस बदलाव में पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। एक बात और बदलाव का हिस्सा बन रहे युवाओं को इस पर इतराते हुए बुजुर्गों या अन्य लोगों को शर्मसार करने की जरूरत नहीं है। बल्कि उन्हें बदलती दुनिया से रू-ब-रू करवाने के जरूरत है क्योंकि कल आप भी इसी डिजीज ऑफ चेंज की शिकार होने वाले हैं।

एकदा

राजपुरुष का इनाम

राजा भोज समय-समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवाते थे और विजेताओं को सम्मान और इनाम दिया करते थे। एक बार राजा भोज ने राजपुरुष चयन की प्रतियोगिता रखी। इसके लिए एक वाटिका बनवाई गई जिसमें हर तरह की वस्तुएं रखी गईं, लेकिन उन पर उनका मूल्य नहीं लिखा गया। फिर राजा भोज ने एलान करवाया कि जो व्यक्ति इनमें से सबसे कीमती वस्तु लेकर बाहर आएगा, उसे उस साल का राजपुरुष घोषित किया जाएगा। कोई हीरे-जवाहरात लाया, तो किसी ने पुस्तक उठाना ठीक समझा क्योंकि उसके लिए ज्ञान अधिक मूल्यवान था। ऐसे ही कोई गरीब रोटी उठाकर लाया क्योंकि उसकी नजर में रोटी ही मूल्यवान थी। ऐसे कई भक्त भी थे जो ईश्वर की मूर्ति उठाकर लाए। उनके लिए अपने भगवान की प्रतिमा से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था। तभी वहां एक योगी आया। वह वाटिका में काफी देर घूमता रहा और उसके बाद खाली हाथ ही निकल गया। अब राजा भोज सभी व्यक्तियों की लाई वस्तुएं देखने लगे। जब उस योगी की बारी आई तो राजा भोज ने उसके हाथों में कुछ न पाकर उनसे पूछा कि, 'तुम उस वाटिका से क्या लाए हो?' योगी ने राजा भोज से कहा, 'मैं वहां से सिर्फ संतोष लाया हूं, महाराज।' राजा भोज ने आश्चर्य चकित होकर पूछा कि, 'तुम्हारा संतोष क्या सबसे मूल्यवान है?' योगी ने राजा भोज को समझाते हुए कहा, 'हां महाराज, इस वाटिका में आपने जितनी भी वस्तुएं रखी हैं उन्हें प्राप्त कर मनुष्य को खुशी तो अवश्य होगी पर वह क्षणिक होगी। इसे हासिल कर लेने के बाद मनुष्य का मन फिर कुछ और पाने के लिए लालायित हो उठेगा। लेकिन जिसके पास सच्चा संतोष है, वह इन सभी इच्छाओं से ऊपर होगा और सुखी रहेगा।' यह सुनकर राजा भोज को भी खुशी हुई। उन्होंने उस योगी को उस साल का राजपुरुष घोषित कर दिया।

Subrata Dhar

संकलन : **आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'**

प्रत्याशियों और पार्टियों की ओर से जो खर्च होगा, उससे बड़े पैमाने पर अस्थायी रोजगार पैदा होंगे

चुनावी खर्च से क्या इकॉनमी को मिलेगी रफ्तार

मधुरेन्द्र सिन्हा

चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन यह बेहद खर्चीला होने के साथ बड़े पैमाने पर अस्थायी रोजगार भी पैदा करता है। नगर निगम जैसे छोटे चुनाव में भी करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव की करें तो खर्च अरबों रुपये में पहुंच जाता है। बावजूद इसके कि चुनाव आयोग ने इस खर्च पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी हैं।

खर्च की सीमा | पिछले हर चुनाव में आयोग ने बढ़ती महंगाई के हिसाब से उम्मीदवारों के खर्च करने की सीमा बढ़ाई है। लोकसभा चुनाव के लिए अब यह 95 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार तक जा पहुंची है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए खड़े उम्मीदवार कितना खर्च करेंगे, यह उनकी पार्टियों और इलाके पर निर्भर करेगा।

भारी खर्च | स्वतंत्र संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 75-80 चुनाव क्षेत्र ऐसे रहे, जहां 2019 लोकसभा चुनाव में हर संसदीय क्षेत्र में खर्च औसतन 40 करोड़ रुपये हुआ, जबकि इसकी सीमा महज 70 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार थी।

कई गुना बढ़ा खर्च | संस्था का कहना है कि 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, जो अनुमान से कहीं ज्यादा है। वहीं, 2014 लोकसभा चुनाव में 30,000 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि 1999 में कुल खर्च 10,000 करोड़ रुपये था, जिसे उस समय बहुत अधिक माना गया था।

1.2 खरब का चुनाव | सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 1.2 खरब रुपये यानी लगभग 14 बिलियन डॉलर खर्च होंगे। यह राशि पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुल सालाना बजट के एक तिहाई से भी ज्यादा है। अगर यह दावा सही साबित होता है यानी आने वाले लोकसभा चुनावों में सचमुच इतना खर्च होता है तो यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव होगा। जाहिर है, इसमें सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपना योगदान करेंगे, कोई कम तो कोई ज्यादा।

चुनावी खर्च का हिसाब-किताब

- आगामी चुनाव में 1.2 खरब खर्च होगा
- 2019 में 60,000 करोड़ रु. खर्च हुए
- 2014 में 30,000 करोड़ रु. खर्च हुए

कहां जाएगा पैसा | जाहिर है, सत्तारुढ़ दल सबसे ज्यादा खर्च करेगा। कई निर्वाचन क्षेत्रों में रेकॉर्ड खर्च होगा। सरकारी एजेंसियों की रोक-टोक के बावजूद खर्च में कमी नहीं आएगी क्योंकि सवाल अस्तित्व का है। मुद्दा यहां यह है कि क्या यह सारा पैसा, यह सारा खर्च यूं ही जाएगा या बैंकों में जमा होगा? क्या यह कार्यकर्ताओं की जेबों में जाएगा या उम्मीदवारों की? सचाई यह है कि यह पैसा सिस्टम में जाएगा। उम्मीदवार तरह-तरह के खर्चों के लिए पैसे लगाते हैं। कार्यकर्ताओं पर तो खर्च होगा ही, चुनाव प्रचार की व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों को भी बड़ी राशि मिलेगी।

कार्यकर्ताओं को रोजगार | लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार को हजारों कार्यकर्ताओं की सेवा लेनी होती है। हर बूथ पर कार्यकर्ता रखने से लेकर प्रचार करने तक। वह जमाना गया जब पार्टी या उम्मीदवार के नाम पर कार्यकर्ता खुद-ब-खुद आ जाते थे और योगदान देते थे। अब ऐसा नहीं होता। कार्यकर्ता की हैसियत और उसकी ताकत के हिसाब से उसे पैसे मिलते हैं, जो वह उस पूरी चुनाव अवधि यानी दो या तीन महीने तक पाता रहता है। यह भी एक तरह का रोजगार है।

Uday Deb

कई क्षेत्रों की बढ़ेगी आय | ऐसे ही ट्रांसपोर्टरों, रसोइयों, खाने-पीने का सामान बेचने वालों, होटेलों-रेस्तरां, प्रिंटिंग प्रेस वालों, संचार साधनों की व्यवस्था करने वालों को भी लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों से पैसे मिलते हैं। झंडे-पर्चे की अगर पार्टी ने व्यवस्था कर दी तो ठीक अन्यथा उम्मीदवार खुद ही उन पर खर्च करता है। यह सारा खर्च लगातार बाजार में पहुंचता रहता है।

सरकारी खर्च का असर | चुनाव सुचारू रूप से करवाने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर खर्च करती है। इसके लिए लाखों कर्मियों को तैनात किया जाता है और उन्हें भत्ते वगैरह दिए जाते हैं। यह उनके वेतन के अलावा होता है। अन्य तरह की व्यवस्थाओं के लिए भी सरकारें पैसे खर्च करती हैं, जैसे इनके खाने-पीने की व्यवस्था वगैरह। हजारों ट्रक और अन्य वाहन भी किराये पर लिए जाते हैं और उनका भुगतान भी होता है। यह सारा धन सिस्टम में आ जाता है, जिससे इकॉनमी की ग्रोथ तेज होती है।

खपत आधारित इकॉनमी | यहां ध्यान रखने वाली बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था खपत आधारित है न कि निर्यातोन्मुख। असल में भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत का योगदान 60% के करीब है। इसलिए यहां ग्राहकों का व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। अगर वे जमकर खरीदारी करते हैं तो उससे उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ता है।

काला धन | चुनाव जैसे मामले में जहां पैसा संबद्ध लोगों को मिलता है, वहां खर्च भी तेजी से होता है। इस धन का बड़ा हिस्सा वाइट मनी नहीं होता है और चंदे वगैरह के रूप में आता है। जो बैंकों में जमा नहीं होता बल्कि सीधे खर्च कर दिया जाता है। खर्च करने की यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में तेजी लाती है।

अस्थायी रोजगार | चुनाव में लाखों लोगों को अस्थायी रोजगार मिलता है। उन्हें जो मेहनताना मिलता है, वह पैसा भी वे अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नकदी का प्रवाह कम होता है, वहां चुनाव के समय काफी हलचल रहती है क्योंकि उम्मीदवारों या पार्टियों का पैसा उन तक पहुंचता है। इस पैसे से वे अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और इससे खपत में बढ़ोतरी होती है।

क्या होगा असर | यह सरकारी योजना मनरेगा की ही तरह है, जहां कामगारों को सही पारिश्रमिक मिलता है और उनके खर्च पूरे करने में काम आता है। खैर, यह खपत बड़े पैमाने पर होती है। इससे काफी पैसा इधर से उधर होता है, जो आखिरकार दुकानों-बाजारों में जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में थोड़े समय के लिए ही सही तेजी आती है। कई बार यह रुझान बना रह जाता है क्योंकि पैसे का एक साइकल (चक्र) बन जाता है, जो अर्थव्यवस्था को सहारा देता रहता है। इस बार चुनाव में रेकॉर्डतोड़ राशि खर्च होने का अनुमान है और इसलिए इसके पॉजिटिव असर भी देखने को मिलेंगे।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

E-Waste की सुनामी

क्या पृथ्वी पर इंसानों से ज्यादा उसका पैदा किया गया कचरा इकट्ठा हो गया है? सांप के जहर से भी जहरीला कचरा? पिछले हफ्ते ई-वेस्ट पर आई UN की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में ई-कचरा इतना ज्यादा हो चुका है कि उसे ढोने में ही डेढ़ करोड़ ट्रक लग जाएंगे। जानते हैं दिनोंदिन बढ़ती इस मुसीबत के बारे में...

धरती का बोझ

पिछले हफ्ते आई UN की रिपोर्ट 2022 में दुनिया का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है

चीन, अमेरिका व भारत दुनिया में टॉप पर।

6.2 करोड़ टन सालाना ई-कचरा।

सालाना औसत बढ़ोतरी 2.6 मिलियन टन की।

2010 के बाद से हुई 82% की वृद्धि।

रीसाइक्लिंग की तुलना में वृद्धि 5 गुना तेज।

भारत का भार

भारत तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक।

413.7 करोड़ किग्रा. कचरा 2022 में।

औपचारिक क्षेत्र केवल 4 लाख टन कचरा संभाल सकता है।

5% कचरा केवल होता है रीसाइकल।

95% कचरा डीलरों के पास जाता है।

20.6 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स घरों में बेकार पड़े।

40% ने माना कि उनके पास कम से कम 4 उपकरण बेकार।

धन की बात

91 बिलियन डॉलर 2022 ई-कचरे में शामिल धातुओं का मूल्य।

19 बिलियन डॉलर का तांबा

15 बिलियन डॉलर का सोना

16 बिलियन डॉलर का लोहा

28 बिलियन डॉलर 2022 में कचरा रीसाइकल से मिला कच्चा माल।

कचरे में क्या है

33% खिलौने, माइक्रोवेव अवन, वैक्यूम क्लीनर, ई-सिगरेट। 12% होता है रीसाइकल।

46 लाख टन लैपटॉप, मोबाइल फोन, जीपीएस उपकरण, राउटर। 22% रीसाइकल।

6,00,000 टन फोटोवोल्टिक पैनल मिलते हैं ई-वेस्ट में

हाल रीसाइक्लिंग का

17.4% ही होता है रीसाइकल दुनिया में।

56.5% दक्षिण कोरिया में सबसे ज्यादा रीसाइकल

32.5% स्वीडन भी है रीसाइक्लिंग में अव्वल

51.1% स्पेन में सबसे ज्यादा लैंडफिल

29.9% स्विट्जरलैंड का भी ठीक है हाल

भविष्य का हाल

2022 से 33% अधिक होगा ई-वेस्ट।

24 लाख टन 2030 में बेकार फोटोवोल्टिक पैनल।

2030 तक 20% तक गिर सकती है रीसाइक्लिंग।

2030 तक 60% ई-कचरा रीसाइकल किया तो होगा $38 बिलियन का लाभ।

2030 तक यह 8.2 करोड़ टन होगा कचरा

कायदा कानून

2023 में 81 देशों के पास ई-कचरा कानून।

2019 में 78 देशों के पास था इसका कानून।

46 देशों के पास इकट्ठा करने के घोषित टारगेट।

36 देशों के पास रीसाइक्लिंग टारगेट।

जहर का असर: प्रदूषण से किडनी, लीवर, हृदय रोग में बढ़ोतरी। इनसे निकलते हैं आर्सेनिक, बेरियम, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, कैडमियम, जस्ता जैसे जहरीले पदार्थ।

(स्रोत : UN, एक्सेंचर, ICEA)

कंटेंट : राहुल पाण्डेय
ग्राफिक्स : अर्जुन सिंह

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

हमारे आज के काम का असर कल पर ज़रूर पड़ता है

स्वामी विवेकानंद

मान लो कि इस कमरे में एक गेंद है और हम सबके हाथ में एक-एक बल्ला है। सैकड़ों बार हम उसे मारते हुए इधर से उधर करते रहते हैं जब तक कि वह कमरे से बाहर नहीं चला जाता है। किस वेग से और किस दिशा में वह बाहर जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जब वह कमरे में था तब उस पर कितनी शक्तियां कार्य कर रही थीं। उन शक्तियों से जब ज्यादा शक्तियां उस पर कार्य करेंगी, तभी वह गेंद बाहर जाएगा। हमारी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं ऐसे ही आघात हैं। मानव-मन वह गेंद है जिसे आघात दिया जाता है।

यह संसार मानो एक कमरा है जिसमें मनरूपी गेंद के ऊपर हमारे नाना कार्य-कलापों का प्रभाव पड़ता है और इसके बाहर जाने की दिशा और गति इन सारी शक्तियों के ऊपर निर्भर है। इस तरह संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उन्हीं के आधार पर हमारा भावी जीवन तय होगा। इसलिए हमारा वर्तमान जीवन हमारे विगत जीवन का परिणाम है। और इसी तरह हमारा भविष्य हमारे वर्तमान जीवन का परिणाम होगा। एक उदाहरण लो। मान लो मैं तुम्हें एक शृंखला देता हूं, जिसका आदि-अंत नहीं है। उस शृंखला में हर सफेद कड़ी के बाद एक काली कड़ी है और उसका भी कोई आदि-अंत नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि वह शृंखला किस प्रकृति की है? पहले तो उसकी प्रकृति बताने में तुम्हें कठिनाई होगी क्योंकि वह शृंखला तो अनंत है। पर शीघ्र ही तुम्हें पता चलेगा कि यह तो एक ऐसी शृंखला है जिसकी रचना काली और सफेद कड़ियों को एक के बाद एक जोड़ने से हुई है। इतना भर जान लेने से ही तुम्हें संपूर्ण शृंखला की प्रकृति का ज्ञान हो जाता है।

बार-बार जन्म लेकर हम एक ऐसी ही अनंत शृंखला की रचना करते हैं जिसमें हर जीवन की एक कड़ी है और इस कड़ी का आदि है जन्म और अंत है मरण। अभी जो हम हैं और जो हम करते हैं, थोड़े परिवर्तन के साथ उसी की आवृत्ति बार-बार होती है। इस तरह अगर हम जन्म और मरण इन दो कड़ियों को समझ लें तो हम उस संपूर्ण मार्ग को समझ सकते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव भी हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रहा है। हम आते और जाते हैं। जैसे कीड़ा अपने ही भीतर के पदार्थों से बने तंतुओं को मुंह से निकाल-निकालकर अपने चारों तरफ कोया बना लेता है और उसमें अपने को बांध लेता है, वैसे ही हम भी अपने ही कर्मों के जाल में स्वयं अपने आपको बांधते रहते हैं।

कार्य-कारण-नियम के इस जाल में हम एक बार उलझ क्या जाते हैं कि इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। एक बार हमने यह चक्र चला दिया और अब इसी में पिस रहे हैं। इस तरह यह दर्शन बतलाता है कि मनुष्य अपने ही अच्छे-बुरे कर्मों से बंधता चला जाता है। आत्मा न कभी आती है, न जाती है। यह न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती है कि प्रकृति नहीं बल्कि वही गतिशील है। जब तक आत्मा ऐसा सोचती रहती है तब तक वह बंधन में रहती है, पर जब उसे यह पता चल जाता है कि वह सर्वव्यापक है तो वह मुक्ति का अनुभव करती है। जब तक आत्मा बंधन में रहती है तब तक उसे जीव कहते हैं। जीव यानी आत्मा ऊंचे या नीचे स्तर पर आती-जाती रहती है। यही सुप्रसिद्ध पुनर्जन्मवाद का नियम है। यही सृष्टि का नियम है।

प्रस्तुति : दिलीप लाल

गौरी हथिनी का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है...

आमेर के किले में अभी 88 हाथी पर्यटकों को ढोने का काम करते हैं। इन्हें तकलीफ देकर और डराकर नियंत्रित किया जाता है। जंजीरों में बांध कर रखा जाता है

प्रीतंभरा प्रकाश

22 साल की गौरी ने हाल ही में एक रूसी पर्यटक मारिया पर हमला कर दिया। इस घटना के वायरल विडियो में दिख रहा है कि गौरी अपनी सूंड से मारिया को पकड़ती है, उठाती है और दो बार घुमाकर जोर से पटक देती है। यह विडियो जयपुर के ऐतिहासिक आमेर के किले के परिसर का है।

गौरी के प्रति चिंता | मारिया के हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया है। इसके बाद भी उन्होंने गौरी के प्रति गहरी चिंता जताई है। उन्होंने राजस्थान की डेप्युटी सीएम दीया कुमारी को पत्र लिखकर इस हथिनी को बचाने की गुहार लगाई है।

मारिया की गुजारिश | मारिया ने लिखा है, 'मैं गौरी को और ज्यादा सजा नहीं दिलाना चाहती। उसके स्वास्थ्य के लिए और दूसरे लोगों को संभावित घातक हमले से बचाने के लिए मैं आग्रह करती हूं कि उसे टूरिस्टों को अपनी पीठ पर लादकर घुमाने के लिए मजबूर करना बंद करें। उसे सैंक्चुरी में भेजें, जहां वह जीवनभर की पिटाई, यातना और मानसिक आघात से उबर सके।'

दुकानदार का मामला | बताया जा रहा है कि गौरी वही 86 नंबर की हथिनी है, जिसने दो साल पहले एक स्थानीय दुकानदार को बुरी तरह घायल कर दिया था। उस समय भी उसे सैंक्चुरी में भेजने की मांग उठी थी, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

हाथी की जगह कार | PETA (पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) इंडिया ने राजस्थान सरकार से गौरी को किसी सैंक्चुरी में भेजने और पर्यटक सवारी के लिए हाथियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। PETA इंडिया के एडवोकेसी प्रॉजेक्ट की डायरेक्टर खुशबू गुप्ता का कहना है कि अक्टूबर 2022 में गौरी ने जिस पर हमला किया था, वह आज तक अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। उस हमले के बाद करीब 45 दिन तक गौरी को कोठरी में बंद रखा गया। फिर सेहत को सही बताकर उसे 'फिट फॉर राइडिंग' का सर्टिफिकेट दे दिया गया। गौरी की शारीरिक हालत देखकर उसकी मानसिक सेहत का पता कैसे लगाया जा सकता है?

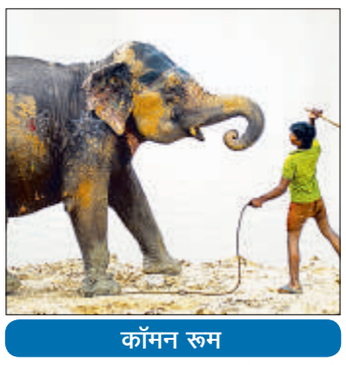

कॉमन रूम

क्रूरता भरा व्यवहार | आमेर में किले तक की चढ़ाई के लिए हाथी की सवारी का सिलसिला दशकों से जारी है। अभी कुल 88 हाथी पर्यटकों को ढोने के काम में लगे हुए हैं। खुशबू गुप्ता बताती हैं कि इन हाथियों को तकलीफ देकर और डराकर नियंत्रित किया जाता है। इस्तेमाल में न होने पर उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है।

मानसिक बीमारी | कैदी की तरह रात काटने के बाद ये सारा दिन राजस्थान की तपती पथरीली धरती पर टूरिस्टों को ढोने का काम करते हैं। सवारी के दौरान उनके महावत मुट्ठी में बड़ी-सी कील छिपाकर रखते हैं, उससे हाथी को खुरचते रहते हैं, ताकि वह कंट्रोल में रहे। ऐसे बुरे बर्ताव से होने वाली निराशा इन संवेदनशील पशुओं में से कुछ को आपे से बाहर कर हमलावर बना देती है। हाथी का झूमना और सर इधर से उधर घुमाना उसकी मानसिक बीमारी के लक्षण होते हैं। यह हाथी का तरीका होता है कहने का कि, 'जो तुम मुझसे करवा रहे हो, वह मुझे नहीं करना।'

मालती पर जुल्म | 44 नंबर की हथिनी मालती भी आमेर के किले में कैद करके रखी गई है। साल 2017 में पर्यटकों को ढो रही 48 साल की मालती की सरेआम 8 लोगों ने मिलकर लाठियों से पिटाई की थी। वह विडियो वायरल हुआ था। मालती की गलती बस इतनी थी कि उसने एक केला देख लिया और उसे लेने दौड़ पड़ी। अब मालती का बिहेवियर एबनॉर्मल हो चुका है। आज तक मालती का केस कोर्ट में चल रहा है। कुल 120 पशु चिकित्सकों ने मालती को मानसिक रूप से पीड़ित घोषित किया है।

बक्से में बंद सलाह | खुशबू बताती हैं कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से एक्सपर्ट आए थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सलाह दी कि हाथी की सवारी बंद कर बैटरी या इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया जाए। इस रिपोर्ट पर अमल के साथ हाथियों को सैंक्चुरी में भेजने की जरूरत है।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सरवॅन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्स:(022) 2760 5275।फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रिपोर्टर: (022) 66353636, 22733636 फैक्स: (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्क: मुंबई, ठाणे व रायगढ़ जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्क: रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेलापुर, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजाग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 27 मार्च • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

कोई भी आपको आपकी मर्जी के बिना नीचा नहीं दिखा सकता।
-एलेनोर रूजवेल्ट

जेएनयू में लाल सलाम

जवाहरलाल यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हुए छात्र संघ चुनाव में वाम ने जेएनयूएसयू में जीत हासिल की। गया (बिहार) के छात्र धनंजय को अध्यक्ष चुना गया जो विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को सभी चार केंद्रीय सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि 28 साल बाद जेएनयू छात्र संघ को दलित अध्यक्ष मिला है। धनंजय ने एबीवीपी के उमेशचंद्र को 922 मतों से हराया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अविजीत घोष उपाध्यक्ष पद पर जीते। इस बार 73% मतदान हुआ, जो बीते बारह वर्षों में सबसे अधिक है। इस जनमत को नफरत और हिंसा की राजनीति को खारिज करने वाला ठहराते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने

महिलाओं की सुरक्षा, कोष में कटौती, छात्रवृत्ति वृद्धि, बुनियादी ढांचा और जल संकट को अपनी प्राथमिकताओं में गिनाया। देश को अनेक प्रसिद्ध शिक्षाविद्, इतिहासकार, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ देने वाला जेएनयू एनआईआरएफ की रैंकिंग में लगातार सर्वश्रेष्ठ तीन विश्वविद्यालयों में शामिल रहता है। शुरुआत से ही यहां सेक्युलर होने का दावा करने के पीछे वामपंथी रुझान होने के आरोप लगते रहे हैं। इस पर वामपंथ द्वारा उकसाई हिंसा का लंबा इतिहास होने का आरोप भी है। कहना गलत नहीं है कि यह कैम्पस अपनी प्रसिद्धि के साथ-साथ विवादों में भी घिरा रहता है। बीते दिनों महिषासुर की पूजा से लेकर भारत तेरे टुकड़े होंगे तथा दीवारों पर लिखे गए जातिसूचक नारों के लिए यह यूनिवर्सिटी खासी विवादित रही। विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर गिरने से बचाने और माहौल को हिंसा से बचाने के प्रयासों के वायदों के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं कही जा सकती। यहां देश भर से आने वाले छात्र स्वर्णिम भविष्य के सपने लेकर आते हैं जिन्हें इन विवादों और लड़ाई-झगड़ों से बिलावजह खासा व्यवधान झेलना पड़ता है। देशविरोधी गतिविधियों में छात्र संघ की भूमिका के कारण जो छवि धूमिल हुई है, वह धनंजय के समक्ष चुनौती होगी। उन्हें जाति विरोधी मसलों को भी गंभीरता से लेना होगा। ऐसे वक्त में जब लोक सभा चुनाव का माहौल चरम पर है, जेएनयू के चुनाव पर सब की नजरें टिकी थीं। दक्षिणपंथी रुझानों के प्रति युवाओं की नीरसता काफी विरोधाभाषी मानी जा सकती है। कैम्पस की चारदिवारी के भीतर और बाहर की विचारधाराओं तथा रुझानों को अलग कर पाना मुश्किल हो सकता है।

गिरफ्तारी के खिलाफ रैली

विपक्षी दलों का गठबंधन 'इंडिया' देश के हितों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बृहस्पतिवार 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय और कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महारैली घोषणा की है। आप 'इंडिया'-इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस-का घटक दल है। महारैली में 'इंडिया' गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व शिरकत करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों को समान अवसर नहीं दिए जा रहे

हैं। लवली ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोष जताते हुए अपनी पार्टी के खातों को 'फ्रीज' (लेन देन पर रोक) का भी जिक्र किया। कहा कि महारैली न सिर्फ राजनीतिक रैली होगी, बल्कि देश में लोकतंत्र को बचाने और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ साझा आवाज उठाने का भी आह्वान करेगी। बहरहाल, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की ऐसी तैयारियों से लगता है कि वह अपने प्रति आम जन के मन में सहानुभूति पैदा करना चाहता है। दरअसल, आप और 'इंडिया' गठबंधन को लगता है कि अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल की ईमानदार होने की जो छवि है, उसे सहानुभूति में बदला जाए। विपक्ष इसलिए भी उत्साहित है कि एक जमाने में इंदिरा गांधी, जयललिता और लालू प्रसाद यादव ने अपनी गिरफ्तारी पर स्वयं को उत्पीड़ित दिखाकर आम जन के मन में सहानुभूति की लहर पैदा कर दी थी। और इसके सहारे राजनीतिक रूप से कमबैक करने में सफल रहे। बेशक, जनता के मन में यह भाव रहा है कि केजरीवाल सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। उपराज्यपाल के साथ उनकी सरकार के टकराव से इस धारणा को बल मिला है। कई मौकों पर उपराज्यपाल के निर्देश और आदेशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा तक खटखटाया गया और इसका स्पष्ट संदेश भी जनता तक इस रूप में पहुंचा कि केंद्र केजरीवाल सरकार के कामकाज में अड़चन डाल रहा है। केजरीवाल भी बड़ी कुशलता से संदेश आम जन तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। समूचा विपक्ष अब इसी प्रकार की 'सिंपेथी' की तलाश में है।

आपबीती/संजय बिश्नोई

मित्रता में विश्वासघात

आज का समय और दौर जिस हिसाब से चल रहा है, किसी पर भी विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है क्योंकि आज के दौर में खतरा आपको बाहरी व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपके ही अपने किसी मित्र से हो सकता है। वो दोस्त आपके साथ क्यों जुड़ा है, और आपसे वह क्या प्राप्त कर सकता है, इस बात को समझ कर ही दोस्ती करनी चाहिए।

इस दोस्ती को क्या नाम दूं समझ नहीं आ रहा है। जहां दोस्ती में भी समझ और विचार-विमर्श को स्थान दिया जाए लेकिन आप इस बात को नजरंदाज करोगे तो निश्चित ही किसी बड़ी समस्या को निमंत्रित करोगे। हो सकता है कि आज आपके लिए तारीफों के पुल बांधने वाला कल आपके ही किसी अपने के सामने आपको नीचा दिखाने में कोशिश करे। इस बात को जेहन में उतार लिया जाए तो अच्छा है कि आपके लिए जो व्यक्ति कभी जिंदगी था, वो समय के साथ-साथ काल रूप में कब परिवर्तित हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कम से कम मेरे क्षणिक अनुभव से इतना सीख लीजिए कि आपकी वजह से आपके किसी अपने पर मुसीबत आ रही है तो स्पष्ट मान लेना चाहिए कि आपकी ही कमी रही है, कहीं न कहीं। अक्सर ऐसी स्थिति में मित्रता का यही धर्म है कि उसके लिए आपको चाहे जो करना पड़े वो करो लेकिन उसे उस समस्या से निजात दिलाओ और यदि इसके लिए आपको वो कदम उठाना पड़े जिसे आप जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकते तो वह कदम भी आपको उठा लेना चाहिए अन्यथा किसी अन्य को धोखेबाज कहने से पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि आपकी वजह से मुसीबत भी एक हिसाब से धोखा ही है।

दुनिया की जद्दोजेहद में मैंने जो भी दोस्त खोए हैं, उसके लिए उनको जिम्मेदार ठहराना मुझे ठीक नहीं लगता। जाहिर सी बात है कि मैं किसी एक कारण से इतना परेशान नहीं हुआ कि कलम उठानी पड़ रही है। कुछ ऐसे भी दर्द हैं जो कहे नहीं जा सकते। बाकी रही बात दोस्ती की तो किसी भी दोस्त को अपनी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए खासकर उस दोस्त को जिसने जीवन काल में बड़ी ठोकर नहीं खाई हो क्योंकि उसे दर्द का भान ही नहीं होगा तो वो आपको समझेगा भी नहीं।

जन सरोकार व संघ का विस्तार

मुद्दा

अवधेश कुमार

नागपुर में संपन्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा के दौरान संपूर्ण भारत और भारत में अभिरुचि रखने वाले विश्व भर के मीडिया का एकत्रीकरण था। सामने लोक सभा चुनाव के कारण ऐसा लग रहा था कि वहां से इसके संबंध में कुछ रणनीति ऐसी बनेगी, ऐसा वक्तव्य आएगा जो समाचार, बहस और विचार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होगा। लंबे अनुभव के बावजूद पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की धारणा बदली नहीं है कि चुनाव या राजनीतिक दल या सरकार को फोकस करके संघ के आयोजन नहीं होते। यह संभव नहीं कि चुनाव हो और इसमें संघ की अभिरुचि नहीं हो या उसमें उनकी कोई भूमिका हो ही नहीं।

यह भूमिका किस रूप में हो सकती है? इस बारे में सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का वक्तव्य ध्यातव्य है-चुनाव देश के लोकतंत्र का महापर्व हैं। संघ के स्वयंसेवक सौ प्रतिशत मतदान के लिए समाज में जन-जागरण करेंगे। समाज में इसके संदर्भ में कोई भी वैमनस्य, अलगाव, बिखराव या एकता के विपरीत कोई बात न हो, इसके प्रति समाज जागृत रहे। राजनीति और चुनाव को सर्वोपरि मान लेने वाले इस माहौल में सहसा विश्वास करना कठिन है कि देश का सबसे बड़ा स्वयंसेवकों का संगठन मतदाता जागरूकता या समाज में सौमनस्य आदि की दृष्टि से ही चुनाव के दौरान काम करेगा।

यह पत्रकारों और मीडिया संस्थानों की जिम्मेवारी है कि देखें कि ऐसा होता है या नहीं? ऐसे सभी संगठनों, जो सीधे दलीय चुनावी राजनीति में शामिल नहीं हैं, की यही यथेष्ट भूमिका हो सकती है। मतदान में किसी दल या उम्मीदवार को अवश्य सहयोग करिए लेकिन संगठन के रूप में चुनावी भूमिका नहीं होनी चाहिए। आप मतदाताओं के बीच जाएं, उन्हें मुद्दों के प्रति जागरूक करें, मतदान के लिए प्रेरित करें तथा इस बीच राजनीतिक दलों के परस्पर आक्रामक तीखे बयानों, आरोपों तथा समाज के अंदर मतदान के लिए वैमनस्य फैलाने वालों या तनाव और हिंसा पैदा करने वालों के असर को कम करने की कोशिश करें। संघ स्वयं को अगर समाज में एक संगठन की जगह समाज का संगठन मानता है तो उसके लिए कोई राजनीतिक दल दुश्मन नहीं हो सकता। हां, राजनीतिक दलों की नीतियां उसके विरुद्ध हैं यानी उसके अनुसार देश हित में नहीं हैं, तो तात्कालिक विरोध किया जा सकता है। प्रतिनिधि सभा ऐसी बैठक होती है जिसमें संघ के सभी शीर्ष पदाधिकारी, प्रांत स्तर के पदाधिकारी और 36 आनुषंगिक संगठनों के प्रमुख या प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। इस नाते 1500 वैसे प्रमुख प्रतिनिधियों की एक जगह उपस्थिति, विमर्श और निर्णय अत्यंत महत्त्व के होंगे। इसमें सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का पुनर्निर्वाचन हुआ और वे

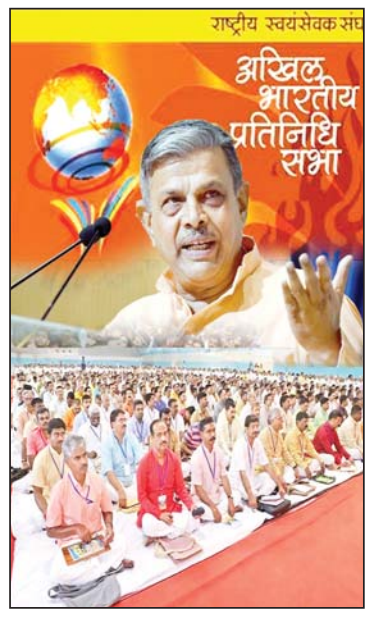

2027 तक पद पर रहेंगे। संघ पर निष्पक्षता से अध्ययन करने वाले इसका खंडन करते हैं कि यहां चुनाव होता ही नहीं। चुनाव नियमित होते हैं किंतु ज्यादातर अन्य संगठनों या राजनीतिक दलों की तरह पदों की होड़ न होने के कारण नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं होती।

प्रतिनिधि सभा से घोषित कार्यक्रमों में अहिल्याबाई होल्कर के जन्म के 300वें वर्ष में मई, 2024 से अप्रैल, 2025 तक जन्म वर्ष मनाया जाना है। कितने राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों को अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के महत्त्व का आभास है? कौन राष्ट्रीय संगठन समाज विशेषकर महिलाओं को प्रेरणा देने की दृष्टि से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेगा? इसके अलावा जो विषय वहां चर्चा में थे उनमें स्वयंसेवकों द्वारा वर्ष में किए गए मुख्य कार्य, श्रीराम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का राष्ट्रीय जागरण की दृष्टि से प्रभाव, संदेशखालि की भयावह घटना और मणिपुर, पंजाब आदि शामिल थे। अगर होसबोले कहते हैं कि स्वतंत्र भारत में संदेशखालि जैसी घटनाएं झकझोर देने वाली हैं, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए तथा इसमें सभी दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़कर महिला सुरक्षा और समाज के इस विषय पर एक मत से ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा करने की कोई सोच भी नहीं सके तो इससे कौन असहमत हो सकता है?

दुर्भाग्य से राजनीतिक, बौद्धिक एवं आंदोलनात्मक एक्टिविस्टों की दुनिया में इतना तीखा विभाजन है कि यह सोचकर कहीं भाजपा को इसका चुनावी लाभ न मिल जाए अनेक दल, संगठन, बुद्धिजीवी और पत्रकार इसे बड़ा मुद्दा बनाने से बचते हैं। ऐसे लोग संघ पर कोई टिप्पणी करेंगे तो समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्वाभाविक है कि 2025 की विजयदशमी को संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसकी चर्चा होगी और उसके अनुसार योजनाएं बनेंगी। हालांकि संघ यही कह रहा है कि उसे जब तक संसार है तब तक काम करते रहना है, उसमें अनेक 100 वर्ष आएंगे तो 100 वर्ष का कोई ऐसा विशेष महत्त्व नहीं है किंतु उसका ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा शाखा और संपर्क विस्तार हो यही लक्ष्य सामने आ रहा है और उसकी पुष्टि प्रतिनिधि सभा में हुई।

संघ द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 की 68,651 शाखाओं के मुकाबले संघ की शाखाओं की संख्या बढ़कर 73,117 पर पहुंच गई। जिन स्थानों पर शाखा लगती हैं, उनकी संख्या 42,613 से बढ़कर 45,600 हो गई। प्रतिनिधि सभा में तय हुआ कि 2025 की विजयादशमी से पूर्ण नगर, पूर्ण मंडल तथा पूर्ण खंडों में दैनिक शाखा तथा साप्ताहिक मिलन का लक्ष्य पूरा होगा। शाखाओं की संख्या एक लाख करने का लक्ष्य है। राममंदिर के उद्घाटन समारोह से पहले अयोध्या से लाए गए पूजित अक्षत को घरों में बांटने के दौरान संघ एवं समवैचारिक संगठनों के 44 लाख 98 हजार कार्यकर्ता 5 लाख 98,778 गांवों तक पहुंचे थे। 19 करोड़ 38 लाख परिवारों तक अक्षत पहुंचाया गया और 22 जनवरी को पांच लाख 60 हजार स्थानों पर 9.85 लाख कार्यक्रम हुए।

अन्य अनेक संगठनों की समस्या है कि भारत के जनमानस को न समझने के कारण उचित भूमिका नहीं निभाते या विपरीत चले जाते हैं। दूसरी ओर संघ उसे समझ कर उसके अनुसार भूमिका निभाता है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करता है। आप संदेशखालि को इसलिए महत्त्व नहीं देंगे कि इससे भाजपा को लाभ हो जाएगा तो जनमानस, जो उनकी आवाज उठाएगा, उसके साथ जाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 के 68,651 शाखाओं के मुकाबले संघ की शाखाओं की संख्या बढ़कर 73,117 पर पहुंच गई। जिन स्थानों पर शाखा लगती हैं, उनकी संख्या 42,613 से बढ़ कर 45,600 हो गई। प्रतिनिधि सभा में तय हुआ कि 2025 की विजयादशमी से पूर्ण नगर, पूर्ण मंडल तथा पूर्ण खंडों में दैनिक शाखा तथा साप्ताहिक मिलन का लक्ष्य पूरा होगा। शाखाओं की संख्या एक लाख करने का लक्ष्य रखा गया है

जीआई टैग हासिल कर चुकी है लाकाडोंग हल्दी

- मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेतक (जीआई) पहचान मिल चुकी है। जयंतिया हिल्स के लाकाडोंग क्षेत्र में पाई जाने वाली इस हल्दी में उच्च करक्यूमिन तत्व होता है
- जीआई पहचान मिलने से लाकाडोंग हल्दी किसानों को विपणन में मदद मिलेगी और ग्राहकों को प्रामाणिक उत्पाद
- लाकाडोंग हल्दी दुनिया की सबसे अच्छी हल्दी की किस्मों में शुमार की जाती है जिसमें करक्यूमिन की मात्रा 6.8 से 7.5 फीसद होती है। रंग गहरा होता है, और यह जैविक रूप से उपजाई जाती है

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

विश्व बैंक : बांग्लादेश ने 2018 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया। दस साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत में बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन वह अपने यहां बेहद असमानता, बेरोजगारी और लोकतंत्र में ह्रास की कीमत चुका रहा है। भारत में परिवर्तन जरूरी है : नफरत और नारेबाजी की बजाय विश्लेषणात्मक, तथ्योन्मुख और विज्ञानोन्मुख होना होगा।

कौशिक बसु, अर्थशास्त्री
@kaushikcbasu

भगदड़ रोकने के उपाय तलाशने होंगे

धार्मिक स्थल | ऋतुपर्ण दवे

भारत में धार्मिक आयोजनों की भीड़ में भगदड़ आम हो चुकी है। ऐसी घटनाओं में मौतें होना न नई हैं, और न ही अब हैरान करने वाली। लेकिन लगता है कि गंभीरता को जानते-समझते हुए भी सीख नहीं लेने से इन मौतों पर विराम तो दूर सोचना भी बेमानी लगता है। दो-चार दिन बाद बात आई-गई हो जाती है। बीते दिनों वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में रंगभरी एकादशी की रंगीली होली की शुरुआत के एक दिन पहले भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि एक श्रद्धालु ने दम तोड़ दिया जबकि एक की तबीयत बिगड़ गई। भारी भीड़ के दबाव में फंसी महिलाओं और बच्चों की चीखें निकलती रहीं और पुलिस की मुस्तैदी इस बात पर ज्यादा थी कि अति विशिष्टजनों की सेवा में कोई खलल न पड़े।

ऐसी ही एक घटना अगस्त, 2022 में घटी जब श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा-वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और बांके बिहारी मंदिर में रात 2 बजे मंगला आरती के दौरान दम घुटने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 9 घायल हो गए। आरोप लगे कि भीड़ नियंत्रित कराने वाले अपने परिजनों को वीआईपी दर्शन कराने में जुटे थे तो कई वीडियो बनाने में मशगूल रहे। परिसर में श्रद्धालु क्षमता 800 लोगों की है, जबकि वहां 25-30 हजार श्रद्धालु मौजूद थे। धार्मिक आयोजनों में भारी भीड़ जुटना नया नहीं है। लेकिन हादसों के बाद समझ आता है कि सुरक्षा कैसी होती है? वैज्ञानिकों ने 1900 के बाद से विश्व में भगदड़ या भीड़भाड़ की घटनाओं का एक डेटाबेस तैयार किया ताकि ऐसी मौतों को रोकने के उपायों को खोजा जा सके। इसमें 1900-2019 के बीच ऐसी 281 घटनाएं शामिल की जिनमें या तो कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई या दस से ज्यादा लोग घायल हुए। यही आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में भारत और पश्चिमी अफ्रीका ऐसी दुर्घटनाओं के सबसे बड़े केंद्र हैं। वक्त के साथ बढ़ती तकनीक के बावजूद तीन दशकों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

भारत में बीते कुछ वर्षों के दौरान मंदिरों और अन्य हिन्दू धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ में सैकड़ों जानें गईं। 25 जनवरी, 2005 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के मंधारदेवी मंदिर में वार्षिक तीर्थयात्रा में 340 से अधिक श्रद्धालुओं की कुचल कर मौत हो गई, सैकड़ों घायल हुए। नारियल तोड़ने से सीढ़ियों में फिसलन से यह भगदड़ हुई। 3 अगस्त, 2008 को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नैना देवी मंदिर में

भू-स्खलन की अफवाह से मची भगदड़ में 162 जान चली गईं, 47 लोग घायल हुए। 30 सितम्बर, 2008 को राजस्थान के जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में बम विस्फोट की अफवाह से मची भगदड़ में 250 लोगों की मौत हुईं और 60 से ज्यादा घायल हुए। 4 मार्च, 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में कृपालु महाराज के राम जानकी मंदिर में मची भगदड़ में 63 लोगों की मौत हुई जो वहां कपड़ा और भोजन लेने आए थे।13 अक्टूबर, 2013 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले में रतनगढ़ मंदिर के पास नवरात्रि उत्सव के दौरान भगदड़ में 115 लोगों की मौत हुईं और 100 से अधिक घायल हुए।

ऐसे और न जाने कितने हादसों ने सैकड़ों जान ली हैं। दुर्भाग्यवश कभी भगदड़ में फंस जाएं तो थोड़ी सतर्कता बरत कर खुद को बचाया जा सकता है। अपनी ताकत बेवजह भीड़ के खिलाफ दूसरों को धकेलने में न लगाएं। चीखने-चिल्लाने या शोर मचा कर भी ताकत जाया न करें। कोशिश करें कि पैर फैला कर रखें ताकि धक्का लगने पर संतुलन बना रहे। धैर्यपूर्वक गहरी सांसें लेकर शांत रहें। बजाय विपरीत दिशा में जाने के हमेशा भीड़ के साथ चलें जिससे बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हाथों को अपनी छाती के सामने किसी बॉक्सर की तरह अड़ा रखें ताकि सीना सुरक्षित रहे जिससे आप खुद को सुरक्षित रख सकेंगे। भीड़ में गिरने पर उठ नही पा रहे हों तो तिरछे हो जाएं, दोनों पैरों को सीने से चिपकाएं, सिर पर हाथ रख कर खुद को बचाने की कोशिश करें ताकि सीना, पसली और सिर बचा रहे। दीवारों और बैरिकेडिंग से भी दूर रहें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि खुली जगह में जल्द से जल्द पहुंच जाएं।

यह कहना कि एकाएक भीड़ आ गई गलत है। आजकल धार्मिक स्थलों के पूरे क्षेत्र, गलियारों, चौक, चौराहों में स्थानीय प्रशासन, पुलिस या निजी सुरक्षा के लिए लगे सीसीटीवी कैमरों के अलावा सैटेलाइट से भी भीड़भाड़ की जानकारी लेना संभव है। हर पल पता होता है कि कहां से कितनी भीड़ आ रही है। यही प्रबंधन तो करना है ठीक वैसे, जैसे ट्रैफिक का करते हैं। इसके लिए जगह-जगह प्रतीक्षालय बनें, उनमें जलपान, प्रसाधन और आराम तथा छायादार सुविधा हों। बड़े-बड़े स्क्रीन हों जिन पर गंतव्य का लाइव प्रसारण होता रहे ताकि श्रद्धालु खुद मानसिक रूप से आगे जाने से पहले भीड़ के अनुरूप तैयार हों या कुछ पल सुकून से और प्रतीक्षा कर लें। प्रायः भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थल आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। हादसों से सीख कर ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों के प्रबंधक और स्थानीय तंत्र भी खुद को बदलें। इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक पद्धतियों और क्राउड मैनेजमेंट से स्थिति काफी हद तक बदल सकती है ताकि भीड़, भगदड़ से होने वाली मौतों पर काबू पाया जा सके।

सूर्य शक्ति | सद्गुरु

हठ योग का मकसद ऐसे शरीर का निर्माण है जो आपके जीवन में बाधा न हो, बल्कि अपनी चरम संभावना में विकसित होने की ओर एक सोपान हो। अपने शरीर को इसके लिए तैयार करने के लिए आप कुछ सरल चीजें कर सकते हैं, और अपने अभ्यास से अधिकतम लाभ पा सकते हैं।

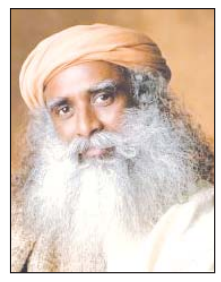

1) सूर्य नमस्कार से पहले ठंडे पानी से स्नान करें अभ्यास शुरू करने से पहले, सामान्य तापमान से थोड़े ठंडे पानी से स्नान करें। अगर एक खास मात्रा में पानी आपके शरीर के ऊपर से बहता है या आपका शरीर सामान्य तापमान से कुछ ठंडे पानी में डूबा हुआ रहता है, तो एपथिलियल कोशिकाएं संकुचित होती हैं। योग के अभ्यास के लिए जरूरी है कि कोशिकाएं संकुचित हों और कोशिकाओं के बीच का अंतर खुल जाए क्योंकि हम शरीर की कोशिका संरचना को ऊर्जा के एक अलग आयाम से सक्रिय करना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा जीवंत और सक्रिय इसलिए लगते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाओं का ढांचा ज्यादा ऊर्जावान होता है। जब वह ऊर्जा से सक्रिय होता है, तो वह लंबे समय तक ताजगी भरा रहता है। यह करने का एक तरीका है, हठ योग। 2) सूर्य नमस्कार के बाद पसीने को त्वचा में मलें चाहे आप आसन कर रहे हों, सूर्य नमस्कार या सूर्य क्रिया अगर आपको पसीना आए, तो उस पसीने को तौलिये से न पोंछें। हमेशा उसे वापस मल दें, कम से कम अपने शरीर के खुले हिस्सों में। आप पसीने को पोंछ देते हैं, तो उस ऊर्जा को बहा देते हैं, जो आपने अभ्यास से पैदा की है। 3) सही मात्रा में पानी पिएं। योग के अभ्यास के बाद स्नान से पहले कम से कम डेढ़ घंटे इंतजार करें। अगर कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार द्वारा एक तरह की स्थिरता और शरीर पर थोड़ा अधिकार पा लेता है, तो उसे सूर्य क्रिया नामक अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया से परिचित कराया जा सकता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य क्रिया का आसान रूप है, दूसरे शब्दों में वह सूर्य क्रिया का 'देहाती भाई' है। सूर्य शक्ति नामक एक और प्रक्रिया है, जो और भी दूर का रिश्तेदार है। आप मांसपेशियां मजबूत करने और शारीरिक मजबूती के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको सूर्य शक्ति करना चाहिए।

रीडर्स मेल

मतदान अनिवार्य किया जाए

लोक सभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदान अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन मतदान का विकल्प अपनाया जाना चाहिए। कंप्यूटर के जरिए मतदान की सुविधा देनी चाहिए। जिनके पास कंप्यूटर हैं, वे इस तरीके से मतदान कर सकते हैं। विश्व के जिन देशों में अनिवार्य मतदान का नियम है, वहां मतदान न करने पर जुर्माना सहित कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। भारत में अनिवार्य मतदान को बनाने के लिए वैसी ही सख्ती दिखानी जानी चाहिए। लोकतंत्र में संविधान की ओर से आम व्यक्ति को सबसे बड़ा अधिकार सरकार चुनने का दिया गया है। कोई इस अधिकार का उपयोग नहीं करता है, तो यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए, वहीं इसके बाद भी वोट नहीं डालते हैं, तो इसके लिए सजा का प्रावधान हो।

अंकित सोनी 'आदित्य', धार, मप्र

भारी पड़ रहा बदलता मौसम

तापमान का उतार-चढ़ाव लोगों के जीवन पर भारी पड़ने लगा है। इस साल होली के दिन न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस था जो सामान्य से छह डिग्री कम था। होली के दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री हो गया। मार्च के अंत में पहली बार इस स्तर पर तापमान पहुंचा। एक ही पखवाड़े का यह बदलाव सामान्य नहीं है। भले ही इसे वायु परिवर्तन की आहट न मानें लेकिन यह खतरे की दस्तक जरूर है। तापमान में बदलाव से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है जिसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। अचानक तपती धरती और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत के राज्यों में चिलचिलाती गर्मी की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में हीट वेव से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। पहाड़ी राज्यों में मार्च के आखिर का तापमान 2-3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है।

कांतिलाल मांडोत, सूरत, गुजरात

एक साथ चुनाव, नहीं अनूठा प्रयोग

एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है, जब लोक सभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गए थे। यह क्रम तब टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणों से समय से पहले भंग कर दी गईं। 1971 में लोक सभा चुनाव भी समय से पहले हो गए थे। जाहिर है जब इस प्रकार चुनाव पहले भी करवाए जा चुके हैं तो अब क्या समस्या है। संविधान ने हमें संसदीय मॉडल प्रदान किया है, जिसके तहत लोक सभा और विधानसभाएं पांच वर्षों के लिए चुनी जाती हैं, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर हमारा संविधान मौन है। संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, जो इस विचार के विपरीत दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 85(2)(ख) के अनुसार राष्ट्रपति लोक सभा को और अनुच्छेद 174(2)(ख) के अनुसार राज्यपाल विधानसभा को पांच वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य के राजनीतिक समीकरण में अप्रत्याशित उलटफेर होने से वहां फिर से चुनाव की संभावना बढ़ जाती है।

रवि रंजन, नई दिल्ली
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-33, अंक 224
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी
संपादकीय
संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

घुटने टेकता पाकिस्तान

पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नकदी संकट से हर कोई परेशान है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार केवल 8 बिलियन डॉलर का रह गया है जिससे डेढ़ महीने तक के सामान का आयात किया जा सकता है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार के चलते पाकिस्तान को अगले दो महीने में एक बिलियन डॉलर यानी 8.30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। एक तरफ उस पर कर्ज लौटाने का दबाव है तो दूसरी ओर 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से उसे 3 बिलियन डॉलर कर्ज मिलने की समय सीमा भी खत्म हो रही है। अगर कर्ज मिल भी जाए तो भी इस बात की उम्मीद कम है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कुछ सुधर जाएगी। पाकिस्तान का व्यापार लगभग लुप्त हो चुका है और इस वर्ष पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है। अगर नई सरकार भी लड़खड़ाई तो यह दर और भी नीचे आ सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान अब एक बार फिर अपनी हेकड़ी छोड़कर भारत के साथ व्यापार शुरू करने का इच्छुक दिखाई देता है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत से व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई है। इससे साफ है कि पाकिस्तान की नई शहनवाज शरीफ सरकार देश को आर्थिक संकट से निकालने की चुनौती किसी न किसी तरह पार कर लेना चाहती है। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत के साथ व्यापार को एकतरफा तरीके से रोक दिया था। उससे पहले दोनों देशों में पुलवामा के आतंकी हमले और भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किए जाने के बाद संबंध काफी तनावपूर्ण चल रहे थे।

पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। एक तरफ पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान आतंकवादी गिरोह से मिलकर हमारे सैनिकों का खून बहाएं और दूसरी तरफ वह भारत से फायदा उठाए, यह संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध तोड़कर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान गेहूं, चीनी, घी और दवाइयां रूस, यूएई, मिस्र, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों से आयात कर रहा है। दूर देशों से आयात करने में पाकिस्तान का शिपिंग चार्ज काफी बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के अवमूल्यन ने इस संकट को और गहरा दिया है। इस समय एक डॉलर की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। भारत कई देशों को जिस दर पर गेहूं बेच रहा है पाकिस्तान को दूसरे देशों से उससे कहीं अधिक पैसे खर्च करके गेहूं खरीदना पड़ रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच अधिकतर व्यापार सड़क मार्ग से ट्रकों के माध्यम से होता था। इससे आयात खर्च काफी कम आता था। पाकिस्तान को भारत से चीनी भी सस्ती मिल रही थी। लेकिन अब उसे चीनी के लिए भी अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला कोई पहली बार नहीं किया है। 2021 में पाकिस्तान ने भारत से कपास और धागे के आयात की अनुमति दी थी। कोरोना महामारी के दौरान भी पाकिस्तान को दवाओं का संकट झेलना पड़ा था। पाकिस्तान भारत से कपड़ा उद्योग से जुड़ी चीजें कुछ जैविक रासायन, जीरा, धनिया, सरसों भी आयात करता था। भारत पाकिस्तान से खजूर, छुहारे, फल, सेंधा नमक और सीमेंट भी आयात करता था लेकिन भारत इन चीजों के लिए पाकिस्तान पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है। विश्व बैंक के शोध से पता चलता है कि अगर पाकिस्तान का भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध होता, तो उसका निर्यात जीडीपी और रोजगार पर समान प्रभाव के साथ 80 प्रतिशत तक बढ़ सकता था। इन अनुमानों से निष्कर्ष निकालते हुए, पाकिस्तान के माल का निर्यात, जो 2022 में केवल 31.5 बिलियन डॉलर था, अगर भारत के साथ व्यापार का एहसास हुआ तो लगभग 25 बिलियन डॉलर अधिक हो सकता है। विश्व बैंक के एक अन्य अध्ययन से पता चलता है कि पाकिस्तान की कुल अप्राप्त व्यापार क्षमता में भारत की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत है।

पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया था। एक तरफ पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान आतंकवादी गिरोह से मिलकर हमारे सैनिकों का खून बहाएं और दूसरी तरफ वह भारत से फायदा उठाए, यह संभव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से व्यापारिक संबंध तोड़कर अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारी है। पाकिस्तान गेहूं, चीनी, घी और दवाइयां रूस, यूएई, मिस्र, ब्राजील, सिंगापुर आदि देशों से आयात कर रहा है। दूर देशों से आयात करने में पाकिस्तान का शिपिंग चार्ज काफी बढ़ गया है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए के अवमूल्यन ने इस संकट को और गहरा दिया है। इस समय एक डॉलर की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है।

भारत के साथ गहरा आर्थिक जुड़ाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अन्य गंभीर समस्याओं का समाधान करने में भी मदद कर सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति भी शामिल है, जिसके कारण पिछले वर्ष गरीबी में वृद्धि हुई है। किराया मांगने वाला निजी क्षेत्र जो लगातार सुरक्षा और अनुकूल कर उपचार की पैरवी करता है और लंबे समय से चला आ रहा ऊर्जा संकट, चल रही आर्थिक आपदा के कारण और भी गंभीर हो गया है। 2022 के बाद से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट को देखते हुए भारत के साथ व्यापार बहुत मूल्यवान साबित हो सकता है।

पाकिस्तान के व्यापारी, सीमांत क्षेत्रों के बेरोजगार हुए लोग अब मांग करने लगे हैं कि भारत से व्यापार शुरू किया जाए। पाकिस्तान के रुख में नरमी नई संभावनाओं का संकेत तो देती है लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि आतंकवाद और व्यापार साथ-साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करना बंद करे और भारत के साथ मिलकर शांति के पौधे रोपे तो भारत उसे फिर से सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा दे सकता है। भारत से दोस्ती ही उसे संकटों से निजात दिला सकती है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

...तुम्हारे संघर्षों से ही एक दिन

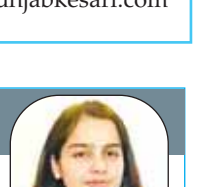

जब-जब पहाड़ इंसानों के रास्ते में आएगा,
पहाड़ टूटेगा और इंसानी हौसला जीत जाएगा,
इन बेदर्दों की बस्ती में तुम्हारा दर्द किसे समझ आएगा,
जिंदा लाशों से सहानुभूति की उम्मीद खुद से बेईमानी कहलाएगा,
तुम्हारे अनगिनत सवालों को अक्सर तानाशाह दबाना चाहेगा,
पर तुम्हारे संघर्षों से ही एक दिन जग में सवेरा नया आएगा !!

गीता पाढा

यदि कोई रंग न हो जीवन में तो...?

डा. विजय दर्डा
संपादक : लोकमत समूह
पूर्व राज्यसभा सांसद

ठीक-ठीक याद नहीं कि वो उम्र का कौन सा वर्ष था जब होली मेरे दिल में इस कदर समाई कि जिंदगी को रंगों में भिगो दिया। निश्चय ही वो कच्ची उम्र रही होगी, वो उम्र जब जेहन हर दास्तां को यादों के रूप में समेटना शुरू करता है तो होली की स्मृतियां उसी उम्र से मेरी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बनना शुरू हो गईं। होली आज भी मेरा पसंदीदा त्यौहार है। यादों के आइने में देखता हूं तो होली के भी कई रंग नजर आते हैं। खूब होली खेली, रंगों की होली खेली, जज्बातों से भरी होली खेली, प्रेम और अपनेपन की होली खेली, जो दूर थे उनको नजदीक करने की होली खेली, फूलों और केसर संग होली खेली, अपनों को गले लगाकर खेली, बिना भांग की ठंडाई में मस्ती की होली खेली। मैं कई बार सोचता हूं कि यदि जिंदगी में कोई रंग न होता तो जिंदगी कैसी होती? रंग न होते तो ये पूरी प्रकृति ही ऐसी न होती। फिर शायद इंसान भी ऐसा नहीं होता जैसा वह प्रकृति के साथ विकसित हुआ।

प्रकृति ने हमें रंगों से ऐसा सराबोर किया है कि जिंदगी के पन्ने खुशनुमा हो जाना स्वाभाविक है, होली के दिन हर साल हम यह अनुभव भी करते हैं। मुझे याद है, यवतमाल में मेरे घर के बाहर होली के दिन शानदार जश्न जैसा माहौल होता था, मेरे प्रिय बाबूजी वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहर लाल दर्डा के साथ होली खेलने के लिए हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग जमा होते थे। वहां अपनेपन के रंग से सभी रंग जाते थे, ये त्यौहार है ही ऐसा कि हर मजहब के लोग प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। यहां तक कि जो राजनीतिक रूप से दूसरी विचारधारा के लोग थे, वे भी होली का त्यौहार मनाने पहुंचते थे, सबके लिए ठंडाई और मुंह मीठा करने का इंतजाम होता था। आज जब उन दिनों को याद करता हूं तो मुझे जाने-माने कवि हरिवंश राय बच्चन की होली पर लिखी ये पंक्तियां याद आ जाती हैं...

होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, जो हो गया बिराना उसे भी अपना कर लो...

होली है तो आज शत्रु को बांहों में भर लो, होली है तो आज मित्र को पलकों में धर लो...

मुझे लगता है कि होली मनाए जाने के पीछे निश्चय ही सामाजिक सौहार्द एक गंभीर विषय रहा होगा। एक ऐसा दिन निर्धारित करना जब लोग सारे बैर-भाव भूलकर एक हो जाएं, मौजूदा दौर में तो यह त्यौहार और भी प्रासंगिक नजर आता है।

मुझे यह भी याद है कि हम सफेद कुर्ता-पायजामा पहनते थे ताकि उस पर रंग पूरी शिद्दत के साथ खिल सकें। तब केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल नहीं होता था, हम संगी-साथियों के साथ टेसू के फूल एकत्रित करने जंगलों में जाते थे, जिससे रंग तैयार होता था। हल्दी वाले गुलाल तैयार किए जाते थे। बचपन के उन दृश्यों ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी कि हमें त्यौहारों को प्रकृति के आसपास रखना चाहिए। टेसू के फूल आज भी बहुतायत में उपलब्ध होते हैं लेकिन कितने लोग इसका

इस्तेमाल करते हैं? हां, गुलाल को लेकर कुछ जागृति आई है और ऑर्गेनिक गुलाल का प्रचलन बढ़ा है लेकिन आज भी जब मैं एल्युमीनियम पेंट में रंगे-पुते चेहरे देखता हूं तो ऐसे लोगों पर तरस आता है। हर साल केमिकल वाले रंगों के कारण न जाने कितने लोगों की आंखें क्षतिग्रस्त होती हैं। इसीलिए मेरी मान्यता है कि होली हमें प्राकृतिक रंगों से ही मनानी चाहिए। होलिका दहन के लिए हमें पेड़ भी नहीं काटने चाहिए, त्यौहार प्रकृति के संरक्षण के लिए होते हैं, विनाश के लिए नहीं।

मेरी मां जिन्हें मैं प्यार से बाई कहता हूं, मुझे होली से जुड़ी कई कहानियां सुनाया करती थीं लेकिन मुझे वो कहानी बड़ी अच्छी लगती थी कि भगवान कृष्ण का रंग श्यामल था और इसकी शिकायत वे अपनी मां से करते थे कि राधा का रंग इतना गोरा है मेरा श्यामल क्यों, तो उनकी मां ने कहा कि राधाजी को अपने रंग में रंग दो, भगवान श्रीकृष्ण ने राधाजी को अपने रंग में रंग दिया। उन दोनों का यह प्रेम होली का प्रतीक बन चुका है, आज भी हम होली के जो गाने गाते हैं, उनमें से ज्यादातर इसी प्रेम के रंग में रंगे होते हैं, हमारी फिल्में तो ब्रज की होली के गीत से भरी पड़ी हैं।

जब उम्र की दहलीज पर थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे मन में ख्याल आया कि हमारा ये पसंदीदा उत्सव कितना पुराना है? अब कोई ठीक-ठाक प्रमाण तो नहीं है लेकिन यह जानकारी जरूर मिलती है कि ईसा से 600 साल पहले भी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में होली का वजूद था। कालिदास रचित ग्रंथ कुमारसंभवम् में भी होली का जिक्र आता है। चंदबरदाई ने हिंदी का जो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा, उसमें भी होली का अद्भुत वर्णन है।

सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, मीराबाई या फिर कबीर हों, होली सबकी रचनाओं का अभिन्न अंग रहा है, कई मुगल शासक भी होली का त्यौहार मनाते थे। बहादुर शाह जफर को तो यह बहुत पसंद था कि होली के अवसर पर उनके दरबारी उन्हें रंगों में रंग दें। जफर ने तो गीत भी लिखा...

'क्यों मो पे रंग की मारी पिचकारी
देखो कुंवरजी दूंगी मैं गारी'

ऐसी रचनाओं से हमारा साहित्य भरा पड़ा है। मेरे एक प्रोफेसर भारतेंदु हरिश्चंद्र की लिखी ये कविता हमें सुनाया करते थे जो मुझे आज भी याद है और बेहद पसंद भी है...

गले मुझको लगा लो ऐ दिलदार
होली में/बुझे दिल की लगी भी तो ऐ यार होली में...

नहीं ये है गुलाले-सुर्ख उड़ता हर जगह प्यारे/ये आशिक की है उमड़ी आहें आतिशबार होली में...

गुलाबी गाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो/मनाने दो मुझे भी जानेमन त्यौहार होली में

तो आइए, मिलजुल कर जिंदगी के कोरे पन्नों को रंगीन बनाते रहें, हम सबकी जिंदगी रंगों से भरी रहे, प्रेम, स्नेह और अपनेपन के रंग में हम सब हमेशा रंगे रहें।

मदरसों को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है

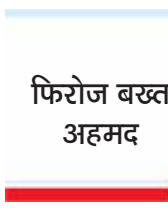

फिरोज बख्त अहमद

भारतीय मदरसे नाना प्रकार के कारणों को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। अभी एक ताज़ा-ताज़ा फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड कानून को असंवैधानिक ठहरा दिया है। इसका मदरसा छात्रों के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। खंडपीठ ने यूपी सरकार को एक योजना बनाने का भी निर्देश दिया है ताकि वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। यह फैसला यूपी सरकार की राज्य में इस्लामी शिक्षा संस्थानों का सर्वेक्षण करने के फैसले के कई महीनों बाद आया है। कानून को अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को योजना बनाने का भी निर्देश दिया, जिससे वर्तमान में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके।

भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार, मदरसा शिक्षा प्रणाली के तहत संचालित मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 19132 है, जबकि 4878 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी संचालित हो रहे हैं। देश में सर्वाधिक मदरसे उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें 11621 मान्यता प्राप्त और 2907 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें विदेशों से मदरसों के फंडिंग की जांच के लिए अक्टूबर 2023 में एक एसआईटी का गठन भी किया गया था। अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर रिट याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार और अन्य संबंधित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसा के प्रबंधन पर आपत्ति जताई गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है की मदरसों पर आपत्ति जताई गई है। इससे पूर्व कई सरकारों में मदरसे शक के दायरे में आ चुके हैं।

यदि इन मदरसों को बंद कर दिया गया तो इससे मुस्लिम समाज का बड़ा हनन होगा। चूंकि मुस्लिमों में निर्धनता बहुत है, वे अंग्रेज़ी माध्यम या अन्य स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते। अत: शिक्षा का एकमात्र रास्ता उन के पास मदरसे का रह जाता है। जहां तक मदरसा बोर्ड पर ताला डालने की बात कही जा रही है, उससे अच्छा यह होगा कि इस शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से मजबूत बनाया जाए कि इसके बच्चे दीन और दुनिया दोनों विभागों में सक्षम हों। इस से पूर्व कि मदरसा शिक्षा पर कोई टिप्पणी की जाए, समझना होगा कि मदरसा शिक्षा प्रणाली क्या है।

वास्ताव में मुस्लिमों की धार्मिक शिक्षा पद्धति मदरसों में होती है। मदरसों में पढ़ाई का तरीका और पाठ्यक्रम अलग-अलग होते हैं, जो उनके संबद्ध बोर्ड, प्रबंधन और शिक्षण पद्धति पर निर्भर करते हैं। इस शिक्षा में क़ुरान को कंठस्थ करना, हदीसों में दक्षता प्राप्त करना, सर्फ-ओ-नह्व (व्याकरण), तफसीर, फिकह और विषयों की शिक्षा दी जाती है। इसके अतिरिक्त अरबी भाषा बोलने, लिखने और समझने का भी प्रावधान होता है। यह शिक्षा पिछले 1400 वर्ष से चल रही है और भारत के संविधान अनुसार यहां किसी भी धर्म और उसकी शिक्षा को प्रचलित करने की इजाज़त है, जिसके कारण, यहां पर बिना किसी रोक-टोक के मदरसा शिक्षा चलती आ रही है। वैसे एक समय ऐसा भी था कि बहुत से ग़ैर मुस्लिम बच्चे भी मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे से शिक्षित थे।

वास्तव में यह सारा पचड़ा मदरसा बोर्ड को लेकर है। खंडपीठ का मानना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में एक ही शिक्षा प्रणाली चलनी चाहिए। दूसरी बात यह कि मदरसा प्रणाली में बच्चे केवल धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जबकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में दुनियावी अर्थात व्यावहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे बच्चा दुनिया में अपनी जीविका अच्छे से चलाने में दक्ष हो जाता है। वैसे मदरसे के बच्चों में अन्य बच्चों की तुलना में प्रतिभा की कमी नहीं होती है। इसका प्रमाण यह है कि मदरसे का बच्चा, क़ुरान जैसी मोटी किताब को बिना किसी भूल या किसी मात्रा की गलती किए कंठस्थ कर लेता है। इस बात की ओर कई बार असम के मुख्यमंत्री, हिमंत बिसवा सरमा ने भी इशारा किया है कि उनकी इच्छा है कि इन मदरसे के बच्चों को यदि स्कूली शिक्षा में डाल दिया तो ये डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि भी बन सकते हैं और साथ ही साथ क़ुरान पर भी महारत हासिल कर सकते हैं।

यह बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी मदरसा छात्र को व्यावहारिक शिक्षा का वरदान प्राप्त हो जाए तो वह अजब-गज़ब कर सकता है, जैसा उत्तर प्रदेश के एक मदारसा छात्र वसीम-उर-रहमान ने कर दिखाया, जो किरण हाफिज़ होने के साथ-साथ हैदराबाद में एक इन्कम टैक्स कमिश्नर भी हैं क्योंकि उन्होंने आईएएस की शिक्षा पास कर उच्च स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के जयपुर, रामगढ़ मदरसा जामियातुल हिदाया में मदरसा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, भूगोल आदि के साथ-साथ खेल-कूद का भी बढ़िया मामला है। यहां के बच्चे क्रिकेट, फुटबाल, बास्केट बॉल, टेबल टैनिस, बैडमिंटन आदि भी खेलते हैं।

एक बार असम के एक मदरसे पर बुलडोजर चला दिया गया कि किसी बंगलादेशी आतंकी संस्था से उनका संबंध था। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और यदि ऐसा है तो ठीक है मगर हर मदरसे के बारे में ऐसा विचार रखना ठीक नहीं। इससे मुस्लिम समुदाय स्वयं को प्रताड़ित समझता है। सीएम बिसवा सरमा यदि चाहते हैं कि मदरसों से वे वैज्ञानिक, शिक्षक आदि निकालें तो यह बहुत अच्छी सोच है, मगर मात्र कह भर देने से यह नहीं होने वाला। इसके लिए उन्हें मदरसों को आधुनिक बनाना होगा और ब्रिज कोर्स शुरू करना होगा जिसका अर्थ है कि धार्मिक शिक्षा के साथ व्यावहारिक शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है ताकि ये बच्चे ज्ञान प्राप्त करके अपना और देश का नाम रोशन कर सकें। वैसे मदरसों से शिक्षा प्राप्त कर बच्चे इमाम, खतीब, मुअज्जिन, वाइज़ आदि ही बन पाते हैं। कुछ भी हों मदरसों को रहना होगा मगर साथ ही साथ उनके आधुनिकीरण की भी आवश्यकता है।

दिल्ली में यह क्या हो रहा है ?

आर.के. सिन्हा
पूर्व राज्यसभा सांसद

अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की शराब नीति के जिन आरोपों के आधार पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें साबित होना भर ही बाकी है। वे लगातार केन्द्र सरकार और सरकारी अफसरों से लड़ने-झगड़ने के मूड में ही रहे। उन्होंने एक तरह से मान लिया कि देश भर में वह ही अकेले ईमानदार हैं। बाकी दुनिया भ्रष्ट है। उनसे उम्मीद थी कि वह देश में साफ-सुथरी और वैकल्पिक राजनीति का रास्ता साफ करेंगे।

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पहले भी सरकारें और मुख्यमंत्री रहे, पर कभी कोई ऐसा मसला नहीं आया। दिल्ली की चुनी हुई सरकारों और केन्द्र सरकारों के बीच मजे-मजे में विकास के सब काम होते रहे। पर सन् 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनते ही हंगामा शुरू हो गया और होने लगा रोज का क्लेश, तकरार और आरोप-प्रत्यारोप का दौर।

दिल्ली में 1951-52 में पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए। दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश बने। चौधरी साहब 1952 से 1955 तक मुख्यमंत्री रहे। उन्हें कांग्रेस ने हटाया और यहां का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया सरदार गुरुमुख निहाल सिंह मुसाफिर को।

गुस्ताखी माफ, कम ही दिल्ली वालों को पता है कि दिल्ली के दूसरे मुख्यमनंत्री एक सिख सज्जन थे। वे पहली दिल्ली विधानसभा के स्पीकर थे। वे 13 फरवरी, 1955 से 31 अक्टूबर, 1956 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद विधानसभा का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। मुसाफिर जी ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने नहीं दीं। मुसाफिर जी के पुत्र एस. निहाल सिंह प्रख्यात पत्रकार थे। वे इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संपादक भी रहे।

बहरहाल, 1966 में दिल्ली को एक महानगर परिषद मिली। यह विधानसभा के समकक्ष थी। महानगर परिषद का मुखिया कार्यकारी पार्षद होता था। इस पद पर विजय कुमार मल्होत्रा और जगप्रवेश चंद्र जैसे नेता भी रहे। दिल्ली को 1991 में फिर से संविधान में संशोधन करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। नए परिसीमन के तहत विधानसभा का 1993 में चुनाव हुआ। उसके बाद मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसे दिग्गज नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान केन्द्र में कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाली और कभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें काम करती रहीं। पर दिल्ली में विकास का पहिया कभी थमा नहीं। जब मदन लाल खुराना मंख्यमंत्री बने तब देश के प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिंह राव थे। कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थीं, तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तब भी दिल्ली का भरपूर विकास हो रहा था। कहीं कोई विवाद ही नहीं था। सारे विवाद आपसी बातचीत से हल हो रहे थे। अटल जी और शीला दीक्षित ने दिल्ली में मेट्रो रेल का विस्तार और बिजली की समस्या का स्थायी समाधान किया। यह बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते रहे कि दिल्ली में बिजली की 24 घंटे सप्लाई उनकी वजह से मुमकिन हुई। हालांकि, उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि दिल्ली में पेयजल संकट का वह हल क्यों नहीं कर सके। क्यों यमुना मैली ही होती रही? कैसे दिल्ली बन गई दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी? अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों के जवाब देने की कभी जरूरत महसूस नहीं की।

विधानसभा का 1993 में चुनाव हुआ। उसके बाद मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसे दिग्गज नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान केन्द्र में कभी कांग्रेस के नेतृत्व वाली और कभी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें काम करती रहीं। पर दिल्ली में विकास का पहिया कभी थमा नहीं। जब मदन लाल खुराना मंख्यमंत्री बने तब देश के प्रधानमंत्री पी.वी.नरसिंह राव थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई।

आप जब दिल्ली में जी.टी. रोड से आगे बढ़ते हैं, तो आपको दूर से ही और गाजीपुर के इन पहाड़ों में कुछ औरत-मर्द कुछ बीनते हुए नजर आ जाते हैं। जिस राजधानी दिल्ली में हरी-भरी लुटियंस दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली छावनी और दर्जनों अन्य शानदार एरिया हैं, वहां लगभग सौ एकड़ एरिया में फैले कूड़े के किले शर्मसार करते हैं। इनके आसपास बेबस लोग रहते हैं, इनसे हर वक्त भयंकर दुर्गंध आती रहती है। अब तो दिल्ली विधानसभा और नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं। पर यह कूड़े के किले पहले की तरह से खड़े हैं या यह कहिये कि प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं। यह कहना होगा कि दिल्ली नगर निगम ने कूड़े के निस्तारण और इसकी री-साइक्लिंग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। क्या इन काले पहाड़ों को हटाने से मोदी सरकार ने मना किया था?

राजधानी के एक बड़े भाग में लुटियंस दिल्ली आती है। इसमें केन्द्रीय मंत्री, सांसद, बड़े उद्योगपति वगैरह रहते हैं। इसके रख-रखाव पर मोटा बजट खर्च होता है। राजधानी के नई दिल्ली एरिया की देखभाल नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) करती है। यहां पर तो कमोबेश सब कुछ ठीक है। इसकी तुलना दुनिया के किसी भी शहर के हिस्से से की जा सकती है। इधर कोई कूड़े के पहाड़ भी नहीं हैं। मसला शेष दिल्ली का है। उसका हल भी मुमकिन है अगर कूड़े की-साइक्लिंग को लेकर रफ्तार से काम चले। फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को अपने को पाक साफ करना होगा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

संपादकीय जागरण

बुधवार, 27 मार्च, 2024 : चैत्र कृष्ण - 2 वि. 2080

जोखिम ही प्रतिफल का निर्धारण करता है

कांग्रेस छोड़ो अभियान

चुनावों से पहले नेताओं का पालाबदल कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का जैसा सिलसिला कायम है, वह देश के इस सबसे पुराने दल की दयनीय दशा और स्याह भविष्य को ही रेखांकित करता है। हालांकि भाजपा और कुछ अन्य दलों के चंद नेता कांग्रेस की शरण में भी गए हैं, लेकिन इसकी तुलना में उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने की संख्या कहीं अधिक है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या जिस तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उससे तो यह लगता है कि पार्टी छोड़ो जैसा कोई अभियान चल रहा है। गत दिवस लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी भाजपा में शामिल हो गए। उनके कांग्रेस छोड़ने से पार्टी नेतृत्व को हैरान-परेशान होना चाहिए, लेकिन शायद ही ऐसा हो, क्योंकि राहुल गांधी आम तौर पर ऐसे नेताओं को डरपोक या अवसरवादी करार देकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। वह और उनके करीबी यह देखने-समझने के लिए तैयार नहीं कि आखिर क्या कारण है कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह का भाजपा में जाना इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा आघात है, क्योंकि पंजाब उन राज्यों में है, जहां कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है और भाजपा तीसरे-चौथे नंबर के दल के तौर पर देखी जाती है।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस छोड़ने वालों में कई ऐसे नेता भी हैं, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, जैसे अशोक चह्वाण, मिलिंद देवड़ा, सुरेश पचौरी। इसके पहले राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के सदस्य कहे जाने वाले अधिकांश नेता भी कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में एक बड़ी संख्या उनकी है, जो अपने जनाधार के लिए जाने जाते हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में बहुत कम ऐसे हैं, जो अपने बलबूते चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। राहुल गांधी भले ही यह दिखाएं कि कांग्रेस नेताओं के जाने से पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह है अब फर्क पड़ता दिख रहा है। कुछ नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं और कुछ तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। कांग्रेस भले ही यह दिखा रही हो कि वह भाजपा का मुकाबला करने मे समर्थ है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वह अपने नेतृत्व वाले मोर्चे आइएनडीआइए को वैसा आकार नहीं दे सकी, जिसकी आशा की जा रही थी। इसके लिए कांग्रेस अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस का क्षरण इसलिए शुभ संकेत नहीं, क्योंकि भाजपा के समक्ष वही सही मायने में एक राष्ट्रीय दल है। अन्य राष्ट्रीय दलों में कोई भी ऐसा नहीं, जिसकी जड़ें देश भर में हों। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी आवश्यक होता है, लेकिन सत्तापक्ष उसकी मजबूती की चिंता नहीं कर सकता।

उचित कदम

दिल्ली में बिजली और पानी पर दी जा रही सब्सिडी को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बीच दिल्ली सरकार के योजना विभाग की सचिव का पत्र जारी कर इस बारे में दिल्लीवासियों को स्थिति स्पष्ट किया जाना सर्वथा उचित है। सचिव ने पत्र जारी कर कहा है कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ लोग अपने निजी हित के लिए भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के कारण दिल्ली सरकार की जनहित योजनाएं और दी जा रही सब्सिडी बंद कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसका सब्सिडी बंद होने या जारी रहने से कोई लेना-देना नहीं है। सरकार की कोई भी योजना किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होती, बल्कि वह नीतियों और बजटीय प्रविधानों पर आधारित होती है।

> राजधानी के लोगों को भ्रमित कर मौजूदा राजनीतिक हालात का फायदा उठाने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए

मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आप और भाजपा में राजनीतिक घमासान जारी है। आप जहां ईडी द्वारा सीएम की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बता रही है, वहीं भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री पर पद छोड़ने का दबाव बना रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री के गिरफ्तार होने को लेकर दिल्ली सरकार की योजनाओं और सब्सिडी को बंद किए जाने संबंधी भ्रम फैलाया जाना अत्यंत निंदनीय है। दिल्ली सरकार की सचिव ने पत्र अवश्य जारी किया है, लेकिन सरकार को ऐसा भ्रम फैला रहे लोगों की पहचान करने और उनपर सख्त कार्रवाई करने को लेकर पहल करनी चाहिए। राजधानी के लोगों को भ्रमित कर मौजूदा राजनीतिक हालात का फायदा उठाने वालों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रूस का यह आरोप विश्वसनीय दिखता है कि मास्को में आतंकी हमले के पीछे यूक्रेन की भूमिका है?

आज का सवाल

क्या आदर्श चुनाव आचार संहिता को और कड़ा किए जाने की आवश्यकता है?

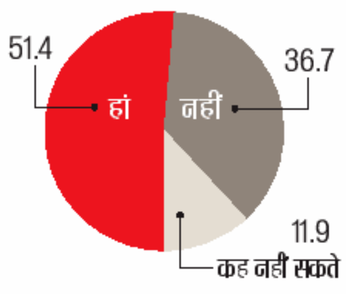

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

नागरिकता कानून पर विषवमन

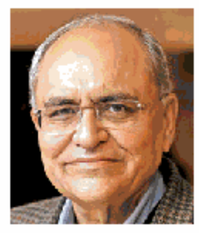

बलबीर पुंज

जिस सीएए को विवादों में घसीटने का प्रयास हो रहा है, वह तो भारत के मानवतावादी और बहुलतावादी सनातन डीएनए के अनुरूप ही है

इन दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का मामला चर्चा में है। यह मामला अदालत के साथ ही सार्वजनिक विमर्श के दायरे में भी है। किसी भी कानून पर नजरिये में भिन्नता बहुत स्वाभाविक है, मगर कुछ दल तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों की अवहेलना करते हुए समाज में घृणा और भय फैलाने के साथ मिथ्या आरोप लगाने में व्यस्त हैं। कहा जा रहा है कि सीएए संविधानसम्मत नहीं है और यह अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करता है। इसका निर्णय तो शीर्ष अदालत ही करेगी, परंतु इस मामले में भड़काऊ बयानबाजी हैरान करने वाली है। बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे सीएए को लागू नहीं होने देंगे, जबकि इस कानून का राज्य सरकारों से कोई लेना-देना नहीं।

शरद पवार इस कानून को लोकशाही पर आक्रमण कह रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को गोडसे के सोच वाला बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान तो और भी अचंभित करने वाला रहा। उन्होंने सीएए को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि 'पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में करीब ढाई-तीन करोड़ अल्पसंख्यक हैं। यदि इनमें से एक-डेढ़ करोड़ भी भारत आ जाएं, तो हम उन्हें कहां बसाएंगे? नौकरी कैसे देंगे? पूरी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी..यह 1947 से भी बड़ा प्रवास होगा...।' क्या यह बयान भड़काऊ नहीं? केजरीवाल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार विदेशी अल्पसंख्यकों को भारत आने का निमंत्रण देने जा रही है, जबकि सीएए तो उनके लिए है जो संबंधित तीन पड़ोसी देशों में मजहबी प्रताड़ना से परेशान होकर 2014 से पहले भारत आ गए थे। ऐसे शरणार्थियों से कानून एवं व्यवस्था को खतरा पहुंचने की बात कहने वाले क्या देश में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी-रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति को देखते हैं? राजधानी दिल्ली सहित देश के कई क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं। कुछ घटनाओं पर गौर करें तो 6 मार्च, 2021 को दिल्ली-एनसीआर में लूटपाट एवं डकैती की दर्जनों वारदात कर चुके तीन बांग्लादेशी बदमाशों, 22 अक्टूबर, 2020 को राजधानी के कई क्षेत्रों में एटीएम उखाड़कर ले जाने वाले बांग्लादेशियों, 6 अगस्त 2019 को कर्नाटक की एक डकैती में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा था। हरियाणा स्थित नूंह में गत वर्ष शोभायात्रा पर पथराव करने वालों में रोहिंग्या मुस्लिम भी शामिल थे। इसी तरह हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस बल पर हमले के पीछे भी कई रोहिंग्याओं के हाथ होने का आरोप है। ऐसी एक अंतहीन सूची है। क्या सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने रोहिंग्या-बांग्लादेशी मुसलमानों से जुड़ी इन आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कुछ बोला या उन्हें 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा' माना?

एक आवश्यक कानूनी पहल है नागरिकता संशोधन अधिनियम ● फाइल

स्वघोषित सेक्युलरवादी और 'लेफ्ट-फासिस्ट' अवैध रूप से भारत में घुसे उन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने के साथ सम्मानजनक नौकरी सहित अन्य सुख-सुविधा देने का प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन करते हैं, जिनके बंधु-बांधव अपने मूल देश म्यांमार में असंख्य हिंदू-बौद्ध अनुयायियों का नरसंहार कर चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, अगस्त 2017 में रोहिंग्या आतंकियों ने म्यांमार में अलगाववाद से ग्रस्त प्रांत रखाइन में 99 हिंदुओं को तालिबानी तरीके से मौत के घाट उतारकर उनकी महिलाओं का मतांतरण किया था। जांच पश्चात मृत हिंदुओं के शव एक सामूहिक कब्र में मिले थे। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच दल ने अक्टूबर 2023 में इसे 'अंतरराष्ट्रीय अपराध' घोषित किए जाने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड और जिहादियों को स्थानीय रोहिंग्या मुस्लिमों का समर्थन मिलने के बाद 2017 में म्यांमार सत्ता-अधिष्ठान सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य हुआ था। इसके चलते लाखों रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित ठिकाने की खोज में म्यांमार से पलायन कर गए। क्या इसके बाद उनके आचरण में कोई बदलाव आया? दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार ने सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था कि म्यांमार से शरणार्थी बनकर बांग्लादेश के काक्स बाजार पहुंचे रोहिंग्या मुस्लिम राहत शिविरों में रोहिंग्या हिंदू महिलाओं का जबरन सिंदूर मिटाकर, चूड़ियां तोड़कर और मतांतरण करके उन्हें दिन में पांच बार नमाज पढ़ने के लिए विवश कर रहे थे। स्वयंभू सेक्युलरवादियों का यही वर्ग पाकिस्तान के उन अहमदिया मुस्लिमों से भी सहानुभूति रखता है, जिनका भारत के रक्तरंजित विभाजन में बड़ा योगदान रहा।

जिस सीएए को विवादों में घसीटने का प्रयास हो रहा है, वह कानून तो भारत के मानवतावादी एवं बहुलतावादी सनातन डीएनए के अनुरूप ही है। इजरायली प्रतिकार में तबाह गाजा-पट्टी के मुस्लिमों को राहत-सामग्री पहुंचाना, संकटग्रस्त अफगानिस्तान को रसद आपूर्ति करना और आपदाग्रस्त तुर्की में 'आपरेशन दोस्त' से राहत-बचाव कार्य चलाना इसका जीवंत प्रमाण है। ऐसे में साझी विरासत के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति भारत की नैतिक जिम्मेदारी है। चीनी आक्रमण के बाद भारत ने तिब्बती बौद्ध अनुयायियों को ऐसी ही सुविधाएं प्रदान की थीं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी मजहबी कारणों से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देते रहे है। 1989-90 में अमेरिकी सीनेटर फ्रैंक लौटेनबर्ग के प्रयासों से अमेरिका ने सोवियत संघ और ईरान के अल्पसंख्यकों को शरण और नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया था। इस संशोधन के अंतर्गत ईरान में अल्पसंख्यक ईसाई, बहाई और यहूदियों को उनके धार्मिक उत्पीड़न पर शरण और नागरिकता दी गई। इसी तरह ब्रिटेन में 'राष्ट्रीयता और सीमा अधिनियम' के माध्यम से गुलामी और मानव तस्करी के पीड़ितों को नागरिकता और शरण देने का प्रस्ताव है। इस पृष्ठभूमि में विदेश में मजहबी कारणों से उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू-सिख अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएंगे? विभाजन के बाद भारत में जहां मुसलमानों की संख्या छह गुना से अधिक बढ़ गई है, वहीं पाकिस्तान में हिंदू-सिख आबादी 16 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत से भी कम, तो बांग्लादेश में हिंदू-बौद्ध आबादी हिस्सेदारी 28 प्रतिशत से गिरकर आठ प्रतिशत रह गई है। अफगानिस्तान में 1970 में सात लाख गैर-मुसलमान थे, जो गृहयुद्ध, मजहबी हिंसा और तालिबानी राज में घटकर अंगुलियों पर गिनने लायक बचे हैं। क्या भारत हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों का प्राकृतिक घर नहीं? इस प्रश्न का उत्तर सीएए में समाहित है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

चुनावी चंदे का चक्रव्यूह

राजीव सचान

चुनावी चंदे की पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करना जितना आसान है, ऐसी प्रक्रिया बनाना उतना ही कठिन

राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के जरिये चंदा देने की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड का जो विवरण सार्वजनिक किया, उसके अनुसार चुनावी बांड के जरिये सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वह केंद्र के साथ कई राज्यों में सत्ता में है। चंदा अन्य विरोधी दलों को भी मिला है, लेकिन वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उन्हें मिला चंदा तो जायज है, लेकिन जो भाजपा को मिला, वह नाजायज है। चुनावी बांड के जरिये चंदा देने की व्यवस्था ने दो चिंताजनक पहलू उभारे हैं। एक यह कि कई ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया, जिनके खिलाफ सीबीआइ, ईडी अथवा आयकर विभाग की जांच चल रही थी। चूंकि ऐसी कुछ कंपनियों को चंदा देने के आगे-पीछे ठेके भी मिले, इसलिए यह संदेह उभरा है कि कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में तो इन कंपनियों ने अपनी जेब नहीं ढीली की? कांग्रेस ने तो यह कहने में संकोच भी नहीं किया कि चुनावी बांड के जरिये 'चंदा दो-धंधा लो' का खेल चल रहा था। सच क्या है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जिन दलों को चुनावी बांड के जरिये चंदा मिला और जो इस तरह से चंदे के लेन-देन को गलत मानते हैं, वे उसे वापस कर दें? खैर, दूसरा चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया, जो घाटे में चल रही थीं। एक पहेली यह भी है कि चुनावी बांड से चंदा देने वालों में कुछ नामी कंपनियों के नाम नहीं दिखे। क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने किसी को चंदा दिया ही नहीं? जिन कुछ कंपनियों को लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनसे चंदा उगाही की, उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को भी चंदा दिया है। क्या उन्होंने भी चंदा उगाही की है?

चुनावी बांड के पहले चंदे की व्यवस्था पूरी तरह अपारदर्शी थी। तब ज्यादातर चंदा नकद दिया जाता था। तब दलों को 20 हजार रुपये से कम के चंदे का विवरण न बताने की छूट थी। इसके चलते कई दल यह बताते थे कि उन्हें करोड़ों का चंदा मिला तो, लेकिन वह सब 20-20 हजार रुपये से कम का यानी फुटकर ही था। कोई भी समझ सकता है कि यह सही नहीं हो सकता। पहले किसी को यह पता नहीं चलता था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। यह मानकर चला जाना चाहिए कि इसके चलते राजनीतिक दलों को अच्छा-खासा कालाधन मिलता होगा। चुनावी बांड की व्यवस्था खत्म होने के बाद से भारतीय राजनीति के फिर से कालेधन से संचालित होने की आशंका कहीं अधिक बढ़ गई है। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि जनता को यह पता चले कि किसने किसको कितना चंदा दिया, लेकिन इसकी कोई विश्वसनीय व्यवस्था बनाना आसान नहीं। इससे इन्कार नहीं कि चुनावी बांड की व्यवस्था जिस इरादे से लाई गई थी, वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज कोई यह बताने वाला नहीं कि चुनावी चंदे की नीर-क्षीर व्यवस्था क्या हो सकती है? चुनावी चंदे की साफ-सुथरी प्रक्रिया का कोई कारगर सुझाव उनके भी पास नहीं, जो चुनावी बांड के विरोध में खड़े थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं।

चुनावी बांड के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन ● प्रेट्र

चुनावी चंदे का एक तरीका यह हो सकता है कि कारोबारी अथवा कंपनियां अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत चुनाव आयोग को दें और फिर वह आयोग दलों को उन्हें मिले मत प्रतिशत के हिसाब से उनमें बांट दे, लेकिन यदि कोई अपने पसंदीदा दल को ही चंदा देना चाहे तो? कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं कि वे किसी को चंदा न देना चाहें। क्या उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा? चुनावी चंदे को लेकर यह एक सुझाव बार-बार आता है कि सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिले, लेकिन क्या इसके बाद दलों को सरकारी कोष से मिले धन से अधिक खर्च करने से रोका जा सकता है? क्या यह किसी से छिपा है कि एक बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं। वे खर्च करोड़ों में करते हैं, लेकिन कागजों में लाखों में ही दिखाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि सभी इस पर तो जोर दे रहे हैं कि चुनावी चंदे की साफ-सुथरी व्यवस्था बने, लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इसके साथ ही ऐसी भी व्यवस्था बने, जिससे कोई भी सरकार अपने किसी पसंदीदा कारोबारी या कंपनी को नियम-कानूनों में ढील देकर ठेका न दे सके और न ही अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उस पर अनुचित दबाव डाल सके। आखिर कौन नहीं जानता कि कुछ कारोबारी और कंपनियां किस तरह दल विशेष की सरकार में दिन दूनी-रात चौगुनी गति से प्रगति कर जाती हैं या फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाता है? साफ है कि समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और खोजा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड की व्यवस्था इसलिए खत्म की, क्योंकि उसने पाया कि गोपनीयता के अधिकार से सूचना का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अधिकार को खुद सुप्रीम कोर्ट कोई भाव नहीं देता और इसीलिए उच्चतर न्यायपालिका के जज अपनी संपत्ति का विवरण घोषित नहीं करते। इसे ही कहते हैं 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे।' यदि आप राहुल गांधी नहीं हैं तो शायद यह मानते होंगे कि सारे कारोबारी चोर नहीं होते। आखिर ऐसे जिन कारोबारियों ने चुनावी बांड कानून के गोपनीयता वाले प्रविधान के तहत इस भरोसे चंदा दिया होगा कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं होगा, उनका क्या दोष?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का वास्तविक अर्थ

हमारे अमूल्य जीवन का मूल्य ब्रह्मांड में उपलब्ध किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं आंका जा सकता। जीवन वास्तव में समय की पटरी पर चलने वाली एक ऐसी गाड़ी है, जिसमें गंतव्य तक पहुंचने का आनंद भी है तो कहीं गत्यावरोधकों का त्रास भी है। जीवन में सुख की चाहे कितनी ही सामग्री क्यों न हो, किंतु छोटी सी प्रतिकूल घटना भी कष्ट उत्पन्न कर देती है। किसी अपने के द्वारा जरा सा अपमानजनक प्रसंग पीड़ा दे जाता है। थोड़ी सी निंदा मन की प्रसन्नता छीन लेती है। किसी के कटु शब्द जीवन में कड़वाहट पैदा कर देते हैं।

हम सभी अपने-अपने अतीत के साए में घिरे वर्तमान को मानसिक द्वंद्वों से घसीटते हुए वक्त गुजारते हैं। जीवन को जीते कम और ढोते ज्यादा हैं। नित-प्रति बहुत कुछ अनदेखा-अनचाहा और अनहोना होता है। ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार भाव से जीना ही जिंदादिली है। इस जिंदादिली का राज है कि जो भी मिला, उसका आनंद उठाएं। जो भी कुछ अच्छा-बुरा, शुभ-अशुभ, अनुकूल-प्रतिकूल मिला है, उसे समग्रता से स्वीकार करें। अभिप्राय मात्र इतना ही है कि जीवन के समस्त क्षणों का, प्रत्येक परिस्थितियों का सदुपयोग करने की कला सीखना ही जिंदादिली से जीना है। हम जितना स्वीकार भाव की क्षमता को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन उतना ही जीवंत होता जाएगा।

यह सदैव स्मरण रहे कि सुख और दुख दोनों ही अपने नहीं हैं। हमें इनका चुनाव नहीं, अपितु दोनों को स्वीकार करना होगा। दुख हमें कमजोर बनाता है और सुख हमें बंधन में डाल देता है। प्रतिकार में दुख और स्वीकार में सुख, यह सूत्र जीवन में जिंदादिली पैदा कर सकता है। जिस दिन अप्रिय वस्तु, अनचाहा व्यक्ति और प्रतिकूल परिस्थिति का सहयोग और वांछित वस्तु, प्रिय व्यक्ति एवं अनुकूल परिस्थितियों का वियोग, इन दोनों को प्रसन्नता से स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन को वास्तविक अर्थ मिल जाएगा।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

होली का संदेश समझने की जरूरत

'रंग और उमंग का पर्व' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी पढ़ी। हमारे देश में रंगों का जो त्योहार मनाया जाता है, ऐसा त्योहार दुनिया के शायद ही किसी देश में मनाया जाता हो। हमारे देश में भी यह त्योहार सभी वर्गों के लोग मिल-जुलकर मनाते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ बहुत से लोगों की रुचि अन्य त्योहारों की तरह अब होली में भी कम हो गई है। होली के रंग भी अब फीके से पड़ने लगे हैं। आधुनिक जीवनशैली और स्मार्टफोन की बढ़ती लत का असर इस त्योहार पर भी पड़ता दिख रहा है। जबकि यह त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन के साथ ही दूसरों की जिंदगी में भी खुशी के रंग भरने की कोशिश करनी चाहिए। हम किसी भी तरह से दूसरों के मददगार बनते हैं तो इससे हमें भी एक अलौकिक सुख की अनुभूति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। हमारे देश में हमेशा खुशियों के रंग बिखरते रहें, इसके लिए हमेशा देश के हित में काम करने चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे देश में खुशियों का रंग फीका पड़ जाए।

raju09023693142@gmail.com

चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहमियत

कभी किसी ने कहा था कि चुनाव एक ऐसा काम है, जिसे हम भारतीय बहुत अच्छी तरह से करते है। चाहे लोकसभा, विधानसभा या पंचायती राज के चुनाव क्यों नहीं हो। चुनाव इतने बहुरंगी और रोमांचक कहीं नहीं होते है, जितने उत्तर प्रदेश में। इस राज्य में खासी गर्मी रहती है। एनडीए के 68 के टिकट का आवंटन होने के बाद देश की नजर उत्तर प्रदेश के गुणा-भाग पर टिकी हुई है। लोकसभा की 80 सीटों वाले प्रदेश से ही दिल्ली की राजगद्दी मिलती है। इस बार राजनीतिक मंथन शुरू हो चुका है। भाजपा का दावा है और प्रयास रहेगा कि 80 में से 80 सीट भाजपा ले जाएगी। भाजपा के लिए ये संभव है। जबकि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि शायद खाता भी न खुल पाए। मुलायम सिंह यादव व मायावती की राजनीतिक महत्वकांक्षाओं में प्रधानमंत्री का पद भी शामिल था। लेकिन सभी योजनाओ पर पानी फिर गया। बिहार में नीतीश और लालू ने 1990 से प्रधानमंत्री बनने के लिए कमर कसी थी। लेकिन सपने साकार नहीं हुए। कांगेस और केजरीवाल जैसे नेता मन में भ्रष्टाचार लेकर ही राजनीति में आए। जिसके चलते अरबों के मालिक बन सके। देश को लूटने वाले और नैतिकता को कलंकित करने वाले नेताओं को कभी वोट न दे। गांधी-नेहरू खानदान वाले राहुल गांधी ने इस उम्मीद से अपने पिता-दादी और परदादा के योगदान की दुहाई दी कि शायद कांग्रेस को खोई जमीन मिल जाए। लेकिन नेहरू-गांधी खानदान की राजनीतिक यात्रा शायद पूर्ण होने की कगार पर है। राज्य सहित देश में कांग्रेस के पांव उखड़ चूके है। राहुल जहां गए, भीड़ खींचने में कामयाब हुए, इसका खास कारण गांधी परिवार के चिराग को नजदीक से देखने की लालसा जगी थी। लेकिन लोगो की नजदीकियां बढ़ीं तो पता चला कि साहबजादे प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस की उपलब्धि शून्य रही है। भाजपा विकास की ऊंचाइयों को छू रही है तो राहुल मूल्यहीन मुद्दे से लोगों को नाराज कर रहे हैं।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

अमर्यादित मोहब्बत की दुकान

कांग्रेस नेत्री के हैंडल से जिस तरह मंडी (हिमाचल प्रदेश) लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत के लिए असहनीय, अमर्यादित व बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। यह सर्वथा निंदनीय ही नहीं वरन कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक लाइन मोहब्बत की दुकान और महिला सशक्तिकरण की बुनियाद पर सवालिया निशान ज्यादा उठाते हैं। इस विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग का संज्ञान लेना स्वागत योग्य है। वहीं, वर्तमान परिदृश्य से लगता है कि कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में माहिर हो चुकी है। कभी कांग्रेस पार्टी को वाराणसी में युवा वर्ग शराबी नजर आता हैं। कभी देश का प्रधानमंत्री पनौती नजर आता है। कभी मोदी के परिवार को लेकर तंज कसा जाता है। लेकिन बंगाल के संदेशखाली में दलित महिलाओं पर अत्याचारों सहित दुष्कर्म की पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं पर चुप्पी साधना यकीनन मीठा-मीठा गप-गप और कड़वा-कड़वा थू-थू को ही चरितार्थ करता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मासूम बच्चों की हृदय विदारक हत्या पर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तुष्टिकरण की छिछली राजनीति की, लेकिन इसी विषय पर लगा जैसे कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया। इस तरह बदायूं और संदेशखाली राजनीतिक पर्यटन स्थल की सूची से बाहर हो। 31 मार्च को दिल्ली में होने वाली आइएनडीआइए की रैली से कितना लाभ होता है, यह समय के गर्भ में है।

दीपक गौतम, सोनीपत

X पोस्ट

कोई माने या न माने, लेकिन नवीन जिंदल का कांग्रेस छोड़कर जाना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।

पंकज शर्मा@Pankaj_Sharma

कंगना रनोट बहुत स्पष्टवादी हैं। वह बिना लाग-लपेट बोलती हैं। ऐसे लोग राजनीति में कम ही मिलते हैं!

प्रभाकर मिश्रा@PMishra_Journo

पंजाब से सांसद और बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। वजह यही बताई जा रही है कि न आलाकमान तक पहुंच, न सुनवाई और न किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई। कांग्रेस की दशा-दिशा को देखते हुए चुनाव जीतने की कोई गारंटी भी नहीं थी। अभिषेक उपाध्याय@upadhyayabhii

हिमाचल में भाजपा ने कांग्रेस के सभी छह बागियों को विधानसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। अब इनसे चुनाव में हारे हुए भाजपा के प्रत्याशी इन्हीं का प्रचार करेंगे। राजनीति से ज्यादा मजेदार कुछ हो तो बताओ।

अरविंद चोटिया@arvindchotia

भाजपा में बाहरी लोगों के आने से कोई समस्या नहीं है। पार्टी बड़ी होती है तो लोग जुड़ते ही हैं, लेकिन ऐसे लोग जो भाजपा का मूल चरित्र ही समाप्त कर देने पर तुले हैं, उनका बढ़ते जाना खतरनाक है। हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

जनपथ

महिला नेता ही करे महिला का उपहास,
नई गिरावट का करे तब समाज अहसास।
तब समाज अहसास 'लड़ेगी कैसे लड़की',
जब देवियां प्रबुद्ध दिखेंगी उस पर भड़की!
महिला का कर्तव्य नहीं है क्या ये पहला,
करे स्वयं सम्मान दिखे जब उसको महिला!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय संपादक-प्रदीप कुमार शुक्ल*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 34 अंक 252

****

उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। - सुभाष चंद्र बोस

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर कथित अभद्र टिप्पणी से उपजा विवाद इसका ताजा उदाहरण है कि राजनीति में शालीनता के स्तर कैसे पार किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों को शायद सोशल मीडिया ने असीमित मैदान दे दिया है।

मर्यादा किसे चाहिए?

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा उम्मीदवार व अभिनेत्री कंगना रनौत पर कथित तौर पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला इसका ताजा उदाहरण है कि व्यक्ति और विचारधारा के विरोध किस सीमा तक व्यक्तिगत और सीमाहीन हो चुके हैं। सोशल मीडिया कलुष फैलाने का खुला मैदान दे देता है और समर्थक-विरोधियों की तकरार मूल प्रश्न से हटकर मर्यादाहीन टिप्पणियों पर चली जाती है। मामला तूल पकड़ने पर सुप्रिया श्रीनेत ने बेशक पोस्ट डिलीट कर दी हो और सफाई में वह अपने सोशल मीडिया खाते के किसी और द्वारा इस्तेमाल होने की बात कर रही हों, लेकिन समर्थकों द्वारा उनके बचाव में जो दलीलें दी जा रही हैं, वे भी कोई कम हैरान करने वाली नहीं हैं। जो समर्थक अतीत के उदाहरणों से श्रीनेत की कथित टिप्पणी का बचाव कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं पता है कि दो गलत से एक सही की सिद्धि नहीं होती, बल्कि इससे गलती करने वालों की मनःस्थिति का ही पता चलता है। संतोष की बात है कि इस टिप्पणी पर कंगना रनौत की प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा संतुलित और संयमित दिखी है। उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत अपनी राजनीतिक विचारधारा के चलते लंबे समय से विरोधियों के निशाने पर रही हैं। कुछ वर्ष पहले जब मुंबई में उनके दफ्तर के एक हिस्से को अवैध बताते हुए बीएमसी ने गिरा दिया था, तब भी तत्कालीन सरकार के नेताओं और राजनीतिक विरोधियों ने उनके बारे में काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। खिल्ली उड़ाने का यह सिलसिला नया नहीं है। देश की राजनीति में महिलाओं पर शर्मनाक टिप्पणी करने वाले नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। राजनीतिक विरोध करते-करते अचानक व्यक्तिगत कुंठाएं सार्वजनिक तौर पर सामने आ जाती हैं। हेमा मालिनी, जयाप्रदा से लेकर लंबी सूची है, जिन्होंने इन टिप्पणियों को झेला है। और अब तो, सोशल मीडिया में तर्कवीर और ट्रोल में फर्क करना मुश्किल हो

जाता है। बावजूद इसके, कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों से तो यह उम्मीद रहती ही है कि वे सार्वजनिक विमर्श का स्तर ऊपर उठाएं, न कि मर्यादाहीन बातों को हवा दें। बात सिर्फ महिलाओं को लेकर मर्यादापूर्ण आचरण की नहीं है, सार्वजनिक जीवन की सामान्य मर्यादाएं भी होती हैं, जिनका ध्यान रखने की अपेक्षा राजनीतिक दलों से तो की ही जानी चाहिए। यदि सब एक-दूसरे पर दोषारोपण को ही अंतिम मान लेंगे, तो मन के कलुष और मर्यादाहीन व्यक्तिगत टिप्पणियों से सार्वजनिक जीवन की शुचिता को बचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा?

इस्लामी पड़ोसियों से परेशान पाकिस्तान

पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी, जो दशकों से मित्र थे, अचानक शत्रु बन गए। ईरान और अफगानिस्तान से हाल ही में पाकिस्तान की झड़प हो चुकी है, जबकि पिछले कुछ वर्षों से भारत-पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम लागू करने का निर्णय लिया, जिसके कारण कई वर्षों से सीमा पर माहौल शांतिपूर्ण है।

लोक ज्ञान कहता है कि कोई भी देश अपने पड़ोसियों को नहीं चुन सकता, उसे अपने पड़ोसियों के साथ सह-अस्तित्व में रहना होता है। वर्ष 2023 में पाकिस्तान के कुछ पड़ोसी, जो दशकों से मित्र थे, अचानक शत्रु बन गए, जबकि जिसे उसने हमेशा अपना दुश्मन माना, वह अच्छा मित्र बन सकता है। पाकिस्तान चार देशों से घिरा है, जिनमें से दो-ईरान और अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क हैं। बाकी दो देश हैं-उसका सबसे करीबी सहयोगी चीन और उसके पूर्व में भारत, जिसके साथ नियंत्रण रेखा पर लगातार झड़पें होती रहती हैं। भारत की सीमा पर दोनों ओर से हमले होते रहे हैं, जिससे दोनों तरफ के कश्मीरियों और उनकी संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों से दोनों देशों ने नियंत्रण रेखा पर युद्धविराम लागू करने का निर्णय लिया। युद्धविराम संधि के कारण कई वर्षों से माहौल शांतिपूर्ण है।

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

पाकिस्तान तब हैरान रह गया, जब कुछ हफ्ते पहले ईरान ने बलूचिस्तान के अंदरूनी इलाकों पर बमबारी की। जिन इलाकों पर बमबारी की गई, वे शहरों एवं कस्बों से बहुत दूर रेतीले रेगिस्तान और पहाड़ों में स्थित थे। ईरान ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, बल्कि कुछ ईरान-विरोधी गुटों के खिलाफ था, जो पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ आतंकवादी हमले करते थे। अगले ही दिन, पाकिस्तानी वायु सेना ने पाकिस्तान-ईरान सीमा पर हमला किया, जिसमें कई लोग हताहत हुए। पाकिस्तान ने कहा कि उसने ईरान के अंदर उन आतंकवादी शिविरों पर हमला किया, जिनका इस्तेमाल ये आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने के लिए करते थे।

वैसे इस वाकये से हैरान ईरान ने अपनी ही सरकार के भीतर कुछ मजबूत तत्वों को दोषी ठहराया, जिन्होंने ईरान की घरेलू समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान को ईरान की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि वह सीमा

के दोनों ओर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना चाहता है और स्थिति नियंत्रण में प्रतीत होती है। जैसा कि एक विश्लेषक ने कहा, यह न केवल दोनों पड़ोसियों के लिए अच्छा है, बल्कि इस क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। स्थिति को और अधिक बिगड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए विनाशकारी होगा।

उसके बाद अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का विवाद बढ़ गया, क्योंकि पाकिस्तान के उत्तरी इलाके वजीरिस्तान में तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने आतंकवादी हमला किया, जिसमें सेना के दो अधिकारी मारे गए और कई घायल हो गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर हुए इस हमले को गंभीरता से लिया जाएगा और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। अगली सुबह पाकिस्तानी वायु सेना के बमवर्षकों ने अफगानिस्तान के भीतर हमला किया और टीटीपी के कुछ शिविरों को नष्ट कर दिया। हालांकि फिलहाल वहां शांति और सन्नाटा है।

जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था, तो पाकिस्तान ने अंतरिम सरकार का स्वागत किया था। उसे उम्मीद थी कि एक बार नई सरकार काम करने लगेगी और कानून-व्यवस्था में थोड़ा सुधार होगा, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि टीटीपी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की धरती पर आतंकी हमले न करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने यह संदेश देने के लिए हर कूटनीतिक उपायों का इस्तेमाल किया। कई उच्च स्तरीय सैन्य और असैन्य प्रतिनिधिमंडल काबुल गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि पाकिस्तान को किन बातों पर आपत्ति है और वह अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवादी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पर अफगानिस्तान ने इन चेतावनियों को नजरंदाज कर दिया है।

अंततः पाकिस्तान ने हजारों अवैध अफगान शरणार्थियों एवं प्रवासियों को वापस भेज दिया, जिससे काबुल नाराज हो गया। फिर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडीकोटल सीमा और बलूचिस्तान में चमन सीमा पर ट्रकों को गुजरने की अनुमति नहीं देते हुए व्यापार बंद कर दिया। तालिबान सरकार ने इसकी शिकायत की और आश्वासन दिया कि वह टीटीपी को नियंत्रित करेगी। फिलहाल टीटीपी के लगभग 6,000 आतंकवादी अपने परिवारों के साथ अफगानिस्तान में शरण लिए हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को तब सैन्य अभियान चलाकर पाकिस्तान से बाहर कर दिया गया था, जब वे सख्त शरिया नियमों और पाकिस्तान के और भी इस्लामीकरण की मांग करने लगे।

जैसा कि एक विश्लेषक का कहना है, 'टीटीपी वस्तुतः अपने अफगान समकक्ष अफगान तालिबान का विस्तार बन गया है और हैरानी की बात नहीं कि अमेरिकी युद्ध की समाप्ति और अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में भारी वृद्धि हुई है।' टीटीपी के ताजा हमलों के बाद पाकिस्तान ने आतंकी हमलों के लिए सीधे तौर पर तालिबान शासन को जिम्मेदार ठहराया है। उत्तरी वजीरिस्तान में ताजा आतंकवादी हमले के बाद आईएसपीआर ने एक बयान में कहा, 'अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार न केवल आतंकवादियों को हथियार दे रही है, बल्कि अन्य आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित पनाहगाह भी प्रदान कर रही है और साथ ही पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में भी शामिल है।'

ईरान और अफगानिस्तान, दोनों ने पाकिस्तानी वायु सेना की ताकत देखी है। पाकिस्तान की तुलना में ईरान की वायु सेना छोटी और कम प्रभावी है और वह इस बात को जानती है। अफगानिस्तान के पास वायु सेना है ही नहीं, लेकिन जवाबी कार्रवाई के तौर पर वह सीमा पार भारी जमीनी हथियारों का इस्तेमाल करेगा।

पाकिस्तान में ऐसी आवाजें जोर-शोर से उठ रही हैं कि अफगान तालिबान के साथ और अधिक राजनयिक जुड़ाव की जरूरत है, क्योंकि दोनों पक्षों के ऐसे सैन्य अभियानों से क्षेत्रीय शांति पर भी गंभीर असर पड़ेगा। टीटीपी पर लगाम लगाने या उसे बाहर निकालने के लिए काबुल पर दबाव बनाना होगा, जो द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट का कारण है। साथ ही, पाकिस्तान चीन जैसे दोस्तों और मजबूत सहयोगियों से उम्मीद करता है कि वे उसकी शिकायतों को अफगानिस्तान तक पहुंचाएं, जो वहां भारी निवेश कर रहे हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

दादा भगवान

अकेलापन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक धारणाओं के कारण होता है। ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

आत्म-साक्षात्कार से आनंद की अनुभूति होती है

अकेलापन *अकेला होना नहीं है। अकेलेपन का मतलब है कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। जब आप भीड़ के बीच होते हैं, तब भी यह अनुभति हो सकती है। अकेलेपन का अर्थ है कि आप स्वयं से, दूसरों से और समाज से खुद को अलग महसूस करते हैं। 'मैं अकेला हूं' की अनुभति एक ऑक्टोपस की तरह है, जो किसी को नकारात्मकता के अंधेरे आवरण में जकड़ लेती है। यह कड़वी अनुभूति आमतौर पर कठिन समय में अधिक अनुभव की जाती है, जैसे कि कोविड-19 महामारी और युद्ध के दौरान! अकेलापन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक धारणाओं के कारण होता है। ज्यादातर ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि समाज में कोई भी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सच यह है कि वह खुद को स्वीकार नहीं करता, जिस कारण खुद के प्रति नकारात्मकता की भावना पैदा होती है। यह खुद का सम्मान न करना, दूसरों की अपेक्षाओं के कारण खुद पर तनाव और दबाव डालने का परिणाम है। जब हम दूसरों के सोचने के तरीके के साथ सामंजस्य बिठाने में विफल होते हैं, तो भीतर से निराश महसूस करते हैं। भले ही हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर पाते। यह आंतरिक अक्षमता हमें नकारात्मक विचारों की ओर ले जाती है।*

अकेलापन अनुभव करने का मूल कारण अपने बारे में सच्ची समझ की कमी है। कुछ लोग अपने दुख को भूलने के लिए दूसरे कामों में खुद को उलझा लेते हैं। हालांकि, यह केवल थोड़ी देर का विकर्षण है, जो व्यक्ति को व्यस्त महसूस कराता है, अकेलेपन से तात्कालिक राहत प्रदान करता है। उसके बाद अकेलेपन की वही अनुभूति फिर से सामने आती है। इसका अर्थ यह है कि हम अकेलेपन की इस अनुभूति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे दूर भाग रहे हैं। जबकि अकेलेपन की अनुभूति को स्वीकार करना इसे दूर करने का पहला कदम है। तभी हमें इससे बाहर निकलने का उपाय मिल सकता है। नकारात्मक विचार हमें तभी तक वश में रखते हैं, जब तक हम उन्हें अपने भीतर रहने देते हैं! नकारात्मक विचारों को नहीं सुनने से हमारा निश्चय और आत्मविश्वास बेहतर होता है। महान लोगों की जीवनी या आत्मकथा पढ़कर हम सही समझ और सकारात्मकता, दोनों प्राप्त कर सकते हैं।

खुद के बारे में गलतफहमी के साथ-साथ अपनी अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए आत्म-साक्षात्कार जरूरी है। जब हमें किसी आत्मज्ञानी पुरुष से पता चलता है कि हम कौन हैं, तब गहरा अंधेरा आंतरिक शांति में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार, आत्म-साक्षात्कार अकेलेपन को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। भीतर से आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है और आत्म-साक्षात्कार के बाद गलत या नकारात्मक भावनाओं से लड़ने की शक्ति दोगुनी हो जाती है।

संतोष का आधार...

सूत्र

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो विभिन्न समाज में रहते हुए विकसित हुआ है। सामाजिक संबंध आपसी विकास और संतोष का आधार बनते हैं। इसलिए अकेलापन महसूस होने पर व्यक्ति निराशा और नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। लेकिन आत्म-साक्षात्कार से हम अपनी वास्तविक क्षमता को जानकर नकारात्मकता से लड़ सकते हैं।

दूसरा पहलू

जिन भौगोलिक क्षेत्रों में सौ साल से ज्यादा उम्र के स्वस्थ लोग काफी होते हैं, उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है।

ब्लू जोन की जीवन शैली में छिपा लंबी उम्र का राज

हमेशा जवान बने रहने और लंबी उम्र हासिल करने की चाहत रखने वालों के लिए अरबों पाउंड का उद्योग दुनिया भर में चल रहा है, जिसमें बुढ़ापा रोकने वाले उत्पादों से लेकर पूरक आहार तक बनाए और बेचे जा रहे हैं। बीसवीं सदी के ब्रिटेन में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 46 साल थी, जो आज 82 साल के आसपास है। जाहिर है, पहले के मुकाबले हम आज लंबा जीवन जी रहे हैं और संभवतः इसका कारण चिकित्सा विज्ञान की तरक्की और रहन-सहन व कामकाज की स्थितियों में आया सुधार है।

जस्टिन रॉबर्ट्स

लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुरानी और समय के साथ बढ़ती जाने वाली बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। दिल की बीमारियां इनमें सबसे ऊपर हैं। इसलिए जब हम यह सोच रहे हैं कि लंबा जीवन कैसे जिएं, तो हमारी दिलचस्पी यह सोचने में होनी चाहिए कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रहें? दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहों की खोज की गई है, जहां सौ साल की आयु पूरी कर चुके शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ लोगों का अनुपात कहीं ज्यादा है। इटली के सार्डिनिया द्वीप में ऐसे भौगोलिक स्थानों की पहचान के लिए अध्ययन किया गया, जहां सौ साल से ज्यादा उम्र के लोग काफी हैं। इन जगहों को 'ब्लू जोन' कहा जाता है। इन जगहों में अब सार्डिनिया के साथ-साथ इकारिया (ग्रीस), ओकिनावा (जापान), निकोया (कोस्टारिका) और लोमा लिंडा (कैलिफोर्निया) भी शामिल हो गए हैं।

हालांकि अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि दीर्घायु में आनुवंशिकता केवल 20 से 25 प्रतिशत तक ही निर्णायक होती है। दिलचस्प यह भी है कि सब्जियां, फल, फलियों जैसे खाद्यों (प्लांट फूड) से भरपूर आहार इन सभी इलाकों में अच्छा-खासा मिलता है। जैसे-लोमा लिंडा के लोग शाकाहारी हैं। ओकिनावा में लंबी उम्र के लोग बैंगनी शकरकंद, सोया और हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा करते हैं। सार्डिनिया में स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली सब्जियों, पारंपरिक खाद्य पदार्थों, शहद और चीज आदि के अलावा मांस और मछली का सेवन संतुलित रूप में ही किया जाता है। जबकि कुछ ब्लू जोन ऐसे हैं, जहां लोग जैतून का तेल, वाइन, चाय आदि का सेवन करते हैं, क्योंकि इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में यह विचार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि लंबी उम्र पाने वाली आबादी क्या नहीं कर रही है, जितना यह विचार करना कि लंबी उम्र के लिए ये लोग क्या करते हैं।

-साथ में जोसेफ लिलिज एवं मार्क कॉर्टनेज *(द कन्वर्सेशन)*

अब सार्डिनिया के साथ-साथ इकारिया, ओकिनावा, निकोया और लोमा लिंडा जैसे क्षेत्र भी ब्लू जोन में शामिल हो गए हैं। इन क्षेत्रों में प्लांट फूड से भरपूर आहार काफी मिलते हैं।

कुछ ब्लू जोन ऐसे हैं, जहां लोग संतुलित पारंपरिक खाद्य के अलावा जैतून का तेल, वाइन, चाय आदि का सेवन करते हैं, क्योंकि इनमें एंटी- ऑक्सीडेंट होते हैं।

आंकड़े

शीत भंडारगृह

फलों, सब्जियों की बर्बादी रोकने के लिए शीत भंडारगृह (कोल्ड स्टोरेज) जरूरी होते हैं। देश में सबसे ज्यादा शीत भंडारगृह उत्तर प्रदेश में हैं।

स्रोत : कृषि मंत्रालय

सच्चा संत वही है, जो अपने को तुच्छ समझता है। भगवान के भजन का तरीका बताता है। जो अपनी पूजा करवाता है, वह ईश्वर तो छोड़ो, संत भी नहीं है।

सच्चा संत कौन

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

देवराहा बाबा हमेशा लोगों को सदाचार का पालन करने, अपने कर्तव्यों को निभाने तथा हर क्षण भगवान को याद रखने की प्रेरणा देते थे। एक बार प्रयागराज के कुछ भक्तजन वृंदावन आए, तो उनके दर्शन के लिए पहुंचे। देवराहा बाबा ने पूछा, 'प्रतिदिन भगवान की पूजा व उनके नाम का जाप तो चल रहा है न?'

उनमें से एक ने कहा, 'बाबा, हम पहले भगवान की पूजा करते थे, पर अब हमने एक संत को गुरु बना लिया है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों तक पूजा करने के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। इसलिए अब हमारे दर्शन कर समझ लो कि ईश्वर के दर्शन कर रहे हो। मेरे नाम का जाप करो। उनके आदेश से ही हमने राम-कृष्ण की पूजा छोड़ दी। अब उन्हीं के नाम का कीर्तन करते हैं।'

यह सुनकर देवराहा बाबा बोले, 'बेटा, तुम स्वयंभू अवतार के झांसे में आकर भटक गए हो। जो संत भगवान की पूजा छुड़वाकर अपनी पूजा कराता है और अपने नाम का मंत्र देता है, वह भगवान तो छोड़ो, संत भी नहीं है। सच्चा संत वही है, जो अपने को तुच्छ समझता है। भगवान के भजन का तरीका बताता है।'

देवराहा बाबा के वचन सुनकर उनकी आंखें खुल गईं।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 25 जनवरी, 1957

सुहरावर्दी ने की अमेरिका की खुशामद

सुहरवर्दी द्वारा अमरीका की खुशामद

अंकारा, १४ जनवरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री सुहरवर्दी ने कल यहां पर कहा कि वह चाहते हैं कि अमरीका बगदाद पैक्ट में शामिल हो जाय। इससे यह पैक्ट में शामिल होगा। इससे यह पैक्ट और मजबूत ही हो जायगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह कह नहीं सकते कि अमरीका हमारी प्रार्थना स्वीकार भी करेगा अथवा नहीं।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सुहरावर्दी ने अमेरिका की खुशामद करते हुए कहा कि अमेरिका भी बगदाद पैक्ट में शामिल हो जाए, तो यह पैक्ट मजबूत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी वह यह नहीं कह सकते कि अमेरिका इसे स्वीकार करेगा या नहीं।

चीन है कि बाज नहीं आ रहा

चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उसे अलग-थलग करने की कोशिश करनी चाहिए।

शिवदान सिंह — **पड़ोस**

पिछले कुछ समय से चीन बार-बार भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत के नाम से पुकार कर भारत के साथ तनाव की स्थिति पैदा करना चाह रहा है। हालांकि भारत सरकार ने बार-बार इसका खंडन करते हुए दुनिया को बताया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग है। अमेरिका ने भी कड़े शब्दों में चीन को चेताते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चीन अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है।

बीते आठ मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क संचार को बेहतर बनाने के लिए वहां पर सेला सुरंग मार्ग का उद्घाटन किया था। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए चीन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह दक्षिणी तिब्बत का क्षेत्र है।

चीन के इस दावे का भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कड़े शब्दों में खंडन किया है और

अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को दोहराया है।

कहने को तो चीन में कम्युनिस्ट शासन है, परंतु वास्तव में चीन में शी जिनपिंग की सरकार अब भी सामंतशाही प्रणाली की तरह काम कर रही है, जिसके कारण चीन की जनता त्रस्त है और वहां पर चारों तरफ तनाव देखने को मिलता है।

अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन ने पड़ोसी देशों की भूमि पर कब्जा करना शुरू किया और 1951 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसी नीति के तहत चीन ने अपने 16 पड़ोसी देशों की भूमियों पर अवैध कब्जे किए हैं।

जब भी हमारी सरकार अरुणाचल प्रदेश में कोई भी विकास कार्य करती है, चीन आपत्ति जताने लगता है। लेकिन इस बार भारत के दावे की पुष्टि अमेरिका जैसी महाशक्ति देश ने भी की है और बहुत से पश्चिमी देश भी भारत के पक्ष में हैं। चीन और भारत के बीच में 3,488 किलोमीटर की सीमा है, जिनमें 1,597 किलोमीटर पूर्वी लद्दाख, 544 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, 220 किलोमीटर सिक्किम तथा 1,126 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है! अरुणाचल की सीमा का अधिकांश भाग तिब्बत से सटा हुआ है! चीन के साथ लंबे समय से हमारा सीमा विवाद चल रहा है, जिसे चीन सुलझाना नहीं चाह रहा है।

इसी के चलते चीन ने अक्तूबर 1962 में भारत पर हमला कर दिया, जिसके लिए भारतीय सेना तैयार न थी। नतीजतन भारत के अक्साई चिन क्षेत्र में 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन ने अवैध कब्जा कर लिया, जिस पर वह आज तक कायम है! इसके बाद सिक्किम के नाथुला पर 1967 में चीन ने हमला किया, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिर 1986 में अरुणाचल के सोमद्रोंचू नाम के क्षेत्र में चीन ने एक हेलीपैड बनाने की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया! इसके बाद भारत सरकार ने इस पूरे क्षेत्र में सड़क और पुलों का निर्माण किया, ताकि सेना के टैंक सीमा तक पहुंच सकें!

सोमद्रोंचू की झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए वार्ताएं शुरू हुईं और 1993 एवं 1996 में चीन के साथ सीमाओं पर शांति बहाली के लिए समझौते किए गए! इन समझौतों में यह तय किया गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास दोनों देशों के सैनिक बिना हथियारों के ही निगरानी करेंगे! लेकिन चीन बार-बार इसका उल्लंघन करता रहा है! हालांकि भारत ने चीन से लगती सीमा क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारी मजबूत की है और हवाई पट्टी, सड़क एवं पुलों का निर्माण किया है।

दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड गठबंधन किया है। चीन भली-भांति भारत की तैयारी के बारे में जान चुका है, फिर भी वह समय-समय पर भारत से उलझने से बाज नहीं आ रहा है। जब तक चीन का कब्जा तिब्बत पर बना रहेगा, तब तक वह पूरे दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए खतरा बना रहेगा।

इसलिए भारत को मजबूती से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत पर चीन के गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए! चीन को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने से उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, जिसके दम पर वह एशियाई देशों को अपनी कर्ज नीति के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने पर ही चीन की आक्रामक विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाया जा सकता है।

Times/AllNewsEpaper.com

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

कागजी फरमान ही न बने आदर्श आचार संहिता

चुनावों के दौर में राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और राजनेताओं से यह अपेक्षा हमेशा की जाती है कि वे कानून के दायरे में रहकर प्रचार में जुटेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं को लेकर हर बार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू होती रही है। चुनाव आयोग ने इस बार स्टार प्रचारकों की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने और चुनाव चिह्न जब्त करने जैसी सख्ती अमल में लाने की चेतावनी दी है। चुनाव आयोग इस तरह का सख्त फैसला कितनी आसानी से ले पाएगा यह कहना मुश्किल है, फिर भी आयोग की इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए।

आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में चुनाव आयोग अब तक संबंधित व्यक्तियों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को नोटिस देता रहा है। लेकिन राजनीतिक दल की मान्यता खत्म करने जैसी सख्ती ऐसे मामलों में पहले कभी दिखी नहीं। वैसे भी आयोग को कमजोर नख-दंतों के कारण समय-समय पर आलोचना का शिकार होना पड़ता है। लम्बे समय से यह मांग की जाती रही है कि आदर्श आचार संहिता सिर्फ कागजी फरमान तक ही नहीं होना चाहिए बल्कि चुनाव आयोग को सख्त फैसले भी करने चाहिए। आचार संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि जाति व सम्प्रदाय के आधार पर वोट देने की अपील किसी भी स्तर पर नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा उल्लंघन प्रचार में इसी शर्त का होता दिखता है। जब राजनीतिक दल जाति व समुदाय के आधार पर टिकट देने में पीछे नहीं रहते तो फिर इसी के नाम पर वोट मांगने वाले भला क्यों पीछे रहने लगें? जहां तक बात स्टार प्रचारकों की है, राजनीतिक दल सोच-समझ कर अपने स्टार प्रचारक तय करते हैं। ऐसे में इनसे उम्मीद भी की जाती है कि वे सभाओं में संबोधन के दौरान सियासी मर्यादाओं का पालन करेंगे। लेकिन जब सियासी बयानबाजी एक-दूसरे को नीचा दिखाने के स्तर पर आने लगे तो फिर आयोग के ऐसे फैसलों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। राजनीतिक रूप से दुष्प्रचार का बड़ा जरिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी बनते जा रहे हैं। आयोग को निगाहें चौकस रखनी ही होंगी।

राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने व चुनाव चिह्न जब्त करने जैसी सख्ती हो तो उसका आधार भी मजबूत होना चाहिए। किसी पार्टी के स्टार प्रचारक को प्रतिद्वंद्वी पार्टी की तरफ से प्रलोभन देकर आचार संहिता के विपरीत कृत्य करने के लिए कहने के खतरे भी कम नहीं हैं। वैसे भी अब तक के अनुभव बताते हैं कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश जितने सख्त दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा कमजोरी इनकी पालना के वक्त नजर आती है।

जम्मू-कश्मीर में सबसे कम मतदान हुआ

जम्मू और कश्मीर राज्य में वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में सबसे कम 44.97 प्रतिशत मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान लक्षद्वीप में 85.21 प्रतिशत हुआ।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

लोकसभा चुनाव 2024

कांग्रेस के 148 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई

पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 148 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। कांग्रेस ने देशभर में कुल 421 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। बसपा के सबसे ज्यादा 345 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी।

उत्तर प्रदेश भाजपा के समक्ष बुंदेलखंड की सभी सीटें बचाने की चुनौती

अलग राज्य का सपना पूरा करने की आस लिए मतदाता करेंगे वोट

पत्रिका LIVE चुनाव मैदान से

कानपुर
डॉ. संजीव मिश्र

उत्तरप्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, पर बदले में उसे उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलता। अलग राज्य से लेकर भरपूर पानी तक के तमाम टूटते सपनों के बीच एक बार फिर बुंदेलखंड बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देने की तैयारी कर रहा है।

बुंदेलखंड की चर्चा होते ही बेरोजगारी, जल संकट और पलायन सबसे पहले याद आता है। उत्तरप्रदेश में कानपुर से झांसी और महोबा-चित्रकूट तक वृहद बुंदेलखंड की दस लोकसभा सीटों में से सभी सीटों पर इस समय भाजपा काबिज है। भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती इन सीटों को बचाना ही है। पार्टी ने दस में से नौ सीटों पर अपने मौजूदा सांसदों को ही टिकट दिया है, सिर्फ कानपुर के टिकट की घोषणा होनी अभी बाकी है।

कांग्रेस-सपा गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से कानपुर और झांसी सीटें आई हैं, तो समाजवादी पार्टी जालौन, हमीरपुर-महोबा, बांदा-चित्रकूट, फतेहपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद व अकबरपुर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा-बसपा के बीच गठबंधन था और इसका सीधा मुकाबला भाजपा से था। इस बार यह लड़ाई बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ सीटों पर तो त्रिकोणात्मक संघर्ष होने की भी उम्मीद है।

विन्ध्य पर्वत पर स्थित कालिंजर दुर्ग अपराजेय दुर्गों में से एक है।

पक्ष-विपक्ष के दावे

विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी और किसानों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। बेरोजगार युवा परेशान हैं। वहीं भाजपा के नेता बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर के साथ विकास और विरासत के मसले पर जनता से वोट मांग रहे हैं। विपक्ष कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है तो भाजपा क्षेत्र से डकैती उन्मूलन का दावा भी कर रही है।

गगरी न फूटै ...

बुंदेलखंड में जल संकट का आलम यह रहा है कि यहां मालगाड़ियों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ती थी। एक क्षेत्रीय लोकोक्ति खूब चर्चित रही है, 'गगरी न फूटै, खसम मरि जाए' यानी पानी इतना कम है कि एक बार पति की मौत भले ही हो जाए, पर पानी का घड़ा न फूटे। भाजपा जल संकट दूर कर घर-घर जल पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष अब भी जल संकट की भयावहता की बात कर रहा है। इस चुनाव में भी यह मसला तेजी से उठने की उम्मीद है।

चुनावी मुद्दों की कमी नहीं

अलग राज्य, जल संकट और पलायन का मसला खुलकर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2007 में यह प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेज चुकी है। भाजपा ने भी अलग बुंदेलखंड राज्य का वादा किया था। प्रतिभा पलायन का मसला भी है।

चुनावी चटकारा

पहले लगाए आरोप, अब करेंगे सम्मान

राजस्थान में भाजपा के एक पूर्व विधायक ने लोकसभा के टिकट के लिए कांग्रेस ज्वॉइन कर ली है। इन्होंने भाजपा में रहते हुए तीन माह पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। नई पार्टी में जाने की बधाई देने घर आए कार्यकर्ता ने उनसे पूछ लिया कि अब उनका सामना कैसे करेंगे जिनके लिए अभद्र बातें बोल रहे थे, अब आप उनकी पार्टी में ही आ गए हैं तो आए दिन मेल मिलाप करना पड़ेगा। इस पर पूर्व विधायक कुछ नहीं बोल पाए। जोर देकर पूछा तो इतना ही कह पाए कि अब विचाराधारा एक हो गई है। पहले कुछ भी कहा हो, पर अब पूरा सम्मान करेंगे। उसी समय वहां खड़े लोगों ने थोड़ा दूर जाकर चुटकी लेते हुए कहा, जब चुनाव लड़े तो अपशब्द कहे व अब उनकी पार्टी में आ गए तो सम्मान करेंगे, यह नहीं सोच रहे हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का भी कोई आत्मसम्मान है।

राग सियासी

लेवल प्लेइंग फील्ड हो,
करो ना खाते फ्रीज।
राहुल खरगे सोनिया,
बोले हृदय पसीज।
बोले हृदय पसीज,
लड़ें हम डटकर कैसे।
ठप है हर इक चीज,
हाथ में नहीं है पैसे।।
नड्डा साधे निशान,
पूछते इतना केवल।
करते गर भुगतान,
बात फिर होती लेवल।।

-राम नरेश गौतम

कर्नाटक आइटी सिटी की चार सीटें: चार नए और चार पुराने चेहरे

बदला सियासी गणित, पारा चढ़ा और चटख हुआ चुनावी रंग

पत्रिका LIVE चुनाव मैदान से

बेंगलूरु
राजीव मिश्रा

सदाबहार मौसम के लिए विख्यात आइटी सिटी बेंगलूरु का मिजाज पिछले कुछ वर्षों में काफी बदला है। गर्मियां पहले से ज्यादा तीखी हो गई हैं तो सियासत भी काफी बदली है। कभी एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे भाजपा और जद-एस अब साथ हैं, जिससे बेंगलूरु की चार लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का चुनावी गणित गड़बड़ा गया है। इन सीटों पर वोक्कालिगा समुदाय का अच्छा प्रभाव है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी वोक्कालिगा समुदाय में लोकप्रिय हैं इसलिए मतों के विभाजन से इनकार नहीं किया जा सकता।

डीके बंधुओं को गढ़ में चुनौती: हाल ही में देश को विभाजित करने वाले विवादास्पद बयान से सुर्खियों में आए डीके सुरेश की बेंगलूरु ग्रामीण में गहरी पैठ है। इस लोकसभा क्षेत्र के लगभग 27.64 लाख मतदाताओं में से 17 लाख शहरी और 10 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। अमित शाह ने बेहद चतुराई से यहां जयदेव कार्डियक हॉस्पिटल के पूर्व निदेशक डॉ सीएन मंजुनाथ को उम्मीदवार बनाया जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं। चिकित्सक के तौर पर मंजुनाथ के लिए लोगों में काफी सम्मान है। लेकिन, सुरेश ताल ठोक कर कहते हैं कि लड़ाई का मजा तभी है जब प्रतिद्वंद्वी मजबूत हो। क्या डीके बंधुओं के गढ़ में भाजपा उलटफेर कर पाएगी? इस लोकसभा क्षेत्र पर कर्नाटक ही नहीं, पूरे देश की नजर होगी।

प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक बैंगलोर पैलेस। इसे 1878 में बनाया गया था।

अंदरूनी कलह हारी तो ही जीत

बेंगलूरु उत्तर राज्य का सबसे बड़ा और देश का तीसरा बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। जद-एस के सहयोग से भाजपा के लिए यहां लड़ाई आसान होनी चाहिए थी। पर जेंटलमैन छवि के सदानंद गौड़ा का टिकट कटने और शोभा करंदलाजे को प्रत्याशी बनाने से बात बिगड़ गई है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद एमवी राजीव गौड़ा को उतारा है। अंदरूनी कलह और सदानंद गौड़ा की नाराजगी से यहां भाजपा के लिए दिक्कत हो सकती है।

मोहन की राह में मंसूर

बेंगलूरु मध्य सीट पर जीत-हार में राजस्थान समुदाय के लोग अहम भूमिका निभाते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे रहे हैं। भाजपा ने वोक्कालिगा समुदाय के अपने सांसद पीसी मोहन, तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय से राज्यसभा के पूर्व उप सभापति के. रहमान खान के बेटे मंसूर खान को उम्मीदवार बनाया है। मोहन के खिलाफ स्थानीय असंतोष से कांग्रेस उत्साहित है।

सूर्य की सौम्या से भिड़ंत

बेंगलूरु दक्षिण सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार के चलते चर्चा में रही है। भाजपा से यहां पुन: तेजस्वी सूर्य उम्मीदवार हैं। भाजपा यह सीट 1991 से कभी नहीं हारी, पर परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या के मैदान में आने से सूर्य को कड़ी चुनौती मिलेगी।

प्रथम चुनाव में प्रति मतदाता 60 पैसे आया था खर्च

बेलगाम होते चुनाव खर्च को कम करने की चुनौती

नरेन्द्र सिंह सोलंकी

चुनावों के दौरान राजनीतिक दल पानी की तरह पैसा बहाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी भारत का चुनाव दुनिया में सबसे महंगा होने वाला है। इस साल के लोकसभा चुनावों में लगभग 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है।

देश में पहली बार जब 1951 में आम चुनाव हुए थे, तब करीब 17 करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया था। उस समय प्रति मतदाता 60 पैसे का खर्च आया था। इस तरह पहले आम चुनाव में सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं, 2019 तक आते-आते यह खर्च 6500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। विशेषज्ञों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यह राशि बढ़ने वाली है। 2009 से 2014 के बीच तो चुनाव का खर्च करीब तीन गुना बढ़ गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में जहां 1114.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, तो 2014 में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए। साल 2004 में यह खर्च बढ़कर प्रति मतदाता 17 रुपए हो गया और 2009 में इस खर्च में कमी आई और यह खर्च प्रतिमतदाता 12 रुपए रहा। वर्ष 2014 के चुनाव में इसमें भारी बढ़ोतरी देखी गई। साल 2014 में प्रति मतदाता खर्च 46 रुपए पहुंच गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में यह खर्च बढ़कर 72 रुपए प्रति प्रति मतदाता पहुंच गया था। देश में सबसे कम खर्चीला लोकसभा चुनाव 1957 का था। तब चुनाव आयोग ने सिर्फ 5.9 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस तरह से भारत का 2019 का लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव रहा, साथ ही यह अब तक का दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में इसके और बढ़ने की संभावना है।

लोकसभा चुनाव का खर्च भी कई कारणों से बढ़ा है। एक तो मतदाताओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। दूसरा प्रत्याशियों से लेकर पोलिंग बूथ और संसदीय क्षेत्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 1951-1952 के लोकसभा चुनाव में 53 पार्टियों के 1874 उम्मीदवार 401 सीटों से मैदान में उतरे थे। 2019 में यह संख्या काफी बढ़ गई। पिछले आम चुनाव में 673 पार्टियों के 8054 उम्मीदवारों ने 543 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। देशभर में कुल 10.37 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए थे। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा राज्यों के आधार पर 54 लाख से 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 70 लाख से 95 लाख रुपए कर दी गई थी। इसी तरह, विधानसभा क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा राज्यों के आधार पर 20 से 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 से 40 लाख रुपए कर दी गई थी। वर्ष 2020 में चुनाव खर्च की सीमा का अध्ययन करने के लिए चुनाव आयोग ने एक समिति का भी गठन किया था।

भाजपा डायरी

टिकट बंटवारे से मिल रहा पार्टी लाइन का सबक

दिल्ली की हवा के रुख को समझने वाले मान चुके हैं कि भाजपा नए रास्ते पर चल पड़ी है। पहले विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री चुनकर बदलाव का संकेत दे दिया था। लोकसभा चुनाव के टिकट बंटवारे में भी कमोबेश वही फार्मूला अपनाया जा रहा है। फार्मूला यह कि पार्टी लाइन से भटकने वालों को टिकट नहीं।

जिन पर दाग लगे हैं, दाग कैसे भी हो सकते हैं, पार्टी उनसे भी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। वरुण गांधी का उदाहरण सामने है। उम्र भी ज्यादा नहीं है, पर टिकट कट गया। पर वरुण की मां को टिकट मिल गया। यानी मतलब समझने की जरूरत है। नए चेहरों को भाजपा में पहले शायद ही इतनी बड़ी तादाद में मौका मिला हो। महिला शक्ति वंदन को भी टिकट वितरण में चरितार्थ किया जा रहा है। अब तक घोषित

398 प्रत्याशियों में 66 महिलाओं को मैदान में उतारा जा चुका है। जबकि पिछले चुनाव में 436 उम्मीदवारों में सिर्फ 55 ही महिलाएं थीं। लगभग सौ नए चेहरे लाना भी पार्टी की दूरगामी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अनेक मौजूदा सांसदों के टिकट कटने के बावजूद पहले जैसी बगावत के सुर कहीं से सुनने को नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली के लुटियंस जोन में राजनीति के जानकारों का मानना है कि ये बदलाव जारी रहने वाले हैं। रणनीति यह दिखाने की भी है कि पार्टी चुनाव जीत रही है। पार्टी के छोटे-बड़े नेताओं का मानना है कि चुनाव में वोट प्रत्याशी के नाम पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर ही पड़ेंगे, तो फिर चिंता किस बात की।

-कमल बाबू

पत्रिका साक्षात्कार: पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से बातचीत

'भाजपा की मदद करने में जुटी हैं ममता बनर्जी'

*पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी राज्य के बेरहामपुर लोकसभा क्षेत्र से ताल ठोकने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को इस सीट से चौधरी को चुनौती देने की कोशिश की है। राज्य में कांग्रेस के अस्तित्व को बचाए रखने की जिम्मेदारी चौधरी पर है। कांग्रेस नेता से पत्रिका के **मनोज कुमार सिंह** की बातचीत के प्रमुख अंश...*

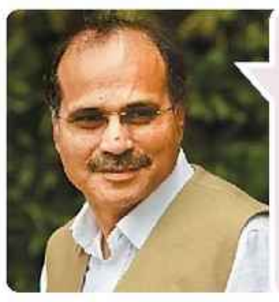

Q सात चरणों में चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले से निष्पक्ष चुनाव होने की कितनी उम्मीद है?

पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा स्थिति है, उसमें सात या इससे अधिक चरण में मतदान कराना ही पड़ेगा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी व संगठन के बल पर एक दिन में हिंसा और वोट की लूटपाट से चुनाव जीतने की योजना बना रखी थी। चुनाव में राज्य के पुलिस प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। देखना होगा कि चुनाव आयोग इसका कैसे सही उपयोग कर पाता है।

Q तृणमूल कांग्रेस ने बेरहामपुर से पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को प्रत्याशी बनाया है। आपके विरुद्ध यह रणनीति कितनी कारगर होगी?

यह तो समय और बेरहामपुर के मतदाता ही बताएंगे कि चुनावी मैदान में क्रिकेट का फंडा कितना असरदार होगा। ममता बनर्जी ने भाजपा की मदद करने के लिए मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश की है। उन्हें पीएम मोदी के नाराज होने का डर है इसलिए 'इंडिया' गठबंधन से नाता तोड़ लिया। अगर उनकी नीयत ठीक होती तो वे विपक्षी गठबंधन से यूसुफ पठान के लिए गुजरात में लोकसभा सीट की मांग करतीं या उन्हें राज्यसभा में भेजतीं।

Q क्या निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होने पर संशय है?

लोगों को शांतिपूर्वक मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था करने की अपील हम चुनाव आयोग से करते रहे हैं। मतदान से एक-दो दिन पहले ही केंद्रीय बल तैनात होगा तो लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा। तैनाती पहले से करनी होगी।

Q सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को घोटाला बताया जा रहा है?

तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस दिन सदन में इलेक्टोरल बॉन्ड को वित्तीय कानून में शामिल किया, हम उसी दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि देश की कानून-व्यवस्था किसी भी गैर-कानूनी कदम को रोकने में सक्षम है, चाहे वह बहुमत के बल पर ही क्यों न किया गया हो।

पोलीटून

कांग्रेस डायरी

पंजाब में भाजपा, कांग्रेस से आए नेताओं के सहारे

होली का रंग अब उतरने को है, लेकिन सियासी रंग अब लोगों पर चढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार शुरू होने को है। वहीं कांग्रेस पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। अब पंजाब जैसे राज्य में भाजपा कांग्रेस से आए नेताओं के भरोसे नजर आती है। दरअसल, पंजाब के लुधियाना से तीन बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भाजपा का दामन थामा है।

बिट्टू गांधी परिवार के बेहद नजदीकी माने जाते रहे हैं। वे पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते हैं। इसलिए उनका भाजपा में जाना खास मायने रखता है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए खूब काम किया था। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। इससे पहले लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड़ के पुत्र

सुनील जाखड़ भाजपा में शामिल हुए थे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सियासत में उबाल आया हुआ है। पूर्ण बहुमत के बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हराने में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के तत्कालीन छह विधायकों को भाजपा का सहारा मिल गया है।

विधायकी जाने के बाद अब वहां हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस भी इस बार भाजपा को उसके अंदाज में ही जवाब दे रही है, लेकिन इन जवाबों में भाजपा जितनी तीव्रता नहीं है। कांग्रेस मुख्यालय में अब दलबदल को आम बात मान लिया गया है। इस पर अब कोई अधिक चर्चा भी नहीं करता है।

-पंजा सिंह

आज का सवाल

जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर बार-बार सवाल क्यों उठते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

प्रकृति के साथ खिलवाड़

प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। सिर्फ दिखावे के लिए पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। वृक्षारोपण का सिर्फ ढोंग किया जाता है।

-गोपाल जे. धारकर, बुरहानपुर, मप्र

जन सहभागिता की जरूरत

भले ही सरकारें प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पानी की तरह बजट बहा रही हों परंतु जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं हो पा रहा। प्रदूषण नियंत्रण में आमजन की सहभागिता आवश्यक है।

-गजानंद गुरु, जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

इसे स्कैन करें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'प्रदूषण कम क्यों नहीं हो रहा?'
प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://rb.gy/zspwg0

https://t.me/NewsPaperPaid

कल्पमेधा

संस्कृति के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं।

– चार्ल्स डार्विन

आतंक की सरहद

आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान दोहरा रवैया अख्तियार करता रहा है। एक तरफ तो वह भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को हथियार की तरह इस्तेमाल करता रहा है, मगर दूसरी तरफ अपने ही बलूचिस्तान इलाके में आतंकवाद से लड़ना उसके लिए चुनौती बना हुआ है। सोमवार को बलूचिस्तान प्रांत के तुरबाद शहर में नौसैनिक अड्डे पर आतंकवादियों ने हमला किया और गोली बरसाते हुए अंदर घुसने का प्रयास किया। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा इलाके में चीनी नागरिकों के एक काफिले पर हमला किया, जिसमें पांच चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सैनिक ठिकानों या फिर चीनी नागरिकों पर ये हमले नए नहीं हैं और न ये केवल बलूचिस्तान प्रांत तक सीमित हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वहां इस कदर ताकतवर है कि वह जब-तब पाकिस्तानी सुरक्षाबलों को चुनौती देती रहती है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस ने बलूचिस्तान प्रांत से आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के इरादे से हर तरह के कड़े कदम उठाए हैं, वहां के बेगुनाह लोगों पर भी खूब अत्याचार किए हैं, मगर उनके इरादे कमजोर करने में उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है।

दरअसल, बलूचिस्तान प्रांत के लोगों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार उनके प्रांत के हितों की अनदेखी करती है। फिर, उस इलाके के लोग पाकिस्तान में चीन की बढ़ती दखल का पुरजोर विरोध करते रहे हैं। उनकी कहना है कि चीन उनके इलाके में घुस कर उनके संसाधनों का दोहन कर रहा है। दरअसल, पाकिस्तान में 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' के तहत कई परियोजनाएं चल रही हैं। बलूचिस्तान प्रांत के लोग उनका विरोध करते रहे हैं। इससे पहले भी चीनी नागरिकों पर कई बार हमले हो चुके हैं। ताजा हमला उसी की एक कड़ी है। मगर पाकिस्तान हुकूमत की मजबूरी यह है कि वह इन परियोजनाओं के नाम पर चीन से काफी पैसा ले चुकी है और इन दिनों जिस आर्थिक बदहाली के दौर से देश गुजर रहा है, उसमें वह चीन का दामन छोड़ नहीं सकती। चीन से उसकी दोस्ती न केवल आर्थिक कारणों से, बल्कि भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की वजह से भी है। चीन से दोस्ती करके वह भारत पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश करता है, मगर हकीकत यह है कि अपनी इस लचर रणनीति में वह खुद चीन के पंजे में अपनी गर्दन फंसा चुका है। अगर वह बलूचिस्तान प्रांत के लोगों के विरोध पर गंभीरता दिखाता, तो शायद आतंकवादी उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते।

बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवाद इतना ताकतवर हो चुका है कि उसके चलते पाकिस्तान को ईरान और अफगानिस्तान के साथ रिश्तों में संतुलन साधना भी कठिन हो गया है। कुछ महीने पहले ही ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत के कुछ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उसके इलाके में हवाई हमले किए। विचित्र है कि जब भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के विरुद्ध जंग छेड़ने की बात उठती है, तो पाकिस्तान उसमें सहयोग करने का आश्वासन देता है, मगर हकीकत यह है कि वह आतंकवादियों का सबसे सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान खुद भी इस बात से वाकिफ है कि उसकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा आतंकवाद है, मगर वह उस पर अंकुश लगाने को लेकर कभी संजीदा नजर नहीं आता।

उमंग में लापरवाही

जागरूकता की कमी और व्यवस्थागत लापरवाही का नतीजा एक बार फिर होली के मौके पर सामने आया, जब कई लोग बुरी रह झुलस गए। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में कुछ लोग घर की छत पर होली खेलते हुए एक-दूसरे पर रंग और पानी फेंक रहे थे। इसी बीच पास से गुजरते उच्च क्षमता के बिजली के तार पर पानी चला गया और उसमें अचानक विस्फोट हो गया। इसकी चपेट में सात लोग आए और गंभीर रूप से घायल हो गए। यों यह एक हादसा है, पर इसे बहुस्तरीय लापरवाही का नतीजा माना चाहिए। समझना मुश्किल है कि किसी खुशी के मौके पर लोग संभावित खतरों की अनदेखी क्यों करते हैं। अपनी छतों पर होली खेलते लोगों को क्या यह जानकारी नहीं थी कि वे जिस तरह एक-दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं, वह अगर बिजली के तार से छू गया तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं?

विडंबना है कि एक ओर आम लोग जागरूकता की कमी के चलते अक्सर लापरवाही कर बैठते और ऐसे हादसों के शिकार हो जाते हैं, वहीं संबंधित सरकारी महकमों को यह ध्यान रखना जरूरी नहीं लगता कि आम लोगों के लिए किसी सुविधा का विस्तार करते हुए जोखिम के लिहाज से या तो उचित सुरक्षात्मक व्यवस्था की जाए या फिर इंसानी आबादी के लिए खतरनाक साबित होने वाली किसी चीज को लेकर जरूरी कायदे तय किए जाएं। इस व्यवस्थागत कमी के अलावा किसी पर्व-त्योहार के मौके पर आम लोग आए दिन भारी लापरवाही बरतते देखे जाते हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, जब राजस्थान के कोटा में शिवरात्रि के मौके पर शिव बरात में शामिल लोगों में से किसी का झंडा उच्च क्षमता के तार से छू गया और उसमें चौदह बच्चे झुलस गए। ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं, मगर न तो आम लोग उनसे सबक लेते हैं और न ही प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षित इंतजाम किए जाते हैं। सवाल है कि घनी बस्ती में अगर जानलेवा साबित होने वाले उच्च क्षमता के बिजली के तार इंसानी गतिविधियों की पहुंच में गुजर रहे हों, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

विदेशी शिक्षा का बढ़ता आकर्षण

विदेशी शिक्षा के जादू में और भी बहुत कुछ ऐसा है, जो दुनिया भर के विद्यार्थियों को अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया की ओर खींच रहा है, जिसके बल पर वहां एक शानदार शिक्षा उद्योग बन गया है।

अभिषेक कुमार सिंह

हर साल लाखों भारतीय विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले की होड़ में शामिल होते हैं। इनमें से ज्यादातर का सपना विदेश में पढ़ाई कर वहीं बस जाने का होता है। मगर ये सपने किस अंजाम तक पहुंच रहे हैं, इसके असंख्य उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि मुल्कों से लगातार मिल रहे हैं। कनाडा से ताजा सूचना है कि हमारे सैकड़ों छात्रों ने फर्जी एजंटों के जाल में फंस कर ऐसे विश्वविद्यालयों में दाखिला ले लिया है, जिनकी डिग्री की कोई विशेष मान्यता कनाडा तक में नहीं है। खुद कनाडा सरकार ने माना है कि बीते कुछ वर्षों में वहां के कई शिक्षण संस्थानों ने पैसा कमाने के इरादे से जरूरत से ज्यादा विदेशी छात्रों को दाखिला दिया है। हालात से निपटने के लिए इस साल की शुरुआत में कनाडा सरकार ने जनवरी से अगले दो साल के लिए विदेशी छात्रों की संख्या में कटौती करने की घोषणा की है।

वैसे तो भारत में भी अच्छी शिक्षा लगातार महंगी हो रही है। बहुत सारे लोगों के लिए निजी स्कूल-कालेजों में शिक्षा का खर्च उठाना भारी पड़ने लगा है। मगर इसका एक विरोधाभास यह है कि लोग अपने बच्चों को विदेशी डिग्री के लिए बाहर भेजना पसंद करते हैं। इसके वास्ते समान डिग्री या पाठ्यक्रम के लिए दस गुना ज्यादा खर्च खुशी-खुशी उठाने को तैयार हैं। कुछ वर्ष पहले 'एसोचैम' ने टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज के साथ मिलकर एक सर्वेक्षण के आधार पर 'रीअलाइनिंग स्किलिंग टुवर्ड्स मेक इन इंडिया' नामक रपट तैयार की थी। उसमें बताया गया था कि भारतीय अभिभावक हर साल अपने बच्चों की शिक्षा पर छह से सात अरब डालर खर्च करते हैं।

एक अध्ययन के मुताबिक आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जाकर स्नातक स्तर की पढ़ाई में औसतन 15 हजार अमेरिकी डालर से लेकर 50 हजार अमेरिकी डालर का वार्षिक खर्च छात्रों को उठाना पड़ता है। इसके अलावा वहां रहन-सहन के अन्य खर्चे अलग होते हैं, जिसे वहन करने के लिए छात्र कोई न कोई काम करते हैं। इसके मुकाबले भारत में शिक्षा काफी सस्ती है। वर्ष 2013 में एक अंतरराष्ट्रीय बैंक द्वारा कराए गए सर्वेक्षण- 'द वैल्यू आफ एजुकेशनः स्प्रिंगबोर्ड फार सक्सेस' के अनुसार 'अंडरग्रेजुएट कोर्स' के लिए भारत में बाहर से पढ़ने आए छात्र का फीस और रहने-खाने का वार्षिक औसत खर्च 5643 डालर है, जिसमें से महज 581 डालर फीस के रूप में चुकाए जाते हैं। इसके विपरीत, आस्ट्रेलिया में यह खर्च 42,093 डालर, सिंगापुर में 39,229 डालर, अमेरिका में 36,565 डालर और ब्रिटेन में 35,045 डालर वार्षिक होता है।

पंद्रह देशों में 4500 अभिभावकों पर किए गए सर्वेक्षण में यह बात भी निकलकर सामने आई थी कि भारत में भले सबसे सस्ती उच्च शिक्षा मिल रही हो, लेकिन 62 फीसद भारतीय अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा और सिंगापुर भेजने को अहमियत देते हैं। वे ऐसा

क्यों करते हैं, इसका एक जवाब ब्रिटिश कंपनी- 'क्यूएस' (क्वैकुरेली साइमंड्स लिमिटेड) द्वारा प्रकाशित 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' में दिया गया। इस 'रैंकिंग' में शामिल पहले 200 विश्वविद्यालयों में से एक भी भारतीय नहीं था। आइआइटी मुंबई इस सूची में 222वें स्थान पर थी, जबकि आइआइटी दिल्ली 235वें स्थान पर।

> **यों** देश में फिलहाल करीब चार सौ विश्वविद्यालय और लगभग बीस हजार उच्च शिक्षण संस्थान हैं। इनमें सात लाख से ज्यादा प्राध्यापक कार्यरत हैं। मोटे तौर पर इन शिक्षण संस्थानों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। पर यह तथ्य हैरान करने वाला है कि इनमें से कोई भी विश्वविद्यालय उस स्तर की शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है, जिसके बल पर उसे दुनिया के अव्वल सौ विश्वविद्यालयों में शामिल किया जा सके। अच्छी शिक्षा के इसी अकाल का अंजाम है कि विदेशी विश्वविद्यालयों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने के लिए हर साल भारत से डेढ़ से पौने दो लाख छात्र विदेश चले जाते हैं।

फिर विदेशी शिक्षा के जादू में और भी बहुत कुछ ऐसा है, जो दुनिया भर के छात्रों को अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया की ओर खींच रहा है, जिसके बल पर वहां एक शानदार शिक्षा उद्योग बन गया है। एक उदाहरण अमेरिकी शिक्षा व्यवस्था से लिया जा सकता है। अमेरिका में कानून और चिकित्सा- दो ऐसे पेशे हैं जिनमें भरपूर कमाई की संभावना होती है। वहां कानून की मुकम्मल पढ़ाई में सात से आठ वर्ष लग जाते हैं और मेडिकल की पढ़ाई कर डाक्टर बनने में ग्यारह वर्ष लगते हैं। इसमें भारतीय मुद्रा के हिसाब से एक से डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होता है। इन दोनों पाठ्यक्रमों के लिए येल, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की गणना सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में होती है। मगर इतनी महंगी शिक्षा के बावजूद ऐसा नहीं कि अमेरिकी या ब्रिटिश अभिभावक अपने बच्चे को मेडिकल या एमआइटी से स्नातक कराने के लिए अपना घर-बार या कारोबार दांव पर लगा दें या बैंकों से कठिन शर्तों पर कर्ज लें।

अमेरिका में बच्चों की स्कूली शिक्षा की नींव को भी काफी मजबूत बनाया जाता है। प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त होती है। हालांकि वहां के सरकारी यानी काउंटी स्कूलों के साथ-साथ वहां भी प्राइवेट स्कूल हैं, जो अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि काउंटी स्कूलों से निकला बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चे से किसी मामले में उन्नीस साबित हो।

यह भी ध्यान रखना होगा कि विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा का तंत्र एक उद्योग का रूप ले चुका है। चीन और भारत से करीब चार-पांच लाख युवा हर वर्ष वहां उच्च शिक्षा के लिए पहुंचते हैं। दूसरे देशों से भी बड़ी तादाद में छात्र वहां जाते हैं। इससे अकेले अमेरिका को हर वर्ष 25-30 अरब डालर की कमाई हो जाती है। इसके उलट भारत में सरकारी मदद के भरोसे चल रहे आइआइटी, आइआइएम या मेडिकल कालेज ढांचागत सुविधाओं में अपेक्षित सुधार करने की बजाय न्यूनतम सुविधाओं और सामान्य वेतनमान पर न्यूनतम फैकल्टी से काम चलाने को विवश हैं। अपने देश में निजी कालेजों में तो और भी खराब नजारे दिखाई पड़ते हैं, जहां तदर्थ फैकल्टी के बल पर बड़े-बड़े पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

यों देश में फिलहाल करीब चार सौ विश्वविद्यालय और लगभग बीस हजार उच्च शिक्षण संस्थान हैं। इनमें सात लाख से ज्यादा प्राध्यापक कार्यरत हैं। मोटे तौर पर इन शिक्षण संस्थानों में डेढ़ करोड़ से ज्यादा छात्र पढ़ाई करते हैं। पर यह तथ्य हैरान करने वाला है कि इनमें से कोई भी विश्वविद्यालय उस स्तर की शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहा है, जिसके बल पर उसे दुनिया के अव्वल सौ विश्वविद्यालयों में शामिल किया जा सके। अच्छी शिक्षा के इसी अकाल का अंजाम है कि विदेशी विश्वविद्यालयों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पाने के लिए हर साल भारत से डेढ़ से पौने दो लाख छात्र विदेश चले जाते हैं। बेहद कमजोर हो चुके रुपए के मद्देनजर यह और भी जरूरी लगने लगा है कि या तो छात्रों को देशी विश्वविद्यालय ही कायदे की शिक्षा देने का इंतजाम करें, अन्यथा देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर खुलें, जिनके जरिए विदेशी डिग्री पाने का सपना थोड़े सस्ते में पूरा हो सके। जब देश में ही विदेशी परिसर मौजूद रहेंगे, तो इससे विदेशी शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च में कटौती से लेकर वे सारे फायदे हो सकेंगे, जिनके लिए विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत लाने की वकालत होती रही है।

स्वतंत्रता के दायरे

मेघा राठी

कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में व्यक्ति को बांधना नहीं चाहिए, उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, ताकि रिश्तों की मिठास और गरमाहट बनी रह सके। वास्तव में व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति के साथ ही जन्म लेता है। शैशवास्था और बाल्यावस्था के आरंभिक काल में वह स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है, लेकिन बड़ा होते हुए परिवार और समाज में रहकर वह सीखता है कि उसकी स्वतंत्रता के दायरे कहां तक हैं। रूसो ने कहा है- 'मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ और हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।' दरअसल, ये जंजीरें कैद करने वाली कारा की जंजीरें नहीं हैं, जो कष्ट देती हैं। अगर ये जंजीरें न हों तो स्वच्छंद समाज में व्यवस्था की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

खानपान, रहन-सहन, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक स्वतंत्रता किसी भी देश का कानून अपने मानकों के आधार पर दे सकता है। हम अपने स्वतंत्र विचारों के प्रवाह में भले ही समाज के बनाए नियमों, रीति-रिवाजों के विरुद्ध हो भी जाएं और उनका सामना करें, फिर भी व्यक्ति किसी न किसी रूप में बंधन में रहेगा ही। पूर्ण मुक्त हो पाना असंभव है। अगर ऐसा होता है तो दूसरों के साथ ही व्यक्ति स्वयं को भी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि जो लोग इस स्वतंत्रता के कारण चोटिल होते हैं, वे उसे भी प्रतिक्रिया में अपने व्यवहार या वचनों द्वारा चोट पहुंचा ही सकते हैं और इसके लिए कम से कम वे लोग उनके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते, जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाया होता है। सभी अपने व्यवहार और वचनों के लिए स्वतंत्र हैं। यों भी हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ करना चाहिए।

यह सच है कि व्यक्ति को अपने संबंधों में यह विश्वास होना चाहिए कि वह जैसा है, जिस रूप में है, जिस स्वभाव में है, खुद को उसी रूप में किसी के समक्ष प्रकट कर सके। उसे किसी बनावट के व्यवहार के लिए विवश नहीं होना पड़े, लेकिन यह बहुत बार सामने वाले पर भी निर्भर करता है कि वह उसके मूल रूप को कितनी सहजता से स्वीकार कर पाता है। किसी भी प्रकार के संबंधों में स्थायित्व के मूल अर्थ में व्यक्ति की वास्तविकता को पाना है और जब इंसान के मूल रूप को स्वीकार करने के बाद भी भाव वैसे ही बने रहें, तो उनके मध्य प्रेम समाप्त नहीं होता और न ही दुख का कारण बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य पूर्ण स्वच्छंद हो जाए। उसे जो भी करना है, वह बिना सोचे-समझे करे। इसकी फिक्र न करे कि उसके किसी कार्य का दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी तो उसी के मुताबिक आनी है!

दरअसल, स्वतंत्र विचारों के कारण व्यक्ति को रोक-टोक पसंद नहीं आती। नतीजतन, वह अपने इस प्राकृतिक स्वभाव की वजह से अनजाने में ही खुद से जुड़े लोगों को भावनात्मक रूप से आहत कर देता है। ऐसी परिस्थिति में सहन की सीमा समाप्त होने के बाद लोग उनसे प्रेम होने के बाद भी दूर होने लगते हैं या उन पर ध्यान देना बंद कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। हमारी अपनी स्वतंत्रता हमें प्रिय हो सकती है, मगर दूसरों की स्वतंत्रता भी इतनी ही अहम है। एक कहावत भी है, 'व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है, जहां दूसरे व्यक्ति की नाक आ जाती है।'

कोई भी समाज एक व्यवस्था के तहत चलता है और उसी पर आधारित होता है। अगर व्यवस्थाएं न हों तो जनजीवन, सामाजिकता अस्त-व्यस्त हो जाएगी। मनुष्य को स्थायित्व देने में व्यवस्था का बहुत योगदान होता है। स्वतंत्र व्यक्ति को व्यवस्थित होने में मुश्किल पेश आती है। उसे लगता है कि यह उसकी आजादी में दखल है। स्वतंत्र व्यक्ति अपनी आजादी की सीमाएं नहीं बांधना चाहता। वह नहीं चाहता कि वह जैसा करना चाहता है, उसे वैसा करने से रोका जाए। उसे लगता है कि इंसान समझदार होता है, अपना भला-बुरा जानता है और अपने जीवन पर उसका अधिकार है। इसलिए किसी को भी इसमें दखल देने का हक नहीं है। मगर जब वह देखता है कि यह स्वतंत्रता उसे पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रही है और वह जैसा है, लोग उसे वैसा ही स्वीकार नहीं कर रहे, तब उनके अंदर आक्रोश उत्पन्न होता है। यह आक्रोश किसी सार्थक बदलाव के लिए सहायक नहीं होता, बल्कि यह कुंठाओं को जन्म देने लगता है। मन की घुटन बढ़ाने लगता है। ऐसे में एक आक्रोशित व्यक्ति न तो वैयक्तिक विकास पर ध्यान देता पाता है और न ही समाज के लिए कुछ कर पाने की अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर पाता है।

देखा जाए तो प्राकृतिक स्वतंत्रता घातक बिल्कुल भी नहीं है। उसे नुकसानदेह बना लिया जाता है बंधनों के साथ समायोजन के अभाव में। अगर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ भावनाओं को भी जीवन में स्थान देगा तो उसे सामाजिक जीवन और रिश्तों में तालमेल बनाने में समस्या नहीं आएगी और न ही उसके संपर्क में आने वाले लोगों को दिक्कत होगी। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता का अंतर समझ कर भी व्यक्ति स्वयं को समायोजित कर सकता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता में तलवार की पैनी धार भी होती है, जिसे कुछ हद तक व्यवस्था की म्यान में संभालना आवश्यक है, अन्यथा स्वतंत्रता अकेलेपन की सहगामिनी बन कर रह जाती है।

दुनिया मेरे आगे

> **प्रा**कृतिक स्वतंत्रता घातक बिल्कुल भी नहीं है। अगर व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ भावनाओं को भी जीवन में स्थान देगा तो उसे सामाजिक जीवन और रिश्तों में तालमेल बनाने में समस्या नहीं आएगी और न ही उसके संपर्क में आने वाले लोगों को दिक्कत होगी।

चौपाल

दागी नुमाइंदे

'लोकतंत्र का उत्सव' (संपादकीय, 18 मार्च) में वर्णित तथ्यों में नेताओं द्वारा एक दूसरे के प्रति अनवरत आपत्तिजनक बोल, हिंसा की घटनाएं, पैसे और उपहार के खेल सहित दीर्घकाल तक चुनावी प्रक्रिया का जीवंत चित्रण किया गया है। मान्यता है कि कोई भी उत्सव लंबी अवधि तक आयोजित नहीं होता। पूर्व के लोकसभा चुनावों के साक्ष्य बताते हैं कि हर बार इसकी संचालन अवधि में वृद्धि हो रही है, जिससे अनेक चुनौतियों सहित विकास की गति धीमी हो जाती है। देश के करीब पैंतीस सांसदों के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले न्यायालय में दर्ज हैं, जबकि लोकसभा के 44 फीसद और राज्यसभा के 33 फीसद सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले चल रहे हैं। विगत बजट सत्र में लोकसभा में 34 फीसद और राज्यसभा में 24.4 फीसद ही कामकाज हो सके थे। इससे समझना आसान है कि आगामी नूतन भवन के लोकसभा में जो माननीय शपथ लेंगे, उनके आचरण और चरित्र में कोई आश्चर्यजनक बदलाव दिखेगा। चुनावी सुधार की पूर्व दशकों की अनुशंसाओं में से न्यूनतम अंश भी लागू किया जाता तो लोकतंत्र का यह उत्सव संपूर्ण देशवासियों के लिए सुखद होता।

– अशोक कुमार, पटना, बिहार

स्वच्छता के दौर में

भारत की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है। देश का एक नागरिक और दिल्ली निवासी होने के नाते किसी को भी यह बेहद कष्टपूर्ण स्थिति दिखाई दे सकती है। हाल ही में जारी किए गए सर्वे के अनुसार विश्व के 100 बड़े शहरों में 86 भारत में हैं और देश की 96 फीसद आबादी दूषित हवा में सांस लेने पर मजबूर है। इसमें सुधार करने के लिए देश की सभी सरकारों, नागरिकों और पर्यावरणविद को मिलकर युद्ध स्तर पर काम करना होगा। राजनेताओं द्वारा दावे जरूर बड़े-बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही सामने है कि भारत में प्रदूषण विकराल रूप धारण कर चुका है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों का और कोयला, कूड़ा, कचरा जलाने से पैदा होने वाला धुआं इन सभी शहरों में प्रदूषण का बड़ा कारण है, लेकिन महानगरों की धूल भरी सड़के, गंदे पानी का समुचित निकास न होना, गलियों और नालियों के समुचित व्यवस्था न होना, कूड़ा प्रबंधन के मामले में विफलता और फुटपाथ पर अतिक्रमण भी इसके कारण हैं।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

प्यास के बरक्स

कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने बंगलुरु में कार धोने, बागवानी, निर्माण और रखरखाव के लिए पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर भी आइपीएल के लिए बंगलुरु में मैचों के दौरान हर दिन करीब 75,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इतने लीटर पानी की आवश्यकता को देखते हुए कब्बन पार्क वेस्टवाटर शोधन संयंत्र से पानी की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया गया है। यह प्रशासकीय संवेदनहीनता का प्रमाण है कि जनता के लिए पानी की भारी कमी होने के बावजूद वह इतनी बड़ी मात्रा में पानी व्यवस्था क्रिकेट के लिए करने को तैयार हो गए हैं। अगर पानी की कमी है तो मैच को अन्य शहरों में स्थानांतरित किया जा सकता है या निरस्त किया जा सकता है। मगर मैच होगा, भले ही जनता प्यासी रहे या शहर छोड़ कर चली जाए।

– विभूति बुपक्या, खाचरोद, मप्र

राजनीति का चेहरा

पुराने वक्त में एक समान विचारधारा वाले लोग सता के लिए राजनीति पार्टियां बनाते थे। अब विचारधारा का स्थान सत्ता और कुर्सी पर केंद्रित ज्यादा है। राजनीति पार्टियों के लिए विचारधारा केवल नारा रह गया है। जीत की संभावना हो तो विचारधारा के समझौते मंजूर करने को भी तैयार हैं। वहीं हफ्ते भर पहले शामिल हुए नेता को पार्टियों द्वारा टिकट दिया जाना सक्रिय राजनीति में जाने का सपना लिए सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ छलावा होता है। पार्टियों में पाला-बदल से गुटबाजी, विद्रोह और कितने नेता विपक्ष के तोड़े जाएं, इसकी प्रतिस्पर्धा में तब्दील हो रही है। दिलचस्प है कि जिस पार्टी की निंदा और कमियां गिनवाने में दशकों बीत गए उस पार्टी में रातों-रात शामिल होकर उसके गुणगान करने लगते हैं। इन घटनाओं से राजनीतिक गरिमा में गिरावट आती है।

– महेश कुमार, सिद्धमुख., राजस्थान

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com
https://t.me/AllNewspaperpaid

चिंतन

होली पर स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ने तोड़े रिकार्ड

भारत सरकार की वोकल फॉर लोकल मुहिम का असर अब दिखने लगा है। इस होली पर मेड इन इंडिया घरेलू उत्पादों की रिकार्ड बिक्री हुई है। भारतीय उपभोक्ताओं ने चीन को तगड़ा झटका दिया है। अब तक होली, दिवाली जैसे अहम त्योहारों के अवसर सस्ते चीनी उत्पाद से भारतीय बाजार पटे रहते थे, इसके चलते भारतीय घरेलू निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ता था, और इस कारण वे उत्पाद निर्माण के प्रति उदासीनी होती गई थीं। 2020 की गलवान घटना के बाद से जबसे भारत में चीनी उत्पादों का बायकॉट शुरू हुआ और इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के प्रति आवाज बुलंद की, उसके बाद से भारतीय उपभोक्ताओं में स्थानीय उत्पादों के प्रति चेतना जागृत होनी शुरू हुई। इसी का नतीजा है कि इस बार होली के अवसर पर देश भर में त्योहार से जुड़े घरेलू निर्मित उत्पादों ने बिक्री के सभी रिकार्ड तोड़ दिए। व्यापारी संगठन कैट के सर्वे के मुताबिक इस बार लोगों ने त्योहार मनाने के लिए होली के दिन से पहले तक 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की खरीदारी की, जो पिछले साले के मुकाबले 50 फीसदी ज्यादा है। अकेले दिल्ली में ही 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हुआ। पहले भारतीय व्यापारी चीन के सस्ते सामान को मांगते थे, लेकिन चीन के सामान के बॉयकॉट के चलते व्यापारियों ने देश में बने रंग-गुलाल, पिचकारी की बिक्री की और लोगों ने भी होली पर देश में बने सामानों पर ही जमकर पैसा खर्च किया। पहले होली के दौरान चीन में बने करीब 10 हजार करोड़ रुपये के सामान का आयात किया जाता था, जो इस बार एकदम ना के बराबर रहा। इस बार होली के दौरान केवल भारत में ही बने हर्बल रंग और गुलाल, पिचकारी, गुब्बारे, चंदन , पूजा सामग्री, कपड़ों समेत बाकी सामानों की खूब बिक्री हुई। इसके अलावा भी मिठाइयां, ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम्स, फूल और फल, कपड़े, फ़र्निशिंग फैब्रिक, किराना, एफएमसीजी प्रोडक्ट, कंज्यूमर ड्युरेबल्स समेत दूसरे उत्पादों की भी ज़बरदस्त मांग रही। होली मिलन समारोह के बढ़ते चलन के चलते भी नए तरह के उपभोक्ता वर्ग तैयार हो रहे हैं। होली मिलन समारोह के आयोजन के लिए लोग बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, होटलों, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक पार्क आदि का प्रयोग करने लगे हैं, दिल्ली में ही छोटे-बड़े मिलाकर करीब 3 हज़ार से ज़्यादा होली मिलन समारोह आयोजित किए गए। देश के अन्य शहरों में करोड़ों समारोह आयोजित किए गए। इससे होटल इंडस्ट्री, इवेंट उद्योग, कैटरिंग, म्यूजिक से जुड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। इस बार ऑनलाइन बिक्री ने भी नए रिकार्ड बनाए। क्विक-कॉमर्स प्लेटफार्म्स पर खूब बिक्री दर्ज की गई, इनमें गुलाल, पिचकारी, मिठाई, खाने-पीने का सामान, नारियल तेल, सफ़ेद टी-शर्ट आदि सामानों की मांग रही। फूलों की बिक्री पिछले साल होली के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रही। यह रिकार्ड बिक्री वोकल फॉर लोकल अभियान की सफलता है, भारतीय उपभोक्ताओं के स्वाभिमान की जीत है, आर्थिक राष्ट्रवाद के सपनों को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। भारत को अगर अपने विकसित देश के सपने को साकार करना है तो आर्थिक राष्ट्रवाद के विचार को मजबूती से आगे बढ़ाना होगा, जिसमें स्वदेशी निर्मित उत्पादों के उपयोग को अपनाने की संकल्पना है। विदेश कंपनियां भारत से करीब 11 से 12 लाख करोड़ रुपये सालाना मुनाफा के रूप में ले जाती हैं। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल अभियान से विदेश जा रहे मुनाफे को कम किया जा सकता है। देश में सांस्कृतिक चेतना के साथ आर्थिक राष्ट्रवाद की चेतना भी जरूरी है।

सवाल
सुरेश हिन्दुस्थानी

साफ सुथरी राजनीति के मायने

शराब घोटाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है, उस पर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठाना विपक्ष की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सवालों की परिधि में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर विपक्ष कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इससे इस बात को भी बल मिलता है कि दाल में कुछ काला अवश्य है। प्रवर्तन निदेशालय ने साफ संकेत दिया है कि केजरीवाल शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है। अब यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे आरोप किस हद तक सही हैं या फिर केजरीवाल खुद को निर्दोष साबित कर पाते हैं या नहीं। अगर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगाए गए आरोप प्रमाणित होते हैं तो यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवैधानिक पद के प्रभाव का दुरुपयोग किया है। केजरीवाल अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने आपको ऐसा प्रचारित किया कि एक वे ही भारतीय राजनीति के उच्चतम आदर्श हैं। लेकिन उनके आचरण पर स्वयं अण्णा हजारे ने सवाल उठाए थे, हालांकि अण्णा हजारे के सवालों को केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया। इसका तात्पर्य यही है कि अण्णा हजारे राजनीति में जिस प्रकार का पारदर्शी व्यवहार चाहते थे, वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी समाजसेवी अण्णा हजारे की ओर से साफ सुथरी टिप्पणी आई है, जिसमें अण्णा हजारे ने शराब पर नीति बनाने से रोका था। आज दिल्ली का शराब घोटाला यही चरितार्थ करते हुए लग रहा है कि शराब किसी भी संस्था या व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। यह बात केजरीवाल पर लागू होती है या नहीं, यह तो समय बताएगा, लेकिन जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। केजरीवाल की सरकार पर सवाल उठना तो उसी समय प्रारंभ हो गए थे, जब उनका पहला मंत्री जेल में गया। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। राजनीतिक शुचिता लाने का दम दिखाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस प्रकार के आरोप लगने केवल राजनीतिक विद्वेष नहीं हो सकता। अगर यह कार्यवाही राजनीतिक होती तो स्वाभाविक रूप से इन सभी को जमानत भी मिल जाती। जमानत नहीं मिलने से यह आशंका प्रबल हो जाती है कि भ्रष्टाचार हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता भी केवल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का ही विरोध कर रहे हैं, कोई भी यह नहीं कह रहा कि दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ। यह बात सही है कि राजनीतिक तौर पर तर्क तो कई दिए जा सकते हैं, लेकिन इन तर्कों का आधार क्या है? यह कोई नहीं बता पाता। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिसमें नेता जमानत पर बाहर आकर राजनीतिक वातावरण को स्वच्छ करने की बात करते हैं। क्या वास्तव में ऐसे राजनेता देश के राजनीतिक वातावरण को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य रखते हैं। कदाचित नहीं, क्योंकि आज के राजनीतिक माहौल में राजनेता जैसा अपने आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, वैसा सिद्धांततः होता नहीं है। उनके क्रियाकलाप केवल और केवल भ्रमित करने वाली राजनीति करने की ही होती है। देश में एक समय यह आम धारणा बन चुकी थी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार इस देश की नियति बन चुकी है, लेकिन पिछले दस साल में इस धारणा को बदलने की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। यह सुगबुगाहट कई राजनीतिक दलों को पसंद नहीं आ रही। ऐसे कई राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार के दोषी सिद्ध हो चुके हैं और देश की राजनीति को सुधारने की कवायद कर रहे हैं। अब सवाल यह भी आता है कि क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात करने का साहस दिखा सकते हैं। इसका उत्तर नहीं ही होगा, लेकिन वे फिर राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। भारत में साफ सुथरी राजनीति के क्या यही मायने हैं? क्या ऐसे नेता राजनीति को सही दिशा दे सकते हैं, इसका उत्तर हमें स्वयं तलाश करना होगा? ऐसे ही दिल्ली सरकार के घोटाला में होता लग रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से कहा जा रहा कि गोवा में 45 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से दिए गए। ऐसे में सवाल यही है कि क्या यही साफ सुथरी राजनीति के मायने हैं? तर्क कुछ भी हों, परन्तु अब ऐसी राजनीति से देश को अलग करने का समय आ गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सामान्य नहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी

विश्लेषण
अवधेश कुमार

> दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक ऐसी बड़ी घटना है, जिसकी तुलना किसी भी पूर्व गिरफ्तारी से नहीं हो सकती। ईडी अपने आप कोई मामला दर्ज नहीं करती। सीबीआई, पुलिस या अन्य एजेंसी जब मामला दर्ज करती है और उसमें अवैध लेनदेन का पहलू आता है, तभी ईडी उसमें प्रवेश करती है, क्योंकि धन शोधन अधिनियम तभी लागू होता है जब भ्रष्टाचार में अवैध नकदी लेनदेन का पहलू हो। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठकर खड़ा होने वाला नेता अगर ऐसे शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती। यह विडम्बना ही है कि वह आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक ऐसी बड़ी घटना है, जिसकी तुलना किसी भी पूर्व गिरफ्तारी से नहीं हो सकती। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके पूर्व 2 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे और त्यागपत्र देने के बाद उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई। वस्तुतः केजरीवाल का मामला इस रूप में गुणात्मक रूप से भिन्न है, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियानों, आंदोलन की अगुवाई करते हुए यहां तक पहुंचे। उनके बैनर का नाम ही था इंडिया अगेंस्ट करप्शन और उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा, कई केंद्रीय मंत्रियों जिनमें प्रणब मुखर्जी से लेकर कपिल सिब्बल, पी चिदंबरम आदि शामिल थे, सबको भ्रष्टाचारी बताते हुए उनका त्यागपत्र देने एवं गिरफ्तार किए जाने की मांग की थी। आम लोगों में छवि यह बनी थी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक हीरो अण्णा हजारे की अभिभावकत्व में उभरा है और उसके पास एक टीम है जिसमें लड़ने और व्यवस्था बदलने का माद्दा है। हालांकि लंबे समय तक उनकी घोषणा यही रही कि वह राजनीति में नहीं जाएंगे कोई दल नहीं बनाएंगे। राजधानी दिल्ली में उनकी पूरी लड़ाई ही तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के विरुद्ध थी। पूरी दिल्ली में उन्होंने धरना, प्रदर्शन, सभाएं की और जनता के बड़े समूह को अपने साथ जोड़ा, क्योंकि लोगों को कठिनाइयां थीं और वे जो बात बोलते थे वो व्यावहारिक रूप से सबके जीवन में लागू हो रही थी। शीला दीक्षित, उनकी सरकार और कांग्रेस पार्टी के लिए तब केजरीवाल और उनके साथियों का जवाब देना मुश्किल होता था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठकर खड़ा होने वाला नेता अगर ऐसे शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है तो इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं हो सकती।

किसी का गिरफ्तार होना या उस पर आरोप लगना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं होता। न्यायालय ही उसके दोषी या निर्दोष होने का प्रमाण देता है, इसलिए देश भर के ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के अंत की कामना से किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों उन सबके लिए अत्यंत दुखद स्थिति है। सबकी चाहत यही होगी कि केजरीवाल और उनके साथी भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हो। ऐसा नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी आंदोलन पर भारत के आम लोग लंबे समय तक विश्वास नहीं करेंगे। दिल्ली शराब घोटाला की कानूनी कार्रवाई अब तक जिस दिशा में आगे बढ़ी है और छानबीन के आधार पर जिस तरह की बातें सामने आई है उनमें यह मानना मुश्किल है कि सब कुछ ईमानदारी, नैतिकता, शुचिता की कसौटी पर कसकर ही किया गया। आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी के पीछे भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती है। यह अस्वाभाविक इसलिए नहीं है, क्योंकि कार्रवाई के बाद देश भर के ऐसे नेताओं, पार्टियों और उनके समर्थकों की प्रतिक्रिया यही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का राजनीतिक पहलू है। पहले उनके दाहिना हाथ माने जाने वाले साथी और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और

बाद में आम राजनीति में पार्टी का चेहरा बने राज्यसभा सदस्य संजय सिंह। उसके पूर्व दूसरे मामलों में पार्टी के वित्तीय प्रबंधक के रूप में जाने जाने वाले सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए और केजरीवाल की गिरफ्तारी के दो दिन पूर्व ही उच्च न्यायालय ने उन्हें दोबारा जेल भेज दिया। ऐसे में दिल्ली सरकार के संचालन और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। चुनाव में पार्टी का मुख्य प्रचारक ही अगर अंदर हो तो समर्थकों, उम्मीदवारों की मानसिक स्थिति क्या होगी इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। इस तरह पार्टी के लिए अब तक का यह सबसे बड़ा संकट है।

राजनीतिक पहलू इस प्रकरण का प्रतिउत्पाद ही है। ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंततः उच्च न्यायालय की शरण ली। उनके वकीलों ने दलील दी कि वह बार-बार सम्मन पर इसलिए उपस्थित नहीं होते,क्योंकि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर है। अगर गिरफ्तार हो गए तो लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ठीक से नहीं लड़ पाएगी। न्यायालय ने ईडी के वकील से पूछा कि क्या आप यह गारंटी देंगे कि पूछताछ के साथ उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? ईडी के वकील ने उत्तर दिया कि नहीं, हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तब न्यायाधीश ने उनसे सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा और सब देखने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायालय के इस व्यवहार के बाद सच कहा जाए तो अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हालांकि इससे भी यह निश्चित नहीं होता कि मामले का अंतिम फैसला क्या होगा। बावजूद इसका यह अर्थ तो है ही कि न्यायालय को पहली दृष्टि में संलिप्तता दिखाई पड़ी है। केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए 2 नवंबर, 2023 को पहले सम्मन दिया था। उसके बाद से लगातार 9 सम्मन की वो अवहेलना करते रहे। पहले सम्मन में उनका प्रतिप्रश्न था कि आपने हमें किस रूप में बुलाया है गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में यह बताएं। इसी तरह हर बार उन्होंने प्रश्न उठाए और उपस्थित होने से मना कर दिया। इस प्रकार एजेंसी की अवहेलना के बाद न्यायालय के लिए भी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश कठिन हो जाता है क्योंकि इससे एजेंसी का यह आरोप साबित हो जाता है कि आरोपी जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे।

देखा जाए तो लगभग यही स्थिति मनीष सिसोदिया के मामले में हुई जिन्होंने आरंभ में पूछताछ के लिए जाने से इनकार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल को मिलाकर अब तक 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पूर्व सबसे अंतिम और बड़ी गिरफ्तारी तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की बेटी कविता की थी। आप के सोशल मीडिया प्रभारी कारोबारी विजय नायर, दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों के लिए काम करने वाले अभिषेक बोइनपल्ली, शराब कारोबारी समीर महेंद्रू, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, राज्यसभा सांसद संजय सिंह आदि शामिल है। इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जैसा हम जानते हैं ईडी अपने आप कोई मामला दर्ज नहीं करती। सीबीआई, पुलिस या अन्य एजेंसी जब मामला दर्ज करती है और उसमें अवैध लेनदेन का पहलू आता है, तभी ईडी उसमें प्रवेश करती है, क्योंकि धन शोधन अधिनियम तभी लागू होता है जब भ्रष्टाचार में अवैध नकदी लेनदेन का पहलू हो। इस तरह सीबीआई एवं ईडी दोनों की जांच और कानूनी कार्रवाई समानांतर चल रही है। दोनों ने न्यायालय में आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दायर किया है। मनीष सिसोदिया के निजी सहायक दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन चुके हैं। इस तरह पहली दृष्टि में देखने से मामला अत्यंत सशक्त दिखता है। बावजूद यह भारतीय राजनीति की विडम्बना ही है कि एक समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध खड़ा हुआ हीरो आज ऐसे शर्मनाक भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

आपको ही सब ठीक करना होगा

संकलित
दर्शन

एक बार जब आप सक्रिय रूप से आध्यात्मिक पथ पर चल पड़ते हैं, तो कुछ मूर्ख आपसे कह सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आध्यात्मिक पथ पर होने का मतलब सब कुछ ठीक कर देना नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि चीजें ठीक हों तो आपको उन्हें ठीक करना होगा, और फिर भी केवल कुछ चीजें ही ठीक होंगी, सब कुछ नहीं। आध्यात्मिक पथ पर होने का महत्व आराम तलाशना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को तेजी से आगे बढ़ाना है। इसलिए, जितना आपने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक उतार-चढ़ाव आपके जीवन में घटित हो सकते हैं। जो चीजें दस साल में होतीं, वे दो महीने में हो सकती हैं। सवाल यह है कि आपमें इससे गुजरने का साहस, क्षमता और स्थिरता है या नहीं। यदि आप इस उतार चढ़ाव के समय को बढ़ाना चाहते हैं और आप न जाने कितने जन्म तक वापस आते रहना चाहते हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है। एक बार जब आप गति चाहते हैं और स्थिरता के बिना गति की मांग करते हैं तो आप परेशानी को न्योता दे रहे हैं। साधना को नपे-तुले तरीके से इसलिए बनाया जाता है ताकि एक ओर यह स्थिरता पैदा करती है, दूसरी ओर गति पैदा करती है। यदि आपमें कोई गति नहीं है, तो आप एक कब्र के पत्थर की तरह महसूस करेंगे जो कहीं नहीं जाता। यदि आप बहुत तेज़ हैं, तो यह एक रोलरकोस्टर सवारी जैसा महसूस होता है।

मेहनत से सफलता प्राप्त करना संभव

संकलित
प्रेरणा

एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम सरस्वती था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति और दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति एक मजदूर थे, लेकिन वह ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे। सरस्वती को अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वह अमीर लोगों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करती थी। एक दिन, सरस्वती के पति की एक दुर्घटना में चोट लग गई। वह काम करने में असमर्थ थे, और परिवार की आय पूरी तरह से बंद हो गई। सरस्वती को चिंता थी कि वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगी। सरस्वती ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वह हमेशा खाना बनाना अच्छा करती थी, इसलिए उसने घर का बना खाना बेचने का फैसला किया। उसने अपने पड़ोसियों और दोस्तों को खाना बेचना शुरू किया। उसका खाना इतना स्वादिष्ट था कि जल्द ही गांव में लोकप्रिय हो गया। सरस्वती का व्यवसाय तेजी से बढ़ा। उसने स्थानीय बाजार में अपना खाना बेचना शुरू किया। उसने इवेंट्स की भी कैटरिंग शुरू की। सरस्वती एक अच्छी कमाई करने में सक्षम थी और अपने परिवार का समर्थन कर सकती थी। यह दिखाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए तैयार हैं तो गरीबी को दूर करना और सफलता प्राप्त करना संभव है।

अंतर्मन

आज की पाती

2003 के बाद की चीजें सर्वे में शामिल न हों

भोजशाला में एएसआई सर्वे कर रही है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश पर भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे किया जा रहा है। हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा व आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी सर्वे टीम के साथ रहे। समद ने सर्वे पर आपत्ति जताते हुए उसे रद करने की मांग की है। सदर कमेटी धार के अब्दुल समद खान का कहना है कि 2003 के बाद जो भी चीजें की गई हैं, उनको सर्वे में शामिल न किया जाए। जो चीजें दिख रही हैं, उसे दर्ज करें। हम सर्वे के खिलाफ नहीं हैं। यह बात भी सही है कि सर्वे पूरी तरह से निष्पक्ष रह कर किया जाए ताकि सौहार्द बना रहे।

-रवि कुमार, दिल्ली

ट्रेंड

मरीजों को निकाला

सप्ताहांत में, डब्ल्यूएचओ की टीम विदेश में देखभाल प्राप्त करने के लिए गाजा के कमल अदवान अस्पताल से दो छह वर्षीय मरीजों को निकालने में कामयाब रही। एक बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है, दूसरे को ल्यूकेमिया है। दो देखभालकर्ताओं को निकाला गया।

-टेड्रोस, डब्ल्यूएचओ महानिदेशक

आत्मतत्त्व स्वतः सिद्ध

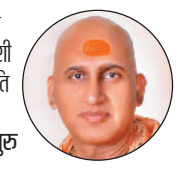

आत्मतत्त्व स्वत: सिद्ध और सनातन है। उसी परम तत्व की अनुभूति हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अपने शाश्वत-अविनाशी स्वरूप का बोध न होना एवं आत्म विस्मृति ही हमारे दु:ख का मूल कारण है।

-अवधेशानंद, आध्यात्मिक गुरु

रोज़गार क्रांति का संकल्प

नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके पास रोज़गार के लिये कोई योजना थी भी? यही सवाल आज हर युवा की ज़ुबान पर है। आखिर हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का झूठ क्यों बोला गया था? कांग्रेस ने युवा न्याय के तहत रोज़गार क्रांति का संकल्प लिया है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

मरूद्यान बना लिया

वे कहते हैं कि आपको किसी भी चीज़ को बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए, लेकिन महिंद्रा ने बस यही किया है, चट्टानों और रेत से अपना खुद का मरूद्यान बना लिया है, जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन कर सकता है।

-आनंद महिंद्रा, उद्योगपति

करंट अफेयर

मुइज्जू पड़ोसियों के साथ मतभेद दूर करें : सोलिह

मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपने उत्तराधिकारी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को 'अड़ियल' रवैया छोड़ने और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ोसियों के साथ बातचीत करने की सलाह दी। सोलिह ने यह टिप्पणी तब की जब कुछ दिन पहले चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने भारत से द्वीपीय देश को ऋण राहत देने का आग्रह किया था। मुइज्जू (45)ने पिछले साल सितंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में सोलिह (62) को हराया था। माफन्नू के चार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते माले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोलिह ने कहा कि उन्होंने मीडिया में छपी खबरें देखी हैं जो बताती हैं कि मुइज्जू ऋण पुनर्गठन के लिए भारत से बात करना चाहते हैं। अधाधु डॉट कॉम नामक समाचार वेबसाइट के मुताबिक सोलिह ने कहा, ''लेकिन वित्तीय चुनौतियां भारत के ऋण के कारण नहीं हैं।'' सोलिह ने कहा कि मालदीव पर चीन का 18 अरब मालदीवियन रूफिया (एमवीआर) का कर्ज है, जबकि भारत का आठ अरब एमवीआर का कर्ज है और उसकी भुगतान अवधि भी 25 साल है। उन्होंने कहा कि हालांकि, मुझे विश्वास है कि हमारे पड़ोसी मदद करेंगे।

ऑफ बीट

खुशी के विज्ञान पर पाठ्यक्रम पढ़ाने से हमने क्या सीखा

जब आप विश्वविद्यालय में एक ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं जो छात्रों को खुशी देता है, तो हर कोई जानना चाहता है कि इसमें क्या राज़ है। आपका तरीका क्या हैं? आपकी शीर्ष दस सिफ़ारिशें क्या हैं? ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले सवाल हैं, जैसे कि खुशी का कोई त्वरित, निश्चित मार्ग है। समस्या यह है कि जीवन में बदलाव लाने वाली कोई नई खोजें नहीं हैं, क्योंकि अधिकांश कार्यों के बारे में पहले ही बात की जा चुकी है। सामाजिक जुड़ाव, सचेतनता, कृतज्ञता पत्र, दयालुता के कार्य, प्रकृति में टहलना, बेहतर नींद, सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करना। ये 80 या उससे अधिक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेपों में से कुछ हैं जिन्हें हमारी भलाई (कुछ हद तक या अधिक हद तक) में सुधार करने के लिए उपयोगी दिखाया गया है, लेकिन अगर हम पहले से ही इतना जानते हैं कि किस चीज से लाभ होता है, तो हम अभी भी खुशी से जुड़े तरीके के लिए अनुरोध क्यों कर रहे हैं? डेटा हमें बताता है कि छात्र और युवा नाखुश हैं, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि यूके और यूएस में युवाओं में खुशहाली सबसे कम है। हमने 2019 में कुछ चिंताजनक गिरावट की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिए ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में खुशी के विज्ञान पाठ्यक्रम को पढ़ाना शुरू किया।

हमारा पता
हरिभूमि कार्यालय
नजदीक इंडस पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, रोहतक-124001 फोनः 9253681019-20
ई-मेल : haribhoomi@gmail.com
वेब-साइट : www.haribhoomi.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 34

मजबूत बैंकिंग जरूरी

तकरीबन एक दशक तक फंसे कर्ज यानी गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में इजाफा होने तथा जोखिम आंकने, खासकर कॉर्पोरेट ऋण के जोखिम के अंकन में शिथिलता के बाद अब देश का बैंकिंग क्षेत्र अच्छी स्थिति में नजर आ रहा है। उसका मुनाफा बढ़ रहा है और निवेशकों का विश्वास नए सिरे से बहाल हो रहा है। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री तथा इंडिया बैंक्स एसोसिएशन के एक सर्वेक्षण में इसकी पुष्टि हुई है। सर्वेक्षण में 23 बैंकों को शामिल किया गया था और उसने दिखाया कि बैंकिंग क्षेत्र कई मानकों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें परिसंपत्ति की गुणवत्ता तथा ऋण वृद्धि शामिल थी। सर्वे के निष्कर्षों में यह भी कहा गया कि बैंक अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) व्यवस्था को अपनाने को भी तैयार हैं और वे जलवायु अनुकूलन तथा उत्सर्जन में कमी की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। इसमें पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां अपनाने को आर्थिक मदद देने, कागज का इस्तेमाल कम करने तथा तटीय इलाकों में जैव ईंधन का इस्तेमाल रोकने जैसे कदम शामिल हैं। ये पर्यावरण, सामाजिक और संचालन (ईएसजी) पहलों का हिस्सा हैं। सर्वेक्षण में शामिल बैंकों में से 83 फीसदी ने कहा कि उनके ऋण मानक आसान हुए हैं या अपरिवर्तित रहे हैं। उन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक वृद्धि का अनुमान दर्शाया, एनपीए में कमी आने की बात कही और कहा कि क्षेत्रवार जोखिम में कमी आने की उम्मीद है। चुनिंदा क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक ऋण वितरण में इजाफा हुआ है। इसमें अधोसंरचना, लौह और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण तथा औषधि क्षेत्र शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही क्षेत्र हैं जहां एनपीए का स्तर भी अधिक है। अगर इन क्षेत्रों की पहुंच आसान ऋण तक बनी रहती है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बैंकों को एक बार फिर फंसे हुए कर्ज के चक्र में फंसने से बचना चाहिए। आमतौर पर बैंक अपने बही खातों में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को लेकर संतुष्ट हैं। सर्वेक्षण में शामिल 77 फीसदी बैंकों ने कहा कि बीते छह महीनों में उनके एनपीए में कमी आई है। आधे से अधिक बैंकों का मानना है कि अगले छह महीनों में सकल एनपीए 3-3.5 फीसदी के दायरे में रहेगा। यह आशावाद बेवजह नहीं है क्योंकि सकल एनपीए वित्त वर्ष 2018 के अंत के 11.6 फीसदी से कम होकर गत वर्ष सितंबर में 3.2 फीसदी रह गया था। फंसे हुए कर्ज में नया इजाफा भी कम हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि इससे बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार होगा।

यह बहुत राहत की बात है क्योंकि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंक अच्छी हालत में हैं। बहरहाल भविष्य के मुनाफे को लेकर चिंता बरकरार है। सर्वेक्षण में अधिक ब्याज दर वाले जमा की ओर स्पष्ट बदलाव देखने को मिला। करीब 70 फीसदी बैंकों ने कहा कि कुल जमा में करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट (कासा) जमा की हिस्सेदारी कम हुई है। कासा कम लागत वाली जमा राशि है जो बैंकों द्वारा जुटाई जाती है। कम लागत वाली जमा राशि का अर्थ है कम मुनाफा मार्जिन। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के आपस में जुड़े होने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने से संकट के समय हालात मुश्किल हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने हालिया प्रकाशनों में इस बढ़ते जुड़ाव को रेखांकित किया था। इस संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने फंडिंग स्रोत में विविधता लानी चाहिए और उसे बैंकिंग से इतर ले जाना चाहिए। बहरहाल, बैंकिंग क्षेत्र की सेहत में सुधार से अर्थव्यवस्था में वृद्धि को गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने महामारी के बाद आर्थिक सुधार को मदद देने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाया और अब वक्त आ गया है कि निजी क्षेत्र पूंजीगत व्यय में इजाफा करे। बेहतर बैंक बैलेंस शीट से यह बदलाव संभव हो सकता है।

बिनय सिन्हा

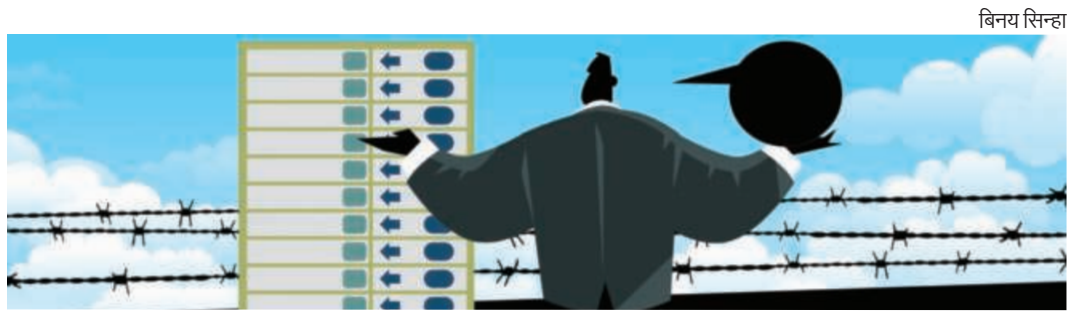

राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थान

एक फलते-फूलते लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महत्त्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही संवैधानिक रूप से सशक्त संस्थानों को मजबूती प्रदान करना भी अहमियत रखता है। बता रहे हैं श्याम सरन

भारत में अठारहवीं लोक सभा के चुनाव आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक होने जा रहे हैं। यह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा आयोजन है और इसका प्रबंधन करना खासा चुनौतीपूर्ण है। 1.4 अरब की आबादी में करीब एक अरब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों का चुनाव करेंगे जो अगले पांच वर्ष तक उन पर शासन करेंगे। ऐसा अन्य उदाहरण नहीं मिलता और यह सभी भारतीयों के लिए जश्न और गौरव का विषय है। लोकतंत्र के लिए केवल चुनाव पर्याप्त नहीं हैं लेकिन वे इसके लिए अनिवार्य हैं। वे चुने हुए राजनीतिक नेतृत्व को वैधता प्रदान करते हैं ताकि वह शासन कर सके। यह दीगर विषय है कि ऐसे नेतृत्व का समझदारी और जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल किया जाता है या नहीं।

लोकतंत्र की अवधारणा छठी सदी ईसा पूर्व के एथेंस में देखी जा सकती है जहां पहली बार जनता के शासन का विचार सामने रखा गया। समय के साथ 'लोगों' की परिभाषा बदलती गई और इस दौरान यह अधिक समावेशी होती गई। जिन लोगों को अपने नेता चुनने का अधिकार था वे संपत्ति धारण करने वाले हो सकते थे। महिलाओं को इससे बाहर रखा गया क्योंकि उन्हें दास माना जाता था। लोकतंत्र का अर्थ समानता नहीं था। बहरहाल, सीमित दायरे में ही सही प्रतिनिधित्व वाली सरकार को राजनीतिक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया।

इसके विपरीत राष्ट्रवाद अपेक्षाकृत नया विचार है। इसकी जड़ें सत्रहवीं सदी में तलाश की जा सकती हैं जब यूरोप में तीस वर्ष के युद्ध के बाद वेस्टफेलिया का शांति समझौता हुआ था। इससे ऐसे नियम उभरे जो यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर काबिज सत्ताओं के बीच के रिश्तों का संचालन करने वाले थे। हर सत्ता को मानचित्र पर तय ढंग से अपनी क्षेत्रीय सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होता था जिसे अन्य देश मान्यता प्रदान करते थे। इन सीमाओं के भीतर राजनीतिक संस्थाओं को अधिकार प्राप्त होते हैं और उनके पास शक्तियों के स्तर पर भी एकाधिकार होता है। इसी आधार पर क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उनके संप्रभु नियंत्रण को पहचाना जाता, अन्य संस्थाओं द्वारा उनका सम्मान भी किया जाता और इसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। यह इतिहास का सबसे अहम राजनीतिक और वैचारिक घटनाक्रम था। इसके साथ ही राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की अवधारणा पैदा हुई। एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा भी मानचित्रों की कला में प्रगति से संभव हुई क्योंकि उसकी बदौलत सटीक सीमांकन संभव हुआ।

अपने शुरुआती दौर में राष्ट्रवाद जातीय पहचान और संबद्धता से जुड़ा था। देशों के बारे में अक्सर यही माना जाता था कि वे साझा इतिहास और संस्कृति वाले जातीय समूहों से बने होते थे। राष्ट्रवाद ने ऐसी जातीय पहचानों पर नए सिरे से जोर दिया। परंतु ऐसे देश उदाहरण के लिए फ्रांस और जर्मनी आदि 18वीं और 19वीं सदी में बहु जातीय, बहु सांस्कृतिक और बहु धार्मिक साम्राज्यों के साथ मौजूद रहे। इनमें ऑस्ट्रियन-हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये कई देशों में बंट गए जो अधिकतर साझा जातीयता पर आधारित थे। रूस इसका अपवाद था जहां 1917 की क्रांति के पश्चात जार के दौर के बहु जातीय और बहु धार्मिक साम्राज्य के स्थान पर सोवियत समाजवादी साम्राज्य तैयार हुआ। यह सात दशक तक बना रहा और फिर इसका भी कई राष्ट्र राज्यों में विभाजन हो गया। ये नए राज्य पुरानी जातीय और सांस्कृतिक पहचानों पर आधारित थे, बस सोवियत संघ का हिस्सा होने के कारण अब उनमें अन्य जातीयताओं के लोग भी शामिल हो गए थे और यह उनके बीच आपसी तनाव की वजह भी बना जैसा कि हमने हाल ही में नगोर्नो कराबाख को लेकर अजरबैजान और अर्मीनिया के विवाद में देखा। बहरहाल कई देश बहु जातीय और बहुधार्मिक भी बन गए और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण थे। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ जातीयता भी लोगों की राष्ट्रीयता में अहम भूमिका निभाती है।

एक वास्तविक बहुलतावादी राज्य अधिक हाल की घटना है और इसके सूत्र दूसरे विश्व युद्ध के दौर में तलाशे जा सकते हैं जब बड़े पैमाने पर प्रवासियों ने असाधारण तरीके से राष्ट्रीय सीमाएं पार की थीं और समता के विचार ने जोर पकड़ा। यूरोप के कई देश तथा अमेरिका बहुलतावादी देश बन गए। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि नागरिकता का आधार जातीय, सांस्कृतिक या धार्मिक नहीं रहा बल्कि राज्य के प्रति वफादारी इसकी वजह बन गई। स्वतंत्र भारत ने भी इसे अपनाया। इसकी वजह से प्रवासियों और मूल समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है और बनती है।

एक राष्ट्र राज्य को लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि लोकतंत्र हर नागरिक को देश की सफलता में हिस्सेदारी देकर राष्ट्रवाद को बल दे सकता है। दो शक्तिशाली राजनीतिक विचारों यानी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के साथ आने से देश बनाने वाले लोगों में बदलाव आ सकता है।

भारतीय संविधान का निर्माण करने वालों के सामने एक अहम चुनौती यह थी कि सन 1947 में औपनिवेशिक शासन से आजाद होने वाले भारतीय राष्ट्र राज्य के लिए कौन सी राह तय की जाए। क्या भारत की विविधता और बहुलता को देखते हुए उसे एक राष्ट्र राज्य बनाया जा सकता था? कौन सी बात इसे जोड़े रखती? उन्होंने यह निर्णय लिया कि देश की विविध पहचानों को दबाकर राष्ट्र की भावना पैदा करने की कोशिश आत्मघाती होगी। उन्होंने नागरिकता की एक व्यापक अवधारणा तैयार की जो मौजूदा धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का दमन नहीं करती थी। उन्होंने एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिष्ठान का चयन किया जिसने देश के नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया कि वे अपनी पसंद का नेता चुन सकें। चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी से ही राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। इसके अलावा लोकतंत्र उस बहुलता की गुंजाइश तैयार करता है जो भारत को परिभाषित करती है।

भारत में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद दोनों उसके बदलाव के मजबूत उपकरण हैं लेकिन अन्य मजबूत उपकरणों की तरह उनका भी समुचित इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देश के संविधान में बहुत हद तक संवैधानिक अधिकार प्राप्त संस्थानों और प्रक्रियाओं के रूप में ऐसे उपाय शामिल किए गए हैं जो जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करते हैं। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है लेकिन केवल संविधान में उल्लिखित नियमों के अनुरूप ही शासन किया जा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव इस दिशा में पहला और अपरिहार्य कदम है। जनता और उसके कल्याण के प्रति जवाबदेह संवैधानिक रूप से सशक्त संस्थानों को मजबूत बनाए रखने की प्रतिबद्धता को भी राष्ट्रीय एजेंडे में प्राथमिकता पर रखना चाहिए।

(लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं)

चुनावी वित्त-व्यवस्था के लिए बेहतर समाधान

चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनावों की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही भारत दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कमर कस रहा है। आगामी चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के बीच हाल में हुए दो महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम ने नागरिकों को देश की चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया में सुधार के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त विचार और वजहें दी हैं। पहली, रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट है, जिसने देश में एक साथ चुनाव कराने की व्यावहारिकता का अध्ययन किया। दूसरा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का फैसला है जो निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम देने वाला है।

कोविंद समिति ने एकमत से एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप भी दिया है। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के पीछे एक कारण नीति और शासन संबंधी अनिश्चितता को कम करना है। राजनीतिक दल अक्सर एक के बाद एक अगले राज्य चुनाव की तैयारी में बंध जाते हैं। रिपोर्ट में पेश किए गए तकनीकी कार्य से अंदाजा मिलता है कि एक साथ चुनाव कराने से आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति और सार्वजनिक व्यय जैसे क्षेत्रों में सुधार दिख सकता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से एक साथ चुनाव कराने के विचार में दम है, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। यदि अगली सरकार इन सुझावों पर आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें यह सलाह देना बेहतर होगा कि वे इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें।

हालांकि, देश में एक अहम मुद्दा चुनावी/राजनीतिक फंडिंग है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अदालत ने इस योजना में गोपनीयता के बिंदु को ही खारिज कर दिया और इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करने का कोई औचित्य नहीं पाया है जिसे केवल अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित शर्तों के तहत ही प्रतिबंधित किया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था और उसने अदालत के निर्देश के मुताबिक ही चंदा देने वालों और लाभार्थी दलों के बारे में जानकारी दी है। निश्चित रूप से यह जानना दिलचस्प है कि किसने किसको चंदा दिया है और लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि भारत में राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए एक बेहतर प्रणाली की आवश्यकता है। हालांकि शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना कोई समाधान नहीं है।

अर्थतंत्र

राजेश कुमार

2014 के एक अध्ययन में बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में चुनावों पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे जिसमें से लगभग आधी पूंजी उन स्रोतों से आई जिसके बारे में वैध जानकारी नहीं थी। यह मान लेना अनुचित नहीं होगा कि अब तक इस खर्च की रकम आसानी से दोगुनी हो गई होगी। पैसा स्पष्ट रूप से देश के ही तंत्र से जुटाया जाता है और इसका नीति और शासन पर प्रभाव पड़ता है।

बड़ी मात्रा में धन के इस्तेमाल से राजनीति में दीर्घकालिक समस्याएं पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, जितना ज्यादा पैसा राजनीति में आता है उसमें नए लोगों के प्रवेश करने में बाधाएं और भी बढ़ जाती हैं। इसमें प्रवेश करने में बड़ी बाधाएं अक्सर बाजार और राजनीति दोनों के लिए ही खराब परिणाम की ओर ले जाती हैं। चुनाव की फंडिंग से जुड़ी समस्या को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, संग्रह और खर्च। खर्च के संदर्भ में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों पर प्रतिबंध है कि वे कितना खर्च कर सकते हैं लेकिन राजनीतिक दलों पर इस लिहाज से कोई प्रतिबंध नहीं है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा वाला प्रावधान ठीक से लागू नहीं किया जाता है और शायद इसकी उचित निगरानी के अभाव का एक प्रमुख कारण राज्य की क्षमता की कमी है। यह बेहद जरूरी है कि इन सीमाओं को सख्ती से लागू किया जाए और उल्लंघन करने वालों को तुरंत फटकार लगाई जाए।

निर्वाचन आयोग (ईसीआई) अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त करने या इस उद्देश्य के लिए सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ जुड़कर एक तंत्र तैयार कर सकता है। चुनावी खर्च से जुड़ी जानकारी की मांग की समस्या पर प्रभावी ढंग से ध्यान देने से स्वतः ही फंड की आपूर्ति या बड़ी मात्रा में रकम जुटाने की आवश्यकता से जुड़ी समस्याओं का हल कुछ हद तक किया जा सकता है।

संग्रह सुधारों के संदर्भ में शुरुआती बिंदु यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि हर रुपये का हिसाब हो। भारत भुगतान समाधानों में वैश्विक स्तर पर अगुआई कर रहा है इसलिए नकद चंदे के विकल्प को आसानी से दूर किया जा सकता है। इसके समाधान के लिए अक्सर सरकार की तरफ से चुनावों की फंडिंग करने का सुझाव दिया जाता है और वास्तव में इसे विभिन्न देशों में विभिन्न रूपों में अपनाया है। हालांकि, यदि इसके लिए प्रासंगिक संस्थागत प्रणाली नहीं होगी तब इससे मदद मिलने की संभावना नहीं होगी। उचित सुरक्षा उपायों के बिना राजनीतिक दल अपने संसाधनों को सरकारी निधि से जोड़ सकते हैं। कुछ विश्लेषकों ने चुनाव के बजाय राजनीतिक दलों की फंडिंग का सुझाव दिया है। एक अन्य विकल्प यह है कि स्वतंत्र रूप से प्रबंधित राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं और आयकर लाभ का दावा कर सकते हैं। इस फंड का वितरण राजनीतिक दलों के बीच पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित ऑडिट की शर्त पर पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर किया जा सकता है। इस फॉर्मूले के तहत विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच और पिछले चुनावों में एक निश्चित संख्या में मिले मतों जैसे कारकों पर विचार किया जा सकता है। इससे चंदा देने वालों का डर भी खत्म होगा क्योंकि वे एक राष्ट्रीय कोष में दान कर रहे होंगे और उनका इसके वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। इसके अलावा, यह प्रणाली कंपनियों द्वारा सरकार की नीति पर नियंत्रण बनाने के जोखिम को भी दूर कर सकती है क्योंकि यह चंदा पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर कई राजनीतिक दलों में वितरित किया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था चंदा देने वालों को भी राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने की संतुष्टि भी देगी। चूंकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में अपने मन से चयन की स्वतंत्रता भी संरक्षित की जानी चाहिए। ऐसे में व्यक्तियों और कंपनियों को भी सीधे राजनीतिक दलों के लिए योगदान देने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, ऐसे सभी लेनदेन का खुलासा किया जाना चाहिए और तिमाही आधार पर राजनीतिक दल ही इसका खुलासा करें तो बेहतर है।

इस तरह की प्रणाली भले ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगी लेकिन निश्चित रूप से इससे राजनीतिक फंडिंग से जुड़ा असंतुलन कम किया जा सकेगा और पारदर्शिता आ सकती है। चूंकि यह मुद्दा बेहद अहम है इसलिए अगली सरकार इस मामले की व्यापक जांच के लिए एक पैनल का गठन कर सकती है और दुनिया भर में इस परिप्रेक्ष्य में किस तरह के कदम उठाए जाते हैं उनका अध्ययन कर समाधान सुझा सकती है। ऐसी रिपोर्ट स्वस्थ सार्वजनिक बहस और बाद की नीतिगत कार्रवाई के लिए एक अच्छी शुरुआत साबित होगी।

आपका पक्ष

भारत के डॉक्टरों का पलायन

लेख 'भारत के 2,000 डॉक्टरों को नौकरी देगा ब्रिटेन' भारत से उच्च प्रशिक्षित डॉक्टरों के पलायन पर गंभीर चर्चा करता है। इसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत सरकार इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाए और अपने देश में उनको पर्याप्त अवसर और वेतन का प्रावधान करे। देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत कमी है। सरकार किडनी, कैंसर, लीवर, हृदय रोग, बाल रोग, न्यूरोलॉजी, स्त्री रोग, सर्जरी आदि के विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाकर उनको सम्मानजनक राशि के प्रावधान के साथ नियुक्त करें जिससे सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा की आधुनिक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। सरकार को डॉक्टरों की प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में डॉक्टरों को पर्याप्त वेतनमान देकर देश की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

सरकार को डॉक्टरों के प्रतिभा पलायन पर नियंत्रण करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए

गलत कारोबारी से चंदा न ले राजनीतिक दल

चुनाव में धन वही देगा जो सत्ता गठन के बाद उससे लाभ की या व्यापार की आशा रखता है। किसी दल ने किससे कितना धन लिया यह जानकर जनता क्या करेगी? चुनावी चंदा पारदर्शी रहे तो जनता का क्या फायदा होगा? गलत कारोबार में संलग्न कंपनियों से चंदा नहीं लेना चाहिए।

प्रदीप गौतम सुमन, रीवा

चुनावी बॉन्ड पर रोक उचित फैसला

मतदाता को यह जानने का हक है कि राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से किसके द्वारा आता है। चुनावी बॉन्ड के मामले में दल बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं अपना रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के तहत जनता को पूरी जानकारी न देना सूचना के अधिकार का उल्लंघन भी है। उच्चतम न्यायालय का चुनावी बॉन्डों पर रोक का फैसला हर तरह से उचित है।

मनमोहन राजावत, शाजापुर

फायदे के खेल पर रोक

चुनावी चंदा देने वाले गोपनीयता की आड़ में सरकारों से कई तरह से फायदे लेने की कोशिश कर सकते हैं। आमतौर पर ये फायदे आम जनता के हितों के खिलाफ हो सकते हैं। चुनावी बॉन्ड के आंकड़े बताते हैं कि एक लॉटरी कंपनी ने 1,300 करोड़ रुपये से अधिक का चंदा दिया है और कंपनी वर्षों से आयकर विभाग की जांच के घेरे में है। चुनावी चंदे की पारदर्शी व्यवस्था का मामला चुनाव सुधारों से जुड़ना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

चुनावों में बेवजह खर्च की जरूरत ही क्या

चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को ही फायदा होता है क्योंकि उन्हें चुनाव के समय अपने प्रचार प्रसार के लिए मुफ्त का पैसा मिल जाता है। इस बात की क्या गारंटी है कि चुनावी चंदे का सारा सच देश के सामने आ ही जाएगा? क्योंकि पर्दे के पीछे गलत काम होते हैं। यह भी हो सकता है कि चुनावी बॉन्ड के जरिये काले धन को खपाया जाता हो। इसलिए चुनावी बॉन्ड का खेला ही खत्म कर देना चाहिए। चुनावों में बेवजह खर्च करने की आखिर जरूरत ही क्या है?

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

बांग्लादेश के 53वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सिलिगुड़ी में मंगलवार को बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मिठाइयों का आदान-प्रदान किया।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 27 मार्च, 2024

दैनिक जागरण

जोखिम ही प्रतिफल का निर्धारण करता है

कांग्रेस छोड़ो अभियान

चुनावों से पहले नेताओं का पालाबदल कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का जैसा सिलसिला कायम है, वह देश के इस सबसे पुराने दल की दयनीय दशा और स्याह भविष्य को ही रेखांकित करता है। हालांकि भाजपा और कुछ अन्य दलों के चंद नेता कांग्रेस की शरण में भी गए हैं, लेकिन इसकी तुलना में उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने की संख्या कहीं अधिक है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की संख्या जिस तेजी से बढ़ती चली जा रही है, उससे तो यह लगता है कि पार्टी छोड़ो जैसा कोई अभियान चल रहा है। गत दिवस लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू भी भाजपा में शामिल हो गए। उनके कांग्रेस छोड़ने से पार्टी नेतृत्व को हैरान-परेशान होना चाहिए, लेकिन शायद ही ऐसा हो, क्योंकि राहुल गांधी आम तौर पर ऐसे नेताओं को डरपोक या अवसरवादी करार देकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। वह और उनके करीबी यह देखने-समझने के लिए तैयार नहीं कि आखिर क्या कारण है कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह का भाजपा में जाना इसलिए कांग्रेस के लिए एक बड़ा आघात है, क्योंकि पंजाब उन राज्यों में है, जहां कांग्रेस अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है और भाजपा तीसरे-चौथे नंबर के दल के तौर पर देखी जाती है।

इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस छोड़ने वालों में कई ऐसे नेता भी हैं, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते थे, जैसे अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा, सुरेश पचौरी। इसके पहले राहुल गांधी की युवा ब्रिगेड के सदस्य कहे जाने वाले अधिकांश नेता भी कांग्रेस से विदा ले चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में एक बड़ी संख्या उनकी है, जो अपने जनाधार के लिए जाने जाते हैं। गांधी परिवार के करीबी नेताओं में बहुत कम ऐसे हैं, जो अपने बलबूते चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। राहुल गांधी भले ही यह दिखाएं कि कांग्रेस नेताओं के जाने से पार्टी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो यह है अब फर्क पड़ता दिख रहा है। कुछ नेता चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं और कुछ तो प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपने कदम पीछे खींच चुके हैं। कांग्रेस भले ही यह दिखा रही हो कि वह भाजपा का मुकाबला करने मे समर्थ है, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि वह अपने नेतृत्व वाले मोर्चे आइएनडीआइए को वैसा आकार नहीं दे सकी, जिसकी आशा की जा रही थी। इसके लिए कांग्रेस अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस का क्षरण इसलिए शुभ संकेत नहीं, क्योंकि भाजपा के समक्ष वही सही मायने में एक राष्ट्रीय दल है। अन्य राष्ट्रीय दलों में कोई भी ऐसा नहीं, जिसकी जड़ें देश भर में हों। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी आवश्यक होता है, लेकिन सत्तापक्ष उसकी मजबूती की चिंता नहीं कर सकता।

सुरक्षित चार धाम यात्रा

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा इस वर्ष मई से शुरू होने वाली है। यात्रा को सुरक्षित व निरापद बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। यद्यपि, चुनाव आचार संहिता के बीच शुरू होने वाली इस यात्रा को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कारण यह कि चार धाम यात्रा के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी परिवहन, पुलिस, पर्यटन व लोक निर्माण विभाग के अधिकांश कार्मिक चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे। इन सबके बीच सीमित कार्मिकों से चार धाम यात्रा का सुव्यवस्थित संचालन आसान नहीं होगा। सरकार के निर्देशानुसार सभी संबंधित विभाग व जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। बदरीनाथ व केदारनाथ धाम में चिकित्सालय बन कर तैयार हैं। यहां उपकरणों की खरीद को स्वीकृति मिल चुकी है। अब यहां चिकित्सक व स्वास्थ्य कार्मिकों के तैनाती की तैयारी चल रही है। चार धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए संवेदनशील व दुर्घटना संभावित स्थलों पर सीसी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस विभाग के संचार संवर्ग को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इसका उद्देश्य चार धाम यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखना और आपात स्थिति में त्वरित राहत व बचाव कार्यों का संचालन करना है। भूस्खलन के कारण यात्रा प्रभावित न हो, इसके लिए भारी मशीनें तैनात की जाएंगी। साथ ही यात्रा के लिए चार अप्रैल से आनलाइन ग्रीन कार्ड बनाने की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। सरकार के लिए राहत यह है कि प्रदेश में पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में यात्रा शुरू होने से पहले विभाग को तैयारियां करने का मौका मिल जाएगा।

चार धाम यात्रा के लिए सभी तरह की अनुमति को अभी से भारत निर्वाचन आयोग से पत्राचार किया जाना चाहिए

नागरिकता कानून पर विषवमन

बलबीर पुंज

जिस सीएए को विवादों में घसीटने का प्रयास हो रहा है, वह तो भारत के मानवतावादी और बहुलतावादी सनातन डीएनए के अनुरूप ही है

एक आवश्यक कानूनी पहल है नागरिकता संशोधन अधिनियम। फाइल

इन दिनों नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का मामला चर्चा में है। यह मामला अदालत के साथ ही सार्वजनिक विमर्श के दायरे में भी है। किसी भी कानून पर नजरिये में भिन्नता बहुत स्वाभाविक है, मगर कुछ दल तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए तथ्यों की अवहेलना करते हुए समाज में घृणा और भय फैलाने के साथ मिथ्या आरोप लगाने में व्यस्त हैं। कहा जा रहा है कि सीएए संविधानसम्मत नहीं है और यह अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करता है। इसका निर्णय तो शीर्ष अदालत ही करेगी, परंतु इस मामले में भड़काऊ बयानबाजी हैरान करने वाली है। बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वे सीएए को लागू नहीं होने देंगे, जबकि इस कानून का राज्य सरकारों से कोई लेना-देना नहीं।

शरद पवार इस कानून को लोकशाही पर आक्रमण कह रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी इस कानून को गोडसे के सोच वाला बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान तो और भी अचंभित करने वाला रहा। उन्होंने सीएए को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि 'पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में करीब ढाई-तीन करोड़ अल्पसंख्यक हैं। यदि इनमें से एक-डेढ़ करोड़ भी भारत आ जाएं, तो हम उन्हें कहां बसाएंगे? नौकरी कैसे देंगे? पूरी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी..यह 1947 से भी बड़ा प्रवास होगा..।' क्या यह बयान भड़काऊ नहीं? केजरीवाल दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी सरकार विदेशी अल्पसंख्यकों को भारत आने का निमंत्रण देने जा रही है, जबकि सीएए तो उनके लिए है जो संबंधित तीन पड़ोसी देशों में मजहबी प्रताड़ना से परेशान होकर 2014 से पहले भारत आ गए थे। ऐसे शरणार्थियों से कानून एवं व्यवस्था को खतरा पहुंचने की बात कहने वाले क्या देश में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी-रोहिंग्या मुसलमानों की स्थिति को देखते हैं? राजधानी दिल्ली सहित देश के कई क्षेत्रों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बसे हुए हैं। कुछ घटनाओं पर गौर करें तो 6 मार्च, 2021 को दिल्ली-एनसीआर में लूटपाट एवं डकैती की दर्जनों वारदात कर चुके तीन बांग्लादेशी बदमाशों, 22 अक्टूबर, 2020 को राजधानी के कई क्षेत्रों में एटीएम उखाड़कर ले जाने वाले बांग्लादेशियों, 6 अगस्त 2019 को कर्नाटक की एक डकैती में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले दो बांग्लादेशियों को पुलिस ने पकड़ा था। हरियाणा स्थित नूंह में गत वर्ष शोभायात्रा पर पथराव करने वालों में रोहिंग्या मुस्लिम भी शामिल थे। इसी तरह हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस बल पर हमले के पीछे भी कई रोहिंग्याओं के हाथ होने का आरोप है। ऐसी एक अंतहीन सूची है। क्या सीएए का विरोध कर रहे लोगों ने रोहिंग्या-बांग्लादेशी मुसलमानों से जुड़ी इन आपराधिक घटनाओं के खिलाफ कुछ बोला या उन्हें 'राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा' माना?

स्वघोषित सेक्युलरवादी और 'लेफ्ट-फासिस्ट' अवैध रूप से भारत में घुसे उन रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने के साथ सम्मानजनक नौकरी सहित अन्य सुख-सुविधा देने का प्रत्यक्ष-परोक्ष समर्थन करते हैं, जिनके बंधु-बांधव अपने मूल देश म्यांमार में असंख्य हिंदू-बौद्ध अनुयायियों का नरसंहार कर चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, अगस्त 2017 में रोहिंग्या आतंकियों ने म्यांमार में अलगाववाद से ग्रस्त प्रांत रखाइन में 99 हिंदुओं को तालिबानी तरीके से मौत के घाट उतारकर उनकी महिलाओं का मतांतरण किया था। जांच पश्चात मृत हिंदुओं के शव एक सामूहिक कब्र में मिले थे। संयुक्त राष्ट्र के एक जांच दल ने अक्टूबर 2023 में इसे 'अंतरराष्ट्रीय अपराध' घोषित किए जाने की अनुशंसा की थी। इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड और जिहादियों को स्थानीय रोहिंग्या मुस्लिमों का समर्थन मिलने के बाद 2017 में म्यांमार सत्ता-अधिष्ठान सैन्य कार्रवाई के लिए बाध्य हुआ था। इसके चलते लाखों रोहिंग्या मुसलमान सुरक्षित ठिकाने की खोज में म्यांमार से पलायन कर गए। क्या इसके बाद उनके आचरण में कोई बदलाव आया? दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार ने सितंबर 2017 की एक रिपोर्ट में प्रकाशित किया था कि म्यांमार से शरणार्थी बनकर बांग्लादेश के काक्स बाजार पहुंचे रोहिंग्या मुस्लिम राहत शिविरों में रोहिंग्या हिंदू महिलाओं का जबरन सिंदूर मिटाकर, चूड़ियां तोड़कर और मतांतरण करके उन्हें दिन में पांच बार नमाज पढ़ने के लिए विवश कर रहे थे। स्वयंभू सेक्युलरवादियों का यही वर्ग पाकिस्तान के उन अहमदिया मुस्लिमों से भी सहानुभूति रखता है, जिनका भारत के रक्तरंजित विभाजन में बड़ा योगदान रहा।

जिस सीएए को विवादों में घसीटने का प्रयास हो रहा है, वह कानून तो भारत के मानवतावादी एवं बहुलतावादी सनातन डीएनए के अनुरूप ही है। इजरायली प्रतिकार में तबाह गाजा-पट्टी के मुस्लिमों को राहत-सामग्री पहुंचाना, संकटग्रस्त अफगानिस्तान को रसद आपूर्ति करना और आपदाग्रस्त तुर्की में 'आपरेशन दोस्त' से राहत-बचाव कार्य चलाना इसका जीवंत प्रमाण है। चीनी आक्रमण के बाद भारत ने तिब्बती बौद्ध अनुयायियों को ऐसी ही सुविधाएं प्रदान की थीं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी मजहबी कारणों से सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देते रहे है। 1989-90 में अमेरिकी सीनेटर फ्रैंक लौटेनबर्ग के प्रयासों से अमेरिका ने सोवियत संघ और ईरान के अल्पसंख्यकों को शरण और नागरिकता प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया था। इस संशोधन के अंतर्गत ईरान में अल्पसंख्यक ईसाई, बहाई और यहूदियों को उनके धार्मिक उत्पीड़न पर शरण और नागरिकता दी गई। इसी तरह ब्रिटेन में 'राष्ट्रीयता और सीमा अधिनियम' के माध्यम से गुलामी और मानव तस्करी के पीड़ितों को नागरिकता और शरण देने का प्रस्ताव है। इस पृष्ठभूमि में विदेश में मजहबी कारणों से उत्पीड़न का सामना कर रहे हिंदू-सिख अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएंगे? विभाजन के बाद भारत में जहां मुसलमानों की संख्या छह गुना से अधिक बढ़ गई है, वहीं पाकिस्तान में हिंदू-सिख आबादी 16 प्रतिशत से घटकर दो प्रतिशत से भी कम, तो बांग्लादेश में हिंदू-बौद्ध आबादी हिस्सेदारी 28 प्रतिशत से गिरकर आठ प्रतिशत रह गई है। अफगानिस्तान में 1970 में सात लाख गैर-मुसलमान थे, जो गृहयुद्ध, मजहबी हिंसा और तालिबानी राज में घटकर अंगुलियों पर गिनने लायक बचे हैं। क्या भारत हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों का प्राकृतिक घर नहीं? इस प्रश्न का उत्तर सीएए में समाहित है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

चुनावी चंदे का चक्रव्यूह

राजीव सचान

चुनावी चंदे की पारदर्शी प्रक्रिया की मांग करना जितना आसान है, ऐसी प्रक्रिया बनाना उतना ही कठिन

राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के जरिये चंदा देने की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बांड का जो विवरण सार्वजनिक किया, उसके अनुसार चुनावी बांड के जरिये सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिला। यह स्वाभाविक है, क्योंकि वह केंद्र के साथ कई राज्यों में सत्ता में है। चंदा अन्य विरोधी दलों को भी मिला है, लेकिन वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उन्हें मिला चंदा तो जायज है, लेकिन जो भाजपा को मिला, वह नाजायज है। चुनावी बांड के जरिये चंदा देने की व्यवस्था ने दो चिंताजनक पहलू उभारे हैं। एक यह कि कई ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया, जिनके खिलाफ सीबीआइ, ईडी अथवा आयकर विभाग की जांच चल रही थी। चूंकि ऐसी कुछ कंपनियों को चंदा देने के आगे-पीछे ठेके भी मिले, इसलिए यह संदेह उभरा है कि कहीं केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में तो इन कंपनियों ने अपनी जेब नहीं ढीली की? कांग्रेस ने तो यह कहने में संकोच भी नहीं किया कि चुनावी बांड के जरिये 'चंदा दो-धंधा लो' का खेल चल रहा था। सच क्या है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जिन दलों को चुनावी बांड के जरिये चंदा मिला और जो इस तरह से चंदे के लेन-देन को गलत मानते हैं, वे उसे वापस कर दें? खैर, दूसरा चिंताजनक पहलू यह है कि कुछ ऐसी कंपनियों ने भी चंदा दिया, जो घाटे में चल रही थीं। एक पहेली यह भी है कि चुनावी बांड से चंदा देने वालों में कुछ नामी कंपनियों के नाम नहीं दिखे। क्या यह मान लिया जाए कि उन्होंने किसी को चंदा दिया ही नहीं? जिन कुछ कंपनियों को लक्ष्य करके यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनसे चंदा उगाही की, उन्होंने अन्य राजनीतिक दलों को भी चंदा दिया है। क्या उन्होंने भी चंदा उगाही की है?

चुनावी बांड के पहले चंदे की व्यवस्था पूरी तरह अपारदर्शी थी। तब ज्यादातर चंदा नकद दिया जाता था। तब दलों को 20 हजार रुपये से कम के चंदे का विवरण न बताने की छूट थी। इसके चलते कई दल यह बताते थे कि उन्हें करोड़ों का चंदा मिला तो, लेकिन वह सब 20-20 हजार रुपये से कम का यानी फुटकर ही था। कोई भी समझ सकता है कि यह सही नहीं हो सकता। पहले किसी को यह पता नहीं चलता था कि किसने किसको कितना चंदा दिया। यह मानकर चला जाना चाहिए कि इसके चलते राजनीतिक दलों को अच्छा-खासा कालाधन मिलता होगा। चुनावी बांड की व्यवस्था खत्म होने के बाद से भारतीय राजनीति के फिर से कालेधन से संचालित होने की आशंका कहीं अधिक बढ़ गई है। लोकतंत्र का तकाजा यह कहता है कि जनता को यह पता चले कि किसने किसको कितना चंदा दिया, लेकिन इसकी कोई विश्वसनीय व्यवस्था बनाना आसान नहीं। इससे इन्कार नहीं कि चुनावी बांड की व्यवस्था जिस इरादे से लाई गई थी, वह पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज कोई यह बताने वाला नहीं कि चुनावी चंदे की नीर-क्षीर व्यवस्था क्या हो सकती है? चुनावी चंदे की साफ-सुथरी प्रक्रिया का कोई कारगर सुझाव उनके भी पास नहीं, जो चुनावी बांड के विरोध में खड़े थे और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं।

चुनावी बांड के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रेट्र

चुनावी चंदे का एक तरीका यह हो सकता है कि कारोबारी अथवा कंपनियां अपनी आय का एक निश्चित प्रतिशत चुनाव आयोग को दें और फिर वह आयोग दलों को उन्हें मिले मत प्रतिशत के हिसाब से उनमें बांट दे, लेकिन यदि कोई अपने पसंदीदा दल को ही चंदा देना चाहे तो? कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती हैं कि वे किसी को चंदा न देना चाहें। क्या उन्हें इसके लिए बाध्य किया जाएगा? चुनावी चंदे को लेकर यह एक सुझाव बार-बार आता है कि सरकारी खजाने से राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा मिले, लेकिन क्या इसके बाद दलों को सरकारी कोष से मिले धन से अधिक खर्च करने से रोका जा सकता है? क्या यह किसी से छिपा है कि एक बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में तय सीमा से अधिक पैसा खर्च करते हैं। वे खर्च करोड़ों में करते हैं, लेकिन कागजों में लाखों में ही दिखाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि सभी इस पर तो जोर दे रहे हैं कि चुनावी चंदे की साफ-सुथरी व्यवस्था बने, लेकिन कोई भी यह नहीं कह रहा है कि इसके साथ ही ऐसी भी व्यवस्था बने, जिससे कोई भी सरकार अपने किसी पसंदीदा कारोबारी या कंपनी को नियम-कानूनों में ढील देकर ठेका न दे सके और न ही अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर उस पर अनुचित दबाव डाल सके। आखिर कौन नहीं जानता कि कुछ कारोबारी और कंपनियां किस तरह दल विशेष की सरकार में दिन दूनी-रात चौगुनी गति से प्रगति कर जाती हैं या फिर उनका बेड़ा गर्क हो जाता है? साफ है कि समस्या कहीं और है और समाधान कहीं और खोजा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड की व्यवस्था इसलिए खत्म की, क्योंकि उसने पाया कि गोपनीयता के अधिकार से सूचना का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इस अधिकार को खुद सुप्रीम कोर्ट कोई भाव नहीं देता और इसीलिए उच्चतर न्यायपालिका के जज अपनी संपत्ति का विवरण घोषित नहीं करते। इसे ही कहते हैं 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे।' यदि आप राहुल गांधी नहीं हैं तो शायद यह मानते होंगे कि सारे कारोबारी चोर नहीं होते। आखिर ऐसे जिन कारोबारियों ने चुनावी बांड कानून के गोपनीयता वाले प्रविधान के तहत इस भरोसे चंदा दिया होगा कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं होगा, उनका क्या दोष?

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का वास्तविक अर्थ

हमारे अमूल्य जीवन का मूल्य ब्रह्मांड में उपलब्ध किसी भी मूल्यवान वस्तु से नहीं आंका जा सकता। जीवन वास्तव में समय की पटरी पर चलने वाली एक ऐसी गाड़ी है, जिसमें गंतव्य तक पहुंचने का आनंद भी है तो कहीं गत्यावरोधकों का त्रास भी है। जीवन में सुख की चाहे कितनी ही सामग्री क्यों न हो, किंतु छोटी सी प्रतिकूल घटना भी कष्ट उत्पन्न कर देती है। किसी अपने के द्वारा जरा सा अपमानजनक प्रसंग पीड़ा दे जाता है। थोड़ी सी निंदा मन की प्रसन्नता छीन लेती है। किसी के कटु शब्द जीवन में कड़वाहट पैदा कर देते हैं।

हम सभी अपने-अपने अतीत के साए में घिरे वर्तमान को मानसिक द्वंद्वों से घसीटते हुए वक्त गुजारते हैं। जीवन को जीते कम और ढोते ज्यादा हैं। नित-प्रति बहुत कुछ अनदेखा-अनचाहा और अनहोना होता है। ऐसी परिस्थितियों में स्वीकार भाव से जीना ही जिंदादिली है। इस जिंदादिली का राज है कि जो भी मिला, उसका आनंद उठाएं। जो भी कुछ अच्छा-बुरा, शुभ-अशुभ, अनुकूल-प्रतिकूल मिला है, उसे समग्रता से स्वीकार करें। अभिप्राय मात्र इतना ही है कि जीवन के समस्त क्षणों का, प्रत्येक परिस्थितियों का सदुपयोग करने की कला सीखना ही जिंदादिली से जीना है। हम जितना स्वीकार भाव की क्षमता को बढ़ाएंगे, हमारा जीवन उतना ही जीवंत होता जाएगा।

यह सदैव स्मरण रहे कि सुख और दुख दोनों ही अपने नहीं हैं। हमें इनका चुनाव नहीं, अपितु दोनों को स्वीकार करना होगा। दुख हमें कमजोर बनाता है और सुख हमें बंधन में डाल देता है। जिस दिन अप्रिय वस्तु, अनचाहा व्यक्ति और प्रतिकूल परिस्थिति का सहयोग और वांछित वस्तु, प्रिय व्यक्ति एवं अनुकूल परिस्थितियों का वियोग, इन दोनों को प्रसन्नता से स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन हमारे जीवन को वास्तविक अर्थ मिल जाएगा।

डा. निर्मल जैन

शहरी कृषि का बढ़ता प्रचलन

सुधीर कुमार

शहरी कृषि लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है, क्योंकि अब उन्हें बार-बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है

जनसंख्या में वृद्धि और शहरीकरण के विस्तार के साथ शहरों में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल घटता जा रहा है। आमतौर पर शहरों में कृषि-कर्म का अभाव दिखाई पड़ता है। शहरों में कृषि योग्य या बंजर भूमि पर भवन, आधारभूत संरचनाओं और कल-कारखानों का बसावट होता है। शहरों को खाद्य पदार्थों के लिए सन्निकट गांवों और पैकेटबंद खाद्य सामग्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में शहरी खाद्य सुरक्षा और खाद्य आत्मनिर्भरता के लिए वैकल्पिक कृषि के रूप में 'शहरी कृषि' का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा में शहरी कृषि की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। शहरी कृषि को तीव्र शहरीकरण का उद्धारक माना जाता है। शहरी कृषि तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, खाद्य संकट और जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण समाधान माना जाता है। शहरी कृषि के विभिन्न प्रकार हैं जैसे, किचन गार्डनिंग, रूफटाप गार्डनिंग, वर्टिकल फार्मिंग, कंटेनर गार्डनिंग, मधुमक्खी पालन आदि। शहरी कृषि में स्वयं उपभोग या बिक्री के लिए उगाए गए खाद्य और गैर-खाद्य उत्पाद शामिल हैं। शहरी कृषि में परंपरागत कृषि की तरह न तो विस्तृत भूखंड की आवश्यकता होती है और न ही अत्याधुनिक कृषि संयंत्रों, सिंचाई के साधन और अधिक श्रम-बल की ही दरकार होती है। इसके तहत शहरों में घरों की छत या बालकनी या किसी अन्य खुली जगह खाद्य उत्पादन किया जाता है। वास्तव में शहरी कृषि कंक्रीट के जंगल में 'हरित भविष्य' खोजने का जरिया बन रहा है। यह शहरी आबादी के लिए पौष्टिक और सुरक्षित भोजन तक पहुंच को सुनिश्चित कर खाद्य जरूरत के मामले में आत्मनिर्भर बनाती है। इसके जरिये शहरवासी किसी भी वक्त ताजे फल एवं सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर शहरों में जो सब्जियां पहुंचती हैं, वह ताजी नहीं होती हैं। उन्हें फ्रिज के सहारे 'ताजा' रखा जाता है। वहीं सब्जियों और फलों के उत्पादन में कीटनाशकों के प्रयोग से भी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। शहरी कृषि पूरी तरह जैविक होती है।

शहरी कृषि से होने वाला उत्पादन लोगों को आत्मनिर्भर बना रहा है, क्योंकि अब उन्हें फल-सब्जियों को लाने के लिए बार-बार बाजार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इससे समय और धन की बचत होती है। चूंकि इस तरह की खेती शौक से की जाती है, इसलिए समय का कुशल उपयोग भी होता है। शहरी कृषि के जरिये खेती करने की सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने में कामयाबी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपने स्तर से जलवायु संकट के खिलाफ योगदान दे पाते हैं।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

होली का संदेश समझने की जरूरत

'रंग और उमंग का पर्व' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी पढ़ी। हमारे देश में रंगों का जो त्योहार मनाया जाता है, ऐसा त्योहार दुनिया के शायद ही किसी देश में मनाया जाता हो। हमारे देश में भी यह त्योहार सभी वर्गों के लोग मिल-जुलकर मनाते हैं, लेकिन समय के साथ-साथ बहुत से लोगों की रुचि अन्य त्योहारों की तरह अब होली में भी कम हो गई है। होली के रंग भी अब फीके से पड़ने लगे हैं। आधुनिक जीवनशैली और स्मार्टफोन की बढ़ती लत का असर इस त्योहार पर भी पड़ता दिख रहा है। जबकि यह त्योहार हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन के साथ ही दूसरों की जिंदगी में भी खुशी के रंग भरने की कोशिश करनी चाहिए। हम किसी भी तरह से दूसरों के मददगार बनते हैं तो इससे हमें भी एक अलौकिक सुख की अनुभूति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। हमारे देश में हमेशा खुशियों के रंग बिखरते रहें, इसके लिए हमेशा देश के हित में काम करने चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिससे देश में खुशियों का रंग फीका पड़ जाए।

raju09023693142@gmail.com

अमर्यादित मोहब्बत की दुकान

कांग्रेस नेत्री के हैंडल से जिस तरह मंडी (हिमाचल प्रदेश) लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनोट के लिए असहनीय, अमर्यादित एवं बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, वह सर्वथा निंदनीय ही नहीं, वरन कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक लाइन मोहब्बत की दुकान और महिला सशक्तीकरण की बुनियाद पर सवालिया निशान ज्यादा लगाते हैं। इस विषय पर राष्ट्रीय महिला आयोग का संज्ञान लेना स्वागत योग्य है। वर्तमान परिदृश्य से लगता है कि कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करने में माहिर हो चुकी है। कभी कांग्रेस पार्टी को वाराणसी में युवा वर्ग शराबी नजर आता है। कभी देश का प्रधानमंत्री मोदी और उनके परिवार को लेकर तंज कसा जाता है, लेकिन बंगाल के संदेशखाली में दलित महिलाओं पर अत्याचारों सहित दुष्कर्म की पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं पर चुप्पी साधना यकीनन मीठा-मीठा गप-गप और कड़वा-कड़वा थू-थू को ही चरितार्थ करता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दो मासूम बच्चों की हृदय विदारक हत्या पर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तुष्टीकरण की छिछली राजनीति की, लेकिन इसी विषय पर लगा जैसे कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया। इस तरह बदायूं और संदेशखाली राजनीतिक पर्यटन स्थल की सूची से बाहर हो गए। वहीं अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले को उजागर करने का दंभ भरने वाली कांग्रेस पार्टी आज गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री पर राजनीतिक विलाप करती दिखाई देती है। कितना हास्यास्पद है कि विपक्षी दलों के सिर सुविधा की राजनीति का ग्राफ कितना ज्यादा चढ़ कर बोलता है। निस्संदेह इस तरह की राजनीति दोगलेपन की पराकाष्ठा है। 31 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में होने वाली आइएनडीआइए की रैली से विपक्षी दलों को कितनी राजनीतिक आक्सीजन मिलेगी, समय के गर्भ में विद्यमान है।

दीपक गौतम, सोनीपत

चुनाव में उत्तर प्रदेश की अहमियत

चुनाव इतने बहुरंगी और रोमांचक कहीं नहीं होते हैं, जितने उत्तर प्रदेश में। इस राज्य में खासी गर्मी रहती है। लोकसभा की 80 सीटों वाले प्रदेश से ही दिल्ली की राजगद्दी मिलती है। इस बार राजनीतिक मंथन शुरू हो चुका है। भाजपा का दावा है और प्रयास रहेगा कि 80 में से 80 सीटें वह ले जाएगी। यह संभव लगता है। जबकि कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि शायद खाता भी न खुल पाए। समाजवादी सीटों को लेकर गणित बैठा रही है। मायावती के लिए भी राह आसान नहीं है। खाता खुल भी सकता है या नहीं भी खुल सकता है। चुनाव में मतदाताओं के मन को नहीं भांपा जा सकता है। उत्तर प्रदेश ने आठ प्रधानमंत्री दिए हैं।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****